बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 98

नई शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी शपथ ग्रहण की। भारत जैसे विविधता से भरे लोकतंत्र में दो सफल कार्यकाल के बाद तीसरी बार पद पर लौटना सराहनीय तो है किंतु इस बार मोदी सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझेदारों पर निर्भर रहेंगे। नई सरकार की बुनियादी प्राथमिकताएं जहां आने वाले दिनों में हमारे सामने होंगी, वहीं चिंता इस बात की भी है कि कहीं गठबंधन सरकार में सुधारों को अंजाम देना मुश्किल न साबित हो। बहरहाल अनुभव तो यही बताते हैं कि गठबंधन सरकारें न केवल प्रभावी ढंग से काम करती हैं बल्कि वे ढांचागत सुधारों को भी अंजाम देती हैं। भारत को अगर मध्यम अवधि में निरंतर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करनी है तो उसे निरंतर सुधारों को अपनाना होगा। यह बात ध्यान देने लायक है कि बहुप्रतीक्षित कारक बाजार सुधारों को अंजाम देने का काम तो एक पार्टी के बहुमत वाली सरकारों में भी मुश्किल साबित हुआ है।

ऐसे सुधारों पर सहमति बनाने में अवश्य समय लग सकता है लेकिन सरकार ऐसी पहल से शुरुआत कर सकती है जिन पर साझेदारों को आपत्ति होने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए सरकार को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया जीएसटी परिषद में शीघ्र शुरू करनी चाहिए। हालांकि हाल के वर्षों में जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है। इसकी वजह अनुपालन में सुधार है किंतु दरों की बहुलता के कारण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय परिणाम प्रभावित हुए हैं। एक सामान्य जीएसटी प्रणाली जिसमें सीमित स्लैब हों, वह राजस्व में बेहतरी लाएगी और कारोबारी सुगमता को भी बेहतर बनाएगी। इसके अतिरिक्त भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में कम से कम तीन ऐसे प्रमुख वादे किए गए जिन पर तत्काल अमल शुरू किया जा सकता है।

इनमें से पहला है देश की सांख्यिकीय व्यवस्था। भारत जैसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाले देश में यह अहम है कि आंकड़ों की गुणवत्ता विश्वसनीय हो। ऐसे आंकड़े सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। सरकार ने काफी अंतराल के बाद हाल ही में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला में संशोधन के पहले एक और बार ऐसा करना चाहिए। भारत को उत्पादक मूल्य सूचकांक की भी आवश्यकता है ताकि उत्पादन के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी निरंतरता के साथ विश्वसनीय आंकड़े हासिल करना आवश्यक है। चूंकि कुछ संकेतक पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं इसलिए शायद वे मौजूदा हालात को सही ढंग से सामने नहीं रख पा रहे हों। इससे नीतिगत निर्णय की गुणवत्ता प्रभावित होगी और आर्थिक परिणामों पर असर होगा।

दूसरा है अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय अभियोग नीति। विभिन्न अदालतों में करीब पांच करोड़ मामले लंबित हैं। भारत को अपनी न्यायिक क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है। अदालतों में मामलों का तेज निपटारा कारोबारी सुगमता और देश में रहना दोनों को आसान बनाएगा। तीसरा है पंचायती राज संस्थानों में वित्तीय स्वायत्तता। सर्वाधिक विकसित तथा तेजी से विकसित होते देशों में बुनियादी सरकारी सेवाएं स्थानीय निकाय देते हैं। भारत में स्थानीय निकाय ऐसे अनुदान पर आश्रित होते हैं जो अक्सर अपर्याप्त एवं अनियमित होता है। रिजर्व बैंक के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय कर एवं शुल्क पंचायतों के कुल राजस्व में महज 1.1 फीसदी के हिस्सेदार होते हैं। स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण एक अहम कदम होगा। इसके लिए राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी लेकिन इससे विकास संबंधी नतीजों में बेहतरी आएगी। कुल मिलाकर अगले पांच सालों में बेहतर नीतिगत नतीजे हासिल करने के लिए यह अहम है कि संसद को समुचित ढंग से काम करने दिया जाए। यह सरकार का दायित्व होगा कि वह विपक्ष के साथ सकारात्मक संबंध बनाए तथा बेहतर विधायी परिणाम हासिल करे।

हिंदू-मुस्लिम एकजुटता की राजनीति में वापसी

मुस्लिम वोट भाजपा की सबसे बड़ी चिंता है। आम चुनाव में कमियों की तलाश शुरू भी हो चुकी है। बिना उत्तर प्रदेश में अपनी हालत सुधारे भाजपा की मुश्किलें और उसका पराभव लगातार बढ़ने की आशंका है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

इस आम चुनाव में सबसे कम चर्चित सुर्खी मुस्लिम मतों की ताकत की वापसी है। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिमों की राजनीतिक शक्ति अथवा नए मुस्लिम नेतृत्व का उभार हुआ है। यह केवल मुस्लिम मतों की ताकत की नए सिरे से तलाश है। महत्त्वपूर्ण बात है कि चुनाव नतीजे उस समय आए जब कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा था कि मुस्लिमों को अभी भी लगता है कि वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि भारत पर किसका शासन होगा। टाइम्स नाऊ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, 'मैं मुस्लिम समाज से पहली बार यह कह रहा हूं, उसके पढ़े लिखे लोगों से कह रहा हूं कि आत्ममंथन कीजिए आप पीछे क्यों छूट रहे हैं, इसका कारण क्या है? आपको कांग्रेस के दौर में लाभ क्यों नहीं मिले? इस पर आत्ममंथन कीजिए। आपने यह जो भावना पाली है कि आप तय करेंगे कि कौन सत्ता में रहेगा और किसे हटा दिया जाएगा, वह आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। पूरी दुनिया में मुसलमानों में बदलाव आ रहा है।'

ऐसा लगता नहीं है कि मुस्लिमों ने उनकी बात सुनी। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए, दोनों राज्यों में 'इंडिया' गठबंधन के वोटों का प्रतिशत इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अधिक रहा। बिना मुस्लिम मतों के यह संभव नहीं था। एक्जिट पोल तथा अन्य शोधों से हासिल आंकड़े हमें यही बताते रहे हैं कि मुस्लिमों ने हमेशा रणनीतिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए वोट दिया। हमें यह सवाल पूछना होगा कि इस बार वे इस कदर कामयाब कैसे रहे, खासकर उत्तर प्रदेश में। इतना ही नहीं बिहार और असम में उन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिली जबकि इन दोनों राज्यों में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और 'इंडिया' गठबंधन भी मजबूत है।

इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि 2014, 2019 और 2024 के तीन लोकसभा चुनावों तथा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोक सभा सीट और 403 विधानसभा सीट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके बावजूद उसे बहुमत हासिल होता रहा। इस बार यह नाटकीय बदलाव कैसे?

यह भाजपा की सबसे बड़ी चिंता है। पार्टी की इस अहम कमजोरी को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ के पक्ष-विपक्ष में भी चर्चाएं चालू हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा की इस गिरावट में निरंतरता देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने एक्जिट पोल करने वालों की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और भाजपा के विरोधियों और समर्थकों दोनों को चौंकाया। उत्तर प्रदेश के करीब 20 फीसदी (2011 के बाद जनगणना न होने के कारण सभी आंकड़े लगभग में) के उलट पश्चिम बंगाल में करीब 33 फीसदी मुस्लिम हैं। इसके बावजूद 2019 में भाजपा को वहां 42 में से 18 लोक सभा सीट पर जीत मिली थी। इस बार उसे और अधिक सीट पर जीत की उम्मीद थी लेकिन पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में आधी सीट से कम पर निपट गई आखिर क्यों? भाजपा जिन राज्यों में सीट जीत सकती है वहां वह एक सामान्य फॉर्मूले पर काम करती है और वह है 50 फीसदी से अधिक हिंदू मत हासिल करना। उत्तर प्रदेश में यह कारगर रहा है और इसके कारण करीब 20 फीसदी मुस्लिम मत बेमानी हो गए। पश्चिम बंगाल और असम में मुस्लिम आबादी अधिक होने की वजह से पार्टी को कम से कम 60 फीसदी हिंदू मतों की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे दशकों पुराने इस अवधारणा को खारिज करते हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की राजनीति मुस्लिम मतों को राष्ट्रीय स्तर पर अप्रासंगिक बना सकती है।

हमने अब तक मुस्लिम मतों की शक्ति को लेकर जो भी सवाल उठाए हैं उनका जवाब बेहद सामान्य है: हिंदू वोट। यह स्थापित बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की स्थापना के साथ भारत से जाने के बाद भारतीय मुस्लिमों ने कभी अपने समुदाय के किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं माना। यहां तक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नहीं। उन्होंने भरोसे के लिए हमेशा हिंदू नेताओं की ओर देखा।

सन 1989 तक आमतौर पर वे कांग्रेस के साथ थे लेकिन बाबरी मस्जिद के ताले खुलने के साथ उनका भरोसा दरक गया। तब यह वोट बैंक बचाव का आश्वासन देने वाली अन्य शक्तियों के पास चला गया। इनमें अधिकांश हिंदी प्रदेशों के लोहियावादी समाजवादी नेता थे, मसलन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद। पश्चिम बंगाल में वे वाम दलों के साथ हो गए। महाराष्ट्र और केरल में तथा दक्षिण में अन्य विकल्पों के अभाव में मुस्लिम कांग्रेस के साथ बने रहे।

दूरदराज इलाकों में कुछ मुस्लिम नेतृत्व चुनौती की तरह उभरे। मुस्लिमों ने जिन नेताओं को चुना वे अपने दम पर सत्ता दिला पाने में सक्षम नहीं थे। इन नेताओं ने पर्याप्त संख्या बल वाले हिंदुओं के साथ गठबंधन किया। मुलायम और लालू के साथ यादव तथा पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियां थीं। वाम के साथ बड़ी संख्या में बंगाली हिंदुओं का निम्न वर्ग था और कांग्रेस के साथ विंध्य के दक्षिण का एकजुट वोट बैंक था।

हिंदी प्रदेशों में यह तब तक कारगर रहा जब तक कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच बंट रहा था। तब 28-30 फीसदी मतों के साथ भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सत्ता पाई जा सकती थी। 2002 में मुलायम, 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश यादव और अनेक बार लालू प्रसाद यह कारनामा करने में कामयाब रहे। तरीका यही था कि एक या दो जाति आधारित हिंदू जातियों वोट बैंक तथा मुस्लिमों को अपने साथ करके सत्ता पाई जा सकती थी। मोदी के उभार से यह फॉर्मूला नाकाम हो गया। ज्यादातर हिंदू उनके साथ चले गए और यादव तथा मायावती के पास ही उनके वोट बैंक रह गए।

इस चुनाव में क्या बदला? पहली बात, मुस्लिमों के उन्हीं हिंदू नेताओं ने बीते पांच साल में बहस को बदल दिया और मुस्लिम मुद्दों पर कभी आक्रामक ढंग से बात नहीं की। अगर भाजपा ने 2014 में सात और 2019 में तीन के बाद इस लोक सभा चुनाव में केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया तो इसे समझा जा सकता है। परंतु समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश की 80 लोक सभा सीट में से क्रमशः केवल चार और दो पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 में से छह सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। उनकी कोशिश थी कि मुस्लिमों पर अपनी निर्भरता को छिपाया जाए या कम किया जाए। मुस्लिम धर्मगुरु और कट्टरपंथी भी खामोश रहे। भाजपा को ध्रुवीकरण करने का अवसर नहीं दिया गया। जरा सोचिए कि आखिर भाजपा ने संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा इस तरह क्यों उठाया?

आंकड़े बताते हैं कि बनर्जी भाजपा को 60 फीसदी हिंदू मत पाने से इसलिए रोक सकीं क्योंकि महिलाओं में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। भाजपा को लग रहा था कि संदेशखाली मामला ममता बनर्जी को झटका देगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नतीजा हमारे सामने है।

असम में बदरुद्दीन अजमल को एक भी सीट नहीं मिली। परिसीमन इस प्रकार किया गया कि अधिकांश मुस्लिम मत एक लोक सभा क्षेत्र ढुबरी में केंद्रित हो गए। अब उनका प्रभाव सभी तीन सीट पर नहीं रहा। सीधे मुकाबले में कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने न केवल अजमल को हराया बल्कि वह देश भर में सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीते।

मेरी नजर में यह मुस्लिमों के मस्तिष्क के पुराने ढर्रे पर लौटने का उदाहरण है। वे उन दलों की ओर लौट रहे हैं जो पर्याप्त हिंदू मतों के साथ सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन कर सकते हैं। असम और बिहार से इसे आसानी से समझा जा सकता है। असम में जाति आधारित विभाजन के अभाव के कारण कांग्रेस अधिक हिंदू मत नहीं हासिल कर सकी। बिहार में भाजपा के साझेदारों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने दलित मतों को एकजुट रखा जबकि उत्तर प्रदेश में मायावती ऐसा नहीं कर सकीं।

इन्हीं वजहों से हमें मुस्लिम मत पर्याप्त हिंदुओं के साथ साझेदारी में ताकतवर होते दिख रहे हैं। यह भविष्य की राजनीति का स्पष्ट संकेत है।

नतीजे कर रहे हैरान मगर जनता भी थी परेशान

सामयिक सवाल

निवेदिता मुखर्जी

एक पुरानी कहावत है कि यात्रा का भी उतना ही महत्त्व होता है जितना मंजिल पाने का। वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव और उसके हतप्रभ करने वाले परिणामों के साथ भी लगभग यही कहावत चरितार्थ हो रही है। नतीजे आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है मगर गठबंधन की राजनीति में सियासी उठापटक की आशंका तो बनी ही रहती है।

जब मतगणना चल रही थी तो रोमांच चरम पर था और इंडिया भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को कड़ी टक्कर देता दिख रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों गठबंधनों में कांटे की टक्कर है जबकि कुछ लोगों ने अनुमान जताया कि यह मुकाबला आखिरी दम तक चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि नतीजे सबके लिए चौंकाने वाले थे। मगर पिछले 45 दिन से समाचारपत्रों में प्रकाशित चुनाव से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करने और देश के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं की नब्ज टटोलने गए हमारे सहकर्मियों ने जो देखा उनसे नतीजों को समझने में मदद मिली। हालांकि, कुछ बातें अब भी स्पष्ट नहीं हुई हैं।

सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। वर्ष 2014 और 2019 में हुए लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सभी 26 सीट पर जीत मिली थी। मगर 2024 में उसे बनासकांठा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। राज्य के इस ग्रामीण जिले में दुग्ध उत्पादन प्रमुख व्यवसाय रहा है। इस पर कांग्रेस की गेनीबेन ठाकोर ने भाजपा की रेखाबेन चौधरी को शिकस्त दी। हमारे संवाददाताओं ने गुजरात के कई संसदीय क्षेत्रों में राजनीतिक हवा का रुख परखने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के अन्य हिस्सों की तरह ही रोजगार, महंगाई और ऊंचे कर वहां भी प्रमुख मुद्दे थे। इनके अलावा स्थानीय स्तर पर क्षत्रिय एवं राजपूत से जुड़े जातिगत मुद्दे भी चुनाव पर असर डाल रहे थे। राज्य के राजकोट और सौराष्ट्र क्षेत्रों में क्षत्रियों के आंदोलन की धमक राज्य के उत्तरी हिस्सों बनासकांठा और पाटन में भी दिखी जहां इस समुदाय की अच्छी पकड़ है।

चुनाव के नजदीक आते ही यह चर्चा गर्म हो गई कि कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण भाजपा अपने मजबूत गढ़ गुजरात में एक या दो सीट पर हार का मुंह देख सकती है। ये मुद्दे क्षत्रिय, पाटीदार और पटेल समुदायों से जुड़े थे। मगर ये मुद्दे चुनावी घमासान से जुड़ी विषयों में कहीं न कहीं खो गए। गुजरात को लेकर एक बात जिस पर ध्यान नहीं दिया गया कि मुख्य सौराष्ट्र क्षेत्र में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की। यहां केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों पर एक टिप्पणी कर दी जिससे उन्हें क्षत्रिय समुदाय के गुस्से का सामना करना पड़ा। रूपाला ने अपनी इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगी। रूपाला ने गुजरात में चुनाव से ठीक एक दिन पहले कहा था कि क्षत्रिय मुद्दे से चुनाव नतीजे प्रभावित नहीं होंगे। मंगलवार को आए नतीजे में यह बात दिखी भी और वह भारी मतों से विजयी हुए।

उत्तर प्रदेश ने बहुमत पाने की भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, भले ही राजग मशक्कत से ही सही मगर सरकार बनाने की स्थिति में आ गया। चुनावी मैदान से आ रही खबरों में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि स्पष्ट मुद्दे थे। अयोध्या में मंदिर बनाने के भाजपा को फैजाबाद सहित पूरे राज्य में राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद थी मगर वहां जमीनी सच्चाई कुछ और थी। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में संघर्ष करना पड़ रहा था। फैजाबाद सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से शिकस्त मिली। ऐसा लगा कि राम मंदिर बनने के बाद धार्मिक भावना प्रबल हो गई मगर आर्थिक मुद्दा कहीं न कहीं इस पर भारी पड़ा। एक दूसरे संवाददाता ने जब अयोध्या में स्थानीय लोगों से बात की तो यह बात छन कर आई कि वहां के लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा था। स्थानीय लोगों के अनुसार अयोध्या को एक पर्यटन स्थल बनाने और इसे विश्व के नक्शे पर लाने के चक्कर में यहां कई चीजें महंगी हो गईं और गरीब लोगों की जद से बाहर हो गईं। अयोध्या में व्यावसायिक रियल एस्टेट जोर पकड़ने लगा जिससे लोगों का जीवन और दुष्कर हो गया। यह अलग बात है कि इस प्रक्रिया में रोजगार के अवसर भी सामने आए होंगे।

मुंबई की बात करें तो वहां भाजपा को केवल एक सीट पर जीत मिली। इसके उम्मीदवार पीयूष गोयल उत्तर मुंबई सीट से विजयी रहे। मुंबई महानगर की बाकी पांच सीट दूसरे दलों को मिलीं। उत्तर मुंबई के अलावा मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई दक्षिण सहित तीन अन्य क्षेत्रों में बॉलीवुड कलाकार, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां और छोटे एवं मझोले उद्यमों से जुड़े लोग रहते हैं। क्या ये लोग मांग की खस्ता हालत और उद्योगों द्वारा लचर निवेश के बारे में सोच रहे थे या कोई दूसरा कारण था?

भारत के कुछ अन्य हिस्सों में खासकर उत्तरी भाग में लघु एवं मझोले उद्योग अब भी नोटबंदी से हुए नुकसान से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इसके अलावा लोग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और कोविड-19 के असर भी परेशान करते रहे हैं। पंजाब में विनिर्माण इकाइयों की जरूरत और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के सख्त नियम कारोबारों के लिए बाधा बताए जा रहे हैं।

दिल्ली में भी मतदाताओं ने ऐसी ही आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया था मगर भाजपा यहां सातों सीट पर कब्जा जमाने में सफल रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर बाहर आकर कुछ दिनों तक जमकर चुनाव प्रचार किया मगर इससे उनकी पार्टी की किस्मत नहीं बदली। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस दोनों ही के मत प्रतिशत बढ़े हैं मगर ये सीट में तब्दील नहीं हो सके।

हमने लोक सभा चुनाव में मतदाताओं का मूड टटोलने की शुरुआत रेल यात्राओं के साथ की थी। इन यात्राओं के दौरान हमारे संवाददाताओं ने देश के एक दूसरे से दूसरे हिस्से तक लोगों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों को समझने और उन्हें सामने लाने की कोशिश की।

इन यात्राओं के दौरान लोगों ने रोजगार एवं श्रम से जुड़ी कई आर्थिक मुद्दों का भी जिक्र किया। तो क्या 2024 का लोक सभा चुनाव राजनीति के बजाय आर्थिक मुद्दों के इर्द-गिर्द अधिक घूम रहा था? कम से कम चुनाव के दौरान नजर आईं बातें जीवन एवं जीविका से जुड़ी थीं, हां बाकी विषयों पर फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

आपका पक्ष

जल संकट से निपटने में सभी की भूमिका सुनिश्चित हो

जल संकट समस्या पर प्रशासन सहित सभी का ध्यान आकृष्ट होना आवश्यक है। हर साल अप्रैल-मई में जल संकट से निपटने के उपायों की चर्चा तो खूब जोर-शोर से होती है, लेकिन जून में मॉनसून आते ही सारी कवायदें शिथिल हो जाती हैं। अब हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि जल संकट से जूझ रहे देश के विभिन्न शहरों एवं कस्बों की वर्तमान दुर्दशा क्षितिज पर मंडरा रहे एक वैश्विक संकट को दर्शाती है जो जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और अस्थिर जल प्रबंधन जैसे विभिन्न कारकों द्वारा बढ़ाई गई हैं। पिछले दिनों बेंगलूरु में जल संकट न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि यह सभी शहरों के लिए एक चेतावनी भी है। इस तरह के संकट को रोकने के लिए सक्रिय उपाय महत्त्वपूर्ण हैं। वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और जल-कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश से सुधार हो सकता है। साथ ही सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत स्तर पर जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जल-सुरक्षित भविष्य के निर्माण में आवश्यक स्तंभ हैं। अधिक जल-सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप, सूचित उपभोक्ता विकल्प और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सरकारों को जल प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले नियामक ढांचे को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरह, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जल प्रबंधन को अपनाना चाहिए, ऐसी प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो अपशिष्ट को कम करें और संरक्षण को प्राथमिकता दें।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

बेंगलूरु शहर में पिछले दिनों भीषण जल संकट हो जाने के बाद टैंकरों से जलापूर्ति की गई

खाद्य सुरक्षा और हम

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को दुनियाभर में मनाया गया। इसका शुभारंभ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2018 में किया गया था। इसका एक उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स-2021 अनुसार दुनिया में 2019 में लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बरबाद हो गया। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति 50 किलो खाने की बरबादी हो रही है। देश में भी खाने की बहुत बरबादी तो होती है वहीं भूखे पेट सोने वालों की तादाद भी कम नहीं है। देश में बच्चों में कुपोषण का आंकड़ा भी कम नहीं है। खाने की बरबादी रोकने के लिए सामाजिक या अन्य समारोहों में उचित मात्रा में ही भोजन बनाना चाहिए। फल, सब्जियां भी अधिक मात्रा में नहीं खरीदनी चाहिए जिससे वे बेकार हो जाए। घर में भी जरूरत अनुसार ही भोजन तैयार करना चाहिए। बच्चों को भी भोजन की बरबादी रोकने के बारे में समझाना चाहिए। देश में खाद्य सुरक्षा और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। देश में संतुलित आहार के अभाव में लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो चिंता का विषय है। वैश्विक महामारी कोरोना ने दुनिया को यह भी समझाया कि दूषित भोजन किस तरह आफत बन सकता है। इस महामारी की वजह चीन में कुछ लोगों द्वारा दूषित खानपान था। आज देश में बच्चों का खानपान उचित नहीं होने से बच्चों की सेहत भी खराब हो रही है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (बाएं) ने रविवार को नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 10 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

कई आशंकाओं के साथ मोदी फिर पीएम

पहले दो बार की तरह उत्साह के साथ नहीं बल्कि कई आशंकाओं के बीच रविवार को नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद सम्हाल लिया है। उन्होंने इस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी तो कर ली लेकिन उनकी यह पारी कई तरह के खतरों के बीच शुरू हो रही है। उनके पद सम्हालने के पहले ही यह सवाल पूछे जाने लगे थे कि आखिर यह सरकार कब तक चलेगी।

इन आशंकाओं के मजबूत आधार हैं। उसके कई आयाम भी हैं। पहली बात तो यही है कि मोदी सरकार पहले दो बार की भांति अपने बूते नहीं वरन दो दलों की बैसाखियों पर खड़ी है। आंध्रप्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के चन्द्रबाबू नायडू ने अपने 16 और बिहार के नीतीश कुमार ने अपने जनता दल (यूनाइटेड) के 12 सदस्यों के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस (एनडीए) का हिस्सा बनकर मोदी की ताजपोशी कराई है। दोनों के साथ मोदी व भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खट्टा-मीठा रहा है। एनडीए के कहने को तो और भी कई सहयोगी दल हैं पर इतनी हैसियत किसी अन्य में नहीं है कि वे मोदी सरकार को गिरा सके। टीडीपी और जेडीयू के समर्थन को जितना मजबूत टेका माना जा रहा है, वे ही सबसे कमजोर कड़ियां भी बतलाई जा रही हैं। इसका कारण यह है कि वैचारिक रूप से दोनों पार्टियां भाजपा से दूर हैं। फिर, दोनों के लिये प्रांतीय हित उनकी राजनीतिक वरीयता में हैं। दोनों का इतिहास एनडीए का हाथ कभी धरने का तो कभी झटकने का रहा है।

अगर इस मुद्दे पर बात करें कि आखिर क्यों इन दो पार्टियों के सन्दर्भ व परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जा रहा कि ये दोनों दल एनडीए सरकार से कभी भी अलग हो सकते हैं, तो जवाब है कि अनेक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उनका भाजपा के साथ टकराव होना तय है। मसलन, टीडीपी अल्पसंख्यकों की हितैषी मानी जाती है जबकि भाजपा का नज़रिया इस बाबत जगजाहिर है। जिस टीडीपी के साथ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के साथ हुआ विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, उसने मुस्लिमों के लिये कई तरह की आर्थिक मदद का वादा किया है। इनमें प्रमुख है हज जाने वालों के लिये 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, मदरसों, मौलवियों को हर माह नकद राशि आदि। भाजपा के लोग इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे, कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही, नीतीश बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं और देश में जाति आधारित जनगणना कराने के वे पैरोकार रहे हैं। भाजपा इसके विरोध में रही है। दोनों (चंद्रबाबू-नीतीश) ही अपने-अपने प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से यह मांग लटकाकर रखी गयी है, वह अब भी शायद ही पूरी हो। कारण यह है कि केन्द्र ने अगर यह मांग मान ली तो और भी अनेक राज्यों से यह मांग उठ सकती है। फिर, इसका श्रेय भी क्रमश: टीडीपी एवं जेडीयू को जायेगा और भाजपा या मोदी उसका राजनीतिक लाभ नहीं उठा पायेगी। आने वाले समय में इन मुद्दों पर परस्पर टकराव सम्भावित है। इतना ही नहीं, समान नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर आदि कई ऐसे मसले हैं जिन पर इन दोनों ही प्रमुख धड़ों की एनडीए से एकदम अलग राय है। इन दोनों सहयोगियों के रहते भाजपा इन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ सकेगी; और अगर नहीं बढ़ती तो वह अपने कोर वोटरों को नाराज़ व निराश दोनों ही करेगी। एक बात तो तय है कि भाजपा का मुस्लिम विरोधी एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकेगा जिससे भाजपा कमजोर पड़ेगी क्योंकि यही उसकी मजबूती है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्रप्रदेश में तो टीडीपी को इतना बड़ा जनादेश है कि वह भाजपा पर बिलकुल भी निर्भर नहीं है; पर दिल्ली में उसका साथ छोड़ देने पर केन्द्र सरकार गिर जायेगी। इसलिये चंद्रबाबू कहीं अधिक भारी पड़ रहे हैं। बिहार में अगले वर्ष चुनाव हैं। यदि नीतीश को लगता है कि उनके केन्द्र में एनडीए के साथ रहने से उनका विधानसभा में नुकसान होगा तो वे कोई और फैसला ले सकते हैं।

एनडीए इस बार संसद के बाहर व भीतर भी गिरे हुए मनोबल के साथ दिखाई देगी। जबकि इंडिया ब्लॉक बेहद मजबूती के साथ लौटा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस तकरीबन 100 सदस्यों के साथ उपस्थित होगा। इससे आधी संख्या में मोदी को पानी पिलाने वाली कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी दो स्थानों से जीतकर सदन में आएंगे जबकि मोदी पिछले चुनावों के मुकाबले इतने कम वोटों से जीते हैं कि उसे एक तरह से उनकी हार ही कहा जा रहा है। इस समय की लोकसभा की बैठकों में वे यह नहीं कह सकेंगे कि वे एक अकेले सब पर भारी है। इसके साथ ही मोदी की कहें या भाजपा या एनडीए की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंडिया पहले जैसी मजबूती से खड़ा है। पराजय के बाद भी उसमें कोई दरार नहीं पड़ी है। मोदी का वह दावा कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 जून की शाम को इंडिया बिखर जायेगा। लोकसभा में मजबूत विपक्ष भाजपा को हर रोज परेशान करेगा।

लोगों का एक यह भी अनुमान है कि सरकार चलाने के लिये और पद पर बने रहने की अनिवार्यता के चलते मोदी को सहयोगियों की भरपूर लल्लो-चप्पो करनी पड़ेगी। इससे उनके प्रति होने वाली उपेक्षा से भाजपा के सदस्यों में निराशा व नाराज़गी हो सकती है। यह नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है।

मैं शेरनी हूं!

सोनिया गांधी ने कहा मजाक में मगर यह सबसे सही है। मैं शेरनी हूं। वाकई एक शेरनी की तरह वह लगातार लड़ रही हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने के बाद उन्होंने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे हार गए हैं। नेतृत्व करने का अधिकार खो चुके हैं। सोनिया को अब यह सब कहने और करने की जरूरत नहीं है। राहुल, प्रियंका और पार्टी नई ताकत के साथ सामने आए हैं। मोदी को साधारण बहुमत से भी पीछे रोक दिया। मगर जैसा कि खुद सोनिया ने कहा और सही कहा कि वे स्वभाव से शेरनी हैं।

राहुल का सबसे बड़ा गुण उनकी निडरता माना जाता है। पिछले दस साल में जब अच्छे-अच्छे डर गए। व्यक्ति क्या संवैधानिक संस्थाएं डर गईं तब भी राहुल डटे रहे। इसी पृष्ठभूमि में अमेठी से जीते किशोरी लाल शर्मा की पत्नी ने राहुल के लिए सोनिया गांधी से कहा कि आपने शेर बच्चा पैदा किया है।

दरअसल किशोरी लाल शर्मा का परिवार पंजाबी हैं। और पंजाबी में आम मुहावरा है- शेर पुत्तर! वही उन्होंने हिन्दी में कहा। और सोनिया ने हंस कर जवाब दिया कि मैं भी तो शेरनी हूं।

इस दिलचस्प वाकये के एकाध दिन पहले ही हमने ट्वीट किया था कि संजय गांधी के लड़के को डरते हुए देखना बहुत दुखद है। हमने उसमें कहा था कि सिर्फ डीएनए ही कुछ नहीं होता है। परवरिश, माहौल भी बड़ी चीज होती है। जिसने संजय गांधी को देखा है वह जानता है कि डर और दबना क्या होता है वह संजय जानते ही नहीं थे। उन्हीं के बेटे वरुण को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वे चुप रहे। सब सोचते थे कि वे निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जबर्दस्त सफलता मिली है उस माहौल में वरुण का जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर ठीक है वह नहीं लड़े। लेकिन फिर उन्होंने भाजपा का भी प्रचार किया। मेनका गांधी फिर भी हारीं। और उनकी राजनीति खतम हो गई। मगर इसके साथ मेनका ने बेटे का राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा दिया। वरुण की पहचान गांधी होने के कारण ही थी। और केवल नाम से टाइटल से कुछ नहीं होता है। वह गुण परिवार का आना चाहिए। नहीं तो केवल नाम तो अरुण नेहरू का भी था। मगर आज कौन जानता है? किस को याद है? संजय गांधी का नाम सबको याद है। सबको याद रहेगा। वे तो केवल एक बार ही सांसद बने। और कुछ ही दिन रहे। मगर वरुण तो तीन बार सांसद रहे। लेकिन क्या अगर वे ऐसे ही डरे रहे तो कल कोई उन्हें याद करेगा?

इसी संदर्भ में हमने लिखा था कि संजय गांधी के बेटे को डरा हुआ देखकर दु:ख होता है। मगर साथ ही यह कहा था कि परवरिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही फर्क है सोनिया गांधी और मेनका में। सोनिया गांधी को भी अपने बच्चे बिना पिता के पालना पड़े। छोटे भाई संजय की तरह राजीव गांधी भी असमय चले गए। सोनिया पर भी दुखों का वैसा ही पहाड़ टूटा। परिवार कभी उस समय की तकलीफों, लोगों का साथ छोड़ जाने की बात नहीं करता है। बहुत बड़प्पन के साथ उसने अपना बुरा वक्त काटा। जो जानता है उसे मालूम है कि किस तरह उस वक्त राजीव गांधी के नजदीक रहे लोगों ने भी सोनिया के साथ धोखा किया। सोनिया गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला।

शकील अख्तर

आज ममता बनर्जी की बहुत बात की जा रही है। विपक्ष में सीटें जीतने के मामले में वह तीसरे नंबर पर रहीं। बंगाल में उन्होंने मोदी को रोक दिया। कांग्रेस सौ के बाद सपा 37 और ममता 29 पर रहीं। तो ममता का जिक्र हम इसलिए कर रहे थे कि उस समय 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो वे सोनिया से मिलकर उन्हें पूरी बात बता कर गईं थीं कि कैसे नरसिम्हा राव सीताराम केसरी बंगाल के नेताओं से मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

आज ममता बनर्जी की बहुत बात की जा रही है। विपक्ष में सीटें जीतने के मामले में वह तीसरे नंबर पर रहीं। बंगाल में उन्होंने मोदी को रोक दिया। कांग्रेस सौ के बाद सपा 37 और ममता 29 पर रहीं। तो ममता का जिक्र हम इसलिए कर रहे थे कि उस समय 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो वे सोनिया से मिलकर उन्हें पूरी बात बता कर गईं थीं कि कैसे नरसिम्हा राव सीताराम केसरी बंगाल के नेताओं से मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। ममता राजीव गांधी को हमेशा मानती रहीं। लेकिन उस समय और कांग्रेसी नेताओं ने नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी को खुश करने के लिए सोनिया के खिलाफ खूब षडयंत्र किए। बहुत अभद्र भाषा का भी उपयोग किया।

लेकिन यहां यही बताने के लिए लिखा है कि इन सबसे सोनिया छोटी नहीं हुईं। उनके मन में बदला लेने किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं आई। खुद उनके खिलाफ जो जितेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष का चुनाव लड़े उनके न रहने केबाद उनकी पत्नी कान्ता प्रसाद को टिकट दिया। बेटे जितिन प्रसाद को भी मंत्री भी बनाया। वही जितिन भाजपा में जाकर वरुण की सीट पीलीभीत से चुनाव लड़े और जीते। राजनीति में यह आंख फेर लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है।

राजीव और संजय दोनों के बेटों को धोखा देने का। खैर तो बात सोनिया की कर रहे थे। और इसलिए कि एक पूरी तरह अलग बैक ग्राउन्ड से आकर सोनिया जिस तरह भारतीय परिवेश में रच बस गईं और यहां के मुहावरे तक सीख लिए वह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहां तो उत्तर भारत में ही एक बोली के मुहावरे दूसरी बोली वाले नहीं समझते। एक दूसरे की भाषा बोली का रोज मजाक उड़ाते हैं।

सोनिया ने हिन्दी सीखी। भारतीय परम्पराएं। आप कभी महिलाओं से बात करो तो वे सोनिया के साड़ी बांधने का जिक्र जरूर करती हैं। कहतीं हैं कि जिस ने शुरू से साड़ी नहीं देखी, पहनी हो उसका ऐसी अच्छी साड़ी बांधना बहुत बड़ी बात है।

सोनिया ने जीवन में जितने उतार-चढ़ाव देखे वैसा कम लोगों के साथ होता है। मगर उन्होंने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। विपक्ष में रहीं तब भी और सरकार में रहीं तब भी। दोनों स्थितियों में उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। जब राजनीति में आईं तो कांग्रेसियों ने किया। और फिर भाजपा ने।

विदेशी मूल का सवाल उठाकर उन्हें डराना चाहा। मगर सोनिया को अपने भारतीय बहू होने का इतना गर्व था कि वे पीछे नहीं हटीं। उनके आत्मविश्वास की वजह से ही आज वह आरोप जिसे भाजपा सबसे बड़ा हथियार समझती थी खतम हो गया।

अब सोनिया के खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है। यह सोनिया की बहुत बड़ी जीत है। सोनिया दरअसल भारतीय महिला की उसी जिजीविषा का प्रतीक हैं जो हर विपरीत परिस्थिति में लड़ती रहती है। अपने अलग-अलग दायरों में। परिवार में, नौकरी में, सार्वजनिक जीवन में। और कभी हार नहीं मानती। हर हाल में अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा करती है।

यह देखने की बात है कि कैसे एक विदेशी परिवेश की लड़की ने दूसरे देश की सारी सभ्यता संस्कृति सीखी। भाजपा के लोग भी आज अपनी व्यक्तिगत बातचीत में सोनिया के संस्कारों की तारीफ करते हैं। चाहे एक पत्नी के रूप में, चाहे बहू के रूप में चाहे मां के रूप में। और राजनीति में एक ऐसी नेता के तौर पर जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया हो। लेकिन जनता से किए अपने सब वादे सरकार से पूरे करवाए हों।

किसान कर्ज माफी, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, महिला बिल, आरटीआई सब लेकर आईं। उनकी लाई सरकार थी। मगर कांग्रेसी इनमें से एक भी कानून पर राज़ी नहीं थे। सोनिया को पग पग पर संघर्ष करना पड़ा। वह तो 2011 में वे इन कांग्रेसियों और केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के भरोसे रह गईं कि वे अन्ना हजारे को समझा लेंगे। नहीं तो अगर वे खुद अपने हाथ में मामला रखती तो 2013 में न दिल्ली सरकार जाती और न 2014 में केन्द्र सरकार।

लेकिन सरकारें चली गईं। सोनिया का इकबाल नहीं गया। वह आज भी कायम है। और इसलिए जब वे कहती हैं कि मैं भी शेरनी हूं तो सबको लगता है कि बिल्कुल सही बात है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगा बेरोजगारी संकट

■ डॉ. ज्ञान पाठक

2014 के बाद से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दो कार्यकालों में अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहने की संभावना है, जब तक कि वर्तमान रोजगारहीन विकास मॉडल में बदलाव नहीं किया जाता। लगभग एक अरब कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में से, पिछले कुछ वर्षों से रोजगार में लगे लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास रही है, जो चिंता का विषय है।

इस भयावह जमीनी हकीकत के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के अधिकारी दावा करते रहे कि बेरोजगारी दर में गिरावट आ रही है। यहां तक कि सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से पता चला है कि 2022-23 के दौरान बेरोजगारी दर गिरकर 3.1प्रतिशत हो गयी है। हालांकि, गैर-सरकारी सीएमआईई के ताजा रियल टाइम आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी 7-8प्रतिशत के आसपास मंडराती रही है।

प्रभावी आर्थिक विकास के बावजूद, देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट भयावह बना हुआ है, जो मोदी सरकार द्वारा 2014 से अपनाये जा रहे रोजगार रहित विकास मॉडल का प्रमाण है। लोकसभा के नतीजों ने पीएम मोदी को लोकसभा में बहुमत से वंचित कर दिया, जो उनके लिए और सरकार में एनडीए सहयोगियों के लिए भी एक सबक है।

लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान, जब बेरोजगारी मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा बन गयी, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने एक बयान दिया कि 2022-2023 में 30 मिलियन नौकरियां पैदा की गयीं और पिछले पांच वर्षों में 110 मिलियन से अधिक नौकरियां जोड़ी गयीं। इसका मतलब यह था कि मोदी सरकार ने देश के बेरोजगारी संकट को पहले ही हल कर दिया था, क्योंकि हर साल लगभग 20 मिलियन लोग ही भारतीय श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसका यह भी मतलब था कि मोदी सरकार ने एक साल में 30 मिलियन नौकरियां पैदा करके ज़रूरत से ज़्यादा काम किया।

डावरा ने यह बयान भारतीय रिजर्व बैंक के केएलईएमएस डेटाबेस के 2022-23 के अंतिम आंकड़ों का हवाला देते हुए दिया था, जो पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उत्पादकता के स्तर को ट्रैक करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डावरा के दावे का समर्थन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के वार्षिक पीएलएफएस डेटा से भी नहीं होता है।

यहां यह याद रखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान हर साल 20 मिलियन नौकरियां देने का वायदा किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ, यहां तक कि हर साल जारी होने वाले सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी नहीं। लेकिन अचानक मोदी सरकार के श्रम सचिव ने पिछले महीने मई में कहा कि पिछले साल 30 मिलियन नौकरियां पैदा हुईं।

मार्च में ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि यह मान लेना गलत है कि सरकार बेरोजगारी जैसी सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल कर सकती है। उन्होंने यह बयान नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) के संयुक्त प्रकाशन 'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024: युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल' के लॉन्च के दौरान दिया था। सीईए नागेश्वरन ने आश्चर्य जताया था कि सरकार 'खुद को और अधिक नियुक्त करने के अलावा रोजगार के मामले में क्या कर सकती है', उन्होंने कहा कि 'सामान्य दुनिया में, यह वाणिज्यिक क्षेत्र है जिसे नियुक्तियां करने की जरूरत है।'

रोजगार सृजन पर मोदी सरकार का दृष्टिकोण काफी चौंकाने वाला था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभूतपूर्व बेरोजगारी संकट को हल करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सीईए के इस बयान की आलोचना की थी कि 'सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती'। अगर यह भाजपा सरकार का आधिकारिक रुख है तो यह चौंकाने वाला है, हमें भाजपा से साहसपूर्वक कहना चाहिए कि 'अपनी कुर्सी छोड़ो'।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, 'हमारे युवा मोदी सरकार की दयनीय उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने उनके भविष्य को नष्ट कर दिया है। आईएलओ और आईएचडी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'भारत में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है'। वे रूढ़िवादी हैं, हम बेरोजगारी के बम पर बैठे हैं!' उन्होंने यह भी कहा था कि 2012 से मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी तीन गुना बढ़ गयी है।

भारत के पास राष्ट्रीय रोजगार नीति भी नहीं है, हालांकि श्रम और रोजगार के मुद्दों पर देश में शीर्ष त्रिपक्षीय निकाय भारत श्रम सम्मेलन (आईएलसी) ने 2013 में अपने 45वें सत्र में इसकी सिफारिश की थी। आईएलसी ने 2015 में आयोजित अपने 46वें सत्र में भी इसे दोहराया, उसके बाद मोदी सरकार ने कभी इसका अगला सत्र नहीं बुलाया। मोदी सरकार ने अभी तक देश के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति लाने की कोई योजना नहीं बनायी है।

2017-18 तक भारत की बेरोजगारी दर 6.1प्रतिशत हो गयी थी, जो 45 साल में सबसे अधिक थी। अब भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 ने नौकरी के मोर्चे पर एक गंभीर तस्वीर पेश की है, खास तौर पर भारतीय युवाओं के लिए। इस प्रकाशन से देश को पता चलता है कि लाखों युवाओं को कभी नौकरी नहीं मिल पायी, उनमें से कई की मोदी शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान नौकरी की योग्यता की उम्र ही निकल गयी, और जो किसी तरह नौकरी पाने में कामयाब रहे उनमें से 90प्रतिशत अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, जिनमें से 82प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2022 में 55.8प्रतिशत लोगों के लिए स्वरोजगार ही रोजगार का प्राथमिक स्रोत बना रहा, जबकि आकस्मिक रोजगार में केवल 22.7प्रतिशत और नियमित रोजगार में केवल 21.5प्रतिशतलोग ही थे।

चुनाव प्रचार के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में कहा था कि भारत के 'युवाओं ने नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वाले बनने का विकल्प चुना है'। यह बेरोजगारों लोगों के लिए एक अपमानजनक बयान था, भले इस तरह के भौंडे संवेदनहीन डींगें भाजपा या मोदी समर्थकों को प्रिय लगे हों।

मोदी की तीसरी सरकार में भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. कौशिक बसु द्वारा हाल ही में कही गयी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत की युवा बेरोजगारी दर 45.4प्रतिशत के साथ दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने सरकार से इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया है।

प्रभावी आर्थिक विकास के बावजूद, देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट भयावह बना हुआ है, जो मोदी सरकार द्वारा 2014 से अपनाये जा रहे रोजगार रहित विकास मॉडल का प्रमाण है। लोकसभा के नतीजों ने पीएम मोदी को लोकसभा में बहुमत से वंचित कर दिया, जो उनके लिए और सरकार में एनडीए सहयोगियों के लिए भी एक सबक है। बेरोजगारी सरकार के लिए एक प्रमुख समस्या बनी रहने की संभावना है।

गुरवाणी विचार

शांति के पुंज शहीदों के सरताज गुरु अर्जुन देव

सिखों के पांचवे नानकजी गुरु अर्जुनदेव चौथे नानक गुरु रामदास जी के सब से छोटे पुत्र थे। आप जब बहुत ही छोटे थे तब आप ने नाना तीसरे नानक गुरु अमरदास के पलंग पकड़ कर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे तब गुरु देव ने कहा था कि अभी समय है गुरु नानक की गद्दी आप को ही मिलेगी और आप को वर दिया था-दोहिता वाणी का बोहिता।

आपने ही अमृतसर में रामदास सरोवर में हरिमंदर साहब का निर्माण कराया था। जिसकी नींव उस वक्त के प्रसिद्ध सूफी संत सांई मियां मीर जी से रखवाई गई थी। आपने अमृतसर से कुछ किलोमीटर दूर तरनतारन में भी एक विशाल सरोवर बनवाया जिसकी एक तरफ गुरुद्वारा, दूसरी तरफ अस्पताल का निर्माण करवाया जिसमें कोढ़ रोग से ग्रसित लोगों का मुफ्त ईलाज किया जाता है। आपने ही अमृतसर में सतोखसर रामसर सरोवरों का भी निर्माण करवाया था। आपने भादों सुदी व सन् 1604 को गुरुग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश भी करवाया जिसके मुख्य ग्रंथी भाई बुड्ढा जी थे। इस ग्रंथ में आपने अपनी रचित वाणी और उस वक्त के निर्गुण विचार धारा के पंद्रह भक्तों की वाणी चार गुरसिखों की वाणी और ग्यारह भठों की वाणी संकलित करवाई थी। हरिमंदर साहिब के चार दरवाजे इस बात के प्रतीक हैं कि- उपदेश चहुं वर्णों को सांझां। गुरुदेव की वाणी प्रतिष्ठा देखकर उस वक्त के हाकिम मुगल इनसे बहुत चिढ़ते थे। चन्दु नामक एक अहलकार जो कि अपनी बेटी का रिश्ता इनके बेटे हरगोविंद साहिब से करवाना चाहता था पर गुरुदेव ने साध संगत के कहने पर इंकार कर दिया था। बादशाह जहांगीर के कान हर वक्त मुगल काजी मुल्ला के खिलाफ भरते रहते थे। इधर चंदु ने भी बादशाह के कान भरने चालू कर दिये। इन्हीं सब कारणों से बादशाह ने इन्हें लाहौर बुला भेजा और शर्त रखी कि चाहे आप इस्लाम कबूल कर लो या दो लाख रुपिया जुर्माना भरो और गुरुग्रंथ साहिब में इस्लाम संबंधी वाणी भी अंकित करो पर गुरुदेव ने इस्लाम धर्म मानने और गुरुग्रंथ साहिब में वाणी इस्लाम संबंधी दर्ज करने से इंकार कर दिया और जुर्माना पटाने हेतु नहीं है वरना समाज सेवा इत्यादि के लिए है। तब आप पर काजियों द्वारा फतवा लगा कर यासा कानून के तहत शहीद करने का आदेश दे दिया गया। इस तरह मानवता के कातिलों ने आपको गर्म तवे पर बिठाकर ऊपर से गर्म रेत डाल-डाल कर फिर उबलती पानी के देग में डाल कर बेरहमी से शहीद कर दिया। फिर भी आपके मुख से यही निकलता रहा- तेरा भाणा मीठा लागै- हरि नाम पदारथ गुरदेव। गर्म तवे, गर्म रेत, उबलती देग के पानी के दुखों से बहुत ऊंचे शरीर पर छाले होते रहे फिर भी आपने हंसते-हंसते शहीदी का जाम पी लिया।

शहीदी हमेशा जीवन बख्शती है। शहीद की मौत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरुदेव की इस शहादत ने सिख इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इतिहास कार मोहम्मद लतीफा और इस शहादत को सिख इतिहास का एक नया मोड़ बताते हैं। गुरुदेव की शहादत के चाहे कितने भी कारण बयान किये गये हैं पर आप के द्वारा दबे-कुचले हुए जुल्म के शिकार लोगों में आलम विश्वास पैदा कर दिया गया था और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास ही मुख्य कारण था क्योंकि जबर और जुल्म द्वारा लोगों को कुचल कर उनमें गुलामी का एहसास पैदा कर अपनी सत्ता को बनाए रखने को काफी तानाशाह लग रहा था। संसार जानता है कि गुरुदेव की शहादत के बाद आपके सुपुत्र हर गोविंद साहिब ने छठवें नानक के रूप में मीरी पीरी की दो तलवारें धारण की ताकि सिख जुल्म का मुकाबला कर सके। इस शहादत ने सिखों के महल की एक मजबूत बुनियाद कायम की। जिसका नतीजा दशम पिता गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना के रूप में हुआ। ऐसे शांति के पुंज लासानी शहीद को हम उनकी शहीदी पर कोटि कोटि नमन करते हुए यह प्रणस करें कि उनके बनाये आदर्शों पर चलकर जीवनयापन करेंगे। दीन दुखियों की सेवा नेक कमाई का दसबंध निकाल कर खर्च करेंगे।

इंदर सिंह आहुजा

आपके पत्र

जलवायु परिवर्तन हवाई यात्रा को मुश्किल बना रहा है

पिछले दिनों सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान के वायु विक्षोभ (टर्बुलेंस) की गिरफ्त में आने और 1800 मीटर तक गिरते चले जाने की घटना काफी चर्चा में रही। इसने हवाई यात्रियों में चिंता (और दहशत) भर दी। साथ ही, इसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका की संभावना होने की बात भी सामने आई है।

गौरतलब है कि हवाई जहाज़ों का विक्षोभ का सामना करना एक आम घटना है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। हवाई अड्डों के नज़दीक तेज़ हवाएं टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान विमानों को थरथरा सकती हैं। ऊंचाई पर, तूफानी बादलों के बीच या उनके नज़दीक से गुज़रते समय विमानों को विक्षोभ का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थानों पर तेज़ी से ऊपर और नीचे जाती हवाएं अस्थिरता पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त, पर्वत शृंखलाओं के ऊपर से गुज़रने वाले विमानों को पहाड़ों से उठने वाली हवाएं ऊपर धकेल सकती हैं। इसके अलावा पूरी धरती के इर्द-गिर्द मंडराने वाली शक्तिशाली पवन धाराओं (जेट स्ट्रीम) के सिरों पर हवाई जहाज़ विक्षोभ में फंस सकते हैं।

हो सकता है कि सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान ने तूफान से सम्बंधित विक्षोभ का सामना किया हो या क्लियर-एयर विक्षोभ का सामना किया हो। क्लियर-एयर विक्षोभ बादलों के बाहर होता है और इसका पता लगाना भी कठिन होता है। रीडिंग युनिवर्सिटी के वायुमंडलीय शोधकर्ता पॉल विलियम्स का कहना है कि इस घटना के कारण का पता लगाने के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है।

वैसे पिछले कुछ समय से इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण विक्षोभ की घटनाएं अधिक होने के साथ गंभीर भी हो रही हैं। विलियम्स और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में 1979 और 2020 के बीच उत्तरी अटलांटिक पर क्लियर-एयर विक्षोभ में 55 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वैश्विक स्तर पर भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई है। इस वृद्धि का कारण जलवायु परिवर्तन के कारण जेट स्ट्रीम्स का प्रबल होना बताया जा रहा है।

भविष्य के अनुमान और भी चिंताजनक हैं। जलवायु मॉडलों के आधार पर शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जैसे-जैसे जलवायु गर्म होगी, गंभीर विक्षोभ की घटनाएं अधिक आम हो जाएंगी। साथ ही, गंभीर विक्षोभ की आवृत्ति भी दुगुनी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ानों के दौरान असुविधा की स्थिति लगातार और लंबे समय तक हो सकती है। अलबत्ता, इसका मतलब यह नहीं है कि हवाई यात्राएं अधिक असुरक्षित हो जाएंगी।

वर्तमान में पायलट मौसम विशेषज्ञों से विक्षोभ अनुमान पता करते हैं और इस आधार पर सुरक्षित उड़ान मार्ग तय करते हैं। हवाई जहाज़ में उपस्थित रडार प्रणाली पानी की बूंदों का पता लगाकर तूफानी बादलों से बचने में मदद करती है, लेकिन ये प्रणालियां क्लियर-एयर में होने वाले विक्षोभ के संदर्भ में नाकाम रहती हैं।

लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिग नामक एक तकनीक कुछ हद तक इसका समाधान प्रदान कर सकती है जो रेडियो तरंगों की बजाय प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। काफी दूर से साफ हवा में होने वाले विक्षोभ को भांप सकती है, जिससे पायलट हवाई जहाज़ को इन अदृश्य खतरों से बचाकर निकाल सकते हैं। हालांकि, इसकी उच्च लागत और उपकरणों का अधिक वज़न इसके व्यापक उपयोग में एक बाधा है। बहरहाल, तब तक वायुयान चालक यात्रियों से आग्रह करते हैं कि सुरक्षा के लिए हमेशा सीटबेल्ट बांधे रखें। **(स्त्रोतफीचर्स)**

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllnewsPaperPaid

भारत की जनता ने दिया मजबूत विपक्ष का जनादेश

-नरेंद्र तिवारी 'पत्रकार'

भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विशाल होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की अनेकों विशेषताएं भी है। हर पांच साल में चुनाव के माध्यम से जनता राष्ट्रीय सरकार चुनती है। देश की चुनी हुई सरकार का नैतिक दायित्व है की वह जनता की मौलिक जरूरतों को पूरी करने का प्रयास करें। नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक हालातों की बेहतरी के उपाय निरंतर करती हुई दिखाई देवें। देश आवाम को भारत के संविधान ने मत देने का मूलभूत अधिकार दिया है। हर पांच साल में अपने वोट की ताकत से देश की जनता सरकार बनाती बिगाड़ती है। संविधान द्वारा प्रदत्त वोट देने का अधिकार जनता की असली ताकत है। जनता की इसी ताकत का नाम जनादेश है।

वर्ष 2024 में 17 वीं लोकसभा का अवसान और 18 वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 4 जून को 542 लोकसभा सीटों की मतगणना सम्पन्न हुई। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर एक मात्र उम्मीदवार होने के कारण यहां मतगणना की आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्ष 2024 का जनादेश वर्ष 2014 और 2019 के जनादेश से अलग प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाला दिखाई दे रहा है। विगत दो चुनावों से विलग इस बार जनता ने मजबूत विपक्ष का जनादेश दिया है। जनतंत्र में मजबूत विपक्ष की आवश्कता से इंकार नहीं किया जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार विपक्ष एक महत्वपूर्ण और जरूरी शर्त है। कोई भी सरकार मजबूत विपक्ष के बिना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष की भूमिका सरकार में आने की तैयारी करना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता में मौजूद सरकार की किसी भी मनमानी प्रवृत्ति को रोकना भी होनी चाहिए। एक प्रभावी विपक्ष सत्ता में मौजूद पार्टी के संबंध में एक संयमित भूमिका निभाता है, उसे अपनी कार्यात्मक सीमाओं का उल्लघंन करने से रोकता है और साथ ही एक व्यावहारिक विकल्प का वादा करके लगातार चुनौती पेश करता है। भारत में विगत दो लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने मजबूत सत्ता पक्ष और कमजोर विपक्ष का जनादेश दिया था। इसके उलट 2024 का जनादेश संयमित सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष का जनादेश दिखाई दे रहा है। यह भारत के जनतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता ही है की देश की आवाम ने वर्ष 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बहुमत से नवाजा था। वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुमत से 32 सीटें दूर रखा। भाजपा को अकेले 240 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई जबकि एनडीए गठबंधन को 293 सीटें प्राप्त हुई। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। अकेले भाजपा को बहुमत नहीं मिला। जबकि भाजपानीत एनडीए गठबंधन को देश की सत्ता पर काबिज होने का जनादेश भारत की आवाम द्वारा दिया गया। इसके विपरित कांग्रेसनित इंडिया गठबंधन को 233 सीटें प्राप्त हुई जिसे मजबूत विपक्ष की जवाबदेही देश के मतदाताओं ने सौंपी है। भारत के जनतंत्र की विशालता का अनुमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बयान से मिलता है। उन्होंने बताया लोकसभा चुनाव 2024 में 65.79% मतदान दर्ज किया गया। देश के 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग किया। उनके अनुसार यह अपने आप में विश्व रिकार्ड है। यह सभी जीझ7 देशों के मतदाताओं से 1.5 गुणा और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं से 2.5 गुणा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की विशेषताओं के अनुरूप विशाल क्षेत्रफल में फैले भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में चरणबद्ध रूप से चुनावी प्रक्रिया को सफलता पूर्वक कराने की जवाबदेही देश के चुनाव आयोग ने निभाई है। देश के मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जनता के द्वारा दिया गया जनादेश मजबूत और ताकतवर विपक्ष के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 9 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में शपथ लेने जा रहें है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल पूर्व के दो कार्यकालों से कुछ मायने में अलग होने जा रहा है। इस कार्यकाल में उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। गठबंधन के साथी दलों के साथ साझा कार्यक्रम बनाने होगें। गठबंधन के साझेदार दलों की अपनी विचारधाराएं है। उनके प्रांतों के अपने एजेंडे और घोषणाएं है। नवगठित सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा जो जनता के जनादेश से चुना गया है। देश की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे और चुनौती भरें कार्यकाल की तरफ तो होंगी ही, देश की आवाम विपक्ष के कार्यकलापों की ओर भी आशा पूर्ण नजरों से देख रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने मीडिया द्वारा बताए एक्जिट पोलो की भी पोल खोलकर रख दी। एक्जिट पोल इतने अविश्वनीय कभी नजर नहीं आए जितने झूठे, अविश्वनीय और जमीनी हकीकत से दूर 2024 के चुनाव परिणामों के बाद दिखाई दिए। इस जनादेश ने अनेकों धारणाओं को तोड़ा है। प्रजातंत्र की खूबसूरती को काबिज किया है। यह प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है की जन अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जनता के बुनियादी सवालों पर सरकार और विपक्ष दोनों को ध्यान देना होगा। परिणामों के बाद अनेकों आमलोगों की प्रतिक्रिया सामने आई अधकांश ने इसे मजबूत विपक्ष का जनादेश बताया है। देश की नवगठित सरकार को जनता से जुड़ी मंहगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश करना चाहिए। देश के विपक्ष को भी सरकार का इन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए। अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। सत्ता पक्ष को देश की सरकारी एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक लाभ, हानि के रूप में करने के बजाए भष्ट्राचार पर लगाम लगाने के लिए करना चाहिए। सरकारी एजेंसियों की एक पक्षीय कार्यवाहियों की प्रतिक्रिया भी जनादेश में सुनाई दे रही है। देश के राजनैतिक दलों को इस चुनाव से यह सबक लेना चाहिए की जनता जोड़तोड़ की राजनीति को नापसंद करती है। क्षेत्रीय दलों को तोड़ने प्रांतीय सरकारों को गिराने, भ्रष्ट नेताओं को राजनैतिक संरक्षण दिया जाना देश की आवाम को कभी नहीं सुहाता है। प्रजातंत्र के इस महोत्सव में देश के मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर जिन्हे सत्ता सौंपी उन्हें भी नियंत्रण में रखा और विपक्ष को भी मजबूत किया है। आशा है सरकार और विपक्ष अपनी जवाबदेही पांच साल ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। हर चुनाव की तरह इस बार भी देश का लोकतंत्र विजय हुआ है। जनादेश तो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है।

ब्रेन ट्यूमर के लक्षण दिखे तो तुरंत इलाज कराएं : डॉ. गिरिजा शंकर झा

सहरसा। ब्रेन ट्यूमर में मस्तिष्क की कोशिकाओं और ऊतकों में धीरे-धीरे गांठ बनने लगती है। जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जब यह मस्तिष्क के भीतर बनता है, तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। यदि समय पर इसका इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकता है। ये बातें वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर श्री नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित निन्ती कार्डियक केयर, सहरसा के डॉ. गिरिजा शंकर झा ने कहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ब्रेन ट्यूमर का कारगर और बेहतर इलाज उपलब्ध है लेकिन इसके लिए समय पर इलाज शुरू करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण अगर दिखें तो डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच तुरंत करवानी चाहिए। इसके लक्षणों में सिर में लगातार दर्द रहना, बार-बार मिर्गी के झटके आना, हाथ-पैर में कमजोरी महसूस करना, तनाव में आना, याददाशत कमजोर होना, चिड़चिड़ापन होना, कम सुनाई देना, बोलने में दिक्कत होना, आंखों की रोशनी जाना, बार-बार बेहोश हो जाना आदि शामिल हैं। इसके लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ब्रेन ट्यूमर के दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला ब्रेन के ही टिश्यू से बनता है वहीं दूसरा कहीं और ट्यूमर होने के बाद ब्रेन में फैल जाता है। इस बीमारी का उपचार परीक्षण और लक्षणों की जांच के बाद पता चलता है। ब्रेन ट्यूमर का पता सिटी स्कैन, एमआरआई आदि जांच से लगाया जा सकता है। इन दिनों ब्रेन ट्यूमर का प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर संपूर्ण इलाज संभव हो गया है। डॉ. गिरिजा शंकर झा ने कहा कि सर्जरी, रेडियो थेरेपी और दवाओं से इस रोग का इलाज होता है। रोगी की स्थिति के अनुसार उपचार किया जाता है। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर के लिए बेहतर और आधुनिक तकनीक आ गयी है जिससे इसका इलाज करना आसान हो गया है। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले मरीजों में ब्रेन ट्यूमर के कैंसर में बदलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन जेनेटिक फैक्टर एक अहम कारण माना जाता है।

अयोध्या वासियों को कोसने के पहले वहां की कुछ हकीकत भी जान लीजिये

अशोक भाटिया

अयोध्या लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से निकल जाने का जितना मलाल पार्टी को है, उससे ज्यादा ये लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार इस बारे में कोई न कोई कमेंट या बहस देखने को मिल जा रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राम मंदिर बना दिया गया। सालों से तंबू में रखे गए भगवान राम को भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया। मंडल भी अयोध्या बना दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या छावनी बना दिया गया। अयोध्या स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अयोध्या शहर का कायाकल्प भी किया गया। चौक चौराहे सजाए गए। छोटी मोटी दुकानों को तोड़, सलीके से व्यावसायिक कांप्लेक्स तमीर कर दिए गए। मंदिर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या आने लगे। शहर के आस पास बहुत सारे ओयो रूम और दूसरे होटल भी खुल गए। फिर भी आने वालों को जगह मिलने में दिक्कतें आ रही थी। उनकी संख्या जो इतनी ज्यादा थी कि सबके लिए व्यवस्था हो पाना कठिन था। इस सब से लोगों में खुशी थी। साफ दिख रहा है कि देश भर में अयोध्या जी और भगवान राम के प्रति श्रद्धा है।

फिर राम मंदिर वाली इस सीट से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह कैसे हार गए। भाजपा के कार्यकाल में ही मंदिर के पक्ष में फैसला आया। वहां भव्य मंदिर तामीर कराया गया। और उससे भी भव्य समारोह आयोजित कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वजहें खोजने पर अलग-अलग राय मिल रही है। लेकिन इस पर ज्यादातर लोग सहमत हैं कि ये पूरी लोकसभा सीट सिर्फ अवधपुरी या अयोध्या या फिर राम मंदिर तो नहीं थी। इस सीट का नाम अभी भी फैजाबाद है। यहां 22 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। साथ ही स्वरूप की बात की जाय तो इसे ग्रामीण क्षेत्र वाली सीट माना जा सकता है। क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण ही है।

ये वो आबादी है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा दूसरे किसी इलाके के रहने वाले मतदाता। उनकी जातियां बंटी हुई है। यहां जातियों का समीकरण उत्तरप्रदेश की बहुत सारी सीटों जैसा ही है। कुल मतदाताओं का करीब 21-22 फीसदी हिस्सा दलित वोटरों का है। 12 से 15 फीसदी पिछड़े और तकरीबन 20 फीसदी अल्पसंख्यक। कहने की जरुरत नहीं है कि ये रेशियो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बहुत अच्छे से सूट करता है। ऊपर से एसपी ने यहां से दलित उम्मीदवार भी उतार दिया।

फिर पहले कैसे यहां से भाजपा जीतती रही। इस सवाल का जवाब पर लल्लू सिंह की उम्मीदवारी में खोजा रहा है। वे खुद भी 2014 और 2019 में यहां से सांसद रह चुके हैं। भाजपा इस सीट को पहले भी दो बार जीत चुकी है। यानी ये सीट 4 बार भाजपा के कब्जे में रही है। कहा जा रहा है कि अब वे मतदाताओं से कनेक्ट करने की बजाय अपने समर्थकों को 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कहते सुने गए। ऐसा एक वीडियो सोशल हो रहा है। इसका भी असर हुआ होगा। लेकिन मूल बात है कि अयोध्या के लोगों को मंदिर की व्यवस्था से परेशानियों से जूझना पड़ा है।

मंदिर में दर्शन की बात की जाय तो चुनाव तक मंदिर में लगातार वीआईपी दर्शनार्थियों का आना लगा रहा। इस दौरान प्रशासन सुरक्षा के नाम पर ऐसा इंतजाम करता रहा है कि लोगों का मंदिर के आस पास जाना दूभर हो जाता था। कहा जा सकता है कि दिक्कतों के कारण बहुसे अयोध्या झ फैजाबाद के लोग मंदिर दर्शन करने जा ही नहीं सके। मंदिर के आस पास जो भी स्कूल और अस्पताल वगैरह है वहां जाने आने में रोज लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान एक दिन ऐसा भी आया जब किसी बहुत महत्वपूर्ण राजनेता के आने के कारण बच्चों को परीक्षा देने जाने में भारी मुसीबत हो गई थी। लग रहा था कि उनकी परीक्षा ही छूट जाएगी। इलाके के लोगों ने डीएम से संपर्क किया और तब किसी तरह बच्चे परीक्षा में शामिल हो पाए। याद रखने की जरुरत है कि अलग अलग राज्यों के विधायक झुंड बना कर दर्शन के लिए चुनाव तक पहुंचते रहे हैं। उत्तरप्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष भी सारे विधायकों को लेकर श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण के दौरान मंदिर के आस पास की दुकानों को तोड़ कर हटाया गया। ये लोकल लोगों में नाराजगी का एक बड़ा सबब बना। क्योंकि जिन्हें विस्थापित किया गया, उन्हें कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में महंगी कीमतों पर दुकाने खरीदने को मजबूर होना पड़ा। मंदिर चाहिए तो भोजन भी। भोजन यानी रोजगार।

फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले एक स्थानीय अखबार इस दलील से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ अयोध्या मंदिर के आस पास की दुकानों को विस्थापित किए जाने जैसे एक मुद्दे से भाजपा प्रत्याशी की हार नहीं हुई है। उनका तर्क है कि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है। वो लिखता है उत्तरप्रदेश में जनता ने बदलाव का मन बना लिया था। जहां समीकरण ठीक ठाक रहे वहां जनता ने बदलाव कर दिया। हार सिर्फ लल्लू सिंह की नहीं पूरे भाजपा की है। हां, लल्लू सिंह ने का जो वीडियो आया उसने दलित पिछड़ों को एकजुट कर दिया। ये पहला मौका है कि इस सामान्य सीट से एक दलित समुदाय का उम्मीदवार जीता।

एक दूसरे अखबार के अनुसार प्रत्याशी का चयन गलत था। वे कहते हैं कि लल्लू सिंह वे नेता है जो लोगो से बस इतना ही संपर्क रखते थे कि क्षेत्र में किसी मतदाता के यहां पड़ने वाले कार्यक्रम में रात 10-11 बजे पहुंचे और लिफाफा पकड़ा कर निकल लेते थे । क्षेत्र के लोगों से उनका वैसा कनेक्ट नहीं था जैसा नेता का होना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी और उसके उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जी-जान लगा कर चुनाव लड़ा।

बताया जाता है कि जिन राम जी का नाम पूरे देश की जनता में स्फुरण पैदा कर देता है, उनका नाम उनकी मातृभूमि में कोई संचार नहीं पैदा कर पाता। अयोध्या में जब-जब राम नाम को इनकैश करने की कोशिश की जाती है, अयोध्या की जनता बिफर जाती है। राम जी के प्रति अयोध्या में आत्मीयता है पर जब भी उनका राजनैतिक इस्तेमाल हुआ, मतदाता नाराज हो जाता है। सिर्फ राम के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। सच यह है कि राम नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ने वाले लल्लू सिंह हैट्रिक नहीं लगा पाए। जनता के अपने दुःख-दर्द होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जाएगी तो जनता यूं ही भाजपा से छिटकती रहेगी। लल्लू सिंह दो बार लगातार जीते किंतु वे निराकार चेहरे वाले जन प्रतिनिधि थे, इसीलिए हारे।

भाजपा के लिए 2024 में फैजाबाद से हारना एक बड़ा झटका है। लल्लू सिंह को हराने वाले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से सपा के विधायक हैं। 9 बार विधायक रहने के कारण क्षेत्र में वे विधायक जी के नाम से जाने जाते हैं। पर अब वो सांसद जी बन गए। यह विचित्र है कि जब-जब राम का नाम परवान चढ़ाने में भाजपा सफल रही, तब-तब अयोध्या में उसे हार का मुंह ही देखना पड़ा। अयोध्या विधानसभा सीट भी अक्सर उसके हाथ से जाती रही। लल्लू सिंह अक्सर अयोध्या से ही विधायक रहे, किंतु 2012 के चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट से सपा के तेज नारायण पांडेय जीते थे। 2023 में फैजाबाद (अब अयोध्या) नगर निगम का चुनाव भी भाजपा हारी थी। मजे की बात कि जिस वार्ड में राम जन्म भूमि परिसर पड़ता है, वहां से एक निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी सुल्तान अंसारी को जीत मिली, जबकि इसके तीन साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या ज़िले की पांचों विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती थीं। 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु आधार शिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी किंतु 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले की पांच विधानसभा सीटों में से मिल्कीपुर और गुसाईं गंज हार गई। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा भले राम मंदिर को लेकर पूरे देश में वोट मांगे अयोध्या में उसे वोट नहीं मिलता। अयोध्या एक पूर्णतया धार्मिक नगरी है। हिंदू धर्म की सप्त पुरियों में इसका उल्लेख है। परंतु अयोध्या के राजनीतिकरण को इसने सदैव नकारा।

बताया जाता है कि अयोध्या में 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ऐसी फिजा बदली कि नारा लगा हमें अवधेश पासी ही चाहिए, भाजपा के लल्लू सिंह से हमें कोई सहानुभूति नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दस वर्षों में अयोध्या का अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश के सभी हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेनें, भव्य रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा पर अयोध्या के स्थानीय निवासियों को उनकी जमीनों का मुआवजा देने में भी राज्य सरकार ने भेदभाव किया। सरकार ने विकास कार्यों के लिए जमीन अधिगृहीत की किंतु बदले में किसी को अधिक पैसे मिले किसी को कम। फैजाबाद के भाजपा सांसद लल्लू सिंह और भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जनता की गुहार नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि लोगों को सपा के विधायक अवधेश प्रसाद पसंद आए, जो लोकसभा जीतने के पहले वे मिल्कीपुर (सुरक्षित) से विधायक थे। सपा ने यहां एक बड़ा प्रयोग किया। सामान्य श्रेणी की इस सीट से दलित समुदाय (पासी) के अवधेश प्रसाद को लड़ाया और वे जीत गए। इस तरह अयोध्या में लल्लू हारे और अवधेश जीते। अवधेश शब्द राजा राम का पर्यायवाची है।

कांग्रेस-सपा के जिस गठबंधन को 2017 में नहीं चल पाया था, वह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जमकर वोट बटोरे हैं। उत्तर प्रदेश के जानकारों के मुताबिक इस चुनाव में मुस्लिम वोट ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। संविधान और आरक्षण बचाने के मुद्दे को हवा देकर इंडिया गठबंधन ने भाजपा के कोर हिंदू वोट बैंक को भी बांट दिया। विपक्ष के इस नैरेटिव ने बड़ी संख्या दलितो, पिछड़ों और आदिवासियों को भाजपा से दूर किया। महंगाई और बेरोजगार के मुद्दे ने भी का मुद्दा भी काम करता दिखा।स्थानीय प्रत्याशी लल्लू सिंह पर क्षेत्र में जमीन खरीद और फिर उसे ऊंचे दामों में बेचने का आरोप लगा हुआ है। श्रीराम मंदिर पर फैसले के बाद जमीन खरीद-बिक्री का मामला जोर-शोर से उठा था। इस पर बड़ा जोर दिया गया। इससे लल्लू सिंह की छवि धूमिल हुई और उन्हें कम वोट मिले।

पत्रकारिता और मनोरंजन जगत के अदीप्त सूर्य रामोजी राव का निधन

रामोजी ग्रुप के संस्थापक और रामोजी फिल्म सिटी से संस्थापक रामोजी राव का 87 वर्ष की आयु में शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने पत्रकारिता और फिल्म जगत में कई अनोखे प्रयोग किये। उनके बनाये मंच के माध्यम से भारत की कई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला। उनके जाने से आज सूचना और मनोरंजन जगत का समय ठहर सा गया है। पाठकों और दर्शकों की नब्ज वे अच्छी तरह से टटोल लेते थे। उनमें दलित उत्थान के प्रति विशेष लगाव था।

तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का पूरा नाम चेरुकुरी रामोजी राव है। एक पत्रिका से लेकर मीडिया में डिजिटल क्रांति लाने तक के लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक प्रयोग किये। उनका सफर दूसरों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। फिल्मी दुनिया के लिए शूटिंग का केन्द्र बनाने वाले रामोजी मूलतः एक पत्रकार थे।

पत्रकारिता और मनोरंजन जगत में अपनी प्रतिभा का परिचय देने से पहले उन्होंने वर्ष 1962 में अपना व्यवसायिक सफर मार्गदर्शी चिटफंड्स से शुरू किया था। शुरूआती संदेह के बाद भी उनकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी ने कंपनी को सफल बनाया। आज पूरे देश में इस चिटफंड की मिसाल दी जाती है। इसके बाद उन्होंने मीडिया की ओर रुख किया। वर्ष 1969 में उन्होंने मासिक पत्रिका अन्नदाता के माध्यम से मीडिया क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था। एक किसान परिवार में जन्म लेने के कारण वे जानते थे कि भारतीयों किसानों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता थी। उन्हें नयी तकनीकों से परिचित करने के लिए वे अन्नदाता पत्रिका का संचालन करते थे। 'अन्नदाता' पत्रिका के माध्यम से उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्रों और किसानों के बीच एक सूचना के आदान-प्रदान का स्त्रोत निर्मित किया था। किसानों को उन्नत खेती के लिए आवश्यक तकनीक और नयी मशीनों की जानकारी देने में काफी हद तक सफल भी रहे। कई किसानों को उनकी इस कृषि पत्रकारिता का लाभ मिला। इसकी मदद से उनकी आय में काफी बढ़त हुई। यह रामोजी की पहली विजय थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1974 में मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा। आगे जाकर यही निर्णय उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला ईनाडु आज भी पाठकों और श्रोताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। उनकी देखरेख में की जाने वाली पत्रकारिता में जनसरोकारों को प्राथमिकता दी गयी। सरकार के घोटालों को प्रमुखता से निर्भय होकर छापा गया। देखते ही देखते वे कमजोरों की आवाज बन गये। साल 1976 की पहली छमाही में ईनाडु की प्रसार संख्या (सकुर्लेशन) 48,339 प्रतियां थीं। आज भी ईनाडु 23 केन्द्रों में छपता है। यह आज भी सबसे अधिक प्रसार वाले तेलुगु दैनिक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। खोजी पत्रकारिता को वे सदैव बढ़ावा देते रहे।

वर्ष 1978 में साहित्य प्रेमियों की मॉग पर उन्होंने चतुर और विपुला नामक मासिक पत्रिकाएं प्रारम्भ कीं। चतुर मासिक के उपन्यास के साथ विपुला में विभिन्न भाषाओं में कहानियों का संग्रह प्रकाशित किया जाता था। रामोजी राव का यह अभिनव प्रयोग चार दशकों तक साहित्य प्रेमी पाठकों की पठन प्यास को संतृप्त करता रहा। अब वह समय भी आया जब सूचना क्रांति के अंतर्गत दर्शकों को 24 घंटे अनवरत रूप से टीवी न्यूज चैनल शुरू करने का कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। 27 अगस्त 1995 को तेलुगु में पहले 24 घंटे के चैनल के रूप में शुरू हुआ। उनका यह प्रयोग तो काफी कुछ बदल देने वाला था। कई पत्रकारों को इसके माध्यम से स्वयं का विस्तार करने का अवसर मिला। मीडिया इंडस्ट्री में तो एक समय यह कहा जाने लगा था कि टीवी पत्रकारिता की पाठशाला है ईटीवी न्यूज चैनल। वहीं, ईटीवी तेलुगु टीवी को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

दूरदर्शी विचारों के धनी रामोजी राव ने वर्ष 1999 में ही इंटरनेट क्रांति का महत्व समझ लिया था। यही कारण है कि जब बड़े मीडिया हाउसेस इंटरनेट पर मंथन कर रहे थे तभी उन्होंने अपने प्रकाशनों को वेबसाइट के माध्?यम से परोसना शुरू कर दिया था। eenadu.net वेबसाइट को पाठकों ने भी बहुत सराहा। इसके अतिरिक्त वे एक अंग्रेजी दैनिक भी दो दशकों तक प्रकाशित करते रहे।

प्रतिभाओं को नया मंच देने में इस चैनल ने काफी काम किया। अगस्त 2001 में ईटीवी ने उर्दू में प्रसारण शुरू किया। जनवरी 2002 में रामोजी राव ने एक ही दिन में छह चैनल शुरू करके मीडिया इतिहास में कीर्तिमान रच दिया। आज ईटीवी एक बड़ा नेटवर्क बन गया है जो क्षेत्रीय भाषा के चैनलों के साथ लोगों तक पहुंचता है। देखते ही देखते देश में बोली जाने वाली 13 भाषाओं में उसका प्रसारण आरम्भ हो गया। बड़ों के साथ ही वे बच्चों के मनोरंजन की आवश्यकता को भी समझते थे। ईटीवी बाल भारत के माध्?यम से उन्होंने चार से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दर्शनीय प्रोग्राम बनवाये। 12 भाषाओं में कार्टून प्रोग्राम प्रस्तुत किये जाते हैं।

रामोजी राव ने मनोरंजन जगत में भी कई क्रांतिकारी काम किये। फिल्म शूटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना करके उन्होंने फिल्म उद्योग को बल दिया। उन्होंने फिल्मों में व्याप्त अश्लीलता से दूर रहते हुए गुणवत्तापूर्ण, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक फिल्में बनाने पर जोर दिया। उषा किरण मूवीज की स्थापना करके उन्होंने कल्पना पर आधारित फिल्?मी कहानियों के स्थान पर समाज में व्याप्त समस्याओं पर आधारित कहानियों पर फिल्में बनाने की प्रेरणा दी। वे अपनी अंतिम सांस तक इस निर्णय पर प्रतिबद्ध रहे कि मनोरंजन के साथ ही सूचना की क्रांति का भी विशेष महत्व है। कन्नड़, तमिल, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में 85 फिल्में बनाकर रामोजी राव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तेलुगू सिनेमा के दर्शकों को अच्छी फिल्में उपलब्ध कराने के लिए 2 मार्च 1983 को उषा किरण मूवीज की स्थापना की गई थी। वहीं, उनकी बनायी फिल्म सिटी में आज लगभग 25 हजार से अधिक लोग काम कर रहे हैं। साथ ही, करीब एक लाख लोगों को इसका अप्रत्यक्ष लाभ भी मिल रहा है। आंकड़ों का यह दावा ईनाडु ग्रुप का है। रामोजी फिल्म सिटी के सपने ने हैदराबाद को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र में बदल दिया। इतना ही नहीं यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बन गया। तेलुगु भाषा को संरक्षित करने के लिए काफी काम किया। उन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं जो उनकी सफलता का वर्णन करते हैं। -नीरज तिवारी

मोदी बनाम कुर्सी की गारंटी ?

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

धृतराष्ट्र बोला- हे संजय, कलिकाल में इक्कीसवी सदी के प्रारम्भ में अपने राज्य हस्तिनापुर सहित इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली के बारे में जानने को उत्सुक हूँ तुमने बीसवी सदी तक के हालत के जो डरावने रूह कपाने वाले दृश्य बतलाये उससे मेरी आत्मा लहूलुहान हो गई है। मैं स्वीकारता हूँ की जगदीश्वर श्रीकृष्ण के लाख प्रयास और शांति प्रस्ताव को मैंने अपने बेटे दुर्योधन की हठधर्मिता और महत्वाकांक्षा के सामने मुझे झुकना पड़ा, कुरुक्षेत्र में अनगिनत राजाओं सहित महारथी, रथी, परमवीर योद्धाओं का रक्तपात हुआ, महिलाए विधवा, हुई व बच्चे लाबारिस हुये। कुछ समय बाद हम भी युधिष्ठर को राजपाट सौंपकर वन की ओर निकल रहे इसीलिए तुम्हें तीनों कालों में झाँकने की दिव्यदृष्टि मिली होने से हमारे इस राज्य को कौन कैसे लोग भोगेगे। जैसा की अब तक तुमने बताया की बीसवीं-इक्कीसवीं सदी मे हर घर में दुर्योधन ओर दुशासन जन्म लेंगे, ओर ये लोग ही आपस में खोटे काम कर कर मर जाएँगे । यानी पहले मेरे कारण युधिष्ठिर सत्ता में नहीं रहा अब आगे भी उसे सत्ता नहीं मिलेगी? अखण्ड राष्ट्र खण्ड-खण्ड हो जाएगा। जो भारत खण्ड होगा इसमें महिलाओं ओर बच्चों के गंभीर-घिनौने अपराध होंगे, विधर्मी रसना के स्वाद के लिए गौमाता को कत्ल करेंगे। सत्ता प्राप्त करने के लिए सौ सौ झूठ, कपट, बेईमानी को प्रजा अपना राजा चुनेगी, अगर मजबूत चुना तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मजबूर चुना तो कुर्सियों की मुंह मांगी कीमत व्यापार चलेगा[जब व्यापार चलेगा तो देश क्या खाक चलेगा । यह फिर मानवता कहाँ बचेगी।

संजय वोला- महाराज आपके आत्मचिंतन से कुछ होने वाला नहीं सिवाय मेरा ही समय खराब होता है, ओर आप है की खुद का घर परिवार के साथ न्याय नहीं कर अपने बेटे के सगे नही हुये ओर उन्हे मरवा दिया, फिर कलयुग के लोगों की चिंता मैं क्यों दुबले होते हो। धृतराष्ट्र ने आक्रोश ओर झुंझलाहट में एक गहरी सांस ली ओर कहा- संजय आजकल तुम पहले वाले नरमदिल ओर राजा के प्रति समर्पित नही दिखते जो जली कटी बातें सुनाते हो? तुम हमारे पुराने सेवक हो ओर शिष्टाचार ओर मयार्दा का निर्वहन करने में अग्रणी होते जा रहे हो। मानता हूँ मुझ जैसे नेत्रहीन शासक के दरवार में विश्व के महानतम सलाहकार, मंत्री ओर एक से एक महारथी थे, जो दुनिया के किसी राजदरबर में नहीं रहे तब में उनके नीतिगत वचनो और सलाह सुने बिन न्याय नही कर सका भले मुझे नेत्रहीन को समाज माफ न करे किन्तु मेरी आत्मा खुद के शासन मैं लिए गए हर निर्णय से खुद को माफ कर रही है, तो समझो मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट इसलिए की मुझ नेत्रहीन के बाद यह अखण्ड राष्ट्र सेकड़ों टुकड़े मैं बंट जाएगा, जिनके खंडों पर जिनकी अपनी संप्रभुता होगी वही मेरा यह इंद्रप्रस्थ भरतखण्ड का एक हिस्सा बनने पर वहाँ की प्रजा संविधान को ही अपना धर्म मानेगी। शासन करने के लिए लोग दल बनाए या दलदल, जनता का अभिमत लेकर एक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पूर्णकालिक सरकार चलाये तो ठीक। वरना असंख्य दलों का खंड खंड बहुमत मिलने पर जो ज्यादा सीट जीतने वाला दल होगा वह सत्ता के द्वार पर तो पहुँच जाएगा लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए जो गठजोड़ करेगा वह देश के लिए नही बल्कि एक व्यापारी के तरह सौदेवाजी होगी। संजय महाराज की हर बात को इत्मीनान से सुन रहा था ओर आश्वस्त था की उसने जो महाराज को बताया उससे कहीं अधिक वे सटीक व्याख्या करने में निपुण हो गए।

आजादी के बाद के शासकों ओर शासन की नीति तथा देश की प्रगति ओर नागरिकों के हालातों व परिस्थितियों की जानकारी से महाराज धृष्टराष्ट्र अवगत हो चुके थे ओर जाति धर्म संप्रदायों के झगड़े, फसाद के अलावा शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर चल रहे षडयंत्रो व शिक्षा के बाद युवाओं को नौकरी रोजगार न देने से दुखी होकर संजय को पुकारा ओर संजय ने वही अपने गले का पुराना ढ़ोल पीटना शुरू किया ओर कहा-महाराज में भारत देश के 2024 में सम्पन्न होने वाले महाभारत का हाल सुनाना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। बात 2014 की है गुजरात का एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी भारत का शासक चुन लिया जाता है ओर उसकी विश्वव्यापी ख्याति होती है। वह दूसरी बार अपनी ख्याति को 2019 में भुनाकर पूर्ण बहुमत ले फिर देश का प्रधान बन जाता है। मोदी का अहंकार आकाश छूने लगता है, सभी को सोते-जागते, उठते-बैठते लगता है की मोदी के डंके की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। असल चुनाव एक बड़ा महाभारत है जो कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। फिर इस महाभारत में मोदी का डंका नहीं बजा ओर वे अपने प्रतिद्वंदी राहुल गांधी ओर खुद अपनी ही पार्टी को समझने में चूक कर गए। उनकी निम्नस्तरीय भाषा संवाद में दिये गए भाषण,विभिन्न वेशभूषाओं में पूजा पाठ करके खुद को दिखाने से देशवासी प्रभावित नही हुये। 85 करोड़ लोगों को पाँच किलो गेहूं की लाइन में लगाकर उनकी खाली जेबों का ध्यान न रखना, शिक्षा के बाद नौकरी के इंतजार में ओवरएज होती पीढ़ी का गुस्सा ओर तनाव, अग्निवीर जैसे प्रयोग ने मोदी का डंका पिटवा दिया ओर वे दलदल में गिरने को तैयार हो गए।

संजय बोला-महाराज वर्ष 2024 में मोदी जी अति उत्साह में थे ओर उन्होने जो झूठ, महाझूठ की शुरूआत की तो वह थमने का नाम ही नही ले रही थी। अपने को महान बनाने के लिए अपनी महानता के झूठ के पल बांधते, अपने विरोधियों के प्रति झूठ पर झूठ का जहर उगलते रहे, जनता समझती रही। उन्होने इस बार झूठ बोया, झूठ का अंकुरण पैदा हुआ फ्री झूठ का वृक्ष पैदा हुआ ओर देखते देखते झूठ का जंगल खड़े हो गए। मोदी की गारंटी के नाम से यह प्रचार शुरू हुआ झूठ के जंगल से दहाड़ने वाले मोदी को झूठ की ही फसल काटनी पड़ी। आज पूरा देश देख रहा है मोदी की गारंटी के कारण कुर्सी की जंग शुरू हो गई है। भले ही एनडीए चुनाव जीत गया हो परंतु मोदी की गारंटी चुनव हार गई है, अब यही मोदी की गारंटी पाँच साल के शासन की बागडौर संभालने को है ओर अपने हरेक सहयोगी को कुर्सी देने की गारंटी लो गई है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अपने आत्म गौरव ओर सम्मान को बनाए रखना है। मोदी की जो कुर्सी की गारंटी है वह एनडीए ओर भाजपा नेतृत्व के गठबंधन की डोर पाँच साल तक मजबूत रखने के लिए है किन्तु मोदी जी कुर्सी के लिए सभी तरह के समझौते कर भी ले तो इस मनमाफिक सौदेबाजी के बाबजूद राजनीतिक स्थिरता मजबूत बनी रहेगी इसकी गारंटी उनके पास नहीं है। मोदी जी गारंटी के फेर में अभिमन्यु के तरह चक्र में फसे दिख रहे है जो राजनीतिक झटको ओर अशांति के कमजोर पक्ष को समझते हुये जनता के निर्णय पर चिंतन अवश्य करेंगे। उन्हे समझ लेना चाहिए की अहकार किसी का भी नहीं रहता है ओर वे इस बात का भी आत्ममंथन करे की लोकतंत्र में डंका जनता का ही बजता है, उनका नहीं। महाराज बोले ठीक है संजय कुर्सी की गारंटी यानी शासन करने के लिए गृह, कृषि, रेल, वित्त आदि विभागों की सौदेबाजी ओर बंदरबांट के बाद के परिणामों पर दुबारा चर्चा करूंगा, अब मैं विश्राम की ओर चलता हूँ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भाजपा नीत सरकार

नेता नरेन्द्र मोदी

भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग अपने संख्याबल के आधार पर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार बना चुका है। लोकसभा चुनाव में हालांकि, भाजपा को स्वयं पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन चुनाव-पूर्व गठबंधन राजग को बहुमत से अधिक सीटें मिली हैं। इस गठबंधन में अनेक क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। कहा जाता है कि इन सहयोगियों ने कड़ा लेनदेन किया है, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने राजग सांसदों को संबोधित करते हुए इसका खंडन किया। उन्होंने सांसदों को सतर्क किया था कि वे संभावित मंत्रिमंडल के बारे में किसी प्रकार की अफवाहों का शिकार न बनें। राजग गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की तेलगूदेशम पार्टी-तेदेपा तथा नीतीश कुमार की जनता दल युनाईटेड-जदयू व अन्य दल शामिल हैं। क्षेत्रीय पार्टियां स्वाभाविक रूप से अपने राज्य-विशिष्ट हितों को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन इससे राजग में शामिल पार्टियों में किसी मतभेद या गठबंधन के स्थायित्व पर संदेह की आशंका नहीं है। नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई है कि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति करेगा और इसका लाभ बिहार को भी मिलेगा। मोदी ने कहा कि वह अपनी सरकार के सभी फैसलों से सर्वसम्मति सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने राजग को एक 'जैविक संगठन' बताते हुए कहा कि यह गठबंधन 'सर्व पंथ समभाव' के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एनडीए का अर्थ 'नया भारत, विकसित भारत और आंकाक्षी भारत' है। मोदी ने यह भी याद दिलाया है कि वे किसी प्रकार के दबाव में आने वाले नहीं हैं। मोदी की आत्मविश्वास से भरी इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि भाजपा अपने राजग सहयोगियों के साथ मिल कर राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नीतियां

अपनाएगी और उनको तेजी से लागू करेगी। नायडू ने भी आशा प्रकट की कि नई सरकार जल्दी से और तेजी से काम करना शुरू करेगी।

गठबंधन सरकारों की कुछ अंतर्निहित समस्याओं के बावजूद उन्होंने खासकर 1990 के दशक में सुशासन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सर्वाधिक उल्लेखनीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसने न केवल अनेक चुनौतियों का सामना किया, बल्कि भारत में भावी गठबंधन राजनीति के लिए उदाहरण भी स्थापित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय राजग में 20 से अधिक पार्टियां शामिल थीं जिनके अपने-अपने एजेंडे थे। इसके बावजूद वाजपेयी सरकार ने नाभिकीय आयुधों के परीक्षण किए तथा भारत का विश्व स्तर पर सम्मान बढ़ाया। सरकार ने नाभिकीय परीक्षणों पर लगे प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति सुनिश्चित की। वाजपेयी सरकार की सफल राजनय ने धीरे-धीरे दुनिया के सभी देशों को भारत की उन स्थितियों के बारे में समझाया जिसके कारण उसे नाभिकीय आयुध बनाने का निर्णय करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजग के नव-निर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि यह राजग देश में 15 साल सरकार चला चुका है। इस प्रकार उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चली राजग सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। अटल सरकार ने देश में जिस व्यापक आधार पर ढांचागत निर्माण को गति दी थी, मोदी के नेतृत्व में पिछली दो राजग सरकारों ने उसे अभूतपूर्व गति दी है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने की घोषणा के बाद शेयर बाजार ने भारी छलांग लगाकर सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया। यह इस बात के प्रति विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

भारत में नई राजनीति का युग

भारतीय मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत न देकर गठबंधन राजनीति का नया युग शुरू किया है। हालांकि, भाजपा नीत राजग सरकार बनाने में सफल हुआ है।

नीलांत इलांगमुवा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत में लोकसभा चुनाव ने क्षेत्र में नई राजनीति के संकेत दिए हैं। इससे देशों को अपने राजनीतिक लोकतांत्रिक ढांचों को मजबूत करने का संकेत मिला है। लोकतांत्रिक दृढ़ता का परिचय देते हुए भारतीय मतदाताओं ने भाजपा के वर्चस्व को थोड़ा झटका जरूर दिया है, पर अंततः भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग सरकार बनाने में सफल हुआ है। यह एक राष्ट्र की सामूहिक भावना को स्वर देता है जिसने स्पष्ट रूप से 'शक्ति संतुलन' का पक्ष लिया है। जनता की राय प्रभावित करने के व्यापक चुनाव प्रचार अभियान के बावजूद मतदाताओं ने मोदी के वर्चस्व पर सवाल उठाए हैं। इससे मोदी के जादू और करिश्माई व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा है, पर देश की भावी आर्थिक प्रगति को देखते हुए दुनिया में भारत के कद पर कोई फर्क पड़ने की आशंका नहीं है। भाजपा को इस चुनाव में सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है और उसकी संख्या पिछले चुनाव में मिली 303 सीटों से 92 कम हो गई हैं।

भाजपा के गढ़ समझे जाने वाले उन क्षेत्रों में भी सीटें कुछ कम हुई हैं जहां उसने पिछले दो चुनावों में पूर्ण वर्चस्व प्राप्त किया था। हालिया लोकसभा चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया पर भारी खर्च हुआ है। निर्वाचन आयोग ने भी अधिकाधिक मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने हेतु गूगल समेत सोशल मीडिया पर काफी खर्च किया। राजनीतिक दलों में सोशल मीडिया पर भाजपा ने सबसे ज्यादा खर्च किया। मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों द्वारा भारी खर्च से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक मानकों को प्रभावित करने में विज्ञापनों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। इससे लोकतंत्र को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करने की संभावनायें व जोखिम भी स्पष्ट होते हैं।

लेकिन इसके बावजूद अंततः लोकतंत्र की विजय हुई है। लोगों ने अपनी बातें पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ प्रकट की हैं तथा अनेक लोगों ने धार्मिक विचारधाराओं या व्यक्तिवाद से अलग हट कर अपनी राय प्रकट की है। इससे लोकतंत्र तथा पंथनिरपेक्ष प्रशासन को बल मिला है। यह चुनावी उथलपुथल इस बात का भी संकेत देती है कि अब लोकतांत्रिक देशों में जनता केवल राजनेताओं के खोखले वादों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है और वह वास्तविक जमीनी बदलाव देखना चाहती है। भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा अपनी विजय तथा दुनिया भर में भारत के बढ़े कद के आधार पर विमर्श तैयार किया गया था, पर इसके बावजूद उनके चुनावी प्रदर्शन को धक्का लगा है। भाजपा को विपक्षी दलों द्वारा तैयार जातीय गणित तथा सामाजिक समीकरणों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है और सत्ता पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी है।

भाजपा का आरोप है कि विपक्षी दलों ने मतदाताओं में अनेक मुद्दों पर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया और वे इसमें एक सीमा तक सफल भी हुए। हालांकि, भाजपा 2019 में प्राप्त अपनी पकड़ का काफी हिस्सा बनाए रखने में सफल हुई, पर उसे 92 सीटों का नुकसान हुआ जिसके कारण वह प्रचंड विजय नहीं प्राप्त कर सकी। इससे उसकी रणनीतियों में कमी तथा उसके दावों में जमीनी कमियां उजागर होती हैं। मोदी के प्रचार अभियान में विदेशी मामलों तथा राजनय को काफी स्थान मिला। उसमें दुनिया में भारत के बढ़े कद तथा भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर खासतौर से ध्यान दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि मोदी ने यह काम घरेलू समस्याओं, जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असमानता व देश के कुछ हिस्सों में सामाजिक उथलपुथल से ध्यान हटाने के लिए किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों का खासतौर से चुनाव प्रचार में उल्लेख किया जिसमें वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन और भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भारत के बहुत से नागरिकों के दिन-प्रतिदिन के संघर्षों में कोई कमी नहीं आई थी और इस प्रकार राजनीतिक विमर्शों तथा जमीनी अनुभवों में विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो रही थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले दस साल के कार्यकाल में तकनीक का प्रयोग कर भ्रष्टाचार दूर करने तथा लोगों का जीवन सहज बनाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर जनसंख्या और मतदाताओं की इच्छानुसार समुचित परिवर्तन नहीं दिखाई पड़े। अब हालिया चुनाव में सीटें कम हो जाने पर भाजपा तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जनता की ओर से जवाबदेही तथा परिवर्तन की तेज होती मांगों का सामना करना पड़ सकता है। मोदी की नई सरकार के समक्ष प्रशासन को और ज्यादा पारदर्शी बनाने तथा जन-केन्द्रित करने की चुनौती बनी रहेगी। इसके कारण अब सरकार को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेही का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मोदी की विदेश नीति और घरेलू एजेंडे में एक प्रकार की संगति है जिसके चलते 'हम बनाम वे' का विमर्श तैयार हुआ है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता बार-बार दुहराई जिसमें खासकर आतंकवाद से मुकाबला करना शामिल है। पाकिस्तान और चीन के साथ 2020 में टकरावों के बावजूद भारत द्वारा मुकाबले को राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके उलट मोदी के आलोचकों का कहना था कि चीनी आक्रामकता के प्रति सरकार की नीति एकदम सटीक नहीं थी। हालांकि, इस विरोधाभास के पीछे भू-राजनीतिक जटिलताओं तथा राजनयिक बाधाओं की प्रमुख भूमिका है।

भारत ने विभिन्न विश्व शक्तियों के साथ संबंधों में अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता दी और वह अंतरराष्ट्रीय जगत में उथलपुथल के बावजूद अपनी 'रणनीतिक स्वायत्ता' के रास्ते पर चलता रहा। भाजपा पर विपक्ष का यह आरोप भी है कि उसने घरेलू मामलों पर विदेशनीति मामलों को वरीयता दी। इस प्रकार विपक्ष दुनिया में भारत का कद बढ़ने के बावजूद मोदी के 'राष्ट्रवादी विमर्श' को चुनौती देता है। विपक्ष ने भले ही भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक मानक तोड़ने के आरोप लगाए हों, पर अधिकांश मतदाताओं ने मोदी के दृढ़ दृष्टिकोण को पसंद किया। इससे जनता के मन में मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति की इच्छा प्रकट होती है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा देश में मुद्रास्फीति व बेरोजगारी के मुद्दों से ठीक से नहीं निपट सकी और संभवतः इसी कारण उसे उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा। विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा पैदा कर रही है जिससे उसके आलोचकों तथा पूर्व-समर्थकों में निराशा की भावना पैदा हुई।

1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा की सत्ता तक यात्रा और चुनौतियों का इतिहास है। हालांकि, मोदी की वाराणसी पर छाप से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके प्रयासों से वाराणसी में तेजी से ढांचागत विकास हुआ है और शहर की तस्वीर बदल गई है, लेकिन अनेक स्थानीय लोगों के विचार से इससे वाराणसी की 'परंपरागत' छवि तथा 'जीवनशैली' भी टूटी है जिसका बहुत से लोगों को दुःख है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे एक जटिल परिदृश्य का संकेत देते हैं जहां कुछ परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ दलितों के एक हिस्से में संकट की भावना बनी हुई है।

मोदी की लोकप्रियता के बावजूद वाराणसी में उनकी जीत का अंतर घटा है। भाजपा के अबकी बार 400 पार के नारे ने दलितों के एक हिस्से में संविधान में संशोधन कर आरक्षण को चोट पहुंचाने की भावना पैदा हुई जिसका विपक्ष ने खूब लाभ उठाया और उसे भड़काया। भाजपा के आक्रामक चुनाव प्रचार ने मुसलमानों को विपक्ष के साथ ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया। लेकिन चुनावी नुकसान के बावजूद भाजपा अभी देश की सर्वाधिक मजबूत शक्ति है और सहयोगियों के साथ मिल कर बनी उसकी सरकार इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी। देखना होगा कि इससे आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति में कितने परिवर्तन आते हैं। अगले पांच साल में मोदी सरकार ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का वादा किया है। ऐसे में देखना होगा कि दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में जनता की सोच कैसे परिवर्तित होती है।

गठबंधन की सरकार में राजनय

> मतदाता के फैसले का भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रक्षेपवक्र पर आने वाले लंबे समय तक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भारत ने मतदान कर दिया है और फैसला आ गया है। इसने गठबंधन सरकारों के युग को वापस ला दिया है, गठबंधन सहयोगियों के दबावों को प्रमुख नीतिगत मामलों पर एक दशक के बाद भारत की राजनीति में वापस लाया है। मजबूत, एकल-स्रोत निर्णयों का युग सबसे अधिक संभावना है कि खत्म हो गया है और एक दशक तक वापस नहीं आ सकता है। मतदाता के फैसले का भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रक्षेपवक्र पर आने वाले लंबे समय तक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

पिछले दशक में मोदी सरकार द्वारा पोषित और एक निश्चित स्थिर मंच पर पहुँचे अमेरिका के साथ संबंधों में खलल पड़ने की संभावना नहीं है। मौजूदा व्यापार साझेदारी में जोड़ी गई प्रौद्योगिकी साझेदारी को वाशिंगटन में द्विदलीय समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि वर्ष के अंत में ट्रम्प के अमेरिका लौटने की संभावना में, यह भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में कोई खलल नहीं डालेगा। भारत और अमेरिका ने अतीत में, बंद दरवाजों के पीछे भारत द्वारा नामित आतंकवादी जी एस पन्नून पर कथित हिट प्लान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने में पर्याप्त परिपक्वता दिखाई है। भारत में काम करने वाले ज़्यादातर अमेरिकी व्यवसाय गठबंधन के फ़ैसले से राहत महसूस कर सकते हैं(

क्योंकि यह एक ऐसे प्रधानमंत्री की अतिशयता के बारे में कई चिंताओं (बंद दरवाजों के पीछे उनके अमेरिकी सहयोगियों द्वारा व्यक्त) को दूर कर सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बहुमत है। सरकार में ज़्यादा गठबंधन साझेदारों के आने से, महत्वपूर्ण नीतिगत फ़ैसलों पर असर पड़ने से, उन्हें कई प्रभाव क्षेत्र मिलने से राहत मिल सकती

है। अमेरिका और वैश्विक पूंजी भारत में एक बाज़ार के रूप में सुरक्षित महसूस करेंगे, जब तक कि यह हमेशा की तरह कारोबार हो, कोई आश्चर्यजनक संरक्षणवादी विनियमन न हो और विकास बाज़ार हो। गठबंधन सरकार में, कई जाँच और संतुलन के साथ, एकतरफा फ़ैसलों की गुंजाइश कम होती है। साथ ही, जैसा कि कई विशेषज्ञों ने इस लेखक को बताया, अमेरिका को एशिया में एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सहयोगी पाकर खुशी होगी, ताकि इंडो-पैसिफिक में आक्रामक चीन का मुक़ाबला किया जा सके। भारतीय रक्षा बलों के साथ संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक महत्व की महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करना (भले ही भारत पाँच आँखों के नेटवर्क का हिस्सा न हो), सेमीकंडक्टर पर भारत को साझा करना और सशक्त बनाना, ‚द्व जैसी महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीकों पर मानकों और विनियमों का घनिष्ठ सह-निर्माण प्रभावित होने की संभावना नहीं है। क्वाड, आई2यू2 और व्यापक यूएन आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत और अमेरिका पर इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि, दिखावटी, राजकीय यात्राएं और एक-दूसरे के नेताओं की बड़े पैमाने पर मेजबानी (2019 में ट्रंप का संदर्भ और 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा) कैमरे से दूर, अधिक शांत, कूटनीतिक बातचीत की ओर बढ़ सकती है। मुख्य रूप से मानवाधिकारों, ध्रुवीकरण वाले भाषणों, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म आदि पर मुख्य रूप से अमेरिकी थिंक टैंक और नीति विशेषज्ञों द्वारा भारत की कभी-कभार आलोचना के बावजूद, भारत के लिए द्विदलीय समर्थन है और दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं और इसमें बदलाव की संभावना नहीं है।

यदि भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता एक कमजोर गठबंधन सरकार (यूपीए सरकार 1.0 से एक महत्वपूर्ण सहयोगी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण) का कारण साबित हुआ, तो वर्तमान में द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। केंद्र में एक गठबंधन भारतीय सरकार होने के बावजूद। वाशिंगटन और नई दिल्ली ने अपने वरिष्ठ सांसदों/राजनेताओं/थिंक टैंकों/विशेषज्ञों को रिश्ते के रणनीतिक महत्व के बारे में शिक्षित करने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रपति बिडेन को भले ही अपने पार्टी सहयोगियों या दबाव समूहों से कई मुद्दों पर भारत के प्रति थोड़ा बहुत उदार दृष्टिकोण रखने के लिए कभी-कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे वर्तमान संदर्भ में इस रिश्ते की प्रासंगिकता को समझते हैं।

अगले कुछ महीनों में अमेरिका में एक नए भारतीय राजदूत (पूर्व राजदूत ने सेवानिवृत्ति के बाद 2024 में असफल चुनाव लड़ा था) की संभावना है। अमेरिका में भारतीय राजदूत कई आपसी द्विपक्षीय मुद्दों पर गलियारे में आम सहमति बनाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। अगले राजदूत का चयन एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस पर नज़र रखनी होगी।

आप की बात

नेताओं को सबक

चुनाव परिणामों ने नेताओं को अनेक सबक दिए हैं। कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 हो जाना उसके लिए जश्न मनाने जैसा है। लेकिन इसके पीछे गरीबों को ललचाने व भ्रमित करने के दांव हैं जिनका अब खुलासा हो रहा है। इस बार चुनाव में कुछ दलों ने जम कर घटिया हथकंडे अपनाए। बीजेपी राजस्थान और यूपी मैं अति आत्मविश्वास और भीतराघात के चलते अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इन चुनाव के बाद उसे आत्म मंथन करना होगा। अपने निजी फायदे के लिए पार्टी को चोट पहुंचने वाली कई काली भेड़ों को पार्टी से बाहर करना होगा। नतीजों से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। मगर उसे भी मध्य प्रदेश सहित जिन राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली है वहां आत्ममंथन करना होगा। सभी पार्टियों के चुनावी गणित गड़बड़ाने की प्रमुख वजह कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। कुछ स्थानों पर थोपे गए बाहरी उम्मीदवारों ने भी खेल बिगड़ है। मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद अब अनेक निर्दलीय एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा दूसरे दलों को तोड़ कर भी अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास करे। लेकिन राजनेताओं को चुनाव ने सबक दिया है कि जनता हमेशा दलबदलुओं को स्वीकार नहीं करती है और पुराने कार्यकर्ता इस अवसरवाद के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

शेयर बाजार की छलांग

4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों से महागठबंधन की संभावना और मोदी सरकार की कमजोर संभावना के चलते शेयर बाजार का अंक 76468 से लुढ़क कर 72079 हो गया था, किन्तु जैसे ही मोदी सरकार बनने की संभावना प्रबल हुई, शेयर मार्केट ने आसमान छूना आरम्भ कर दिया और बढ़ते.बढ़ते 7 जून को पूरे समय उच्च स्तर पर बने रहकर 76,795 तक गया। यह अब तक की उसकी सबसे ऊंची छलांग है। महागठबंधन की खिचड़ी सरकार की संभावना शेयर बाजार को भी स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं आई और वो धड़ाम हो गया। जैसे ही मोदी सरकार की सम्भावना बढ़ी और उसने लम्बी-लम्बी छलांग लगना शुरू कर दी। मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इसके और ऊपर जाने की उम्मीद है। इस प्रकार शेयर बाजार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। जनता को खैरातें बांटने या सरकारी खजाना लुटाने का वादा कर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करने वालों को यह कड़ा सबक है। देश के शेयर बाजार तथा व्यापार जगत को नरेन्द्र मोदी की नीतियों पर विश्वास है जो देश की अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें स्थान से पांचवें स्थान पर लाए हैं और अब उसे तीसरे स्थान पर ले जाएंगे।

– **पूजा नेनावा साहू,** पुणे

अविस्मरणीय चुनाव

2024 के लोकसभा चुनाव को लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश और जनता भी खुश। एनडीए की सीटें कम होने में कई कारकों के साथ-साथ अधिकांश राज्यों में बहुत कम मतदान होना भी है। मोदी द्वारा 400 सीटों के दावे से भी स्थिति खराब हुई। लोगों ने सोचा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत तो आ ही जाएगा फिर क्यों हम वोट देने की जहमत उठाएं? हमेशा की तरह पढ़े-लिखे शहरी मतदाताओं के मुकाबले ग्रामीण मतदाताओं ने अधिक संख्या में वोट डालें। इस स्थिति में मतदान बढ़ाने तथा उसे शत प्रतिशत बनाने के प्रयास करने होंगे। अपने मतदान केंद्र से दूर प्रवास करने वालों के लिए ऑनलाइन मतदान करने का कोई पारदर्शी तरीका खोजा जाना चाहिए। साथ ही किसी भी कारण से जेल में बंद व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में जेल में बंद आतंकी भी अल्पमत सरकारों को टेका लगाने के लिए सत्ता में आकर देश की संप्रभुता पर चोट पहुंचा सकते हैं। इस बार जेल से चुनाव लड़ने वाले दो अतिवादी माननीय सांसद की शपथ लेने आने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इन पर आतंकी फंडिंग तथा खालिस्तान समर्थन के आरोप हैं।

–**विभूति बुपक्या,** खाचरोद

जातिवाद का असर

लोकसभा के चुनाव परिणामों में ऐसा प्रतीत हुआ कि देश की राजनीति में जातिवाद का असर अभी काफी है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। स्पष्ट बहुमत की सरकार और गठबंधन की सरकार का आंकलन तो विगत बीस वर्षों में देश की जनता ने कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकारों में सभी संप्रदाय के लोगों का विकास किया गया, करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, देशहित में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई, विदेश नीति भी अपने चरम पर रही तथा विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों ने दस सालों में अकल्पनीय अनुभव किया। इसके बावजूद जनता के बड़े हिस्से ने इन सारी चीजों को अनदेखा कर आंखें बंद कर जाति के नाम पर वोट दिया है। मजेदार बात है कि जातियों तो मुसलमानों में भी हैं, लेकिन वे सब एकजुट होकर भाजपा को हराने वाली पार्टी को वोट देते हैं। देश पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस ने जातीय जनगणना तथा आरक्षण सीमा बढ़ाने की बात कर जातिवाद का असर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जातिवाद विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है।

– **अंकित सोनी,** मनावर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

थोड़ी खुशी, थोड़ा गम

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

यूपी में रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से गांधी परिवार के विश्वासपात्र के एल शर्मा को खड़ा करने की बात हो या अखिलेश को अधिक से अधिक स्पेस मुहैया कराने की, ये सब कारगर साबित हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस में एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिख रहा है, जो स्वाभाविक है। हालांकि बड़ा सवाल आज भी यही है कि इससे आगे की उसकी यात्रा कैसी होगी और इस सवाल का जवाब अब भी कई चुनौतियों से घिरा नजर आ रहा है।

आधा भरा या आधा खाली ग्लास : अगर सहयोगी दलों की जिद के चलते महाराष्ट्र की सांगली और बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने को मजबूर हुए विशाल पाटिल और पप्पू यादव की जीत को जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस की सीट संख्या 101 पर पहुंच जाती है। लेकिन बात सौ पार करने या न करने की उतनी नहीं है। कुल मिलाकर यह चुनाव कांग्रेस के लिए ऐसा नतीजा लाया है, जिसमें यह तय करना मुश्किल है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है।

संगठनात्मक ढांचा : कांग्रेस के लिए यह खुशी की बात हो सकती है कि विपक्षी गठबंधन कठ.ऊकअ. खुद बहुमत के करीब न पहुंचकर भी कम से कम बीजेपी को बहुमत से दूर रखने में कामयाब हो गया। इस लिहाज से खुद कम सीटों पर लड़ने और संविधान की रक्षा के नारे पर सबसे ज्यादा जोर देने की उसकी रणनीति काम कर गई। लेकिन बतौर राजनीतिक दल उसे उन क्षेत्रों पर ध्यान देना ही होगा जहां उसका संगठनात्मक ढांचा लगातार कमजोर होता रहा है।

फिर से नंबर वन: महाराष्ट्र की राजनीति पिछले पांच वर्षों में जिस तरह की उथल-पुथल और घालमेल से गुजरी, उसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी के रूप में उभरना निश्चित रूप से काफी मायने रखता है। वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की आक्रामकता के मुकाबले महाराष्ट्र की गरिमा का सवाल खड़ा करते हुए भी कांग्रेस के सामने अपने सपोर्ट बेस को सुरक्षित रखने की चुनौती होगी।

नई संभावनाएं : यूपी में रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से गांधी परिवार के विश्वासपात्र के एल शर्मा को खड़ा करने की बात हो या अखिलेश को अधिक से अधिक स्पेस मुहैया कराने की, ये सब कारगर साबित हुए। बढ़ी हुई दलित चेतना के साथ खड़े होते हुए कास्ट सेंसस जैसे मसले को आक्रामक ढंग से उठाना भी उत्तर भारत के एक बड़े तबके में कांग्रेस को लेकर उम्मीद जगा रहा है।

सीधे मुकाबले की चुनौती : ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि संविधान और लोकतंत्र को कथित खतरों से बचाने वाली इस चुनावी लड़ाई के बाद कांग्रेस आगे की यात्रा के लिए खुद को कैसे तैयार करती है। खासकर ओडिशा और मध्यप्रदेश जैसे राज्य विशेष तवज्जो की मांग करते हैं। ध्यान रहे, देश में 215 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला रहा, उनमें 70% बीजेपी के पक्ष में गईं। अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को बराबरी की टक्कर देते हुए दिखना है तो उसे इस अंतर को पाटने पर ध्यान देना होगा।

भारतीय मूल की बेटी अंतरिक्ष में पहुंचकर खुशी से झूम उठी, रच दिया इतिहास

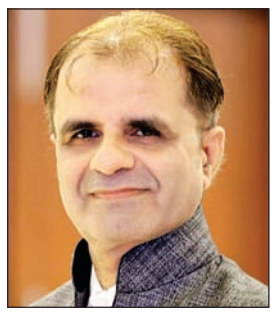

भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान को उड़ाकर स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है-एडवोकेट किशन भावनानी

शाबाश सुनीता विलियम्स !

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पर पूरी दुनियां में भारतीयों की बौद्धिक क्षमता का लोहा माना जाता है। यही कारण है कि आज हम पूरी दुनियां के विकसित से विकासशील देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखें तो उनके सीईओ मूल भारतीय ही होंगे। अभी हमने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए लड़ने के क्रम में तीन मूल भारतीय उम्मीदवार थेजिनमें निक्की हेली अंतिम क्षण तक डटी रही। अनेक देशों के राजनीतिक प्रमुख भी मूल भारतीय ही है जिसमें ब्रिटेन प्रमुख है, व अमेरिका ब्रिटेन सहित कई देशों के संवैधानिक पदों पर व संसद सदस्य भी मूल भारतीय ही हैं जिससे हम सटीकता से कह सकते हैं कि जहां भारतीय का नाम जुड़ा वहां कुछ खास सफलता का झंडा गड़ना तय है। चूंकि अमेरिकी नागरिक भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान को उड़ाकर स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, जो खुशी से झूम उठी है और इतिहास रच दिया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, शाबाश सुनीता विलियम्स! साथियों बात अगर हम अमेरिकी नागरिक भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स के गुरुवार देर रात स्पेस स्टेशन में पहुंचने की करें तो,वह गुरुवार रात 11:03 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने डांस करके अपनी खुशी जाहिर की। बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पहुंचते ही डांस करती नजर आईं। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग के 26 घंटे बाद गुरुवार रात 11:03 बजे स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे गुरुवार रात 9:45 बजे पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में आई परेशानी के कारण पहली कोशिश में यह डॉक नहीं कर पाया। हालांकि, दूसरे प्रयास में स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डॉक कराने में सफलता मिली।दोनों एस्ट्रोनॉट्स बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। बोइंग का स्टारलाइनर मिशन बुधवार 5 जून को भारतीय समयानुसार रात 8:22 बजे लॉन्च हुआ था। फ्लोरिडाके केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशनसे यूएलए के एटलस ५ रॉकेट से लॉन्च किया गया था।विल्मोर और विलियम्स स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट और उसके सभी सिस्टम का टेस्ट करने के लिए करीब एक हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे। बोइंग के स्पेसक्राफ्ट एसयूवी-स्टारलाइनर को डिजाइन करने में सुनीता ने भी मदद की थी। इसस्पेसक्राफ्ट में 7 क्रू सदस्य सवार हो सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट बनने के बाद सुनीता विलियम्स ने ही इसका नाम कैलिप्सो रखा था।मिशन सफल हुआ तो नासा के पास पहली बार 2 स्पेसक्राफ्ट होंगे अभी अमेरिका के पास इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ही है। नासा ने साल 2014 में स्पेसएक्स और बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। स्पेसएक्स 4 साल पहले ही इसे बना चुकी है।सुनीता के आईएसएस पहुंचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनके स्पेस स्टेशन पहुंचने पर एक घंटी बजती सुनाई देती है। दरअसल, ये आईएसएस की परंपरा है कि जब भी वहां कोई नया अंतरिक्ष यात्री पहुंचता है, तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका स्वागत करते हैं।सुनीत विलियम्स ने आईएसएस के सदस्यों को अपना दूसरा परिवार बताया। उन्होंने कहा, आईएसएस मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। साथ ही उन्होंने शानदार स्वागत के लिए सभी एस्ट्रोनॉट्स को धन्यवाद भी कहा। साथियों बात अगर हम सुनीता के अंतरिक्ष में उड़ान भरने के अभियान की करें तो, सुनीता ने उड़ान भरने से पहले मिशन कंट्रोल को संदेश भेजकर कहा था-चलो चलते हैं, कैलिप्सो। हमें अंतरिक्ष ले चलो और वापस ले आओ।सुनीता की मां बोनी पांड्या ने एक मीडिया चैनल को बताया कि उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले उनकी बेटी काफी सकारात्मक थी और अंतरिक्ष में उड़ान भरने को लेकर बहुत ही खुश थी। वहीं, नासा ने आज नया अपडेट देते हुए कहा कि सुनीता और बुच विलमोर दोनों कक्षा में स्टारलाइनरअंतरिक्ष यान पर शुरूआती परीक्षण करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले छह घंटे बहुत ही दिलचस्प रहे हैं।सुनीता विलियम्स का स्टारलाइनर अभियान पांच जून को केप कैनावेरल अंतिक्ष स्टेशन से शरू हुआ। भारतीय समयानुसार यह अभियान रात आठ बजकर 22 मिनट पर शुरू हुआ। यह यान अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में छह जून रात 9 बजकर 45 मिनट पर पहुंचना था। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं।बताया गया है कि बोइंग स्टारलाइनर यान की उड़ान में कई बार, कई वजहों से देरी हुई। आखिरकार, फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इस यान की रवानगी हुई। इस तरह के मिशन पर जाने वाली सुनीता विलियम्स दुनियां की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। मई 1987 में सुनीता ने अमेरिका की नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद वे अमेरिका की नौसेना से जुड़ीं थीं। 1998 में उन्हें नासा द्वाराअंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2012 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन चुकीं हैं।भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार अपने सहयोगी बैरी बुच विलियम्स के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। साथियों बात अगर हम सुनीता विलियम्स के इतिहास रचने की करें तो,भारतीय मूलकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बुधवार को एक अन्य सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशनकई बार के विलंब के बाद फ्लोरिडा के 'केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन' से रवाना हुआ।वर्ष 2012 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान विलियम्स अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन' पूरा करने वाली पहली व्यक्ति बनी थीं। विलियम्स मई 1987 में अमेरिकी नौसैन्य अकादमी से प्रशिक्षण लेने के बाद अमेरिकी नौसेना से जुड़ी थीं, और वह दो अंतरिक्ष अभियानों-2006 में अभियान 14/15 तथा 2012 में 32/33 अभियानों का हिस्सा बनीं। उन्होंने अभियान -32 में फ्लाइट इंजीनियर और फिर अभियान-33 की कमांडर के रूप में काम किया। अंतरिक्ष यान के विकास में असफलताओं के कारण बोइंग के क्रू फ़्लाइट टेस्ट मिशन में कई वर्षों की देरी हुई । यान बृहस्पतिवार को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा।वे अंतरिक्ष में घूमती प्रयोगशाला में एक सप्ताह से अधिक समय बिताएंगे और इसके बाद 14 जून को वापसी के लिए पश्चिमी अमेरिका के एक दूरस्थ रेगिस्तान में उतरने के वास्ते स्टारलाइनर यान में फिर से सवार होंगे। साथियों बात कर हम बात अगर हम स्टारलाइन का पृथ्वी से स्पेस स्टेशन और वापस पृथ्वी पर आने का सफर जाननें की करें तो, एटलस ५ रॉकेट लॉन्च हुआ। 15 मिनट बाद इसने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को रिलीज किया। स्पेसक्राफ्ट के इंजन फायर हुए और ये स्पेस स्टेशन की लगभग 24 घंटे की यात्रा के लिए कक्षा में स्थापित हो गया।स्टारलाइनर हार्मनी मॉड्यूल के आगे वाले पोर्ट पर डॉक हुआ। अपने स्टे के दौरान क्रू स्टारलाइनर के अंदर जाएगा, हैच बंद करेगा और दिखाएगा कि भविष्य में मलबे के साथ टकराव के रिस्क जैसी स्थिति में स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित आश्रय के रूप में काम कर सकता है।विल्मोर और विलियम्स पृथ्वी पर लौटने से पहले लगभग एक हफ्ते तक एक्सपेडिशन 71 क्रू के साथ रहेंगे और काम करेंगे। अनडॉकिंग के बाद,स्टारलाइनर के मैनुअल पायलटिंग का आकलन होगा। चालक दल अनडॉकिंग से लेकर लैंडिंग तक करीब 6 घंटे बिताएगा।पृथ्वी के वायुमंडल में रीएंट्री के दौरान,स्पेसक्राफ्ट 28,000 केएम/घंटे की गति से धीमा होना शुरू होजाएगा। इस दौरान क्रू 3.5 जी तक भार महसूस कर सकता हैरीएंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट की आगे लगी हीट शील्ड को हटा दिया जाएगा।दो ड्रैग और तीन मुख्य पैराशूट स्टारलाइनर की गति को और धीमा कर देंगे। बेस हीट शील्ड डुअल एयरबैग सिस्टम को एक्सपोज करते हुए डिप्लॉय हो जाएगी। 6 प्राइमरी एयरबैग कैप्सूल के बेस पर डिप्लॉय होंगे। ये लैंडिंग के दौरान कुशन की तरह काम करेंगी। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। संभावित लैंडिंग स्थानों में एरिजोना का विलकॉक्स और यूटा का डगवे प्रोविंग ग्राउंड शामिल है। कैलिफोर्निया में एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस एक इमरजेंसी लैंडिंग साइट के रूप में उपलब्ध है।टचडाउन के बाद, चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की बिजली बंद करेगा और मिशन कंट्रोल लैंडिंग और रिकवरी टीमों से सैटेलाइट फोन कॉल के जरिए संपर्क करेगा। रिकवरी टीम स्टारलाइनर के चारों ओर एक टेंट लगाएगी और स्पेसक्राफ्ट में ठंडी हवा पंप करेगी।स्टारलाइनर का हैच खुलने और, लैंडिंग के एक घंटे से भी कम समय बीतने के बाद, दोनों एस्ट्रोनॉट्स हेल्थ चेक के लिए मेडिकल व्हीकल में जाएंगे। फिर नासा के विमान तक पहुंचने के लिए हेलिकॉप्टर में उड़ान भरेंगे।

आईआईटी नहीं तो क्या?

विजय गर्ग

इंजीनियर के उपसर्ग से ग्रस्त देश में, माता-पिता के लिए अपने बच्चों का इंजीनियर बनने का सपना देखना लगभग अनिवार्य है। जूनियर कक्षाओं में आपको बच्चों से तरह-तरह के सपने सुनने को मिलेंगे। आप इच्छुक पायलटों, कला शिक्षकों, टैंगो नर्तकों और फोटोग्राफरों से मिलेंगे। लेकिन एक बार जब वे अपने जूनियर कॉलेज स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप उन्हें आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ कोचिंग संस्थानों में भागते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आखिर इतनी जल्दी क्या है? चूहा-दौड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने जुनून का पालन क्यों न करें? लेकिन फिर भी ऐसे छात्र हैं जो वास्तव में प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने और वहां से स्नातक होने के लिए उत्सुक हैं। कई युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने का सपना देखते हैं। आज पेश किए गए विशाल अवसर अद्वितीय हैं। उन्नत आईटी प्रशिक्षण एक छात्र को आईटी क्रांति में पथप्रदर्शक बनने के लिए तैयार करता है। आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और कई भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्नातक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई आईटी दिग्गजों में शीर्ष पदों पर हैं। समय-समय पर, हम दुनिया भर में कुछ वास्तुशिल्प चमत्कारों को देखते हैं। जरा बुर्ज खलीफा के वास्तुकारों से जुड़े गौरव की कल्पना करें! ऐसे कई छात्र हैं जो इस गौरव और प्रतिष्ठा को साझा करना चाहते हैं। आईआईटी छात्रों को इन सपनों को वास्तविकता में लाने की अनुमति देता है। संकाय और अनुभव की उच्च गुणवत्ता अद्वितीय है। युद्धग्रस्त भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी की स्थापना की गई थी। बाद के वर्षों में, उनकी संख्या के साथ-साथ छात्र क्षमता में भी वृद्धि हुई। उन्होंने दुनिया भर की कंपनियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। जाहिर है, युवाओं ने खुद को इन संस्थानों की ओर आकर्षित पाया। लेकिन ये भी एक दुखद हकीकत है कि आईआईटी में सीटें सीमित हैं. इसलिए, जब कम भाग्यशाली बच्चे जेईई पास करने में असफल हो जाते हैं, तो वे उम्मीद खोना शुरू कर देते हैं जैसे कि उनकी दुनिया खत्म हो गई हो। आओ बच्चों! दुनिया अवसरों से भरी है. क्या आपको लगता है कि फेसबुक बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग को टब्ळ से डिग्री की आवश्यकता थी? उनमें जुनून था और उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया। वह शैक्षणिक आवश्यकताओं से नहीं बंधे। और वह जीत गया! इसलिए, जब आपको एहसास हो कि आप आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं, तो कुछ पल निकालें और आत्मनिरीक्षण करें। अपनी वास्तविक कॉलिंग ढूंढने का प्रयास करें। और अगर आपको यह एहसास हो कि इंजीनियरिंग ही एकमात्र चीज नहीं है, तो अपनी वास्तविक कॉलिंग की दिशा में काम करें। आप निफ्ट, एनआईडी, लॉ कॉलेज, सीए, सीएस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लैब तकनीशियन आदि जैसे संबद्ध चिकित्सा क्षेत्रों के लिए प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। यदि आप वास्तव में कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, तो आप बीसीए और एमसीए करने पर विचार कर सकते हैं। वास्तव में, एमसीए वाले लोगों को इंजीनियरिंग स्नातकों के समान ही भुगतान किया जाता है। और अगर आपको इंजीनियर बनने का शौक है तो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों पर नजर डालें। हमारे पास कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो समान रूप से अच्छी शिक्षा और वातावरण प्रदान करते हैं। वहां आपको बराबर मौके मिलेंगे. और हमेशा याद रखें, प्रतिभा ही मायने रखती है। इन एनआईटी में आपको प्रदान किए गए सभी अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करें। जब आप वास्तव में कड़ी मेहनत और होशियारी से काम करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एनआईटी के साथ, हमें कई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बिट्स पिलानी, बीआईटी मेसरा, एसपीए और राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज मिले हैं। ऐसे कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं जो अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हैं और समृद्ध संकाय और पूर्व छात्रों का दावा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के सीईओ सत्या नडेला आईआईटियन नहीं बल्कि मणिपाल के पूर्व छात्र हैंप्रौद्योगिकी संस्थान। मैं यहां जो बताना चाहता हूं वह यह है कि जब सत्या आईआईटी प्रवेश परीक्षा में असफल हुआ होगा, तो वह भी दुखी हुआ होगा। लेकिन उन्होंने उस असफलता को अपने सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने कॉलेज में कड़ी मेहनत की और सफल होने की आग अपने अंदर हमेशा बरकरार रखी। आज भले ही वह सबसे बड़ी आईटी कंपनी के सीईओ हों, लेकिन उनकी शुरूआत मामूली रही। इसलिए, जब आप भी आईआईटी पास करने में असफल हो जाएं, तो इसे कड़ी मेहनत करने के अवसर के रूप में लें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी ताकतों को निखारें। अपनी सफलता की दिशा में ठोस रास्ता बनाने के लिए आपके पास 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है। अवसर का उपयोग करें. क्या सर जगदीश चंद्र बोस के पास आईआईटी की डिग्री थी? नहीं! उनके समय में आईआईटी की स्थापना भी नहीं हुई थी. उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लेकिन यह उनका प्रयास और प्रयास ही था जिसने उन्हें सर्वकालिक महान वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। आईआईटी बैज होना ही सब कुछ नहीं है। लेकिन उत्कृष्टता प्राप्त करने की दृढ़ता मायने रखती है। और हमारे अपने मिसाइल मैन ए.पी.जे. को कौन भूल सकता है? अब्दुल कलाम! यहां तक ??कि वह आईआईटियन भी नहीं थे. उन्होंने एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की और भारत के मिसाइल मिशन की आत्मा बन गए। लेकिन फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की. और अंत में केवल वही मायने रखता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आईआईटी खराब हैं बल्कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आईआईटी दुनिया का अंत नहीं है। यदि आप वास्तुकला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमेशा ठअळअ के लिए उपस्थित रहें। इससे आपको भारत के प्रमुख आर्किटेक्चर कॉलेजों में आवेदन करने का मौका मिलेगा। योजना एवं वास्तुकला विद्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। ये वे हैं जिनकी भविष्य के वास्तुकारों द्वारा सबसे अधिक मांग है। यदि आप स्वयं को सौंदर्य बोध के साथ संरचनाओं के निर्माण के प्रति अधिक इच्छुक पाते हैं, तो वास्तुकला का अध्ययन करना आपका निर्णय होना चाहिए। आप इंटीरियर डिजाइनिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। आजकल इनकी भारी मांग है. हमारे चारों ओर इमारतें हैं और साथ ही, हम जगह की कमी का भी सामना कर रहे हैं। एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर जानता है कि अधिकतम स्थान का उपयोग कैसे किया जाए। आपने जगह बचाने वाले फर्नीचर का क्रेज देखा होगा। इसलिए, जब लोगों या संगठनों को एक नई इमारत मिलती है, तो वे अपने घर/कार्यालय को प्रस्तुत करने योग्य और आरामदायक बनाने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर से सलाह लेते हैं। अधिकांश निर्माण और आर्किटेक्चर कंपनियां इंटीरियर डिजाइनरों को नियुक्त करती हैं जो आर्किटेक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। इन सभी विकल्पों के साथ, आपको वास्तव में इस पर एक अच्छा विचार करना चाहिए कि क्या आप वास्तव में एक इंजीनियर बनना चाहते हैं? अपने वरिष्ठों, शिक्षकों या दोस्तों से बात करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय माता-पिता मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आगे कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जबकि दुनिया अवसरों से भरी है। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो करियर संबंधी सलाह देती हैं। उनके साथ बातचीत करें. वे हर दिन सैकड़ों छात्रों से निपटते हैं और उनके पास अच्छा अनुभव है। वे आपको आपके व्यक्तित्व और जरूरतों के अनुरूप एक बेहतर करियर विकल्प सुझा सकते हैं।

घोटालों का बढ़ता जाल: छोटे से बड़े स्थानों तक और राष्ट्रीय स्तर पर समाधान की आवश्यकता

लेखक: अपर्णा शर्मा

भारत में घोटालों का इतिहास बहुत पुराना है, और ये घोटाले छोटे-छोटे गाँवों से लेकर बड़े-बड़े शहरों तक फैलते जा रहे हैं। छोटे स्थानों पर भूमि घोटाले, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और पंचायत स्तर पर धन की हेराफेरी आम बात हो गई है। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 2020 में मनरेगा योजना के तहत हुए एक बड़े घोटाले में 8.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी सामने आई थी। छोटे स्तर के ये घोटाले न केवल स्थानीय विकास को प्रभावित करते हैं बल्कि जनता के भरोसे को भी तोड़ते हैं। बड़े शहरों और राज्यों में, घोटालों का पैमाना और भी बड़ा होता है। नगरपालिकाओं में हुए घोटालों के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें ठेके देने में भ्रष्टाचार, सरकारी धन का दुरुपयोग और विकास परियोजनाओं में अनियमितताएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 2013 में मुंबई के आदर्श सोसाइटी घोटाले में पाया गया कि सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर अवैध रूप से अपार्टमेंट्स का आवंटन किया। शैक्षिक क्षेत्र में भी कई घोटाले हुए हैं, जैसे कि 2015 का व्यापम घोटाला जिसमें मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आज भी भारत में मेडिकल परीक्षाओं और चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अन्य मामलों में धांधली जारी है।बैंकिंग क्षेत्र में नीरव मोदी और विजय माल्या द्वारा किए गए वित्तीय घोटाले ने देश की आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाला। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। घोटालों से निपटने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें भ्रष्टाचार-निरोधक कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा और उन्हें समय-समय पर अद्यतन करना होगा ताकि वे वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके अलावा, घोटालों की जांच और दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। तकनीकी उपायों जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिए जो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। जनता का जागरूक होना और अपनी जिम्मेदारी समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है। जब तक लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक घोटालेबाजों को रोक पाना मुश्किल होगा। घोटालों को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। सभी वित्तीय लेनदेन और परियोजनाओं की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिटिंग संस्थानों को स्थापित किया जाना चाहिए जो नियमित रूप से सरकारी खातों की जांच करें।

डिजिटल और तकनीकी समाधान: डिजिटल ट्रांजैक्शन और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सभी वित्तीय लेनदेन और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आ सके। इससे भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे और जनता को सीधे लाभ मिलेगा।

सख्त कानून और त्वरित न्याय: भ्रष्टाचार-निरोधक कानूनों को सख्ती से लागू करना और दोषियों को त्वरित सजा देना आवश्यक है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए जो त्वरित और निष्पक्ष न्याय प्रदान करें। घूसखोरी की शुरूआत छोटे स्तर से होती है घूसखोरी की शुरूआत सबसे छोटे स्तर से होती है और यह बढ़ती लालच का कारण है, जो हर चीज को मुद्रीकृत करने से प्रेरित है। भोजन, आश्रय, शिक्षा झ्र हर जरूरत को पूरा करने के लिए रिश्वत की आवश्यकता होती है। लोग मजबूरी में रिश्वत देते हैं और लेते भी हैं। पूरे सिस्टम को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, नगरपालिकाओं के सफाईकर्मी से लेकर शीर्ष नौकरशाह तक। बदलाव हमारे हाथ में है।

जन जागरूकता और सहभागिता: जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। समाज में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। सामाजिक संगठनों और मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर सकते हैं और जनता को जागरूक कर सकते हैं। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर और सभी स्तरों पर सहयोग से ही हम इस घोटालों के जाल को काट सकते हैं और एक सशक्त, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए, आगामी पीढ़ियों के समाज को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ईमानदार निर्णय लें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सपर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र [9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

सुभाषित: *कष्ट और विपत्ति मनुष्यको शिक्षा देनेवाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहसके साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं।* ❑ *भर्तृहरि शतक*

मोदी मंत्रिमंडलको शपथ

राष्ट्रपति भवनमें रविवारको सायंकाल आयोजित समारोहमें नरेन्द्र मोदीने लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पदका शपथ ग्रहण कर लम्बे अन्तरालके बाद इतिहास रचा है। इसके पूर्व तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने तीन बार प्रधान मंत्री पदकी शपथ ली थी। विदेशी मेहमानों और अन्य अतिथियोंकी उपस्थितिमें नरेन्द्र मोदीका शपथ ग्रहण विशेष रूपसे महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयताकी शपथ दिलायी। इस अवसरपर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलोंके नेता भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (राजग) की मोदी सरकारका तीसरा कार्यकाल प्रारम्भ हो गया है, जो पिछले दो कार्यकालोंसे कुछ भिन्न है। इसबार लोकसभा चुनावमें भाजपाको कुल २४० सीटें मिली हैं, जो बहुमतके आकड़ेसे कम है। राजगका कुल आकड़ा बहुमतसे अधिक है। ऐसी स्थितिमें भाजपाकी अन्य दो प्रमुख सहयोगी दलों-तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और जदयू पर निर्भरता बढ़ गयी है। तीसरे कार्यकालमें सरकारके समक्ष चुनौतियां भी अलग होंगी। राजगके सभी दलोंके साथ समन्वय सबसे प्रमुख चुनौती है। नरेन्द्र मोदीके साथ ७२ अन्य मंत्रियोंने भी पद और गोपनीयताकी शपथ ली। इनमें कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल हैं। सरकारके गठनमें राजग के सभी घटक दलोंको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सभी क्षेत्रों और वर्गोंको समायोजित करनेका प्रयास भी उचित कदम है। पुराने और नये चेहरोंको सरकारमें स्थान दिया गया है। इसके बावजूद ऐसे अनेक लोग भी हैं, जो मंत्रिमण्डलमें स्थान पानेसे वंचित रह गये हैं। उनका असन्तुष्ट होना स्वाभाविक है। मंत्रियोंके चयनमें योग्यता, क्षमता और अनुभवको विशेष रूपसे महत्व दिया गया है, जो सराहनीय है। मंत्रिमण्डलमें महिलाओंके प्रतिनिधित्वपर भी ध्यान दिया गया है। नयी परिस्थितियोंको देखते हुए कुछ राज्योंसे मंत्रियोंकी संख्या कम हुई है। पूर्व मुख्य मंत्रियोंको भी मंत्रिमण्डलमें स्थान देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोहसे पूर्व नरेन्द्र मोदी ने अपने आवासपर सम्भावित मंत्रियोंसे वार्ताकर उन्हें पहले सौ दिनोंके कार्योंके बारेमें जानकारी दी, जो मोदीकी कार्यशैलीका हिस्सा है। गठबन्धनकी नयी सरकारके समक्ष चुनौतियां कम नहीं है। विशेष रूपसे भाजपाका जो एजेण्डा है उसे लागू करनेमें कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, जो स्वाभाविक है। भाजपा अपने महत्वपूर्ण मुद्देपर कैसे आगे बढ़ती है, यह भी देखना होगा। साथ ही जिन लोगोंको अभी मंत्रिमण्डलमें स्थान नहीं मिल पाया है, उन्हें अगले विस्तारतक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

मणिपुरमें हिंसा बेकाबू

पूर्वोत्तर भारतके प्रमुख राज्य मणिपुरमें लम्बे समयसे हिंसक घटनाओंका जारी रहना प्रशासनिक विफलता है। मणिपुरमें मैतेई और कुकी दो समूह हैं जिनके बीच हिंसाकी घटनाएं हो रही हैं। यह गम्भीर चिन्ताका विषय है कि केन्द्र और राज्य सरकार हिंसक घटनाओंको रोकनेका प्रयास तो कर रही है लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही है। हिंसाकी ताजा घटना शनिवारकी है जहां राज्यके जिरीबाम जिलेमें उग्रवादियोंने एक समुदायके ७० से अधिक घरोंको आगके हवाले कर दिया। इतना ही नहीं दो पुलिस चौकियों और वन विभागके कार्यालयको भी फूंक दिया जिससे उनके दुस्साहसको समझा जा सकता है। राजधानी इम्फालसे लगभग २२० किलोमीटर दूर स्थित जिलेके मोधुपुर क्षेत्रके लाभावाई खुनोमें पहाड़ी क्षेत्रके उग्रवादियोंने अंधेरेका लाभ उठाकर कई हमले किये। उग्रवादियोंके खिलाफ अभियानमें सुरक्षाकर्मियोंकी सहायताके लिए ७० से अधिक राज्य पुलिस कमाण्डोंकी टुकड़ीको जिरीबाम भेजा गया है। साथ ही मैतेई समुदायके दो सौ से अधिक लोगोंको खेल परिसरमें बनाये गये राहत शिविरमें ले जाया गया है। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे है। हिंसाके मूलमें उग्रवादियों द्वारा एक व्यक्तिकी हत्या बताया जा रहा है जिसका शव गुरुवार रात जिरीबाममें मिला था। शवपर जख्मके कई निशान थे। इसके बाद लोगोंने जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया और शुक्रवार रात हिंसा भड़क उठी। इस हिंसक वारदातमें किसीके हताहत होनेकी जानकारी नहीं मिली है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है और सुरक्षाके पुख्ता इन्तजाम किये गये हैं। क्षेत्रमें अतिरिक्त सुरक्षाबलोंको तैनात किया गया है, जो उचित है लेकिन मूल समस्या अभी भी वही है जो लम्बे समय से चली आ रही है जिसके समाधानमें शासन प्रशासन पूरी तरह विफल है। इस समस्याका स्थायी समाधान निकालनेकी जरूरत है। दोनों समुदायोंके कटुता और तनावको खत्म करना होगा। समस्याके मूल कारणोंपर नये सिरेसे विचार करनेकी आवश्यकता है। यह केन्द्र और राज्य सरकारकी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी ठोस पहल करे जो दोनों समुदायोंको मान्य हो तभी मणिपुरमें शांति सम्भव है।

लोक संवाद

तापमानसे मुश्किलमें जीवन

महोदय,-इस बार पर्यावरण हमारे नियंत्रणसे बाहर जा रहा है। इस बारके ग्रीष्म कालको ही देख लीजिए, जिसने फरवरीसे ही गर्मीका अहसास दिला दिया और जूनमें पहुंचते-पहुंचते इसने प्रचंड रूप दिखा दिया है। पूरी दुनियामें औसत तापक्रम बढ़ा है। दुनियामें अब प्रचंड गर्मीके दिन धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज दुनियामें ८० प्रतिशत लोग गर्मी झेल रहे हैं। पहले इस तरहके दिनोंकी संख्या २७ प्रतिवर्षके आसपास होती थी, आज वर्षमें ३२ दिन ऐसे हैं जो खतरेकी सीमातक गर्मीको पहुंचा देंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली समेत देशके तमाम कोनोंसे खबरें आ रही हैं कि हीटवेवने परिस्थितियां बदतर कर दी हैं। बढ़ती गर्मीका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमने पृथ्वी और प्रकृतिके बढ़ते असंतुलनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनियाभरमें एक-एक कर प्रकृतिके सभी संसाधन या तो बिखर गये या फिर घटते चले गये। हमने अपनी जीवनशैलीको कुछ इस तरह बना दिया है कि अब हम उन आवश्यकताओंसे बहुत ऊपर उठ गये हैं जो जीवनका आधार मात्र थीं। हमने विलासिताओंको भी आवश्यकताओंमें बदल दिया है, जिनके चलते पृथ्वीके हालात गम्भीर होते चले गये। हमारी जीवनशैलीमें आया बदलाव, बढ़ता शहरीकरण और ऊर्जाकी अत्यधिक खपतके कारण ग्लेशियर हो या नदियां, सूखनेकी कगारपर पहुंच चुकी हैं। दुनियामें करीब २४ प्रतिशत भूमि अब मरुस्थलीय लक्षण दिखा रही है और इसमें भी कुछ देश तो ऐसे हैं, जिनमें हालत ज्यादा गम्भीर हैं। इनमें बोलीविया, चिली, पेरूमें तो २७ से ४३ प्रतिशत भूमि मरुस्थलीय हो चुकी है। अर्जेंटीना, मेक्सिको, प्रागके भी ऐसे ही हालात हैं जहांकी ५० प्रतिशतसे अधिक भूमि बंजर हो चुकी है। आज दुनियाभरमें बढ़ते ग्रासलैंड एवं सवाना जैसे मरुस्थल इसी ओर संकेत करते हैं कि ये भूमि उपयोगी नहीं रही। मरुस्थलीय परिस्थितियां उसे कहते हैं जहां कुछ भी पैदा होना संभव नहीं होता। पूरी धरती लवणीय हो जाती है और पानीकी भारी कमी हो जाती है। अपने देशमें यह मानकर चला जा रहा है कि ३५ प्रतिशत भूमि पहले ही डिग्रेड हो चुकी है और इसमें भी २५ प्रतिशत मरुस्थलीय बननेकी राहपर है। ऐसी स्थिति अधिकतर उन राज्योंमें है जो संसाधनोंकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण थे। जैसे झारखंड, गुजरात, गोवा। इनमें दिल्ली और राजस्थान भी शामिल हैं। इन क्षेत्रोंमें ५० प्रतिशतसे अधिक भूमि बंजर पड़नेके लिए तैयार बैठी है। जरा-सी राहतकी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मिजोरममें अभी दस प्रतिशत ही बंजरपन दिखाई दे रहा है। यदि इनके कारणोंको तलाशनेकी कोशिश करें तो पता चलता है कि दुनियाभरकी ५० प्रतिशत भूमिको अन्य उपयोगमें डाल दिया गया है जहां पहले वन, तालाब या प्रकृतिके अन्य संसाधनोंके भंडार हुआ करते थे। इनमेंसे ३४ प्रतिशत देशोंमें ये अत्यधिक बदलावकी श्रेणीमें है, जबकि ४८ प्रतिशत देशोंमें मध्यम रूपसे बदलाव आया है। वहीं १८ प्रतिशत देशोंमें ज्यादा भूमि उपयोग नहीं बदला है। दक्षिण एशियामें तो ९४ प्रतिशत भूमि उपयोग बदल चुका है और यूरोपमें ९० प्रतिशत। अफ्रीकामें यह प्रतिशत ८९ है। भूमि उपयोगमें बदलावका ही प्रताप है कि आज प्रकृति हमारा साथ तेजीसे छोड़ रही है। जबसे उद्योग क्रांति आयी, तबसे हमने ६८ प्रतिशत वनोंको खो दिया। आज दुनियामें मात्र ३१ प्रतिशत वन बचे हैं। इस तरह एक व्यक्तिके हिस्सेमें करीब ०.६८ ही वृक्ष आयेंगे। अपने देशके हालात तो और भी गम्भीर हैं। दावा किया जाता है कि हमारे पास २३ प्रतिशत भूमि वनोंमें है। यदि इसे भी मान लें, तो भी देशके प्रति व्यक्तिके हिस्से ०.०८ भूमि है। चिन्ताकी बात है कि देशका ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां व्यवसायके रूपमें खननने अपना पैर नहीं फैलाया है। दुनियामें खेतीके पैटर्नमें भी बहुत अधिक बदलाव आया है। अब खेती व्यावसायिक हो चली है और इसमें रसायनोंका भी अधिकाधिक उपयोग होता है। -**अनिल प्रकाश, वाया ईमेल।**

चुनाव परिणामका गहन विश्लेषण

चुनाव परिणामपर बहस कुछ महीनोंतक चलती रहेगी। खबरें बनती रहेंगी। व्याख्या करनेकी दृष्टि हर वर्गकी अलग-अलग होती है। सामान्य व्यक्तिके लिए यही खबर पर्याप्त है कि मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गये हैं। पंडित नेहरूके बाद पहली बार हुआ है। लेकिन कुछ लोग अटके हैं कि तीन सौ भी पार नहीं कर सकी भाजपा।

❑ **कुलदीप चंद अग्निहोत्री**

राजनीतिसे जुड़े जागृत किस्मके लोगोंके लिए खबर है कि चार सौ पार करते-करते तीन सौ भी पार नहीं कर सकी भाजपा। लेकिन एक वर्गके लिए इस खबरकी भी अपनी सीमा है। वह वर्ग सत्तापक्षका विपक्ष होता है। उसके लिए मोटी खबर होगी कि जनताने सत्तापक्षको नकारा। लेकिन एक वर्ग पत्रकारोंका भी होता है। पत्रकारकी एक और समस्या है। कोई जीत जाय, उसकी व्याख्या भी पत्रकारके पास है और वही शख्स हार जाये तो उसकी व्याख्या भी पत्रकारके पास सुरक्षित है या यूं कहें कि उसको करनी ही है। अकादमिक जगतमें जिसे रिसर्च टूल्ज कहा जाता है, वे रिसर्च टूल्ज पत्रकारके पास भी होते हैं, जिनकी मददसे वह हर किस्मकी व्याख्या करता है। पत्रकारके पास हर मर्जकी एक ही दवाके अनुसार वह दवा या रिसर्च टूल आंकड़े हैं। वह आंकड़ोंकी सहायतासे हर संकटमयी हालतमें व्याख्या करता है। उदाहरणके लिए यदि उसे जीती हुई पार्टीको धकियाना ही है तो सीधे गणितके सूत्रोंकी सहायतासे व्याख्या करनी होती है। उदाहरणके लिए यदि जीतने वाली पार्टीने चालीस प्रतिशत मत प्राप्त किये हों और हारने वाली दस पार्टियोंने सब मिला कर साठ प्रतिशत प्राप्त किये हों तो व्याख्या सीधी सपाट होगी, देशकी साठ प्रतिशत जनताने नकारा। जैसे पंजाबमें अकाली दलने पहली बार अपने बलबूते चुनाव लड़ा। अकाली दलको एक सीटपर जीत मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी। अब खबर दो प्रकारसे हो सकती है। अकाली दलने तो फिर भी अपनी साख बचा ली लेकिन भाजपाका तो सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन यही व्याख्या दूसरे प्रकारसे भी हो सकती है। अकाली दलको सभी तेरह सीटोंपर कुल मिलाकर १३.४२ फीसदी वोट मिले जबकि भारतीय जनता पार्टीको १८.६२ प्रतिशत वोट मिले। इसको आधार बनाकर खबरका रंग ही बदल सकता है। अकाली दल तेरह प्रतिशतके आसपास सिमटा, जबकि भाजपा उन्नीस प्रतिशतका आंकड़ा छूनेके नजदीक पहुंच गयी। यदि हिमाचलके चुनाव परिणामकी व्याख्या करनी हो तो राज्यमें सरकारके बावजूद कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। चारों लोकसभा सीटें भाजपाने झटकीं। लेकिन व्याख्या दूसरी तरह भी हो सकती है। विधानसभाकी असल लड़ाईमें भाजपाको कांग्रेसने सिखाया सबक। विधानसभा चुनावमें होते हैं जनताके असल मुद्दे। यह तो रही शब्दोंकी जादूगरी, जिससे कुछ छिप जाता है और कुछ दिख जाता है। लेकिन असलमें क्या है, यह प्रश्न अपने आपमें सचमुच टेढ़ा है। यहां फिर एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि असल क्या है और भ्रम क्या है। असल तो यही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बन गये हैं। लेकिन फिर पूरे देशमेंसे केवल चार सीट जीतनेवाली लालू यादवकी पार्टी भी कह रही है कि भाजपाने जनादेश खो दिया है, उसका अर्थ क्या है। सारे देशमेंसे दो-तीन सीट जीत सकनेवाली सीपीएम भी कह रही है कि वही देशके लोगोंकी नब्जको ठीक तरहसे पढ़ना जानती है। दिल्लीमें सातों सीटोंपर हारनेवाली आम आदमी पार्टीके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी बार-बार कहते हैं कि वे देशके एक सौ चालीस करोड़ भारतीयोंके प्रतिनिधिके तौरपर मार्गदर्शन कर रहे हैं।

उनकी पार्टी उस प्रदेशमें हार गयी जहां उनकी सरकार है और ११७ मेंसे ९२ विधायक हैं। देशपर लम्बे अरसेतक राज करनेवाली पार्टी कांग्रेसको केवल ९९ सीटें मिलीं, फिर भी वह डंकेकी चोटपर कह रही है कि ३४२ सीटें जीतनेवाली भाजपाको देशके लोगोंने नकार दिया है। लेकिन मूल प्रश्न फिर वहींका वहीं खड़ा है। चुनाव परिणाम क्या हैं। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्या सचमुच कांग्रेस जीती है। भाजपा अपने बलबूते स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी, यह सत्य है। यहां अपने बलबूतेकी व्याख्या करना जरूरी है। भाजपाके जो सहयोगी दल हैं, यथा जेडीयू, टीडीपी और आरअलडीए इनके पास जो सीटें आयी हैं (१२, १६, २), उनमें टीडीपी को छोड़ दिया जाय तो बाकी दो दलों की सीटों को जिताने में नरेन्द्र मोदीकी भूमिका ही प्रमुख है। टीडीपीको भी भाजपाका साथ मिल जानेसे कुछ लाभ यकीनन हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाजपाकी अपनी २४० सीटें अपने बलबूते की ही हैं। लेकिन क्या कांग्रेसकी ९९ सीटें उसके अपने बलबूतेकी सीटें हैं। उत्तर प्रदेशसे जितनी सीटें उसे मिली हैं, उसमें अखिलेश यादवकी समाजवादी पार्टीकी बहुत बड़ी भूमिका है। तमिलनाडुमें उसे जो कुछ मिला है, वह डीएमकेके प्रभावके कारण सम्भव हो पाया है। यदि कांग्रेसकी शुद्ध अपने बलबूते प्राप्त की गयी सीटोंकी गिनती करें तो वह साठ-सत्तरके आसपास आकर टिकती है। भाजपाकी २४२ और कांग्रेसकी ७०-७० के बीच बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन भाजपाने अपने बलबूते ३७० पारका नारा दिया था और वह २४२ तक ही पहुंच पायी है, इसलिए ऊपरसे देखनेपर यह पराजय लगने लगती है। लेकिन एक बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि सामान्य भाषा और राजनीतिकी भाषामें बहुत अंतर होता है। कोई भी राजनीतिक दल जब चढ़ाई शुरू करता है तो वह लोगोंको यही बताता है कि वह चोटीपर चढ़नेकी यात्राके लिए निकला है। यदि वह ऐसा नहीं कहेगा तो वह आम जनतामें अपने लिए विश्वास जागृत नहीं कर सकता। उसे अपनी सही ताकतका स्वयं अंदाजा होता ही है। लेकिन उसे जनविश्वास जागृत करनेके लिए राजनीतिक भाषाका ही इस्तेमाल करना होता है। यही कारण है कि सारे देशमेंसे लगभग निष्कासित की जा चुकी कम्युनिस्ट पार्टी भी यह दावा करती है कि वह इस देशकी नब्जको पहचानती है। नब्ज पहचाननेका दावा वह करती है, लेकिन देशके लोग उसे अपनी नब्जपर हाथ नहीं रखने देते। कम्युनिस्ट पार्टीका देशभरमें दायरा पांच सीटोंके आसपास सिमट गया है, लेकिन वह फिर भी चिल्लाती है कि देशने नरेंद्र मोदीकी सरकारको नकार दिया है। अरविंद केजरीवालको जेलसे बाहर निकलनेके लिए, बार-बार आवेदन करनेके बावजूद जमानत न मिलनेके बाद भी पूरा विश्वास है कि सारे देशकी धड़कन उसीपर लगी हुई है। यही राजनीतिक विश्वास और राजनीतिक भाषाका हुनर है। लेकिन राजनीतिक विश्वास सचाईसे बहुत दूर नहीं निकल जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह मुंगेरी लालके हसीन सपने बन जाते हैं। भाजपाकी २४२ और कांग्रेसकी ९९ सीटोंमें यही अंतर है। जाहिर है कि भाजपाको तीसका महत्व समझ आ गया होगा, क्योंकि अपने बलबूते स्पष्ट बहुमतके लिए २७२ सीटोंकी जरूरत होती है और कांग्रेसको पता चल गया होगा कि उसके लिए यात्रा अभी लंबी है। इसी बीच यदि भाजपाने तीसके महत्वका सही विश्लेषण कर लिया तो सोनिया परिवारके लिए सत्ताप्राप्त करनेकी यात्रा और लंबी हो जायगी।

नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बन गये हैं। लेकिन पूरे देशमें सिर्फ चार सीट जीतनेवाली लालू यादवकी पार्टी भी कह रही है कि भाजपाने जनादेश खो दिया है। देशमें दो-तीन सीट जीतने वाली सीपीएम भी कह रही है कि वही देशके लोगोंकी नब्जको ठीक तरहसे पढ़ना जानती है। दिल्लीमें सातों सीटोंपर हारनेवाली आपके मुखिया केजरीवाल भी कहते हैं कि वे देशके एक सौ चालीस करोड़ भारतीयोंके प्रतिनिधिके तौरपर मार्गदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसको केवल ९९ सीटें मिलीं, फिर भी वह कह रही है कि ३४२ सीटें जीतनेवाली भाजपाको देशके लोगोंने नकार दिया है।

देशको मजबूत सरकारकी जरूरत

शीर्ष तीसरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बननेकी भारतकी राह अपनी युवा आबादीकी शक्तिका उपयोग करनेकी क्षमतापर निर्भर है। युवा नेतृत्वपर देशका जोर महज रणनीतिक नहीं, बल्कि देशके भविष्यके लिए रणनीतिक अनिवार्यता है।

❑ **हर्ष रंजन**

जापान, वर्ष २०१० तक करीब पांच दशकोंतक संयुक्त राज्य अमरीकाके बाद दुनियाकी दूसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बना रहा था। फिर वह तीसरे स्थानपर फिसल गया क्योंकि चीनने दूसरा स्थान हासिल कर लिया और फिर अगले १३ वर्षोंके अंतरालमें वर्ष २०२३ में जापान जीडीपीके मामलेमें चौथे स्थानपर आ गया, क्योंकि जर्मनीने उसे धकेल कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर भारतने निरन्तर विकासकी कहानी देखी और काफी नीचेसे ऊपर चलते हुए दुनियाकी पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और जल्दी ही जापानको पांचवें स्थानपर धकेलते हुए चौथे स्थानपर पहुंचनेके लिए भारत तैयार है। जापानके सबसे लम्बे समयतक प्रधान मंत्री रहे स्वर्गीय शिंजो आबे अपनी आक्रामक विदेश नीति और एक विशिष्ट आर्थिक रणनीतिके लिए जाने जाते थे, जिसे लोकप्रिय रूपसे एबेनॉमिक्सके नामसे जाना जाता है। बेहद लोकप्रिय और बेहद विवादास्पद राजनेता रहे आबेने लिबरल डैमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को दो बार जीत दिलायी। एबेनॉमिक्स थ्री ऐरोज यानी तीन तीरोंपर केन्द्रित था। पहला आक्रामक मौद्रिक नीति, दूसरा राजकोषीय समेकन और तीसरा विकास रणनीति। जबकि पहले दोसे बेहतर परिणाम मिले, लेकिन विकास और आधारभूत परिवर्तनोंके पैमाने विफल रहे, क्योंकि रणनीतिकारोंने इस तथ्यको नजरअंदाज कर दिया कि जापानी अर्थव्यवस्था बढ़ती आबादी और बढ़ते सामाजिक कल्याण खर्चोंका सामना कर रही है। यहीं भारतके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीकी सोच-सामने आती है। जब उन्होंने जन-धन खातोंके माध्यमसे वित्तीय समावेशन किया, महिलाओंको सशक्त बनानेके लिए दर्जनों योजनाएं लांच कीं, युवाओंमें सकारात्मक सोच विकसित करनेके लिए स्टार्टअप और कौशल विकासपर जोर दिया तो दरअसल वह लांग टर्मके विकासके लिए नहीं, उन पहलुओंको पहलेसे ही संबोधित करना चाह रहे थे जहां जापान उतना सफल नहीं हो पाया था। भारतकी आबादीकी औसत आयु ३० सालसे भी कम है, लगभग २९.५ वर्ष। लेकिन आनेवाले वर्षोंमें भारतकी आबादीकी आयु बढ़ेगी। उम्मीद है कि २०५० तक भारतीय जनसंख्याकी औसत आयु लगभग ३९ वर्ष होगी। वर्ष २००० में जापानी आबादीकी औसत आयु इतनी ही थी। यहींपर पिछले दस सालोंसे चल रहा देशका विजन सामने आता है। इन वर्षोंमें देशकी सोच और दृष्टि आम तौरपर लम्बी अवधिके लिए रही है। भारत २०४७ तक पूरी तरहसे विकसित राष्ट्र बननेकी योजना बना रहा है, जब हम आजादीके सौ साल मनायंगे तो योजना बनाना और ऐसे रुख अपनाना जरूरी है जो भले ही अजीब और अनूठे लग सकते हैं, लेकिन समय आनेपर इसके परिणाम मिलेंगे और जापानकी कहानी नहीं दोहरायी जायगी। इसके बिल्कुल विपरीत, जापानकी अर्थव्यवस्थाकी कहानी सतर्कताकी घंटी बजाती है। एक समय दुनियाकी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा जापान संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और जर्मनीके बाद चौथे स्थानपर खिसक गया है। पर्याप्त सरकारी प्रयासों और मौद्रिक प्रोत्साहनके बावजूद, जापानकी आबादीकी बढ़ती उम्रने इसकी आर्थिक गतिशीलताको बनाये रखनेके लिए आवश्यक संरचनात्मक और शासन सुधारोंमें बाधा उत्पन्न की है। यह जनसांख्यिकीय चुनौती आर्थिक नवाचार और विकासको आगे बढ़ानेमें युवा नेतृत्वके महत्वपूर्ण महत्वको बताती है।

युवा नेतृत्वपर देशका जोर महज एक राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि भारतके भविष्यके लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। युवा नेता नये दृष्टिकोण, नवीन समाधान और एक मजबूत ऊर्जा लाते हैं जो शासन और नीति-निर्माण प्रक्रियाओंको पुनर्जीवित कर सकते हैं। सम-सामयिक तकनीकी प्रगति और वैश्विक रुझानोंसे उनकी निकटता उन्हें तेजीसे विकसित हो रही दुनियाकी जटिलताओंसे निबटनेमें सक्षम बनाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्योंमें युवा नेताओंको शीर्षपर रखकर एक ऐसी शासन संस्कृति देशमें आ रही है जो चुस्त, उत्तरदायी और दूरदर्शी है। ऐसा नहीं है कि यह काम सत्तापक्षने ही किया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा, पुष्कर धामी और मोहन यादव आदि हैं तो दूसरी तरफ विपक्षकी ओरसे राहुल गांधी और अखिलेश यादवका उभरना पार्टी राजनीतिसे ऊपरकी बात है। भारत और जापानके बीच बहुत बड़ा अंतर है। वर्तमानमें जहां भारतकी औसत आयु २९.५ वर्ष है, वहीं जापानकी औसत आयु ४९.६ वर्ष है। यह जनसांख्यिकीय असमानता वैश्विक आर्थिक रुझानोंको अनुकूलित करने और आकार देनेके लिए देशोंकी संबंधित क्षमताओंको महत्वपूर्ण रूपसे प्रभावित करती है। संरचनात्मक सुधारोंको लागू करनेमें जापानकी चुनौतियां उसके अदूरगामी नेतृत्वका प्रत्यक्ष परिणाम हैं, जो जोखिम लेने और नवाचार करनेके लिए कम इच्छुक है। भारतके लिए इस खतरेसे बचना महत्वपूर्ण है और यहां मोदी इसीलिए जरूरी हैं। जापानके अनुभवसे सीखते हुए, यह स्पष्ट है कि हर स्तरपर उम्रदराज नेतृत्व, खासकर वह जो नयी तकनीक सीखने और युवाओंकी सोचसे अपनी सोचका तालमेल करानेमें अक्षम हो, आर्थिक प्रगतिमें बाधा बन सकता है। इसलिए शीर्ष तीसरी वैश्विक अर्थव्यवस्था बननेकी भारतकी राह अपनी युवा आबादीकी शक्तिका उपयोग करनेकी क्षमतापर निर्भर करती है।

परमात्माका विधान

❑ **श्रीराम शर्मा**

इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य स्वाधीन नहीं है, उसका जीवन परमात्माके विधानके अनुसार ही चलता है। न्यायकी दृष्टिसे उसका विधान भी स्वतंत्र होना चाहिए। ईश्वरने कर्म फलका एक सुदृढ़ नियम बना दिया है, इसीके अनुसार मनुष्यका भाग्य बनता बिगड़ता है। भ्रम इस बातसे पैदा हो जाता है कि कई बार प्रत्यक्ष रूपसे कर्म करनेपर भी विपरीत परिणाम प्राप्त हो जाते हैं तो लोग उसे भाग्यचक्र मानकर परमात्माको दोष देने लगते हैं। किन्तु यह भाग्य तो अपने पूर्व संचित कर्मोंका ही परिणाम है। यहां मनुष्य जीवनके विराट रूपकी कल्पना की गयी है और एक जीवनका दूसरे जीवनसे संस्कारजन्य संबंध माना गया है। इस दृष्टिसे भी जिसे आज भाग्य कहकर पुकारते हैं, यह भी कलके अपने ही कर्मका परिणाम है। सृष्टिके प्राणियोंमें चेष्टा न हो तो अबतक जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। भाग्यका रोना रोनेका अर्थ तो इतना ही समझमें आता है कि हम अपने कर्मके लिए सचेत नहीं हो पाये हैं। अपनी शक्तियोंका दुरुपयोग अब नहीं तो तब किया था, जिसका कट आघात भोगना पड़ रहा है, परन्तु प्राकृतिक विधानके अनुसार तो यह भाग्य अपनी ही रचना है। अपने ही किये हुएका प्रतिफल है। मनुष्य भाग्यके वशमें नहीं हो सकता क्योंकि उसका निर्माता मनुष्य स्वयं है। परमात्माके न्यायमें अभेद देखें तो यही बात पुष्ट होती है कि भाग्य स्वयं हमारे द्वारा अपनेको संपन्न करता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वास्तवमें हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कर्म फल किसी भी दशामें नष्ट नहीं होता। किसी न किसी समय वह अवश्य सामने आता है। विवशतावश उस समय उसे भले ही भाग्य कहकर टाल दिया जाय, परन्तु उससे कर्म फलका सिद्धांत तो नहीं मिट सकता। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। यदि स्वेच्छापूर्वक परमात्मा ही जिसे जो जी चाहे देने लगे तो इस सृष्टिकी सारी न्याय, व्यवस्था बिगड़ जायगी। हम उस स्वतंत्रताको किस तरह काममें लगायें, यह एक अलग बात है किन्तु अपना कल्याण करनेका अधिकार हमें ही है। न इसके लिए किसीको दोषी ठहराया जा सकता है और न किसीके भरोसे ही बैठा जा सकता है। अपने सुख-दु:ख, उन्नति-अवनति और स्वर्ग-नरकका कारण मनुष्य स्वयं है। फिर दु:ख या आपत्तिके समय भाग्यके नामपर संतोष कर लेना और भावी सुधारके प्रति अकर्मण्य बन जाना ठीक नहीं है।

स्वयंके बदलनेसे ही बदलेगा समाज

❑ **भारत डोगरा**

सब जानते हैं कि समाजको बदलनेकी शुरुआत निजी जीवनके बदलावोंसे होती है, लेकिन आम तौरपर इस जानी-पहचानी अवधारणाको हम अनदेखा करते रहते हैं। जाहिर है इसे बार-बार याद दिलाते रहनेकी जरूरत है। इस बार इस लेखमें इसी विषयको खंगालनेकी कोशिश करेंगे। समाज-सुधारकी चर्चा तो कई स्तरोंपर होती है, परन्तु व्यक्तिगत जीवनमें सुधारकी चर्चा कम हो गयी है। अब चर्चा व्यक्तिगत स्वतंत्रताओंकी अधिक है। व्यक्तिगत सुधार या व्यक्तिके आदर्शोंकी नहीं, परन्तु समाज तो बहुतसे व्यक्तियोंसे मिलकर ही बनता है और व्यक्तिगत जीवनमें सुधार एवं आदर्शके महत्वके बिना समाज सुधार भी आगे बढ़ सकेगा, इसकी संभावना कम है। सवाल यह है कि आदर्श समाजकी सोचके अनुरूप व्यक्तिगत जीवन जीना है तो उसकी अनिवार्य शर्तें क्या हैं। संभवत: सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारा जीवन सादगी और समतापर आधारित होना चाहिए। आधुनिक जीवनमें यह धारणा बहुत मान्यता प्राप्त कर चुकी है कि जितनी अधिक उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर सको, जीवन उतना ही बेहतर होगा, जितना वैभवकारी घर बना सको, उतना ही जीवन सार्थक होगा। दूसरी ओर सादगीकी अवधारणा बताती है कि हम अपने एवं अपने परिवारके सदस्योंको कोई शारीरिक कष्ट दिये बिना अपनी जरूरतोंको जितना कम रख सकें, जीवनकी सार्थकता उतनी ही बढ़ती है। चूंकि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, एक परिवार और दूसरे परिवारकी परिस्थितियोंमें बहुत अंतर हो सकता है, अत: सादगीका आदर्श सामने रखनेके लिए उपभोक्ता वस्तुओंकी कोई सूची नहीं बनायी जा सकती। बुनियादी बात हमारे सोचकी है, जीवन मूल्योंकी है। एक बार हमने इस सोचको ऐसा बना लिया कि सार्थकता उपभोक्ता वस्तुओंको बढ़ानेमें नहीं, यथासंभव कम करनेमें है तो हम सादगीके रास्तेपर आ चुके हैं। व्यक्तिगत जीवनमें समताका अर्थ यह है कि जितनी भी संपत्ति या आय हमारे पास हो, अपनी जरूरतों और जरूरी बचतको पूरा करनेके बाद वह गरीबी कम करनेके लिए या किसी इतने ही जरूरी सार्वजनिक हितके कार्यमें खर्च होनी चाहिए। समताका एक अर्थ यह भी है कि अपनेसे कमजोर आर्थिक हैसियतवाले जितने भी लोग हमारे दैनिक जीवनमें सम्पर्कमें आयें, उनसे हम न्यायसंगत व्यवहार करें। चाहे वे हमारे नियमित कर्मचारी हों या घरेलू कार्यमें सहयोग करनेवाले, रिक्शा चालक या कुली, उनके प्रति हमारा व्यवहार यही होना चाहिए कि उनसे जितना सहयोग हम अपनी सीमाओंके बीच कर सकते हैं, उतना अवश्य करें। ईमानदारी एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसकी चर्चा प्राय: होती है, परन्तु ईमानदारी अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। ईमानदारीके साथ समता और सादगीके आदर्शोंको भी जीवनमें अपनाना जरूरी है। समता और सादगीके आदर्श आपसमें बहुत नजदीकी तौरपर जुड़े हुए हैं। इन दोनों आदर्शोंको अपनानेसे जीवनमें बहुत-सी विकृतियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं, कई बेकारकी बातोंसे समय बच जाता है और तरह-तरहके रचनात्मक और सार्थक कार्योंके लिए समय उपलब्ध होने लगता है। जो उपभोक्ता वस्तुएं समाज और पर्यावरणके स्तरपर हानिकारक सिद्ध हो चुकी हैं, उनसे दूर रहना आवश्यक है। तंबाकू, शराब, अन्य तरहके नशीले पदार्थ, दुर्व्यसन एवं ऐय्याशीकी सामग्रीका किसी भी आदर्श जीवनमें स्थान नहीं होना चाहिए और कमसे कम अपनी कमजोरीको छोड़नेकी इच्छा जरूर होनी चाहिए। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि आदर्श व्यक्तिगत जीवनमें किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, लिंगके प्रति भेदभाव या नफरतकी जगह नहीं हो सकती। व्यक्तिगत जीवन इन सभी तरहके भेदभावों और उनसे उत्पन्न कुंठाओं और विकृतियोंसे मुक्त होना चाहिए। आदर्श जीवनके लिए किन गुणोंकी आवश्यकता है, इसकी तो बहुत लंबी सूची तैयार की जा सकती है, परन्तु यदि हम एक मूल बातको पकड़ना चाहते हैं तो वह यह है कि हम दूसरोंको दु:ख-दर्द न दें, अपितु जहांतक संभव हो, जितना अवसर हमें मिल सके, हम दूसरोंका द:ख-दर्द कम करनेका ही प्रयास करें। ईमानदारीसे अपनी आजीविका तो हमें कमानी ही है, अपनी एवं अपने परिवारकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करनी हैं, यह जिम्मेदारी निभाते हुए जितना हमसे बन सके, हम दूसरोंका द:ख-दर्द कम कर सकते हैं तो वह प्रयास हम जरूर करें, उससे पीछे न हटें। अपने नजदीकी संबंधोंमें प्रयास और सद्भावना होनेके बावजूद प्राय: हम रिश्तोंमें हावी होने, अपनी हस्ती स्थापित करनेका प्रयास करते हैं। इस कारण नाहक बहुत दु:ख-दर्द उत्पन्न होता है। नजदीकी मानवीय संबंधोंको एक-दूसरेपर हावी होनेके स्थानपर हमारी भी जय हो, तुम्हारी भी जय हो, के सिद्धांतपर जीना चाहिए। जो हमारी कुंठाएं हैं, दूसरोंके प्रति संकीर्ण सोच है, उससे मुक्त होनेका प्रयास कर, अपने आसपास एक खुला, मुक्त माहौल बनाना चाहिए। दूसरोंका दु:ख-दर्द कम करने, उनपर हावी न होने, सह अस्तित्व और सहयोगके सिद्धांत केवल नजदीकी लोगोंसे हमारे संबंधोंपर लागू नहीं होते, यह प्रकृतिसे, प्रकृतिके विभिन्न रूपोंसे, विभिन्न जीव-जन्तुओंसे भी हमारे संबंधोंपर लागू होते हैं। प्रकृतिकी हरियालीको बढ़ायें, मूक प्राणियोंके दु:ख-दर्द को कम करें, यह भी जीवनका एक बहुत सार्थक पक्ष है। आदर्श जीवन कुछ बहुत ख्यातिप्राप्त या ऊंचे पदोंपर पहुंचे लोगोंकी बपौती नहीं है। एक व्यक्ति, एक परिवारका सार्थक बदलाव भी दुनियाको बेहतर बनानेके प्रयासोंमें उसकी महत्वपूर्ण देन है। निराशाके कारण हैं तो आशाकी संभावनाएं भी हैं। निराशाके बादलोंसे निकलकर आशाके प्रकाशको फैलाना होगा और छोटेसे छोटे, कमजोरसे कमजोर व्यक्तिकी इस प्रयासमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाज सुधारका रास्ता सरल नहीं है और कह नहीं सकते कि विभिन्न समस्याओंके कारण किसी व्यक्ति या संघटनको इसमें कितनी सफलता मिलेगी। फिलहाल इतना हमारे नियंत्रणमें जरूर है कि बिना कोई देर किये हम अपने निजी जीवनको आदर्श जीवनके नजदीक ले आयें या इस दिशामें सतत प्रयास करते रहें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

अपने दमखम पर ही दुनिया में जीवन को सफल बनाना होता है

इस सांसारिक जीवन में हर किसी को संघर्षों के बल पर जीना होता है। वैसे लोग कहते हैं कि आम लोग इस दुनिया में बस जी रहे मर मर कर, जीवन के संघर्षों के बीच, बस जीने की जो मजबूरियां है, वहीं लोगों को भगवान भरोसे जिलाए जा रही है, जीना इसी का नाम है।यहां जीने बालो को अपने दम खम पर जीना पडता है, जीने की उलझन पग पग पर डेरा डेरा डाले हुए हैं, इसके बीच हर आदमी की बस यही चाहत बनती है, कि वह इस दुनिया में सुख से जीये, पर सवाल उठता है कि लोगों का यह कहना की दुनिया जीने लायक नहीं है, तो यह तो निराशा भरी बाते हैं, इस निराशा का कारण जो कुछ धरातल पर दिखता है, वह तो यही दिखता है कि आज समाज के लोग अपने स्वार्थ में ही जीना, सबसे माकूल समझते हैं, दूसरों के काम आने वाली बातें, अब रही नहीं, दुनिया के लोग अब अपने अपने काम से मतलब रखने में ही ज्यादा सुकून महसूस करने लगे हैं, समाजिक परिवेश आज आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ में ही निहित दिखता है। आदमी आदमी के काम आए ऐसा कुछ है नहीं, संस्कार तो विलुपति के कागार पर ही है, विलुपति चीज ही ऐसी कि जहां यह दिखता ही नहीं कि समाज के लोग एक दूसरे के लिए कहीं खड़े नजर आते हो, हर कोई को अपने से मतलब सा रह गया है। सामाजिक परिवेश इस कदर बदल गया है, कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं रह गया।हर किसी को बस अपने काम से काम का मतलब भर आ गया है, पहले की बातें कुछ और हुआ करती थी, पहले सामाजिक व्यवस्था में लोग जीने में सुकून महसूस करते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं दिखता बस दिखता है, तो लोगों को अपना स्वार्थ और स्वार्थ भी ऐसा की अपने से ही मतलब रह गया है। कोई किसी के दुख सुख का भागी भी बस अपने स्वार्थ और मतलब से ही रखना ज्यादा बेहतर समझते चल रहे हैं। व्यक्ति जी रहा है, यहां हर किसी के लिये जीने की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, इस महंगाई में खाने के लाले पड़े हो तो फिर जीना कैसा? आज हर तरफ हर चीज में प्रदूषण की जो पैठ कमाई के फेरे में सब में समाहित हो गई है, वह हर किसी को खराब बनाता चल रहा है, चाहे मनुष्य का जीवन हो या फिर पशुओं का? सामाजिक व्यवस्था की खामियाँ या आदमी के कार्यों की दक्षता व्यवस्था, सब कुछ प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है, लोगो की चाल से हवाएं दूषित हो गई है, लोगों का मन भी, हर तरफ से दूषित ही दिखता है। जहां तक बात की जाये राजनीतिक व्यवस्थाओं का तो, जिस पर देश में रहने वाले लोगों को जीने खाने और रहने की व्यवस्था का दायित्व डाला हुआ है, वह राजनीतिक व्यवस्था भी इस कदर स्वार्थ में डूब चुका है कि राजनीतिज्ञों को बस अपने से और अपने लोगों से ही मतलब दिखता है, दूसरे लोगों को वह देखना भी नहीं चाहता। राजनीतिक व्यवस्था स्वार्थ में तब्दील हो चुकी है, व्यवस्था ऐसी भी कि जीने खाने के लिये रोजगार नहीं, जीने वालों के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं और घर भी नहीं, यानी स्वार्थ कि जो धार मानव मन में पनपा हैं उससे आज हर कोई इस बात के लिए चिंतित है कि उसका स्वार्थ पुरा हो। इसमें दूसरो के लिए जगह हैं कहां? इस देश की अपनी व्यवस्था है, देश के लोग बस राजनीति को इस रूप में देखते हैं, कि देश चल रहा है, देश की व्यवस्थाएं जैसे भी हो, आदमी तो जी रहा है, आदमी के जीने की कोई सुकून भरी व्यवस्थाएं तो दिखते ही नहीं राजनीति में। आज लोगों की दिलचस्पी इस कदर बढी है कि हर कोई नेता बनकर ही इस दुनिया में जीना चाहता है। हर कोई बहस करता है, हर कोई चिंतन करता है और बस यही कहता है कि दुनिया जीने लायक नहीं रही दुनिया के लोग स्वार्थ से वशीभूत हैं और दुनिया के लोगों में राजनीति की जो चाहत बनी है वह सुख सुविधाओं से लैस दिखती है, राजनीतिज्ञो को सुविधाएं प्राप्त हो रही है, आम आदमी को नहीं मिलता। महंगाई बेरोजगारी समेत अनेक तरह की समस्याएं आम आदमी को घेरे हुए है, परिवार में भी परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, परिवार में आज कोई एक दूसरे भाई बंधु सगे संबंधियों को देखकर उनके दुखों को देखकर दुख नहीं होता, उनके सुखों को लेकर भले ही दुखित हो ले, सुख की चाहत दूसरे में देखना है नहीं, आज परिवार में बाप बेटी की जो स्थिति हो गई है, वह इस कदर संस्कार हीन दिखता है कि जिस बेटे को बाप ने इस धरा पर अवतरित किया, वह बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो समझने लगता है कि उसे भगवान ने इस दुनिया में लाया है और दुख सुख जो भी भगवान दे रहे हैं, मिल रहा है, वह तो बस उनकी ही देन, यानी भगवान की ही देन है, बाप लाख बेटे के दुख में दुखी हो, लेकिन बेटा आज बाप के दुख में शामिल होना नहीं चाहता, हर परिवार में हर किसी के साथ कमोवेस यही स्थिति दिखती है, पारिवारिक परिस्थितियां बद से बदतर हो चली है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी स्वार्थ के घेरे में इस तरह फलीभूत हो रहा है कि हर आदमी अपने आप में खो सा गया है। हर बाप अपने बेटे को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर तरह की कोशिशें मेहनत और दुआएं के लिए लगा रहता है, पर बेटा को इसकी कोई कदर नहीं होती बेटा तो बस कभी जब बाप बनेगा तभी उसके समझ में इन बातों की पैठ होगी, यह बातें उन्हें तभी समझ में आएगी, जब बेटा बाप बन जाएगा। आज की स्थिति में जीना मुहाल हो गया है, हर तरफ संघर्षों की एक लंबी फेहरिस्?त चलती चली जा रही है, हर कोई बस जीने की ललक में समाये मजबूरियों में ही, बस जिए जा रहा है।राजनीतिक सामाजिक और पारिवारिक यह तीनों व्यवस्थाएं आज धूल थुसरीत हो चुकी है। यह लोग कहते हैं और लोगों को कहना भी धरातल पर ही दिखता है।हर किसी को अपने से मतलब सा रह गया है और रहे भी क?यो नहीं, क?योकि जीना तो अपनो का ही हैं न? लेकिन समाज और परिवार के बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है।इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन अच्छे से गुजरता है, वरना जीवन तो कष्टकर होता ही है। आज जो चलन गया गया है, समाज में परिवार में, वह निश्चित रूप से संस्कार हीनता को दशार्ता है।आधुनिक युग में संस्कार को तिलांजलि दे दी गई है। हर कोई अपने आप में समाहित हो चुका है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। बस स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं और यह स्थिति बहुत ही दुखदाई कही जा सकती है, समाज के लिए परिवार के लिए व्यक्ति के लिए। इसलिए यह जरूरी है कि सहयोग बनकर एक दूसरे का सहयोग करें और जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें।

प्रभात वर्मा

सफरनामा सिक्किम की

''मन उमंगें साथ लेकर चल पड़ी यायावरी''

यात्राएँ समृद्ध करती हैं, अनजाने ही अपरिचित चेहरे जाने पहचाने से लगने लगते हैं। इस जन्म से उस जन्म तक यायावरी ही तो है। शायद कोई भी प्राणी इससे बच नहीं सका है।आइए चलिए हमारे साथ हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम।अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है।जहाँ तीस्ता और रंगीत की अविरल धारा सम्पूर्ण क्षेत्र को समृद्ध करती है। मानस यात्रा तो कार्यक्रम बनते ही आरम्भ हो गई थी।तन की यात्रा 27 से शुरू होनी थी। शाम चार बजे सभी लोगों को पिंकी दीदी के घर में एकत्रित होना था। मिनी दो दिन पहले ही मुम्बई से आ गईं थीं ।रश्मि दीदी, कम्बोज दीदी, लेट लतीफ रहने वाली विमल दीदी भी आज समय से आ गईं थीं, रेनू दीदी और हम भी वहीं पहुँच गए । रेनू दीदी से पहली बार मिले थे, बहुत प्यारा नेचर लगा । मिनी तो मिनी ही थीं प्यारी सी कैयरिंग नेचर की। सेवन सिस्टर्स का यह ग्रुप सिक्किम भ्रमण के लिए तैयार था।बहुत दिनों बाद चाची जी से मिले थे, गले लग मन भावुक हो उठा। बहुत सारी घटनाएँ चलचित्र की भाँति घूम गई नमी को समेटते अधरो पर मुस्कान सहेजी... टैक्सी चालक सामान कैरियर पर बाँध रहे थे, चाची जी, पीयूष भइया सहित सभी लोग बाहर आ गए । चाची जी के साथ सबने फोटो खिंचवाई, चिरहुला नाथ स्वामी की जयकार के साथ निकल पड़े । सभी ने अपने घरों में फोन कर के बताया। सुहागी घाटी आते ही रश्मि दीदी को एक किस्सा याद आ गया ''दद्दा जी न आयेंगेह्व बहुत मजेदार किस्सा था, सब हँसते-हँसते लोट-टोप हो गए। दीदी के पास मजेदार किस्सों का खजाना था, बातें करते उतरती धूप के साथ कब प्रयागराज आ गया पता ही नहीं चला। सामान ले कर वेटिंग रूम आ गए।ट्रेन आने में अभी काफी समय था, कहीं तिल भर की जगह नहीं थी, मिनी ने किसी तरह बैठने की जगह बनाई।ए सी चल तो रहे थे, लेकिन उनकी ठंडक गायब थी।सभी को पाथेय की आवश्यकता महसूस हो रही थी लेकिन ग्रहण कैसे किया जाए समस्या थी।मिनी और विमल दीदी कुली की तलाश में घूम रहीं थीं। किसी तरह छः सौ में तय किया और प्लेटफॉर्म नंबर चार की तरफ चल दिए गर्मी के मारे सब का हाल बेहाल हो रहा था । ट्रेन थोड़ा लेट थी, खड़े-खड़े थक गए तो सभी लोग वहीं जमीन पर बैठ गए पिंकी दीदी हँसने लगीं भई हम लोग डाउन टू अर्थ हैं । ग्यारह बजे ट्रेन आने की सूचना प्रसारित होने लगी...गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है...सबने एक साथ गुनगुनाया। राजधानी ट्रेन में बैठे तो लगा कि सचमुच में दृश्यमान यात्रा तो अब आरम्भ की है।सबने अपने घरों में फोन कर बताया और दाई बाई छः फुट की बर्थ पर पैर फैला कर चादर तान ली। कुछ ही देर में निद्रा रूपेण देवी हम सबमें संस्थिता हो गयीं, हम सभी माँ की गोद में आश्वस्त थे।पलकें झपकीं तो देखा मोहक सुबह प्रतीक्षा कर रही थी। सोते समय सोचा था खूब देर तक सोयेंगे लेकिन निद्रा देवी ने अपने समय पर चादर खींच ली। भोर के मंगलकारी देव को प्रणाम कर नव आशा से संचारित जन जीवन, भागते खेत वन उपवन, नग-सरिता, सड़के उन पर दौड़ते शोर मचाते वाहन, विविध कौतूहलों से भरी प्रकृति को निहारते समय के साथ तीव्र गति से भाग रहे थे। मखाने और केले के खेत, चाय के बागान दिखाती हमारी ट्रेन अपने निर्धारित स्थानों पर ठिठकती और भागती रही। हमारे गंतव्य की दूरी लगातार कम हो रही थी । दोपहर 12.30 बजे ट्रेन को न्यू जलपाइगुड़ी पहुँचना था वहाँ से आगे की यात्रा टैक्सी से करनी थी। राजधानी अपने निर्धारित समय पर न्यू जलपाइगुड़ी स्टेशन पर रुकी। पिंकी दीदी ने टैक्सी ड्राइवर को फोन किया वह स्टेशन के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे । सामान ले कर हम लोग बाहर निकले टैक्सी में सामान बाँध कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए । सिक्किम की सीमा के लगते ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगा । चारों ओर हरिताभ वादियाँ अपनी ओर आकर्षित करने लगीं ।जड़ो से जमीन छोड़ते आकाश छूते बाँस के पेड़ों के विशाल सघन वन अद्भुत लग रहे थे। साथ चलती तिस्ता की कल-कल बरबस अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही थी । लगातार चलते रहने के कारण थकान महसूस हो रही टैक्सी चालक से कहा ''भाई कहीं कुछ देर रुक कर चाय पीते हैं '' सावन बोले ''मैम रीवर राफि्टंग कर लीजिए सारी थकान दूर हो जायेगी एकदम तरोताजा हो जायेंगीं '' रश्मि दीदी बोलीं ''भाई तुम तो बस चाय पिला दो वही काफी होगा हमारे लिए '' '' जैसी आपकी मर्जी '' कह मुस्कुरा उठे। कुछ देर बाद आगे राफि्टंग करते लोग नजर आने लगे। तीस्ता के विशाल मनमोहक तट पर एक होटल के सामने हमारी टैक्सी रुकी।मन खुश हो गया हम लोग सीढ़ियों से थोड़ा नीचे गए पानी तक पहुँचना सम्भव नहीं था सो वहीं से वीडियो बनाया और फोटो खींच ऊपर आ गए । चाय बन चुकी थी चाय के साथ कुछ स्नैकस् ले हम लोग होटल की बालकनी से जीवन में स्वाद दे जाने वाले सुन्दर दृश्यों मन में बसाते हुए तिस्ता से विदा ले गंतव्य की ओर बढ़ चले।पाँच छः घंटे की रोमांचक यात्रा करके अपने गंतव्य गंगटोक पहुँच गए । यहाँ तापमान काफी कम था फ्रेश हो कर हमने गर्म कपड़े पहन लिए आज शाम हमें स्थानीय स्थलों का भ्रमण करना था। हनुमान टोंक के बाद हम मॉलरोड पर घूमने लगे। मालवी दीदी ने कुछ सामान खरीद लोगों के शापिंग.. जाग्रत कर दिया, सभी ने कुछ न कुछ खरीद ही लिया। यहाँ पर अजेलिया सहित न जाने कितनी तरह के फूल खिलखिलाते खड़े स्वागत कर रहे थे, इस अनजानी यात्रा पर। सुहानी पर्वतीय शाम और वादियों में गूँजती पंछियों की मोहक स्वरलहरी...और चाहिए भी क्या सुकून के लिए.

क्रमशः

दस्तक प्रभात/प्रीति शर्मा ''प्रीति''

मगही सनेस

पहुना अएलन जेठ में...

ए भाई! अप्पन मगध में एगो पुरान कहाउत हे- भादो के अंधेरिया, माघ के भिनसरिया आउ जेठ के दुपहरिया बड़ी कष्टकारक होवर हे। बकि करथ तर कार... बलेसर बाबू के बेटी के लगन पेहानी के डेट जेठे में मिलल।एक तो कड़कड़ दुपहरिया उ पर गरमी-लहर के चौतरफ मारर। तापमान के मिजाज रोज 40 से पार। बलेसर बाबू के दू बेटी में बड़की बेटी के शादी दू साल पहिले कोरोना काल में हो गेल हल। चट मंगनी पट बियाह। नर कोई आना, नर कोई जाना ।नर कोई हो-हल्ला, नर कोई लाग लफड़ा।बकि छोटकी बेटी के शादी में पूरा परिवार, कुटुम, टोला-महल्ला सब गाजे-बाजे आ गेलन। बड़की बेटी के ससुराल से पहुना के अगवानी में कुलम 10 गो जनानी मरदानी लोग आ गेलन।अब एने दमदगिरी होबे कि ओने गिरथामा के हाल आउ विआह के तइआरी के देखलर जाए। मेहमान के झाड़ संभाल के कोठा वाला एसी रूम देवल गेल। इ सड़ल गरमी में आएल गेल के खतिरदारी, ऊपर से घर पर समान के खरीदारी फिन बिआह के नाम सब विध-विधान। बलेसर बाबू के मिजाज आझ एकदम ठंडा?। उनका लगल कि मेहमान से कुछ मदद मिलत, बकि मेहमान एसी रूम में अइसन सटक गेलन जइसे चिल्लर देह में सटर जा हे।आउ तो आउ उनकर घर से आवल सबके एके हाल हल। देखते देखते बराती के दिन आ गेल। बराती भी तीन गाड़ी से ढोल, बाजा, नगाड़ा, डीजे के साथ नाचते गाते, झुमते- झुमाते सब आ गेलन ।एने मेहमान भी बंड़ी आउ सफारी पहिन के देवानंद नियन हो गेलन फिटफाट। हाथ में रुमाल, मुंह में पान आउ पाकिट के ऊपरे मोबाइल बड़ स्टाइल में... अइसन लग रहल हल जइसे उनकरे शादी हे। बड़ी देरी नाच गान के बाद बराती लगल।मेहमान जी भी खूब छूट के नाचलन?। फिन खाना पीना चलते चलते रात के 1:00 बज गेल। शादी विआह होते होते भिनसरवा होईए गेल। लड़का लड़की के कोहबर मिलल।वोही कोहवर में से सटलका छोटकी कोठारिया में दूनों साढू के भेंट मुलाकात होल, जइसे दूनों सहोदर भाई केतना दिन बाद राम-लक्ष्मण नियन मिल रहलन हे ।कहलो गेले हे-जग में नर मिलिहैं सहोदर भ्राता। खाना पीना के बाद नस्ता पैकिंग के साथ पूरनका मेहमान के सोहगर साली गुलाबी के नएका मेहमान सुमन जी अपना ही बिदाई के बाद लेके चल गेलन। बकि इ मेहमान के मेहमानगिरी बनल सजल रहल।आउ बिना चौठारी के उ कइसे फूर होतन। ओकर पहिले परसुनें गुलाबी साली के यहां के रिसेप्शन में भी जाहीं पड़त। बिआह के घर में अस बस हालत रहबे कर हे, आउ एने मेहमानगिरी से पूरा घर गड़बड़ा रहल हे। पुरनका मेहमान लगातार एसी आउ पंखा जे ऑन करलन, फिन बंदे नर करलन। एही कारन हे कि पंखा जर गेल तर एसी ठंडा होना बंद कर देलक। लकधक कपड़ा में मेहमान अप्पन पूरा जमात के साथ साली के ससुराल रिसेप्शन में अएलन। आते अइसन नाचे गावे लगलन कि सबके धेयान उनके पर। विदाई होल दोसर दिन। साढू-साढू गला मिललन।फिन दूनों अप्पन ससुराली में मिले के वादा करलन। बिआह के आठ दिन हो गेल लेकिन मेहमान के जाए के नाम पर नाकुर झुकुर हो रहल हल।अप्पन ससुराली के जगह से उ टस से मस होबे नर करथ।अब ससुराल में भी मेहमान के नाम हर लोग कुछ कुछ समझ रहलन हल कि पांचों अंगुली घींव में, तो मेहमान के आउ का चाहीं। पूरा माल चूस के फिन खातिरदारी के पूरा पूरा मजा लेके 16 दिन बाद मेहमान ससुराल से अप्पन घर चल गेलन। बकि इ का गंजी अंडरवियर साला के लेके चल गेलन तर ननद अप्पन भौजाई के टिकुली, पाउडर और चूड़ी तहाक लेके चल गेल। फोन आएल...का भाई तर गलती से रखा गेलो हल हम्मर समान में? ।एही से आ गेलो, बकि नियत में तो, कुछ आउ हल।कहलो जा हेर कि नियत पर बरकत होवर हे। मेहमान के रूम के साफ सफाई करल गेल तर चारों कोना तर खैनी-पान, तिरंगा के सीठी त पलंग के नीचे बीड़ी सिगरेट के टोटा।इ हाल पर सास कहलन- हाय रे मेहमान रूम के सफाई करें में आफत में होबइत हे परान।एने ससुर भी दूनों हाथ से माथा पकड़ते कहलन हां! जी ठीके कहित ह - नर होतो हल एतना बबार्दी तब, जेठ में नर करती हल शादी जब। एने छोटका साला भी हां में हां मिलाते कहलन- अइसन जीजा शादी में काहे ला आवे। जेठ नियन जे सब के मन के जरावे।। ओने नऽ होल 400 पार एने सब के मिआज गड़बड़ाएल।अब अषाढ़ के महीना में पूरा के पूरा ससुराल मेहमान जी के इयाद कर रहलक हे, जे सब के नीचे से ऊपरे तक आउ बाहर से भीतर तक जरा-जरा के अपने मोगेंबो नियन हंसी ले ले हरमेसा दांत निपोड़ रहलन हल।सबके एके राग हल- मत आवर मेहमान हम्मर दुआरी, न होतो हमनी से तोर खतिरदारी।

दस्तक प्रभात
डॉ.राकेश कुमार सिन्हा'रवि'

संस्मरण

जीवन साथी

संजीवनी के सरोवर के रूप में विख्यात प्रयागराज तीर्थ की शान चंद्रशेखर आजाद पार्क में सुबह-शाम चहलकदमी करना हर नागरिक की प्राथमिकता होती है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षालय बंद होने के कारण मेरा भी पतिदेव के साथ प्रतिदिन पदार्पण होता था।जैसा कि हम स्त्रियों का स्वभाव होता है कि हम अपने नयन चक्षुओं से प्रतिपल सजग होकर चलती हैं, क्या पता? किस पल कुछ अद्भुत घटित हो जाय। एक दिन प्रातः काल जब भगवान भास्कर अपनी तांब ई छटा बिखेरते हु? तीव्र आरोहण को प्राप्त हो रहे थे उसी समय टहलते हु? समीप से गुजरते एक जोड़े को देख मैं हतप्रभ हो गई। सज्जन सा दिखने वाला एक व्यक्ति स्त्री के हाथ में डोरी बांधकर और डोरी का एक सिरा अपने हाथ में मजबूती से पकड़ कर आगे- आगे चल रहा था। अस्फुट स्वरों में बोलती हुई विक्षिप्ता सी प्रतीत होने वाली वह दुनियां से बेखबर कभी उस व्यक्ति के सम चलती कभी विषम परंतु उस व्यक्ति की उसे पहचान थी शायद तभी वह उसकी दी हुई श्रृंखला में आबद्ध बिना प्रतिकार किए दिशाहीन सी चली जाती थी। शरीर पर मात्र एक गाउन था जिसे आम भाषा में मैक्सी कहा जाता है, सिर पर तेल लगाकर करीने से गुंथी हुई एक पतली सी चुटिया जिसमें नीचे काला फीता लटकता हुआ, पैरों में चप्पल, सामान्य कद, सांवला रंग, निश्छल चेहरा जिस पर अवसाद के जाने कितने परत साफ दृष्टिगोचर हो रहे थे, मैं आश्चर्यचकित सी उन दोनों को देर तक निर्निमेष दृष्टि से देखती रह गई। लगा कुछ तो बड़ा घटित है इनके जीवन में। ध्यान भंग होते ही अनुभव हुआ की पतिदेव तो आगे निकल गए, लगभग दौड़ती सी मैं उनके पास पहुंची और वह सब कुछ जो मैने देखा था उन्हें एक ही सांस में बता गई, परंतु पुरुष मन भावनाओं को कहाँ समझता है? सपाट स्वर में प्रत्युत्तर था अच्छा! चलो घर चलते हैं समय हो चला है। अब तो अक्सर मैं उन दोनों को देखती कभी-कभी वह नहीं दिखते तो अंतर में कुछ खटकने सा लगता, एक दिन अचानक वह स्त्री टहलते टहलते खड़ी होकर जोर-जोर से चीखने लगी मानों प्रलाप सी करती वह अजीब से डरावने स्वर में किसी को मारने काटने को उतावली हो रही थी, मैं तो उसकी प्रतिक्रिया देखकर सहम सी गई थी परंतु उसके साथ चलने वाला पुरुष शांत व निर्विकार भाव से उसे आगे लेकर चलता ही रहा । इसी मध्य छुट्टियां समाप्त हो गई थी वर्षा ऋतु के आगमन के साथ नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो गया था। प्रातः कार्यस्थल के लिए प्रस्थान करना होता था वहीं समयानुसार स्पोर्ट्स ट्रैक पर टहलना हो जाता था। वह जोड़ा अवचेतन मन में कहीं विश्राम करने लगा था। जीवन की आपाधापी में हम व्यस्त हो चले थे। एक दिन हम तीनों मित्रों मैं, सरोज एवं किरन ने प्रस्ताव रखा कि कॉलेज के बाद कंपनी बाग की एक परिक्रमा लगाते हु? घर को लौटेंगे तदनुसार हम तीनों सांध्य टहल के लिए जा पहुंचे, अर्ध परिक्रमा करते हु? जैसे ही गेट नंबर पांच पर पहुंचे वह पुरुष अकेला ही टहलते हु? मुझे दिख गया तो मुझसे रहा न गया मैं तनिक रूक कर उससे पूछी ही बैठी, भैया !आज आप अकेले हो? आपके साथ जो स्त्री थी, वह कहाँ है? वह कौन है? उसे क्या हुआ? पुरुष ने शांत भाव से उत्तर दिया मैडम जी! वह मेरी पत्नी है। मेरे कई बेटे हु? जो पैदा होकर मर गए, अपने सामने अपने दिल के टुकड़ों को जाते देख उसकी यह अवस्था हो गई है, उसे न मन की सुध रही न तन की, हम अभागों पर भगवान को भी दया नहीं आई, जब लेना ही था तो दिया क्यों? हम पति पत्नी जी लेते एक दूसरे के साथ अकेले ही। आप जैसे कई भले लोगों ने हमारी मदद की, बड़े डॉक्टर को दिखाने में । मैने कौतूहल बस पूछा तो डॉक्टर क्या कहते हैं वह ठीक हो जायेगी ना? उसने प्रति उत्तर दिया, डॉक्टर कहते हैं" उसे मानसिक आघात लगा है, सुबह शाम टहलाइये हो सकता है संजीवनी प्राप्ति से कुछ बेहतर होने की उम्मीद बंधे क्योंकि दवाइयां तो शरीर को खोखला कर देंगी । पुनः नम नेत्रों से उसने अपना भी अंतर्मन खोलते हु? कहा मैडम जी क्या मुझे अपने बेटों के जाने का दुख नहीं है? पर हम मर भी तो नहीं सकते ईश्वर की मर्जी के बिना, सो दुख भोग रहे हैं ।मेरा हृदय भर आया, क्योंकि मैं भी तो मां हूं अपने आंख के तारों की। काश मैं इनका बेटा इन्हें लौटा सकती, पर मृत्यु तो मृत्यु लोक का शास्वत सत्य है, मैने पूछा परंतु पत्नी कहाँ है? उसने दुख भरे स्वरों में बताया कि मैं एक दिन दरभंगा चौराहे पर उसे खड़ा करके गया था दवा लेने, तभी मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। किसी ने मुझे अस्पताल में भरती कर दिया, जब मुझे होश आया तो मैं वहां से भागा जहां पत्नी को दो दिन पहले छोड़ आया था, वह अभी भी भूखी प्यासी, बिना सोए वहीं खड़ी थी पुत्र विछोह से विकल, जब की उसे तनिक भी स्मरण नहीं था की वह जिसकी प्रतिक्षा कर रही है वह उसका कौन है? क्या लगता है? फिर भी वह उसका जीवन साथी था जिससे उसकी जीवन डोर बंधी थी, जो पुत्र वियोग से व्यथित होकर भी अपनी अर्धांगिनी को संजीवनी बूटी देने का भागीरथ प्रयास कर रहा था और अनजाने में ही सही हम सभी के समक्ष "जीवनसाथी" शब्द को परिभाषित कर रहा था।

दस्तक प्रभात
स्नेह सुधा, प्रयागराज (उ.प्र.)

कविता

कभी कभी मुकम्मल...

भोर के साथ आदमी
दौड़ना शुरू कर देता है
पूछा कहां जा रहे हो
मुझे नहीं मालूम,
कहां जा रहा हूं
बस जाना चाहता हूं,
हांकना शुरू कर देता है
हांफता है, कांपता है,
हार नहीं मानता है
जहां तक नजर जाती है
समझ लो, अपनी जहां है
इसी मझधार में,
बेवकते अकेले हो जाते हैं
कभी कभी मुकम्मल
होने की ख्वाहिश में
हम पहले से ज्यादा
अधूरे हो जाते हैं
कहता, मेरी स्लाहियत की
कदर नापी नहीं जा सकती है
उड़ते हुए पंक्षी के
पर गिन लेता हूं,
क्या समझे,
भापी नहीं जा सकती है
बड़ी तेज, रौशनी
से भी तेज चलता हूं
धन्यवाद तुम्हारी महारथी,
लेकिन लगाम प्रभु के हाथ,
बेकले हो जाते हैं
कभी कभी मुकम्मल...
क ख ग क्या सीख लिया,
भोर हमारी हो जाती है
मैं जीत गया, तू हार गया,
दहले की सवारी हो जाती है
अरमान अनंत,
बहुत प्यास लगी है
चतेरा तो हूं,
गाड़ी रुकवाई जाती है
धक धक,
चेहरे दे रंग फीके हो जाते हैं
कभी कभी मुकम्मल...

दस्तक प्रभात/दर्शन सिंह

कविता

इंसान बनना होगा

कांटे भरे पगडण्डी पर
नव फूल खिलाना होगा।
कंकड़ पत्थर चुन चुन
सुन्दर राह सजाना होगा।।
उदासीन नौजवानों के
चेहरे पर आस जगाना होगा।
कर्म हीन हाथों को
कौशल विकास कराना होगा।।
भटक रहे कुपथ राही को
सत पथ पर लाना होगा।
भारत माता के फटे वस्त्र
को चादर से ढकना होगा।।
जाति जाति में बटें जनों
की जमात बनाना होगा।
मानव मानव में बढ़ी दूरी
को निकट जुटाना होगा।।
लोकतंत्र के जर्जर रथ की
धूरी बदलना होगा ।
बंचित आवादी के टूटे घर
को महल बनाना होगा।।
हर हाथ को काम खेत
को पानी देना होगा।
कुशल कारीगर के हाथो
को औजार थमना होगा।।
बनेगा विकसित भारत
यह संकल्प कराना होगा।
नयीसरकार को विकास
की बैसाखी देना होगा।।
रावण को जालाने के
पहले अंदर झाकना होगा।
नीज स्वार्थ से ऊपर उठकर
पर हित पे आना होगा।।
तब बननेंगे विश्व शक्ति
सबको समझाना होगा।
भारत माता के परचम
को आकाश दिलाना होगा।।
जाति जाति से ऊपर
उठकर इन्सान बनाना होगा।
तब आयेगा राम राज्य
सबको राज बताना होगा।।

दस्तक प्रभात
राम शंकर शास्त्री

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अनमोल वचन

अंधेरे को कोसने से बेहतर है मोमबत्ती जलाओ। यानी कोसने से बेहतर करना है।
-चीनी कहावत

ब्याज दरें यथावत

भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार आठवीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है यानी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 6.5 फीसद पर बनाए रखा है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 4 फरवरी, 2023 को दर 0.25 फीसद बढ़ाकर 6.5 फीसद की थी। सात जून को आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिनी बैठक में लिए गए इस बाबत निर्णय की जानकारी देते हुए ब्याज दरों के यथावत रहने की घोषणा की यानी मकान, वाहन और अन्य कर्ज महंगे नहीं होंगे। समिति के छह में से चार सदस्यों ने ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने जबकि दो सदस्यों ने इससे अलग राय जताई थी। दरअसल, आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है

जबकि मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी से खुदरा महंगाई में लगातार कमी आ रही है। ईंधन की महंगाई दर में भी कमी जारी है। इसलिए केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने में आसानी रही। लेकिन महंगाई की दर के अपेक्षित से ज्यादा बने रहना सरकार के लिए चिंता का सबब अवश्य है और वह महंगाई चार फीसद के मानक स्तर पर लाने के लिए बराबर सतर्कता बरत रही है। उसकी चुनौती इस मोर्चे पर कड़ी है क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक 2023-24 में महंगाई 4.83 फीसद दर्ज की गई जो अपेक्षित स्तर से ऊंची है। इसके निकट भविष्य में नीचे आने की उम्मीद भी नहीं है। अलबत्ता, वर्ष के ज्यादातर समय इसके 4.5 फीसद के आसपास बने रहने का आकलन है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि की गति के मद्देनजर रिजर्व बैंक पहले ही पूर्वानुमान लगा चुका था कि मुद्रास्फीति 4.5 फीसद के आसपास रहेगी। बाजार का भी यही आकलन था। इस बीच, केंद्र में गठबंधन सरकार शपथ ले चुकी है। भले ही सरकार के रुख को लेकर अनिश्चितता है लेकिन इतना तय है कि सरकार का रुख लचीला रहेगा। वह कुछ डेफिसिट के साथ भी काम चलाना चाहेगी बशर्ते आम जन को सहूलियत मिले। मानसून निकट है, और अच्छा मानसून रहने के अनुमान से भी मौद्रिक मैकेनिज्म से दामों को काबू में रखने का उपाय कारगर माना जाएगा। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को यथावत रखने के साथ ही मुद्रास्फीति में कमी लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अलबत्ता, केंद्रीय बैंक निकट भविष्य में खाद्य मुद्रास्फीति में किसी भी बढ़ोतरी के जोखिम पर बराबर नजर रखेगा ताकि मुद्रास्फीति चार फीसद के स्तर पर लौटे।

जानलेवा होती गरमी

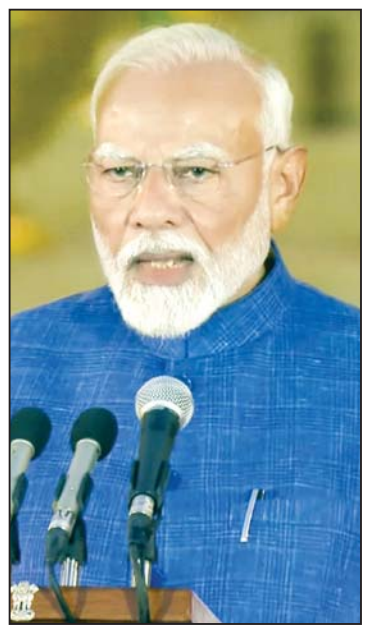

जलवायु वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार मई में महसूस की गई लू अब तक की सबसे अधिक रही। क्लाइमामीटर के शोधकर्ताओं ने मई में देश में प्रचंड व लंबे समय तक चलने वाली लू प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना अल-नीनो का परिणाम बताया। इस बदलाव से पता चलता है कि मौजूदा जलवायु में बीते सालों की तुलना में कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहा जबकि वर्षा परिवर्तन में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण

भारत में लू यानी ताप लहर तापमान की असहनीय सीमा तक पहुंच गई है। तापमान का 50 डिग्री के करीब पहुंचने का कोई तकनीकी समाधान नहीं है। अल-नीनो व मानवजनित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के तहत दुनिया इस तरह के गरम मौसम से जूझ रही है। गरमी और अधिक तेज होती जा रही है। मई में दिल्ली समेत उत्तर के कई इलाकों में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया। उप्र, मप्र, बिहार, झारखंड व ओडिशा में स्थिति काबू से बाहर हो गई। भीषण गरमी के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गईं और हजारों हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए। बिजली की खपत इतनी बढ़ गई कि आपूर्ति संभव नहीं रही। जल भंडारण तेजी से कम होता जा रहा है जिससे जल संकट बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा रहा। मौसम विज्ञानी इसे ला-नीनो इफेक्ट भी मान रहे हैं। उनका कहना है, जिस साल अल-नीनो खत्म होता है, उस साल तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के दरम्यान जटिल परस्पर क्रिया के चलते भविष्य में लू के बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा रहा। याद हो तो इसी अप्रैल में इतनी भीषण गरमी पड़ी कि कहा गया कि यह 120 साल बाद हुआ। भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस जानलेवा गरमी की मार पड़ रही है जिसका असर कृषि व खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा तो होगा ही। सेहत संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। भीषण गरमी को रोकने के लिए विभिन्न सुझाव दिए जाते हैं मगर प्रकृति के इस प्रकोप से बच पाना अब आसान नहीं रहा। वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग तथा कार्बन उत्सर्जन को थामने की बस बातें ही बनाई जा रही हैं। गरमी को रोकना अब आसान नहीं रहा।

परिधि/ सोनम लववंशी

असुरक्षा का दंश

वर्तमान दौर में भारतीय असुरक्षित जीवन जीने और हादसों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। तभी तो आए दिन देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन इन घटनाओं से न तो जनता जागरूक होते दिख रही है और न ही सरकार द्वारा सुरक्षित जीवन मुहैया कराने के लिए कोई ठोस क़दम उठाए जा रहे हैं। हालिया घटनाओं को देखकर लग रहा है जैसे मनुष्य के जीवन का कोई मोल ही नहीं है! इसलिए आम जन के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार को लेकर कोई गम्भीरता नहीं दिखाई जाती है। वैसे तो जीवन जीने की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान देता है और सुरक्षित जीवन जीने योग्य वातावरण निर्मित करना सरकार की जिम्मेदारी है। फिर चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की, लेकिन वास्तविकता इसके इतर है। लापरवाही की आग, लगातार लोगों को अपने आगोश में ले रही है और जो जिम्मेदार लोग हैं, वो तमाशबीन बने हुए हैं।

बीते दिनों गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में भीषण आग लगने से 12 बच्चों समेत 28 लोगों की जान चली गईं। बताया जा रहा है कि छुट्टी का दिन होने के कारण इस गेम जोन में भारी भीड़ मौजूद थी। वेल्डिंग की चिंगारी की वजह से यह हादसा हुआ। यहां मौजूद ज्यादातर सामग्रियां ज्वलनशील थीं। बावजूद इसके यहां आगजनी संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र तक नहीं लिया गया था। इस हादसे का दर्द अभी कम हुआ भी नहीं था कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी डे केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई जबकि 7 से ज्यादा मासूम बच्चे आग में बुरी तरह झुलस गए। विडंबना देखिए कि जिन अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करने और सेहतमंद होने के लिए के लिए आते हैं, वहां अगर इंसानों की मौत होने लगे, तो भला इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? दिल्ली में आग लगने की यह घटना कोई पहली नहीं है लेकिन हैरानी यह देख कर होती है कि इन हादसों से कोई सीख नहीं ले रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी की मानें तो साल 2020 में दिल्ली के 30 अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं हुईं जबकि साल 2023 में 36 अस्पतालों में आगजनी हुई। मौजूदा वर्ष 2024 की बात करें तो अब तक करीब 11 हॉस्पिटल्स में आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार आग की घटनाओं के बावजूद सरकार उदासीन नजर आ रही है।

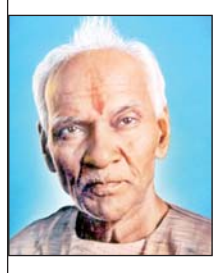

मोदी 3 .0 की ऐतिहासिक शुरुआत

सामयिक

आचार्य पवन त्रिपाठी

लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार की जीत का केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय महत्त्व भी है। अनेक कारणों से इस बात को कहा जा सकता है। सबसे पहले तो देखें कि कई दशकों की जोड़-तोड़ की राजनीति एवं राजनैतिक अस्थिरता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विराम लगा दिया है। आज पूरी दुनिया के शीर्ष नेता एवं नेतृत्व भारत को अत्यंत ही सकारात्मक एवं भरोसेमंद विदेश नीति वाले देश के रूप में देखते हैं। कहना न होगा कि पूरी दुनिया में नरेन्द्र मोदी ने भारत को एक नई पहचान दी है।

रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिला नया जनादेश भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका के लिए नई ऊर्जा देने वाला साबित होगा। ऐतिहासिक रूप से एनडीए की परंपरा अटलबिहारी वाजपेयी के समय से सहभागिता, सहयोग एवं सर्वसम्मति के साथ सबका साथ- सबका विकास की ही रही है। आने वाले पांच साल में भी भाजपा सहित राजग के सभी सहयोगी घटक राष्ट्र निर्माण में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक झलक बीते शुक्रवार को पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई राजग की बैठक में भी देखने को मिल चुकी है। वहां राजग के सभी प्रमुख सहयोगियों ने न सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल पर संतोष जताया, बल्कि अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

दरअसल, देश में गठबंधन सरकार चलाने के मामले में वाजपेयी सरकार को आदर्श उदाहरण के रूप में गिनाया जाता है। अपने घटक दलों और सहयोगी दलों के साथ सहज भाव से रहते हुए आम जनता के जीवन को सहज बनाने और सुविधापूर्ण बनाने में वाजपेयी सरकार के कामकाज को आज भी याद किया जाता है।

वास्तव में 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा गठबंधन 'राष्ट्र सर्वोपरि' के सिद्धांत पर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से इस दृष्टि से बड़े और कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि बिहार के नीतीश कुमार एवं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अपने-अपने राज्यों में अपने पिछले कार्यकालों में सुशासन के लिए ही जाने जाते रहे हैं। इसलिए उनके अनुभव का लाभ भी प्रधानमंत्री को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दोनों नेताओं को उनके अपने-अपने राज्यों में विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है।

चुनावी परिणाम और जनादेश ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत, निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी साबित कर दिया है। ईवीएम का राग अलापने वाले आधारविहीन विपक्ष के मुंह पर यह बड़ा तमाचा है। आज भी 'ब्रांड मोदी' का जलवा बरकरार है। देश के जनमानस में बीजेपी, नरेन्द्र मोदी और एनडीए के प्रति विश्वास को 2024 के जनादेश ने पुनः स्थापित किया है। यह जीत करोड़ों कार्यकर्ताओं, वोटरों एवं कुशल नेतृत्व की जीत है। यह भारतीय प्रजातंत्र की जीत है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः...का भारतीय दर्शन भी निहित है। हर एक प्रजातंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक पड़ाव आता है, जो राष्ट्र की नीति और नियति तय करता है। लोक सभा 2024 के चुनाव परिणाम में तीसरी बार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की विजय ऐसा ही ऐतिहासिक पल है। निश्चित रूप से इस चुनावी विजय ने अनेकानेक सकारात्मक संदेश दिए हैं।

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि 1962 के बाद पहली बार किसी नेता को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने का अवसर मिला है। इसके साथ-साथ यह तो और भी ऐतिहासिक है कि प्रधानमंत्री पद से पहले नरेन्द्र मोदी चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर गुजरात का शासन सफलतापूर्वक चला चुके हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के पुरुषार्थ, तप एवं विकासोन्मुखी राजनीति का परिणाम है कि अनेक झूठे प्रचारों के बावजूद पार्टी विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया आइएनडीआइए गठबंधन अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीटों से भी आगे नहीं जा सका। साठ वर्षों से अधिक समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस तो 100 सीटों के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। स्पष्ट है कि जनता ने विपक्षी गठबंधन को सिरे से नकार दिया है। इस चुनाव ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय विकास एवं कल्याण की राजनीति का है न कि धर्म, जाति, पंथ और सांप्रदायिकता का। एक और विशेष बात जो प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट बनाती है, वह है कि इनकी 'राष्ट्र प्रथम' की सोच और अंतिम छोर पर खड़े देश के हर नागरिक के प्रति संवदेनशीलता। एक ओर जहां विपक्ष ने धर्म और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास किया, वहीं इसके बिल्कुल विपरीत प्रधानमंत्री मोदी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े नागरिक तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत रहे। अब भाजपा एवं एनडीए देश के हर कोने में मजबूती के साथ विस्तार कर रहा है। ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं केरल में पार्टी का वोट प्रतिशत भी तेजी से बढ़ा है।

आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले दो कार्यकाल खासे उत्साहवर्धक रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक पटल पर ऊंची छलांग लगाते हुए अनेक विकसित देशों को चौंका दिया। पिछले 10 वर्षों में जिस संकल्प एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया की पहली पांच अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया है, वह अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे ले जाने की इसी इच्छाशक्ति के साथ शुक्रवार को केंद्रीय कक्ष की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को संदेश दे दिया है कि वे बड़े विदेशी निवेश के लिए अपने यहां सरल एवं सीधी नीतियां बनाएं ताकि विदेशी कंपनियां देश के हर राज्य में अपने लिए अनुकूल वातावरण महसूस करें, और हर राज्य में निवेश के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिला नया जनादेश भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका के लिए नई ऊर्जा देने वाला साबित होगा। एनडीए की परंपरा अटलबिहारी वाजपेयी के समय से सहभागिता, सहयोग एवं सर्वसम्मति के साथ सबका साथ-सबका विकास की रही है, और वह आने वाले समय में विकास को जन-जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है

केसीआर सरकार द्वारा फोन टेपिंग की तेलंगाना सरकार द्वारा जांच कराए जाने के बाद अब टीडीपी ने भी आरोप लगाया है कि जगन सरकार ने विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया था। जो अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कानून की अनदेखी करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हर किए-धरे का नतीजा मिलना तय है।

रोशनी सिंह, पत्रकार
@rohini-sgh

जनता में परिवर्तन की ललक

चुनाव परिणाम | राकेश श्रीवास्तव

वर्तमान चुनाव परिणामों से तथा मतदान में जनता की हिस्सेदारी के प्रतिशत से ऐसा संकेत मिलता है कि भारतीय राजनीति अस्थिरता के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है जिसका उदाहरण किसी एक दल को अपनी बदौलत बहुमत नहीं मिलना है। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा को भी अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसा दौर और कितना लंबा चलेगा, कोई भविष्यवाणी फिलहाल संभव नहीं। परंतु यह निश्चित है कि यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जनमानस इस अस्थिरता को समाप्त करने में किस हद तक सार्थक एवं कारगर भूमिका अदा करता है। वर्तमान चुनाव में मतदाताओं द्वारा ली गई हिस्सेदारी पूर्व में हुए अन्य चुनावों की अपेक्षा कम रही है, तथा चुनाव परिणामों से भी जनता ने अपने परिवर्तन के भूख को बनाए रखने का संकेत सा दिया है।

वैसे परिवर्तन की भूख भारतीय जनमानस में आजादी के बीस वर्ष बाद 1967 से ही प्रारंभ हो चुकी थी। गैर-कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ परंतु राजनीतिक दिशाविहीनता से परिवर्तन को सार्थक एवं गुणात्मक बदलाव में तब्दील नहीं जा सका। कारण था कि गैर-कांग्रेसी सरकारों का नेतृत्व निजी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने कांग्रेस छोड़ के आए लोगों के हाथ में होना। यहीं से प्रतिक्रियावादी ताकतों का उभार भारतीय राजनीति में हुआ जिसके चलते 1977 की लघु क्रांति छोड़ कर गैर-कांग्रेसवाद के पाये पर राजनीतिक दलों द्वारा अब तक अपने को टिकाए रखना है। गैर-कांग्रेसवाद वोटों का समीकरण बैठाने का एक नारा जैसा बन गया है, जिसके माध्यम से जल्दी से जल्दी ताकत बटोरने हेतु भारतीय राजनीति को जातीयता की संकीर्णता में लाकर खड़ा कर दिया गया है और जातीय समीकरण के चलते हिंसा राजनीति का हथियार बन गया। जैसे आज राजनीतिक दलों द्वारा भिन्न भिन्न नामों से हिंसक सेना (हिन्दू वाहिनी, आदम सेना, बजरंग दल तथा अन्य क्षेत्रीय सेनाएं) तैयार करना।

इस प्रवृत्ति को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सामाजिक न्याय का नारा देकर जाने-अनजाने और मजबूत किया। मंडल के मुद्दों को लेकर वीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चे के सबसे बड़े घटक के रूप में ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां

पिछड़ों, हरिजनों व मुसलमानों को न्याय दिलाने के नाम पर समाज को छोटे-छोटे दायरों में बांटने का प्रयास किया गया। ऊंची जातियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़े, हरिजन और मुसलमान समुदाय का चुनावी समीकरण बनाने की सामाजिक न्याय के नाम पर कोशिश की जाने लगी है। चुनावी समीकरणों को राजनीतिक दल विचारधारा के रूप में जनता के सामने पेश करते चले आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी में निजी महत्त्वाकांक्षाओं को संजोए लोगों द्वारा शुरू की गई थी। यही कांग्रेस संस्कृति है जो आजादी के बाद से भारतीय समाज को अस्थिर और हिंसक बनाए हुए है।

कांग्रेस पार्टी के पास एक ही नारा है कि स्थिर सरकार मात्र वह ही दे सकती है, जबकि जनता 1967 से ही लगातार इस नारे के विरोध में मत देती रही है। 1991 के चुनाव में किसी को सरकार बनाने योग्य बहुमत न देना।

1998 में भी जनता ने देश को स्थिर सरकार नहीं दी। और वह स्पष्ट जनादेश न मिलने के कारण वह सरकार केवल तेरह महीने की चल पाई। 1999 में भी जनादेश गठबंधन (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार का मिला। इसी प्रकार 2004 में भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन इस बार वामपंथी राजनीतिक दलों के समर्थन से यूपीए ने सरकार बनाई और इसने 2014 तक दो कार्यकालों के लिए भारत पर शासन किया।) 2014 के नतीजे जरूर अलग रहे। जनता ने स्थिर सरकार के लिए जनादेश दिया। जो भाजपा की अगुवाई में एनडीए के रूप में अगले दो कार्यकाल 2024 तक चली। 2024 में अचानक मोदी के इर्द-गिर्द बनी अजेय छवि खत्म हो गई। मतदाताओं ने यथास्थिति को लेकर असंतोष दिखाया। अब इस नई सरकार को सत्ता में आने के बाद पहली बार गठबंधन के पुराने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा।

दूसरी तरफ इस जनादेश से कांग्रेस नीत विपक्ष को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता का राजनीतिक दलों पर से विश्वास उठ गया है और उनके हर चुनावी नारे के विपरीत मतदान करती चली आ रही है। और अपनी परिवर्तन की भूख को बनाए हुए है। असल में आजादी के 77 साल बाद (इस अवस्था में आदमी पूर्ण वृद्धावस्था में हो जाता है) भी राजनीतिक प्रक्रिया का विकास नहीं हो पाया। किसी भी दल का अखिल भारतीय स्वरूप अब नहीं रहा। दल के स्थान पर नेताओं के गिरोह बन गए। जिसके कारण वैचारिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता समाप्त हो गई है और उसका स्थान निजी महत्वाकांक्षाओं ने ले लिया है। (अभी तक हमारी कोई सर्वमान्य शिक्षा नीति नहीं बन पाई, जो व्यक्ति के विकास का प्रथम चरण होता है।)

लक्ष्य | श्रीराम शर्मा आचार्य

मनुष्य बुराइयों से बचा रहे इसके लिए उसे हर घड़ी अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य सामने रखना चाहिए। यात्रा में गड़बड़ी तब फैलती है जब अपना मूल-लक्ष्य भुला दिया जाता है। मनुष्य जीवन में जो अधिकार एवं विशेषताएं प्राप्त हैं, वे किसी विशेष प्रयोजन के लिए हैं। इतनी सहूलियत अन्य प्राणियों को नहीं मिली। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको सुंदर शरीर, विचार, विवेक, भाषा आदि बहुमूल्य उपहार मिले हैं, इनकी सार्थकता तब है जब मनुष्य इनका सही उपयोग कर ले। मनुष्य देह जैसे अलभ्य अवसर प्राप्त करके भी यदि वह अपने पारमार्थिक लक्ष्य को पूरा नहीं करता तो उसे अन्य प्राणियों की ही कोटि का समझा जाना चाहिए। जन्म-जन्मांतरों की थकान मिटाने के लिए यह बहुमूल्य अवसर है जब मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान और साधनों का उपभोग कर ईश्वर-प्राप्ति की चरम शांति-दायिनी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जिन्हें साधन-निष्ठा की इतनी शक्ति नहीं मिली या जो कठिन तपश्चर्याओं के मार्ग पर नहीं जाना चाहते वे इस जीवन में उत्तम संस्कार, सद्भावनाएं और श्रद्धा भक्ति तो पैदा कर ही सकते हैं ताकि अगले जीवन में परिस्थितियों की अनुकूलता और भी बढ़ जाए और धीरे-धीरे अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने का कार्यक्रम चालू रख सके। पर इस अभागे इंसान को क्या कहें जो आत्म-स्वरूप को भूलकर उसे वासना 'शरीर' को ही सजाने में आनंद ले रहा है। मनुष्य यह देखते हुए भी कि शरीर नाशवान है और अन्य जीवधारियों के समान इसे भी किसी न किसी दिन धूल में मिल जाना है, फिर भी शारीरिक सुखों की मृगतृष्णा में इस तरह पागल हो रहा है कि उसको आप अपने सही स्वरूप तक का ज्ञान नहीं है। शारीरिक सुखों के संपादन में ही वह जीवन का अधिकांश भाग नष्ट कर देता है। जब तक शक्ति और यौवन रहता है तब तक उसकी यह समझदारी की आंख खुलती तक नहीं, बाद में जब संस्कार की जड़ें गहरी जम जाती हैं, और शरीर में शिथिलता आ जाती है, तब फिर समझ आने से भी क्या बनता है। चतुरता तो तब है जब अवसर रहते मनुष्य सुणों का संचय करके इस योग्य बन जाए कि यह यात्रा संतोषपूर्वक पूरी करके लौटने में कोई बाधा शेष न रहे। हमारा सहज धर्म यह है कि हम इस जीवन में प्रकाश की अर्चना करें और उसी की ओर अग्रसर हों।

रीडर्स मेल

हैरान करती चुप्पी

सीआईएसएफ की महिला सिपाही कुलविन्दर कौर द्वारा नवनिर्वाचित सांसद कंगना रानौत को चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर थप्पड़ मारा गया और गालियां दी गईं। इस घटना पर विपक्ष सहित अन्य संगठनों की चुप्पी हैरान करने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया तो और भी निराशाजनक है। उनका कहना है कि हम और पूरा पंजाब कुलविन्दर के साथ खड़ा है। उनका तो यह भी कहना है कि जांच होनी चाहिए कि कुलविन्दर को गुस्सा क्यों आया? कैसा हास्यास्पद बयान है कि उस अपराध की जांच नहीं होनी चाहिए जो हुआ, बल्कि वो अपराध क्यों हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि यदि गुस्से का कारण उचित है, तो किया गया अपराध भी न्यायोचित है। फिर तो सभी अपराधों का निर्णय सड़कों पर अपनी सुविधानुसार करने के लिए हर नागरिक स्वतंत्र है। कल को ऐसी ही घटना टिकैत के साथ भी हो सकती है क्योंकि टिकैत के भी अनेक बयान बहुतों को अच्छे नहीं लगते होंगे। मान भी लिया जाए कि कंगना का कोई बयान कुलविन्दर की माता अपमानित करने वाला था तो उसके विरुद्ध वह संवैधानिक तरीके से निपट सकती थीं।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर

भारत का ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) वित्त वर्ष 23 - 24 की अंतिम तिमाही में शानदार तेजी के साथ बढ़ा है। भारत की जीडीपी मार्च तिमाही में 7.8 फीसद की दर से बढ़ी। पिछले वर्ष समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.02 फीसद दर्ज की गई थी। इकोनॉमी के मोर्चे पर हमारे देश के लिए यह अच्छी खबर है। कोरोना काल के बाद इंडियन इकोनामी ने जोरदार वापसी करते हुए दुनिया को चौंकाया है। बढ़ती इकोनामी देश के लिए शुभ साबित होगी।

ललित महालकरी, इंदौर

पेपर लीक पर अविलंब कार्रवाई हो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक करवाने वाले लोगों के खिलाफ सीधे फांसी की सजा का कानून बनाते रहिए, आवश्यकता है जो पेपर लीक हुए हैं, उनकी परीक्षा अविलंब कराएं। वह भी उसी शुल्क में जो पहले जमा किया जा चुका है। परीक्षा केंद्र भी 100 किमी. के अंदर होना चाहिए। यदि उससे अधिक होता है तो मार्ग व्यय सरकार वहन करे अथवा मार्ग व्यय का पास जारी करे तभी आप की पारदर्शिता एवं कथनी-करनी प्रमाणित होगी।

राजेन्द्र, लखनऊ

बारिश की बूंद-बूंद सहेजनी होगी

समय के साथ देश में जल संकट की समस्या गहराती जा रही है। भूमिगत जल दोहन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक जल स्रोतों का अतिक्रमण हो चुका है। बारिश के पानी से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है लेकिन आज के विकसित दौर में भी बारिश का सिर्फ12 पानी धरती के गर्भ में जा रहा है। शेष बर्बाद हो रहा है। यदि हम बारिश की हर बूंद को धरती के गर्भ में भेजनें में सफल रहते हैं, तो हमें सालों भर पानी की किल्लत नहीं होगी। जल संकट की वजह से कृषि, पशुपालन, मत्स्य और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। बारिश की हर बूंद को धरती के गर्भ तक पहुंचाने के प्रयास हों।

हिमांशु शेखर, गया

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 297
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 10 जून 2024

विकास पर रहे फोकस

NDA सरकार के मुखिया के तौर पर रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। उनके इस तीसरे कार्यकाल पर देश-दुनिया की नजरें टिकी हैं। बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार 3.0 का अजेंडा पिछली सरकारों से किन रूपों में और कितना अलग होगा।

निर्भरता से उपजी मजबूरी | सवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इस बार सरकार सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर है। ऐसे में जिस तरह की स्वतंत्रता के साथ प्रधानमंत्री अपने और अपनी पार्टी के अजेंडे को लागू करते रहे हैं, वैसी आजादी शायद इस बार न मिले। वन नेशन, वन इलेक्शन और UCC जैसे मुद्दों पर इस राजनीतिक मजबूरी की विशेष छाप देखने को मिल सकती है।

मोदी तीसरी बार पीएम

विकास की रफ्तार | जहां तक रोजाना के कामकाज और आर्थिक विकास की रफ्तार की बात है तो उस मोर्चे पर सरकार के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजनीति की लंबी पारी ने पीएम मोदी को दृढ़ता के साथ ही लचीलेपन का भी पाठ पढ़ाया है। कोई कारण नहीं कि राजनीतिक विरोधियों को साथ लेने में दिखाया गया लचीलापन सहयोगियों को बनाए रखने में काम नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, दोनों विकास की राजनीति का चेहरा रहे हैं।

दस साल की यात्रा | दस साल पहले के मुकाबले आज देश विकास के कहीं ज्यादा ऊंचे मुकाम पर खड़ा है। 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। GDP के आकार के हिसाब से हमने पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और 2026 तक जापान तो 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इन लक्ष्यों की ओर तेजी से कदम बढ़ाना नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

दो बड़ी चुनौतियां | इस राह पर दो बड़ी चुनौतियां हैं - बेरोजगारी और असमानता। ILO की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश में 80% बेरोजगार युवा हैं। जहां तक असमानता की बात है तो उसे अक्सर तेज विकास के आगे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन याद रखने की बात है कि तेज विकास को अगर टिकाऊ बनाना हो तो असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

विकसित देश का संकल्प | बहरहाल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से बंधे हैं। ऐसे में मौजूदा जनादेश की सबसे उपयुक्त व्याख्या यही हो सकती है कि कथित तौर पर बांटने वाले राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाए रखते हुए सरकार विकास के अजेंडे पर पूरा ध्यान केंद्रित करे।

चक्र-व्यू

खजूर की गुठली

राहुल पाण्डेय

खत पहले भी देर से अपने पते पर पहुंचते थे, अब भी वही हाल है। हुआ यूं कि पिछले साल मैंने फैजाबाद के मशहूर और मरहूम शायर रफीक सादानी को ख्वाबों में एक खत लिखा। वही शायर, जिन्होंने लिखा था- 'तन के गोरा, मन के गंदा, मस्जिद मंदिर नाम पै चंदा/सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, न तौ नमाजी, न तौ पुजारी/जियो बहादुर खद्दर धारी।' रफीक चाचा का लिखा कुछेक को चिकोटी काटता है तो बहुतों को गुदगुदा भी जाता है। कल फैजाबाद पहुंचा तो उनका जवाब भी एक ख्वाब में मिला। कहते हैं, 'पांडे मियां, तुम्हारा खत मिला।

लिफाफे पर आधी मुहर दिल्ली की थी तो आधी फैजाबाद की। देखते ही समझ गया कि यह खत तुम्हारा है। एक तुम ही दिल्ली-फैजाबाद के बीच अटके हो, वरना फैजाबादियों का फैसला बिलकुल साफ होता है। मगर मैंने लिफाफा नहीं उठाया, क्योंकि मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा था। फैजाबाद में जुमे की नमाज पढ़ो, ना पढ़ो, खाने को मिल ही जाता है। यहां जन्नत में जुमे की नमाज ना पढ़ो तो खाने में सिर्फ खजूर की गुठलियां ही मिलती हैं। खैर, तुमने बताया था कि हिंदुस्तान में कुछ लोग मीर को पैदाइश का तीन सौवां साल मनाने जा रहे हैं। खत मैंने मीर को दिखाया। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि मीर ने यहां हिंदी सीख ली है। अवधी तो उन्होंने तभी सीख ली थी, जब वो दिल्ली से लखनऊ भाग दिए गए थे। फिर यहां पंत भी हैं और निराला भी। इन दिनों मीर भाई रोज पंत और निराला को छायावाद की कविताएं पढ़कर सुनाते हैं तो निराला और पंत उर्दू का मर्सिया पढ़ते रहते हैं। तुम्हारे लिखे के मुताबिक मैंने मीर को बताया कि ऑक्सफर्ड वाले इन दिनों तुम्हारी जीवनी आठ हजार रुपये में बेच रहे हैं। एकबारगी तो मीर खुश हुए, फिर नाराज हो गए। कहने लगे, इतने में तो हमारे वक्त में जमींदारी बिक जाती थी। आठ हजार की किताब कोई खरीदेगा तो पढ़ेगा या अपनी बैठक में सजाकर इतराएगा? इसके बाद तो मीर ऐसा बिदके हैं कि जुमे की नमाज तक पढ़नी छोड़ दी है। हर वक्त फैजाबादियों को अल्ल-बल्ल बोलते रहते हैं। बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे फैजाबाद को अल्ल-बल्ल बोले। पांडे मियां, तुमसे दिली दरख्वास्त है कि आइंदा मुझे मीर का हाल ना सुनाना। बल्कि आइंदा मुझे फैजाबाद का भी हाल मत सुनाना।'

रफीक चाचा का खत मेरे हाथ में फड़फड़ा रहा है। फैजाबाद के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 जून से फड़फड़ा ही जा रहे हैं। मुझे बाहर के लोगों के फड़फड़ाने से फर्क नहीं पड़ता। फैजाबाद को भी नहीं पड़ता। हमारे रफीक चाचा पहले ही लिख गए थे- 'बड़े बहादुर बनत हो बेटा, आए के देखो फैजाबाद।'

एकदा

रूजवेल्ट का संकल्प

फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट 1921 में न्यूजीलैंड के कैंपबेल द्वीप पर ग्रीष्मकालीन छुट्टियां मनाते समय अचानक गिर गए। अमेरिका में उस समय पोलियो बीमारी का खौफ था। गर्मी के हर सीजन में हजारों बच्चे इसके शिकार होते थे। पोलियो का वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और दूषित पानी, भोजन के जरिए इसका संक्रमण बढ़ता है। उस समय रूजवेल्ट ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया था। इस बीमारी ने 39 वर्षीय भावी राष्ट्रपति के पैरों को हमेशा के लिए लकवाग्रस्त कर दिया था। इसके बावजूद, वह अमेरिका के लोगों को पोलियो से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। वर्ष 1932 में वह राष्ट्रपति चुने गए। विश्व आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन समय में उन्होंने अमेरिका का कुशल नेतृत्व किया। रूजवेल्ट अपंग हैं, यह जानकर जॉर्जिया वार्म स्प्रिंग्स फाउंडेशन नामक NGO ने उनके जन्म दिवस पर विश्व पोलियो उन्मूलन के लिए अनुसंधान कार्य करने का निश्चय किया। खुद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पोलियोग्रस्त लोगों की सेवा और चिकित्सा में रुचि ली। उन्होंने जीवन भर की कमाई अपंगों के अनुसंधान कार्य के लिए समर्पित कर दी। सन 1938 में पोलियो के विषाणु का पता लगाया जा सका। वर्षों की खोज और अनुसंधान के बाद 1950 के दशक में Dr. Jonas Salk ने पोलियो का पहला सफल टीका विकसित किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उस समय कहा था, 'मुझे आज इस बात से अत्यधिक संतोष है कि इस सफल अनुसंधान के कारण हम भविष्य में एक दिन अपंगता की घातक आशंका से मुक्ति पा लेंगे।'

संकलन : दीनदयाल मुरारका

ब्रिटेन में चौतरफा चुनौतियों से घिरी कंजर्वेटिव पार्टी के लिए हालात बदतर होते जा रहे

जल्द चुनाव से सुनक को क्या फायदा

हर्ष वी. पंत

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय पूर्व चुनाव का जोखिम उठाने का फैसला किया है। यह घोषणा कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी चौंकाने वाली थी। लेकिन टोरीज के लिए हालात दिनो दिन बद से बदतर ही होते जा रहे थे। ऐसे में सुनक का यह फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को निराशा और आशंका के दौर से बचाने की कोशिश के रूप में सामने आया है।

आर्थिक सुधारों की थीम | सुनक के लिए सबसे अच्छा यही है कि चुनावी मुकाबले को आर्थिक सुधार की थीम पर केंद्रित रखा जाए। महंगाई दर में में आई गिरावट तो एक बड़ा फैक्टर है ही, जनवरी से मार्च के बीच इकॉनमी में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले दो वर्षों में सबसे तेज है। जाहिर है, वह ब्रिटिश मतदाताओं के सामने खुद को ऐसे विकल्प के तौर पर पेश करने वाले हैं जो देश की इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसे में इकॉनमिक रिकवरी की संभावना आगामी चुनावों का एक बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है।

बदलाव का वक्त | हालांकि इससे चुनाव प्रचार में सुनक को फायदा होगा या नुकसान, यह देखना अभी बाकी है। वजह यह है कि लेबर पार्टी भी रोजमर्रा के जीवन की कठिनाइयों को ही मुद्दा बनाने वाली है। और हकीकत यह है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं, जिन्हें लगता है कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई है। लेबर नेता कीर स्टार्मर जोर देते हुए कह रहे हैं कि यह 'बदलाव का वक्त' है। वह इकॉनमी की दुर्गति के लिए 'टोरी अराजकता' को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के लिए दिया गया वोट देश में राजनीतिक स्थिरता लाएगा।

लेबर पार्टी के लिए मौका | ओपिनियन पोल्स ने लगातार लेबर पार्टी को आगे रखा है और देखा जाए तो यह चुनाव विपक्षी दल के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, जो 2005 के बाद से कोई आम चुनाव नहीं जीत पाई है। लेबर पार्टी इस बार शासन संभालने के लिए तैयार दिख भी रही है। स्टार्मर इस बार पार्टी को लड़ाई के केंद्र में लाने में सफल रहे हैं। यह ऐसा ऐसा काम है जो 2007 में टोनी ब्लेयर के जाने के बाद से कोई भी लेबर नेता नहीं कर पाया था।

AFP

आपस में लड़ते कंजर्वेटिव | कंजर्वेटिव पार्टी हाल के वर्षों में अपने आप से ही लड़ती रही है। हालांकि 2019 में बोरिस जॉनसन ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में उनके विवादों से भरे प्रधानमंत्रित्व काल का अंत होने के बाद पार्टी ने कई नेतृत्व परिवर्तन देखे। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट का गवाह बनी है। खासकर ब्रेग्जिट को लेकर उसे आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी एकता भंग हुई। यही नहीं, COVID-19 महामारी से पैदा हुए हालात की बात हो या आर्थिक नीतियों और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों की, लोगों के असंतोष ने पार्टी के लिए जनसमर्थन को काफी कम कर दिया है।

आत्मविश्वास की कमी | सुनक ने डगमगाते टोरी जहाज को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद, उन्हें एक नेता के रूप में गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कंजर्वेटिव कार्यकर्ताओं में ऐसा विश्वास नहीं बन पा रहा कि सुनक उन्हें जीत दिला सकते हैं।

द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं होगा असर
- भारत-ब्रिटेन रिश्ते बेहतर हो रहे हैं
- कंजर्वेटिस की इंडिया पॉलिसी सही
- लेबर पार्टी भी अच्छे रिश्तों के पक्ष में

दिलचस्प है कि इसके बावजूद उन्हें हटाने की कोई कवायद नहीं शुरू हो रही क्योंकि पार्टी में कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा। चुनावी सफलता हासिल करने के लिए नेतृत्व बदलने की बात हो तो इस मामले में कंजर्वेटिव पार्टी खासी निर्दयी मानी जाती रही है। ऐसे में उसके लिए यह दुविधा काफी मारक है। सत्तारूढ़ पार्टी में झलकती आत्मविश्वास की कमी से यह स्पष्ट भी है।

हिंद प्रशांत की ओर झुकाव | पिछले कुछ वर्षों में ब्रेग्जिट से उपजी चुनौतियों में उलझे होने के बावजूद ब्रिटेन ने भारत के साथ रिश्तों की मजबूती को बनाए रखा है। वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देता है। यह बात 'हिंद प्रशांत की ओर झुकाव' की उसकी रणनीति में भी झलकती है जिसका उद्देश्य व्यापक क्षेत्रीय जुड़ाव के तहत भारत के साथ संबंधों को गहराई देना है।

मुक्त व्यापार समझौता | आतंकवाद विरोधी प्रयासों और उससे जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने पर दोनों देश मिलकर काम करते रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है। खास बात यह कि दोनों तरफ से निवेश का प्रवाह बना हुआ है। यूके भारत में सबसे बड़े निवेशकों में है, खासकर सर्विस, टेक्नॉलजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में। दूसरी ओर भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में आईटी, फार्मा और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया है। व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत दोनों देशों के आर्थिक जुड़ाव के लिहाज से खासी अहम मानी जा रही है।

रिश्तों की जीत | दोनों देशों के जुड़ाव के लिहाज से कंजर्वेटिव पार्टी को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उसने डेविड कैमरन के प्रधानमंत्रित्व काल से ही भारत को लेकर सही नीति बनाए रखी है। उधर, स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी भी भारत के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता को न सिर्फ स्वीकार करती है, बल्कि उस पर खासा जोर देती है। ऐसे में साफ है कि ब्रिटिश मतदाता चाहे जो भी फैसला करें, जीत भारत-ब्रिटेन संबंधों की ही होगी।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

1st का चक्कर छोड़ एंजॉय कीजिए 2nd पोजिशन

चांद पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने और उनके बाद Apollo Lunar Module से नीचे उतरे थे बज एल्ड्रिन। आर्मस्ट्रांग किताबों में शामिल हो गए, जनरल नॉलेज का हिस्सा बन गए, जबकि एल्ड्रिन का नाम अब भी तमाम लोग अपोलो मिशन के बजाय जानते हैं उन कार्टून फिल्मों के कारण जिनमें वह केंद्रीय किरदार रहे। बल्कि उनसे ज्यादा तो उनके नाम पर चुटकुले सुनाए गए कि पहला कदम आर्मस्ट्रांग ने रखा था तो दूसरा भी उन्हीं का होगा। वह खड़े होकर एक पैर पर लंगड़ी खेलते हुए तो चांद पर चले नहीं होंगे!

यही विडंबना है दूसरी पोजिशन पर रहने वालों के साथ। उनकी उपलब्धि को हमेशा पहली पोजिशन के साथ बांधकर देखा जाता है। उनका अस्तित्व तब तक याद नहीं आता, जब तक पहले का जिक्र न हो। एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग में अंतर लैंडर से पहले नीचे उतरने भर का है, लेकिन उसी ने एक को दूसरे से बड़ा हीरो बना दिया।

1990 के दशक में ओलिंपिक्स में मेडल जीते एथलीट्स पर एक स्टडी हुई थी। इसमें पाया गया कि सिल्वर के बजाय ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अधिक खुश रहते हैं। सिल्वर यानी दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को यह बात बहुत खलती है कि, काश! थोड़ा और दम लगा देते। काश... दरअसल यही चीज हर उस शख्स के साथ जुड़ जाती है, जो दूसरे स्थान पर आता है। काश, टीम इंडिया ने विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया होता। काश, मैंने वह चैप्टर पढ़ लिया होता, तो टॉप पर होता। इस तरह के काश ने दूसरे स्थान को दुख, निराशा और पश्चाताप का घर बना दिया है। लेकिन, क्या दूसरे स्थान को देखने का यह नजरिया सही है?

किसी ने कहा है कि 'दूसरा स्थान हासिल करना हार नहीं है। यह रिमाइंडर है कि पहला स्थान हासिल करने के लिए और मेहनत करनी है।' दूसरी पोजिशन प्रेरित करती है सुधार के लिए, उकसाती है मेहनत करने को। एक लंबे सफर में यह केवल एक स्टॉप है, डेड एंड नहीं। दूसरा स्थान पहले वाले से हारने से नहीं बना, तीसरे, चौथे, पांचवें और ऐसे ही तमाम दूसरों को हराने से बना है। इस पोजिशन का मतलब है कि सफलता अब बस एक कदम दूर है। जब बाकी का रास्ता तय हो गया, तो वह आखिरी कदम भी पूरा हो ही जाएगा। बस एक लास्ट पुश चाहिए, पिछली बार जितना पसीना बहाया था उसमें थोड़ा ज्यादा बहाना है, थोड़ा अधिक डेडिकेशन।

यह पोजिशन प्रेरणा है और उपलब्धि भी। पहले स्थान पर काबिज हर शख्स को दूसरे स्थान से गुजरकर ही जाना पड़ता है। पहली पोजिशन का महत्व ही इस बात में है कि दूसरी पोजिशन भी है। कहा जाता है कि जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। इस लिहाज से फर्स्ट पोजिशन शिखर जैसी है एवरेस्ट के। वहां पहुंचने के बाद उतरना ही होता है कि किसी तरह डटे रहना है। उसके पास राहत और खुद के लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं। और उसे यह खतरा किससे है? जाहिर तौर पर सेकंड पोजिशन वाले से।

दूसरा स्थान विनम्र बनाता है। अहंकार से दूर रखता है। याद दिलाता है कि कोई भी बेहतर कोई है, लेकिन हम उसकी जगह हो सकते हैं क्योंकि हमारा बेस्ट आना अभी बाकी है। यह सीख हमारे पांवों को जमीन पर टिकाए रखती है वरना सफलता का नशा चढ़ते देर कहां लगती है। तो, दूसरी पोजिशन को कोसिए मत, एंजॉय कीजिए। कई ऐसे लोग हैं जो दूसरा नंबर तो छोड़िए, टॉप 10 में भी नहीं। सेकंड पोजिशन अगर उन्हें ऑफर की जाए, तो वे खुशी-खुशी ले लेंगे। अगर आपके पास पहले से यह पोजिशन है, तो फिर खुश होने की कोई और वजह क्यों चाहिए।

जीवन आनंद

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'जीवन आनंद'

क्यों याद आई वह पुरानी तकनीक

मृत्युंजय राय

शहरी जिंदगी की भागदौड़ ने उन्हें भी बेहाल कर दिया था। जीवन में तनाव घर कर गया था। बेचैनी होती थी। उन्हें लगा कि इन सब की वजह से वह बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अपनी परेशानियां लेकर एक दिन वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें एक ऐसी जगह भेजा, जहां सही तरीके से सांस लेना सिखाया जाता था। उन्हें लगा कि सांस लेना भी कोई सिखाने की चीज है! यह तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है। खैर, डॉक्टर के कहने पर वह सुदर्शन क्रिया का कोर्स करने तो जा पहुंचे, लेकिन बेमन से।

AI Image

एक पल में बदलाव | कोर्स के पहले सेशन में बताया गया कि धीमे-धीमे नाक से सांस लो और उस पर फोकस करो। 'फिर कुछ हुआ...लगा, जैसे किसी एक जगह से उठाकर बड़ी सुखी जगह मुझे रख दिया गया है। यह सब एक पल में हुआ।' इसी दौरान जब उन्होंने अपने ललाट पर हाथ रखा तो वह पसीने से भीगा था। अगले दिन उनका मन शांत बना रहा। पिछली रात को नींद भी बहुत अच्छी आई। उन्हें याद भी नहीं था कि ऐसी नींद इससे पहले कब आई थी। इसके अगले दिन भी वह सुदर्शन क्रिया की क्लास में पहुंचे और दूसरे दिन का भी एक्सपीरियंस यादगार रहा।

फिर मन में आया सवाल | आखिर एक साधारण से कमरे में पालथी मारकर घंटे भर सांसों पर ध्यान लगाने से ऐसा बदलाव कैसे आ सकता है? इसी सवाल ने जर्नलिस्ट जेम्स नेस्टर (James Nestor) को एक ऐसे रास्ते पर चलने को मजबूर किया, जिससे 'Breath : The New Science of a Lost Art' नाम की किताब वजूद में आई। कोई दस बरस तक रिसर्च करने के बाद जेम्स ने यह किताब लिखी है। इसके लिए उन्हें दुनिया में कई जगहों की यात्रा करनी पड़ी। नेस्टर ग्रीस जाकर फ्री डाइवर्स से मिलते हैं, जो गहरे पानी के अंदर कई मिनट तक सांसें रोक सकते हैं। उन्होंने यह हुनर अभ्यास से हासिल किया है। वह ब्रीदिंग के साइंस को समझने के लिए ब्राजील से लेकर लातविया तक की यात्रा करते हैं और कई लोगों से मिलते हैं। वह एक ऐसी जर्मन महिला से मिलते हैं, जिन्होंने सही ब्रीदिंग तकनीक से अपनी रीढ़ की हड्डी की बीमारी को ठीक कर लिया। सांसों की अहमियत को समझने के लिए न सिर्फ उन्होंने साइंटिस्टों से बात की बल्कि बुद्ध धर्म के दस्तावेजों को भी खंगाला। और इतने से भी जब बात बनती हुई नहीं लगी तो उन्होंने खुद पर कई प्रयोग किए।

मुंह से सांस की बुराई | किताब में जेम्स इस विषय को यूं समझाते हैं, 'हम रोज 25 हजार सांसें लेते हैं। इनमें से बहुत सारी सांसें हम मुंह से लेते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। इंसान के पास सांस लेने के लिए नाक है और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन करीब 90 प्रतिशत लोग मुंह से सांस ले रहे हैं और यह उनके बीमार होने का बड़ा कारण है।'

विडियो में सही तरीका | सही ब्रीदिंग तकनीक के बारे में नेस्टर ने जो भी सीखा, उसका ब्योरा उन्होंने किताब के आखिर में दिया है। लोग सही तरीके से सांस लेना सीखें, इसके लिए उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की है। उन्होंने किताब में कई ऐप्स और Youtube tutorials का भी जिक्र किया है, जिनकी मदद ली जा सकती है। Youtube पर ऐसे विडियोज भी मिल जाएंगे, जिनमें जेम्स नेस्टर सांस लेने का सही तरीका सिखाते हैं। अगर आपकी इस विषय में दिलचस्पी है तो एक बार ये विडियो जरूर देखें। अमेरिका के लोगों को तो यह विषय इतना पसंद आया कि जेम्स नेस्टर की इस किताब ने वहां के बेस्टसेलर्स में जगह बनाई।

विचार विंडो

बिन मांगी सलाह क्यों

प्रणव प्रियदर्शी

अपने देश में महिलाओं को यह बिन मांगी सलाह मिलती रहती है कि उन्हें कब और कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। दिलचस्प है कि आम तौर पर पारिवारिक दायरे के अंदर से मिलने वाली ये सलाहें इन दिनों राजनीति में सक्रिय हस्तियों की ओर से भी मिलने लगी हैं। इसकी वजहें हालांकि अलग हैं, लेकिन यह जानना रोचक है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा। दूसरे देशों में भी महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर आने वाली ऐसी सलाहों की संख्या बढ़ गई है। उदाहरण के लिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पूतिन अपने देश की महिलाओं को याद दिलाते हैं कि वहां दादियां और परदादियां सात-सात आठ-आठ बच्चे पैदा करती थीं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तो बच्चे पैदा करना राष्ट्रीय दायित्व बताते हैं। वैसे, इन देशों में जन्म दर में गिरावट एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसा किसी एकाध देश में नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से में हो रहा है। कारण राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक और तरीका उपदेश देने का हो या कानून का डंडा दिखाने का- बेअसर साबित हो रहा है। असल में परिवार के अंदर का इक्वेशन बदल चुका है। पुरुष नहीं, अब महिलाएं तय कर रही हैं कि उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने। अपने पैरों पर खड़ी होती महिलाएं महसूस कर रही हैं कि बच्चे पैदा करना उनके जीवन और करियर से जुड़ी आकांक्षाओं का एक छोटा सा हिस्सा ही है, मगर यह उन आकांक्षाओं के भारी हिस्से को कवर कर लेता है। इसलिए, महिलाएं इस पर्सनल चॉइस पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहीं। निश्चित रूप से घटती जन्म दर किसी भी देश के लिए एक गंभीर समस्या है और कोई भी सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती। लेकिन आज की महिलाएं इसके लिए अपनी आकांक्षाओं की बलि देने को तैयार नहीं। दे भी क्यों, जब खासतौर पर अमीर देशों के पास इमिग्रेशन पॉलिसी को उदार बनाकर इस समस्या को हल करने का आसान विकल्प उपलब्ध है।

AI Image

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

'मैं-मैं' की आदत कर देगी सभी से अलग-थलग

डॉ. संजय तेवतिया

दया और करुणा मनुष्य को संवेदनशील बनाती हैं। दयालु व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। वह सबके हित में कार्य करता है। वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसकी बातें किसी के हृदय को चोट न पहुंचाएं। करुणा सबसे महान धर्म है और क्षमा सबसे बड़ा बल। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में सुख न खोजकर परमात्मा को ही सुख का आधार मान सत्कर्म और भक्ति में लगा रहता है, वह स्वयं संवेदनशील बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो दुखी रहता है और न ही निराश होता है। ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में करुणा और रहमत की भावना पलती है। ऐसे ही व्यक्ति धार्मिक होते हैं। ऐसा कहा जाता है।

धर्मग्रंथ और धर्मगुरु भी कहते हैं कि सभी प्राणियों में भगवान का वास है। तो क्यों न भगवान का स्वरूप मानकर सभी प्राणियों से प्रेम किया जाए। यही सीख हमारे अंदर संवेदनशीलता भरती है। संवेदनशीलता का लक्षण यही है कि अहंकारवश कभी किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो जाए तो उसे अपने विनम्र व्यवहार से संतुष्ट करने का प्रयास करें। इससे आत्मिक संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब कहा जाता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं या सबके लिए कर रहा हूं, तो वहां अहंकार का भाव आता है। ऐसा कहने वाला इंसान अलग-थलग पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है, अहंकार पतन का कारण है। धर्म और अध्यात्म इस पर अंकुश लगाते हैं। ये हृदय में दया और करुणा का संचार करते हैं।

धार्मिक संदेशों में दया को अक्सर एक प्रखर की ऊर्जा या आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में देखा गया है। लेकिन दया हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बनती है। दया मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिसके सहारे वह स्वयं और दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध स्थापित कर सकता है। दया मनुष्य में दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित करती है। इसके माध्यम से हम सहयोग और समरसता को बढ़ावा देकर समाज में समृद्धि और शांति ला सकते हैं। इससे हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह हमें मानवता की सेवा करने और ईश्वर के निकट रहने का मार्ग दिखाता है।

अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति के भाव को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है, इसके लिए दया के दूसरे पहलू अभिमान को कम करना होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि अभिमान की जड़ में पाप का भाव पलता है। इसलिए हमें अपने शरीर में प्राण रहने तक दया भाव का पोषण करते रहना चाहिए। सहानुभूति एक मानवीय गुण है, दूसरों के प्रति इस भाव को रखने से हमारा मन निर्मल हो जाता है, दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि मन में संतोष का भाव पैदा हो तो यह अपना लाभ है। ईश्वर से यही कामना होनी चाहिए कि प्रभु हम पर तुम्हारी दया दृष्टि बनी रहे। और हमारी प्रार्थना पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हो। यही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है।

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

आईना सच बोलता है

हर हफ्ते 'जीवन आनंद' कॉलम में नए-नए लेख पढ़ने को मिलते हैं। असल में सामान्य अखबारी मुद्दों से अलग दैनिक जीवन के अनछुए पहलुओं से जुड़े ये लेख बहुत अच्छे लगते हैं। मन को छू लेने वाली बातें इन लेखों में मिलती हैं। इस बार 3 जून को 'सच दिखाने वाला आपका पक्का दोस्त है आईना' भी शानदार था। सच पूछा जाए तो आईना हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब ही होता है। यही कारण है कि जब हम कहीं बाहर निकलने लगते हैं तो एक बार आईना जरूर देख लेना चाहते हैं। एक शेर याद आ रहा है- कोई भूला हुआ चेहरा नजर आए शायद, आईना गौर से तूने कभी देखा ही नहीं।

रोहन सिन्हा, ईमेल से

हकीकत से याराना

3 जून को 'जीवन आनंद' कॉलम में प्रकाशित लेख 'सच दिखाने वाला आपका पक्का दोस्त है आईना' पढ़ा। आईना ही ऐसा सच्चा साथी होता है जो हमसे कुछ नहीं छिपाता। उसके सामने हम जस का तस दिखते हैं। लेकिन आईने में झांकने का आशय सिर्फ अपना चेहरा देखने तक सीमित नहीं है। कई बार आईना हमें हमारा चरित्र भी दिखाता है। यह दिखाता है कि हम कितना ऊपर उठ चुके हैं या फिर कितना नीचे गिर चुके हैं। यह हमारी कमियों को भी उजागर करता है।

पैंथर तोमर, किशन गंज

खुशियों का खजाना

संगीत सुनना खुशी और सुकून देता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और जीवन में संतुलित दृष्टि हासिल करने में मदद करता है। संगीत कई मूड के होते हैं। जब आप उदास या चिंतित होते हैं, तो पसंदीदा संगीत सुनना आपके मूड को बदल देता है। संगीत हमारे भीतर विभिन्न भावनाओं को जागृत करता है। इससे हम अपने भावनात्मक जीवन को बेहतर समझ पाते हैं। यह बतौर इंसान हमें समृद्ध करता है।

विवेक सिंह, नोएडा

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

जीवन आनंद

अंतिम पत्र

पटनायक के उत्तराधिकारी माने जा रहे पांडियन ने सियासत छोड़ी - खबर - जब सत्ता ही छूट गई तो सियासत में बचा ही क्या!

कविता रावत

कल्पमेधा

उस साहस को जानने का अभ्यास करो, जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है। समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता।

– विवेकानंद

उम्मीदें एवं चुनौतियां

नई सरकार ने शपथ ले ली है। नई उम्मीदें हैं और चुनौतियां भी बेशुमार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली दो सरकारों में भाजपा अकेले बहुमत के पार थी। इस बार जबकि राजग लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, भाजपा की घटक दलों पर निर्भरता है, उनके साथ तालमेल बनाकर चलने की चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल समझौतावादी जनादेश के साथ शुरू किया है। नतीजतन, मोदी के 72 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगियों के 11 मंत्री हैं। साथ ही, देश को मजबूत विपक्ष मिला है। नीतियों को लागू कराने के दौरान सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा। मजबूत विपक्ष सामने है। इससे विपक्ष और असहमति जताने वाली आवाजों को कुछ राहत मिलेगी। सत्ता और विपक्ष – दोनों के लिए आगे का रास्ता अवसरवादी जोड़-तोड़ की राजनीति नहीं, बल्कि आम लोगों की उम्मीदों और संघर्षों में निहित राजनीति होनी चाहिए। इस स्थिति ने संयमित प्रशासन की उम्मीद जगाई है।

राज्यों में प्रभावी दलों के साथ सत्ता साझा करने से मोल-भाव की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन देश के सामने मोदी की सत्ता की मूल प्रकृति सामने है, जो फैसलों में दृढ़ संकल्प वाली है। गठबंधन धर्म इस प्रकृति को लेकर एक गहन विश्लेषण की मांग करेगा। गठबंधन सहयोगियों की राज्य स्तरीय राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो कम से कम अगले चरण के विधानसभा चुनावों तक तस्वीर मोदी के पक्ष में है। तेलगुदेसम पार्टी अपने राज्य में आराम से बैठी है। जद (एकी) को अगले साल विधानसभा चुनावों तक सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा की जरूरत है। लोजपा के चिराग पासवान और फिर से उभर रहे राजद की चुनौती सामने है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भाजपा के दम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जद (सेकु), रालोद और राकांपा जैसे अन्य गठबंधन सहयोगी अपने फायदे के लिए सौदेबाजी से परे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते।

देश में बीते तीन दशकों के आर्थिक उदारीकरण के दौर में लोगों की आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यक्रमों ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया है। विकसित भारत का नारा लोगों के सामने है। लेकिन यह हकीकत भी है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए रोजगार पैदा करने, कौशल विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने जैसे काम अभी शुरू ही हुए हैं। कई मोर्चों पर नीतियां अभी तय हुई हैं। जाहिर है, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बड़ी हैं। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ने की बात रखी है। इसका चिंताजनक पहलू यह भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। मनरेगा योजनाओं पर निर्भरता भी बढ़ी है। स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत को बहाल करना ही होगा और बुनियादी स्तर पर ही बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जाहिर है, जनप्रतिनिधियों को चुन कर संसद में भेजने वाला मतदाता उम्मीद करेगा कि लोकतांत्रिक ढांचे में सभी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। बिना किसी राग और द्वेष, भय एवं पक्षपात के।

परीक्षा पर सवाल

एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए सवालों के घेरे में है। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा यानी नीट के नतीजों में भारी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की है। भारतीय चिकित्सकों के संगठन ने भी सीबाआइ से इसकी जांच की मांग उठाई है। मगर एनटीए का कहना है कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। केवल छह केंद्रों पर प्रश्नपत्र कुछ देर से बांटे जा सके थे। केवल सोलह सौ अभ्यर्थियों की शिकायत है, उसका समाधान किया जा रहा है। पंद्रह सौ विद्यार्थियों को कृपांक दिए गए थे, उनकी पुस्तिकाओं की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। मगर एनटीए की इस दलील से नीट के नतीजों पर कितना भरोसा बन पाएगा, कहना मुश्किल है। आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में धांधली हुई है। हर वर्ष तीन से चार विद्यार्थी ही पहले स्थान पर पहुंच पाते थे, इस बार सड़सठ विद्यार्थियों को पहला स्थान मिला है। छह विद्यार्थियों को बराबर-बराबर अंक मिले हैं।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर गड़बड़ी की शिकायत नई नहीं है, मगर यह एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा में भी देखी जा रही है, तो निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। एनटीए का गठन ही इस मकससद से किया गया था कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोका जा सकेगा। इस परीक्षा में चूंकि लाखों परीक्षार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा जाता और एक ही समय सबको पर्चे जारी किए जाते हैं, इसलिए उसमें पर्चे बाहर जाने की गुंजाइश नहीं रहती। इतना चाक-चौबंद होने के बावजूद अगर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, तो इससे एनटीए की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े होते हैं। एनटीए की तरफ से गठित समिति की जांच से शायद ही असलियत पता चल सकेगी। ऐसे गंभीर मामले को ढंकने-छिपाने की कोशिशों के बजाय निष्पक्ष जांच कराने का कोई भरोसेमंद रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि लोगों को एजंसी की परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कायम हो सके।

पर्यटन क्षेत्र में उभरती नई संभावनाएं

पर्यटन सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा और पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत ने प्रगति की है।

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआइ) 2024 जारी किया है। 119 देशों के इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। इसके पहले 2019 में भारत इस सूचकांक में काफी नीचे, 54वें स्थान पर था। नए टीटीडीआइ सूचकांक में प्राकृतिक मापदंड पर भारत छठवें तथा संस्कृति, कारोबार, चिकित्सा और शिक्षा के लिए यात्रा मापदंडों पर नौवें क्रम पर है। इनमें कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में अठारहवें, हवाई यातायात की प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में छब्बीसवें और जमीनी तथा बंदरगाह बुनियादी ढांचे के मामले में पच्चीसवें स्थान पर है। इस पर्यटन सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इंटरनेट सुविधा और पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत ने प्रगति की है।

देश में घरेलू पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और खासकर धार्मिक पर्यटन ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन नए पर्यटन सूचकांक के आधार पर कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर जहां भारत अपने घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, वहीं घरेलू पर्यटन स्थलों पर विश्व पर्यटन की तरह सुविधाएं और सुंदरता निर्मित करके विदेशों में पर्यटन का मोह पाले हुए घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। गौरतलब है कि दुनिया के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहचान उनकी सुंदरता और पेशेवर तरीके से तैयार किए गए संग्रहालयों से भी है। इसके अलावा वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, साधारण से साधारण पर्यटक के लिए भी उच्च गुणवत्ता की स्थानीय सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के साथ-साथ वहां किफायती कीमत पर ठहरने और स्वच्छ तथा सुरक्षित आवास की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक प्रमुखतया फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, चीन और इटली जाते हैं। इनके अलावा सिंगापुर, विएतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) जैसे देश भी अपनी कुछ विशिष्टताओं से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भारत से बहुत आगे हैं। स्थिति यह है कि अभी भी दुनिया के कुल विदेशी पर्यटकों का दो फीसद से भी कम हिस्सा भारत के खाते में आ रहा है। हालांकि पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब छह फीसद का योगदान करता है, लेकिन इसमें सिर्फ आठ करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से रोजगार मिला हुआ है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाएं हैं, लेकिन यह इस डगर पर बहुत पीछे है। भारत के कई ऐसे अनोखे पर्यटन स्थल हैं, जो देश में पर्यटन के विभिन्न आयामों को चमकीली पहचान दे रहे हैं। भारत की संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खानपान से लेकर नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। भारत के पास हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा, विशाल समुद्री तट और रेत का रेगिस्तान, कच्छ में सफेद नमक का रेगिस्तान, लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान, देश के कोने-कोने में यूनेस्को द्वारा चिह्नित धरोहर स्थलों समेत अभयारण्य और राष्ट्रीय

उद्यान जैसी प्राकृतिक विविधताएं हैं। देश के विभिन्न भागों में तटीय पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन, स्थल अपनी पहचान बनाए हुए हैं।

गौरतलब है कि इस समय दुनिया के पर्यटन प्रधान देशों और भारत के पड़ोसी पर्यटन स्थलों वाले प्रसिद्ध देशों में भारतीय पर्यटकों को लुभाने की होड़ लगी हुई है। इन देशों ने इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारतीय मध्यवर्ग की तेजी से बढ़ती क्रयशक्ति के कारण उनमें विदेश यात्रा की ललक और अभिरुचि बढ़ी है। यही कारण है कि जहां एक ओर विदेशी पर्यटकों के कदम भारत की ओर धीमी गति से बढ़ रहे हैं, वहीं भारतीय पर्यटकों के कदम विदेशों में पर्यटन के लिए छलांगें लगाकर बढ़ रहे हैं। 4 दिसंबर, 2023 को सरकार ने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2022 में भारत यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 85.9 लाख थी। जबकि उस वर्ष करीब दो करोड़ भारतीय पर्यटकों ने देश से बाहर भ्रमण किया। 23 मई, 2024 को प्रकाशित रिजर्व बैंक की रपट के मुताबिक भारतीयों ने वर्ष 2023-24 में विदेश घूमने पर 17 अरब डालर यानी करीब 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं वर्ष 2022-23 में विदेश घूमने पर 13.6 अरब डालर खर्च किए गए थे।

विभिन्न अध्ययन रपटों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मगर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च के ग्राफ की वैसी ऊंचाई नहीं है। निश्चित रूप से भारतीयों का विदेश यात्रा की तरफ तेजी से बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटन के मद्देनजर नुकसान की तरह है। इसमें दो मत नहीं कि भारत में भी विदेशी पर्यटकों से आमदनी बढ़ रही है, लेकिन भारतीयों द्वारा विदेश भ्रमण पर किए जा रहे भारी-भरकम व्यय की तुलना में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से भारत की आमदनी बहुत कम है। विदेशी पर्यटकों से होने वाले आर्थिक लाभ का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि एक विदेशी पर्यटक से औसतन दो लाख रुपए की कमाई होती है। पर्यटकों का खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश का काम करता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार और पर्यटन से जुड़े विभिन्न उद्योग-कारोबार भी बढ़ते हैं।

पिछले एक दशक में देश में घरेलू पर्यटकों, धार्मिक पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन के व्यापक बुनियादी ढांचे और अन्य पर्यटन सुविधाओं को नई वैश्विक पर्यटन सोच के साथ आकार दिया गया है। पर्यटन बजट में लगातार वृद्धि की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत को वर्ष 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के दौरान कार्यसमूह की रणनीतिक रूप से देश के कोने-कोने में दो सौ से अधिक विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेने भारत आए विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी मेहमानों को भारत के पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवा कर भारत के बेजोड़ पर्यटन केंद्रों का वैश्विक प्रचार-प्रसार का अभूतपूर्व मौका मिला। इसके साथ भारत की दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण अब भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की नई संभावनाएं उभर रही हैं।

ऐसे में जरूरी है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र को अधिक जीवंत बनाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्यों और स्थानीय निकायों को पर्यटन विकास के लिए समन्वित रूप से साथ मिलकर काम करना होगा। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए उनकी पसंदीदा पर्यटन गतिविधियां बढ़ानी होंगी। उम्मीद है कि नवगठित सरकार पर्यटन प्रधान देशों की तरह पर्यटन क्षेत्र को और जीवंत बनाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। वर्ष 2030 तक भारत विदेशी पर्यटकों से 56 अरब डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक एक लाख करोड़ डालर की पर्यटन अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में रेखांकित होता दिखाई देगा।

> **विभिन्न अध्ययन रपटों के मुताबिक भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्राओं के दौरान किए जाने वाले खर्च का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मगर विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च के ग्राफ की वैसी ऊंचाई नहीं है। निश्चित रूप से भारतीयों का विदेश यात्रा की तरफ तेजी से बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटन के मद्देनजर नुकसान की तरह है। इसमें दो मत नहीं कि भारत में भी विदेशी पर्यटकों से आमदनी बढ़ रही है, लेकिन भारतीयों द्वारा विदेश भ्रमण पर किए जा रहे भारी-भरकम व्यय की तुलना में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से भारत की आमदनी बहुत कम है।**

बचपन की छुट्टियां

संजय दुबे

इस समय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। एक रिवायत की तरह बच्चों के लिए अब कहीं बाहर घूमने का अवसर है। ज्यादातर बच्चे अपनी नानी के घर जाएंगे। यहीं एक सवाल मन में आता है कि आमतौर पर ऐसा क्यों होता है कि लंबी छुट्टियों में बच्चों को नानी का घर पसंद आता है। आखिर यह चुनाव दादी का घर भी क्यों नहीं होता है? बुआ, बहन या कोई कोई अन्य रिश्तेदार का भी घर हो सकता है! मगर बच्चों को तो मानो किसी ने कान में फूंक दिया गया है कि उन्हें नानी के ही घर जाना है। हालांकि ऐसे भी तमाम बच्चे हैं, जो छुट्टियों में अन्य विकल्प आजमाते हैं, जिसमें वे कोई अन्य कौशल सीखने पर जोर देते हैं। किसी को छुट्टियों में नानी के घर खेलने-कूदने में आनंद आता है, तो कुछ बच्चे रचनात्मक कार्य सीखने में वक्त बिताते हैं। छुट्टियों में नानी के घर गए बच्चे मामा, मौसी के बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें अपनी दुनिया करीब लगने लगती है। यह शहरों-महानगरों में एक तरह से एकाकी होते समाज में अपना स्थान खोजने की कोशिश होती है और मिल जाने पर खुश होकर झूमने की स्थिति होती है।

यों भी गर्मी का मौसम आमतौर पर छुट्टियों के साथ-साथ शादी-ब्याह का भी होता रहा है। इस समय कई बार ज्यादातर लड़कियां अपने मायके पहुंचती हैं। सबके पहुंचने का वक्त आमतौर पर एक ही या आसपास होता है। वह भी दूरी के कारण। यह समझना मुश्किल है कि इस तरह की जुटान बच्चों की नानी के घर या फिर बेटियों के मायके के अलावा कोई और ठौर क्यों नहीं होता है। यह हो सकता है कि कोई महिला अपने मायके से चूंकि संवेदना के साथ जुड़ी होती है और वहां से सीधा जुड़ाव भी इस रूप में बना रहता है कि नाना-नानी अपनी बेटी से मिलने जब उसके ससुराल पहुंचते हैं, तो बच्चों के साथ भी उनका जुड़ाव थोड़ा घना हो जाता है। इसलिए बच्चे भी मौका मिलते ही नाना-नानी के घर जाना चाहते हैं। मगर फिर यह लगता है कि इस तरह का संवेदनात्मक जुड़ाव अन्य रिश्तेदारों के साथ क्यों नहीं हो पाता है। जबकि सभी आपस में एक-दूसरे के साथ आमतौर पर समान स्तर पर जुड़े रहते हैं। जरूरत के समय या अन्य मौकों पर एक-दूसरे के साथ अपना सुख-दुख बांटते रहते हैं।

बहरहाल, पहले जब सब बच्चे नानी के घर जुटते थे, तो जरूरत के हिसाब से खाना बनाने के लिए बड़े-बड़े बर्तन निकाले जाते थे, जो किसी कमरे में जमा करके रखे गए होते थे। तब एल्यूमीनियम को लेकर आज की तरह आग्रह नहीं था कि इसमें बना खाना खाने से कोई गड़बड़ी होती है। इसलिए तब एल्यूमीनियम के बड़े भगौने, तसले, लोहे की बड़ी वाली कड़ाही निकाली जाती थी। घर के बड़े आंगन में खाना बनाते समय अक्सर जमघट लग जाता था। सारी महिलाएं वहीं इकट्ठा रहतीं। घर की बहुएं गांव के हाल-चाल से लड़कियों को अवगत करातीं। कहां क्या हुआ, कहां आजकल क्या चल रहा है आदि। इससे बुआ और मौसियों को पूरे गांव की जानकारी मिल जाती, जिसमें यह भी शामिल होता कि उन्हें किससे, कैसे, कौन-सी बात करनी है या बात नहीं करनी है। उसका एक खाका उनके दिमाग में खिंच जाता था। इसी आधार पर संबंध निभाए, बरते जाते थे।

दूसरी ओर, बच्चों के पलटन की धमाचौकड़ी चलती रहती थी। कई बार उनकी एक टोली बन जाती थी और साथ मिल कर खेलने वाले बच्चों की संख्या पहुंच जाती थी बीस तक। ऐसे में इनका एक अघोषित संगठन बन जाता। शहरों-महानगरों में स्मार्टफोन में सिमटे और कैद होते बच्चों की दुनिया के बरक्स यह जीवन की तरह होता था, जहां बच्चे जमीन पर अपने पांव टिकाते थे और जीवन का सुख प्राप्त करते थे। दुनिया को समझते थे। दोपहर में घर के लोग खा-पीकर आराम करने जाते और बच्चे अपनी टोली के साथ बगीचों और पोखरों का रुख कर लेते। बगीचों में दोपहर का समय बीतना स्वाभाविक था। गर्मी में ठंडक और खेलने की खुली जगह। खेल में कभी कबड्डी, तो कभी गिल्ली-डंडा या फिर अंटी-चौक, गेंदा भड़भड़ आदि। आज की तरह मनोरंजन मोबाइल के एक छोटे पर्दे पर सिमटा क्रिकेट या फुटबाल नहीं था। पूरी दोपहरी बगीचे में खेलते, कब शाम हो जाती, पता नहीं चलता। कभी-कभी बच्चे पोखरों में भी नहाते। न जाने कितनों ने इन्हीं दिनों में तैरने का ढंग सीखा। शहर में तो तरणताल मुश्किल से मिलते हैं और मिलते भी हैं तो कुछ देर के लिए फीस चुका कर।

खेल-कूद कर बच्चे शाम को जब घर पहुंचते तब चना या मकई का ताजा दाना भुना मिलता। आज भी जिन बच्चों की नानी के घर गांव-देहात में हैं, वहां बिना रासायनिक खाद वाले अनाज और सब्जियों से बना भोजन मिल जाता है, जिसका स्वाद बच्चों की जीभ पर ठहर जाता है। वजह यह कि इस तरह के अनाज और सब्जियों की खुशबू और स्वाद शहरी खाने के स्वाद में जमीन-आसमान का फर्क है। समूचा माहौल बच्चों को खुद को महत्त्वपूर्ण होने का अहसास कराता था। गर्मी की छुट्टियां जब खत्म होंगी, तब बच्चे अपनी नानी के घर और वहां के बाग-बगीचों से आम के खट्टे-मीठे स्वाद और अनुभव लेकर, उनसे समृद्ध होकर लौटेंगे और फिर अपनी दुनिया में रम जाएंगे। इस बीच नाना-नानी के अलावा अन्य रिश्तेदार भी इंतजार करेंगे कि कभी बच्चे आकर उनके घर-आंगन में भी जीवन भर दें।

दुनिया मेरे आगे

> **गर्मी की छुट्टियां जब खत्म होंगी, तब बच्चे अपनी नानी के घर और वहां के बाग-बगीचों से आम के खट्टे-मीठे स्वाद और अनुभव लेकर, उनसे समृद्ध होकर लौटेंगे और फिर अपनी दुनिया में रम जाएंगे। इस बीच नाना-नानी के अलावा अन्य रिश्तेदार भी इंतजार करेंगे कि कभी बच्चे आकर उनके घर-आंगन में भी जीवन भर दें।**

चिंता की बात

चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर अभिनेत्री और नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ सीआइएसएफ की युवा सिपाही ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, वह अप्रत्याशित और स्तब्ध करने वाला है। एक महिला सिपाही द्वारा एक महिला सांसद के साथ सार्वजिनक तौर पर की गई यह बदसलूकी एक सामान्य आक्रोश का परिणाम नहीं, बल्कि एक गंभीर घटना है, जिसकी जितनी निंदी की जाए, कम है। यह माना जा सकता है कि कंगना रनौत के किसी बयान से वह महिला सिपाही बहुत आहत और क्षुब्ध थी, लेकिन किसी तरह के ऐसे आम सार्वजनिक बयानों के विरोध में इस तरह का कदम उठाया जाना न तो व्यक्तिगत रूप से ठीक है और न ही लोकतांत्रिक दृष्टि से, क्योंकि जनप्रतिनिधियों या इस तरह के व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान प्रायः दिए जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह का प्रतिशोध दिखाना उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था के प्रति खतरे की घंटी जैसी हैं, जिन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

– रतन कुमार श्रीवास्तव 'रतन', लखनऊ

संवाद से दूरी

स्मार्टफोन ने लोगों की जीवनशैली बदल दी है। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते हैं। हर कोई मोबाइल की अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है कि पास में कौन बैठा है, इसकी भी सुध नहीं रहती। घर-दफ्तर से लेकर यात्रा तक संवाद की कड़ियां टूट गई हैं। हालांकि इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल से कई प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। पैसा भेजने से लेकर संवाद करने तक में आसानी हो गई है, लेकिन इसने बच्चों का बचपन, युवाओं से खेल और समाज से समरसता छीन ली है। अब गांव में भी लोग एक साथ बैठे दिखाई नहीं देते। चाय की दुकानों या चौपाल पर भी पड़ोसियों से चर्चा नहीं होती। शोधकर्ताओं का कहना है कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने और हमारी सहायता के लिए है, लेकिन इस पर अधिक निर्भरता ठीक नहीं। इसीलिए स्मार्टफोन का उपयोग करें, लेकिन इसकी सीमाओं को तय करना भी जरूरी है।

– गोपाल सोनी, मनावर, मप्र

रणनीतिक फैसला

महाराष्ट्र में तोड़फोड़ के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देना भाजपा के लिए खतरनाक साबित हुआ है। इससे तो बेहतर होता कि फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो जनता पर उनकी पकड़ रहती और उनके बेहतर कार्यों से मतदाता प्रभावित होते। अब छह महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नए समीकरण और नए गठबंधन उभरेंगे। अब भाजपा को पिछले विश्वासघात से सबक लेकर ठोक-बजा कर अपना गठबंधन बनाना चाहिए, ताकि मोदी की छवि का फायदा उठाया जा सके और पार्टी में शामिल होने वाले अन्य घटक दल चुनाव बाद अपना फायदा देखकर पलटी न मार सके। महाराष्ट्र में भी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनना तय है। तो भाजपा को ठोक-बजा कर अपने साझीदार तय करने चहिए।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

गलत कदम

इस समय जब कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक को बहुत सोच-समझ कर कदम उठाना चाहिए था, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। वे फ्रांस में आयोजित हो रहे डी-दिवस के आयोजनों को छोड़ कर, चुनावी कार्यक्रम के लिए, ब्रिटेन वापस आ गए। उनके इस कृत्य की पूरे विश्व सहित उनकी खुद की पार्टी के भीतर भी निंदा हो रही है। ऋषि सुनक का यह फैसला बताता है कि उनमें अनुभव की कमी है। चूंकि वे भारतीय मूल के हैं, इसलिए शायद डी-डे पर, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में उनके देश ब्रिटेन का अन्य मित्र राष्ट्र के साथ कैसा योगदान था, कितने ब्रिटिश जवानों को शहीद होना पड़ा था, इसके बारे में सुनक अनभिज्ञ रहे होंगे। तभी वे डी-डे की अस्सीवीं वर्षगांठ को बीच में ही छोड़ कर अपने वतन वापस आ गए। लगता है कि 4 जुलाई के चुनाव में उन्हें तथा उनकी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

कृत्रिम हृदय की ओर

आईआईटी, कानपुर में कृत्रिम हृदय के निर्माण में लगे इंजीनियरों को आगे प्रयोग की मंजूरी मिलना एक बड़ी खुशखबरी है। यह संस्थान साल 2022 में ही कृत्रिम हृदय तैयार कर चुका है और प्रयोगशाला में उसके प्रयोग सफल भी रहे हैं। अब इस कृत्रिम हृदय का प्रयोग एक बकरी में किया जाएगा। कृत्रिम हृदय, जिसे 'हृदयंत्र' नाम दिया गया है, वह ऐसे मरीजों के काम आ सकता है, जिनको हृदय प्रत्यारोपण का इंतजार है। गौरतलब है, भारत में ही प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ लोगों को हृदय की वजह से लाचार होना पड़ता है, पर जब कृत्रिम हृदय को सफलता मिल जाएगी, तो हृदय-रोगियों को नया जीवन मिलेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि जब इस प्रयोग को सफलता मिल जाएगी, तो हृदय प्रत्यारोपण का खर्च दस गुना घट जाएगा। अभी हृदय प्रत्यारोपण के जो विकल्प दुनिया में उपलब्ध हैं, वे पर्याप्त या सुलभ नहीं हैं। अतः भारत में किफायती और सक्षम कृत्रिम हृदय की खोज होती है, तो चिकित्सा जगत के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी।

यह भी एक सुखद संयोग है कि शरीर अभियांत्रिकी पर किसी भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में काम हो रहा है। चिकित्सा का काम वास्तव में आधुनिक समय में इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। आईआईटी, कानपुर के जिन वैज्ञानिकों ने यह अद्भुत निर्माण किया है, उन्होंने बाकायदे ऑपरेशन थियेटर में मौजूद रहते हुए हृदय का ऑपरेशन करीब से देखा है।

सबसे बेहतर विकल्प है कि एक कारगर कृत्रिम हृदय का सृजन जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि हृदय रोग से पीड़ित करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया जा सके।

दरअसल, हमारा शरीर किसी इंजीनियरिंग महायंत्र से कम नहीं है। देश के विख्यात चिकित्सक देवी शेट्टी ने ही आईआईटी, कानपुर को इस प्रयोग और निर्माण के लिए प्रेरित किया था। इस तरह से चिकित्सकों के साथ मिलकर अभियंताओं ने काम किया है और आगे जब एक बकरी में यह प्रत्यारोपण होगा, तब भी ऑपरेशन थियेटर में चिकित्सकों के साथ अभियंता मौजूद रहेंगे। गौर करने की बात है कि पहले कानपुर में हृदय के ठीक नीचे प्रत्यारोपित किया जाने वाला, बैटरी से चलने वाला छोटा पंपिंग उपकरण बनाया गया था। यह एक पंप की तरह काम करता है, जो पूरे शरीर में रक्त संचारित करने में सहायता करता है, जिससे रोगी को एक नया जीवन मिलता है। यह यंत्र भी आईआईटी ने बहुत सस्ते में बनाया था, जबकि ऐसा ही काम करने वाला यंत्र करीब एक करोड़ रुपये में उपलब्ध होता है।

दरअसल, जरूरत एक चालू यांत्रिक कृत्रिम हृदय के बजाय एक जीवंत कृत्रिम हृदय की है, जो पुख्ता रूप से शरीर के अंदर स्थापित होकर बाकी अंगों के साथ तालमेल बिठाकर घुल-मिलकर काम करने लगे। वैसे, कृत्रिम हृदय के साथ यह कोई पहला प्रयोग नहीं है। साल 1938 में पहले कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण एक कुत्ते में किया गया था। 1952 में एक यांत्रिक हृदय बनाया गया, जो शल्य चिकित्सा की स्थिति में आंशिक रूप से कुछ समय के लिए हृदय की तरह काम करता था। खैर, अब मानव हृदय का किसी मानव में प्रत्यारोपण संभव है, लेकिन प्राकृतिक हृदय की उपलब्धता एक बड़ी कमी है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। जब रक्तदान की स्थिति ही अभी पर्याप्त नहीं है, तब हृदय दान के लिए माहौल भला कैसे बनाया जा सकता है? अतः सबसे बेहतर विकल्प है कि एक कारगर कृत्रिम हृदय का सृजन जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया जा सके। इस दिशा में जुटे वैज्ञानिकों की जितनी प्रशंसा की जाए, कम होगी।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 10 जून, 1949

राष्ट्रीयता के लिए कलंक

विगत रविवार को कलकत्ते में धारासभा के उप-चुनाव के सम्बन्ध में जो दुःखद घटनाएं हुईं, वे हमारी राष्ट्रीयता के माथे पर भयानक कलंक हैं। शरत् बाबू के सबसे बड़े भाई श्री सतीशचन्द्र बोस के निधन के कारण पश्चिमी बंगाल की धारासभा में जो स्थान रिक्त है, उसके लिए कांग्रेस की ओर से श्री सुरेशचन्द्र दास उम्मीदवार खड़े किये गये हैं। समाजवादी जनतंत्रीय दल की ओर से शरत् बाबू उनका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो प्रजातंत्र और स्वतंत्र दलों के प्रतिनिधि श्री डी.के. रायचौधरी और श्री एस.सी. राय भी चुनाव लड़ रहे हैं, किंतु वास्तवकि संघर्ष श्री सुरेशचन्द्र दास और शरत् बाबू में ही है। पिछले रविवार को जब दास महोदय के पक्ष का समर्थन करने के लिए देशप्रिय पार्क में एक सार्वजनिक सभा हो रही थी तो एक भीड़ ने उन पर जूते और डंडे उछालने शुरू किये। बाद में कुछ आग लगाने वाले बम भी फेंके गये, जिसके फलस्वरूप २५ व्यक्ति घायल हो गये। बात यहीं तक सीमित नहीं रही; आक्रमणकारियों ने राष्ट्रीय पताके में आग लगा दी और कुछ उन्मादी नवयुवक उस जलती हुई पताका को लेकर प्रदर्शन करते फिरे। यह एक ऐसी घटना है, जिसे सुन और पढ़कर विवेकी देशप्रेमियों के शीश लज्जा से झुक जाते हैं। जो ध्वज जलाया गया वह किसी दल विशेष नहीं, अपितु स्वतंत्र भारत का प्रतीक था और उसका अनादर करना निस्संदेह जघन्य देशद्रोह है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस भीड़ ने यह दुष्कर्म किया वह शरत् बाबू की पक्षपातिनी थी। किसी समय शरत् बाबू कांग्रेस के एक प्रमुख स्तम्भ थे और वयोवृद्ध नेता होने के कारण जनता उनसे उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती रही है। राष्ट्र-नायकों ने भी सदा उन्हें आदर की ही दृष्टि से देखा है। तभी तो नेहरूजी ने अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना करते समय उसमें शरत् बाबू को सम्मानपूर्वक स्थान दिया था। दुःख की बात है कि कांग्रेस के साथ उनका मतभेद दिन पर दिन बढ़ता गया और समय-समय पर उन्होंने कांग्रेस की कटु आलोचना करने में संकोच नहीं किया।... आज उनके दल वाले नीच से नीच साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। रविवार को जो कुछ भी हुआ उसमें शरत् बाबू की कितनी प्रेरणा थी, इस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं। इतना ही पर्याप्त है कि उन्होंने इस गर्हित घटना की निन्दा नहीं की है।

तीसरी सरकार से भी उम्मीदें बेशुमार

नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीसरी बार बागडोर संभाल ली है। अब जिन चीजों पर असहमति है, उन्हें किनारे रखकर तरक्की और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाने होंगे।

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अधिकतर आबादी गांवों में बसती है। दसियों साल से स्कूली निबंधों में कैद यह पंक्ति अब शायद वापस राजनीति के केंद्र में लौट रही है और इसके साथ ही अर्थनीति पर भी इसकी छाप स्वाभाविक है। दूसरी ओर, बढ़ती आबादी पर लगाम कसने की नाकाम कोशिश के बाद उसी आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनसांख्यिकीय लाभांश बताने का हैंगओवर भी सामने आ चुका है। इसका अर्थ है, सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार का इंतजाम सबसे बड़ी प्राथमिकता बन सकता है।

नरेंद्र मोदी की तीसरी केंद्र सरकार ने कार्यभार संभाल लिया, पर तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही सौ दिनों के एजेंडे पर काम चालू हो चुका था, मगर सरकार के अहम सहयोगी इन एजेंडों को कितना पटरी पर रहने देंगे? यहां हिसाब लगाना जरूरी है कि जीडीपी में बढ़त की रफ्तार आठ फीसदी से ऊपर जाने की खुशखबरी आने के ठीक बाद कहीं उस पर ब्रेक लगने का डर तो नहीं पैदा होगा? खासकर, यह देखते हुए कि पिछले कार्यकाल के मुकाबले इस बार सहयोगी दलों की गिनती कम होने के बावजूद उनकी अहमियत बढ़ चुकी है।

जनता दल (यूनाइटेड) के मुखिया नीतीश कुमार और तेलुगुदेशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की तरफ से अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग तो स्वाभाविक है, मगर क्या मोदी सरकार के महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडों या आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोई मांग इनकी तरफ से आ सकती है? अलग-अलग विचारों के बावजूद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों ही आर्थिक और प्रशासनिक मोर्चे पर सुधार व विकास की राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। यानी, इनकी तरफ से आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़ी अड़चन की आशंका नहीं होनी चाहिए।

ध्यान रहे, भारत में बहुत बड़े आर्थिक सुधार ऐसी सरकारों के दौर में हुए हैं, जब या तो मिली-जुली सरकारें थीं या फिर बाहरी समर्थन पर टिकी सरकार देश चला रही थी। साल 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत या अर्थव्यवस्था को खोलने का काम ही पीवी नरसिंहराव सरकार ने किया था, जिसे संख्या-बल के कारण एक कमजोर सरकार माना जाता था। इसी तरह, देवेगौड़ा और गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकारों ने आयकर की स्लैब घटाकर तीन करने का काम और दूरसंचार नियामक ट्राई (टीआरएआई) की स्थापना जैसे बड़े फैसले किए। दूरसंचार, पेंशन, सरकारी घाटे पर लगाम कसने की व्यवस्था, बिजली और बीमा क्षेत्र के अनेक बड़े सुधार अटल बिहारी वाजपेयी की उस सरकार ने किए, जिसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था।

मनमोहन सिंह ने भी यूपीए के दौर में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून और पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार के हवाले करने जैसे बड़े फैसले किए। वैसे, मोदी सरकार के भी पहले कार्यकाल में जीएसटी लागू करने जैसा बड़ा काम हुआ, जिसमें सारी राज्य सरकारों को राजी करना जरूरी था। हालांकि, कई बार पूर्ण बहुमत वाली सरकारें भी वह नहीं कर पाईं, जो वह करना चाहती थीं, जैसे- मोदी सरकार में कृषि कानूनों की वापसी।

यह जरूर है कि गठबंधन में सरकारें ऐसे काम नहीं कर पातीं, जिनसे किसी दल के नाराज होने का डर हो, पर ऐसे काम तेज हो सकते हैं, जिनका फायदा साफ दिखता हो, या जो गठबंधन में शामिल सभी या अधिकतर पार्टियों के एजेंडे से मेल खाते हों। आज का हाल देखें। बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़क, रेल, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना- इसमें भला कौन सी बाधा आ सकती है? श्रम कानूनों में सुधार या बदलाव पर विवाद हो सकता है, लेकिन उसके बिना भी भारत तेज विकास कर रहा है।

वास्तव में, इस वक्त हालात जितने अनुकूल दिखते हैं, वैसे शायद पहले कभी नहीं रहे। अर्थव्यवस्था में बढ़त की रफ्तार 8.2 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को उम्मीद से दोगुना लाभांश दिया है। जीएसटी वसूली नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आयकर व कॉरपोरेट टैक्स के मोर्चे पर कमाई बढ़ती जा रही है। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य भले पूरा न हो, पर अब वे बोझ नहीं, कमाऊ लग रही हैं। मतलब यह कि सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं हैं और जरूरी चीजों पर खर्च की गुंजाइश बनी हुई है।

अब बजट में सरकार को जहां ध्यान देना है, वह यह कि कैसे भारत की तरक्की की रफ्तार बनी रहे या और तेज की जा सके? कैसे नए रोजगार पैदा हों? कैसे गांव, गरीब और किसान तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके और ग्रामीण इलाकों में भी विकास का सपना साकार किया जा सके? पिछले दस साल में यह एक बड़ी समस्या रही है कि सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद काफी खर्च किया, मगर जवाब में निजी क्षेत्र की तरफ से जो खर्च होना था, उतना नहीं हुआ। हां, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंत तक पहुंचते-पहुंचते वित्त मंत्री जरूर यह मानने लगी थीं कि निजी क्षेत्र नए कारखानों और मशीनों में पैसे लगाने लगे हैं। यह होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सरकार के भरोसे विकास नहीं हो सकता। रोजगार बढ़ाने का काम भी तभी होता है, जब सरकार और कारोबारी कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तिमाही-दर-तिमाही कंपनियों के सुधरते नतीजे, शेयर बाजार में तेजी की लहर और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों की तरफ से जबर्दस्त निवेश मिलकर यह संदेश दे रहे हैं कि अब कंपनियों के पास कोई बहाना नहीं है।

ऐसे में, नई सरकार के सामने जो प्राथमिकताएं साफ दिख रही हैं, उनमें अब जनता को खुश करने वाली और उन्हें न सिर्फ वर्तमान, बल्कि भविष्य के प्रति भी आश्वस्त करने वाली योजनाओं पर खर्च और जोर बढ़ाना सबसे ऊपर होगा। सुधारों के मोर्चे पर आगे बढ़ना होगा। जिन चीजों पर असहमति की गुंजाइश है, उनको किनारे रखकर आर्थिक तरक्की और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाने होंगे। जाहिर है, मुफ्त अनाज से खुश होने के बाद अब लोग इससे आगे कुछ चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी जरूरत रोजगार की है, मगर इसके इंतजाम में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में, लोगों को तत्काल खुश करने वाले कुछ एलान बजट में सुनाई दें, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लंबे समय के बाद वह वक्त लौट आया है, जब बजट में वित्त मंत्री को 'गुड पॉलिटिक्स' और 'गुड इकोनॉमिक्स' के बीच संतुलन बैठाना पड़ेगा? इसलिए, बजट बनाना और अर्थनीति संभालना तलवार की धार पर चलने से कम नहीं होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

साल दर साल बढ़ती गरमी से बचने की कवायद जरूरी

यहां स्कैन करें

सुरुचि भड़वाल | मृदा एवं जलवायु विशेषज्ञ

गरमियों में तापमान का 47 डिग्री या इससे पार चले जाना अब सामान्य हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो पिछले दिनों गरमी 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण भारत में इस समय गरमी रहती ही है, लेकिन जलवायु संकट की वजह से पिछले डेढ़ दशक में कई बार तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने से हीटवेव, यानी अत्यधिक गरमी की स्थिति बन जाती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई हिस्से अब हर साल हीटवेव से झुलसने लगे हैं। ग्रीनहाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पिछले करीब 200 वर्षों में 10 सबसे गरम साल 2014 से 2023 तक के वर्ष ही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह प्रवृत्ति आगे भी बनी रह सकती है और हम साल-दर-साल इसी तरह या अधिक गरमी झेलने को मजबूर होंगे।

भारत में किए गए कई अध्ययनों ने यह बताया है कि जलवायु संकट का देश पर किस कदर प्रभाव पड़ रहा है। चरम मौसमी परिस्थितियों की तीव्रता और आने की दर पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है। 'एनर्जी ऐंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट' (टेरी) ने पिछले पांच दशकों के जलवायु पैटर्न को जांचने के लिए एक अध्ययन किया, जिसमें अधिकतम व न्यूनतम तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखती है। चंद क्षेत्रों को छोड़ दें, तो कमोबेश पूरे देश में अधिकतम तापमान में तेज बढ़ोतरी हो रही है। यह वृद्धि प्रति दशक 0.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.4 डिग्री सेल्सियस तक है। देश के पश्चिमोत्तर इलाकों में सबसे तेज बढ़ोतरी (एक दशक में 0.3 डिग्री सेल्सियस) हुई है, जबकि पूर्वोत्तर में गरम दिनों की संख्या (सालाना 10-15 दिन) बढ़ी है। पश्चिमी तट में भी गरम दिनों की संख्या अधिक हुई है, हर साल पांच से दस दिन।

जलवायु संकट के कारण यदा-कदा होने वाली अत्यधिक गरमी का दौर सामान्य, लंबा और अधिक गंभीर होता जा रहा है।

जलवायु संकट गहराने के साथ आने वाले दशकों में अधिकतम तापमान और गरम दिनों की संख्या में आगे बढ़ोतरी ही होगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से व लद्दाख में अधिकतम तापमान में तेज वृद्धि की आशंका है, जो साल 2055 तक 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। जहां तक गरम दिनों की बात है, तो ग्रीष्म ऋतु में चार से 40 दिनों तक तेज गरमी के दिन बढ़ सकते हैं। इसमें राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, गुजरात का पश्चिमी भाग और पश्चिमी तट भी शामिल हैं, जहां 25-30 दिनों तक गरम दिनों में वृद्धि हो सकती है।

सामान्य मौसमी परिस्थितियों के लगातार अधिक बने रहने से हीटवेव पैदा होती है, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार तो लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वे किस खतरे के बीच अपना दिन गुजार रहे हैं। हीटवेव के कारण 'हीट स्ट्रोक' और 'डिहाइड्रेशन' हो सकता है और कुछ मामलों में जान भी जा सकती है। इसके अलावा, अत्यधिक गरमी से उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। समय बीतने के साथ ये परिस्थितियां बढ़ती ही जाएंगी, इसलिए इस पर पर्याप्त ध्यान देने की दरकार है। जलवायु संकट के कारण यदा-कदा होने वाली अत्यधिक गरमी का दौर सामान्य, लंबा और अधिक गंभीर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का आकलन है कि इससे एक अरब से अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

साफ है, मौसम पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मौसम विभाग की चेतावनियों को भी व्यापक तौर पर प्रसारित करने की जरूरत है, जो न सिर्फ आम लोगों को समझ में आए, बल्कि वे उन पर अमल भी कर सकें। कुछ आसान उपाय तो हमारे सामने हैं, जैसे तेज धूप के समय घर के भीतर रहना, अत्यधिक गरमी में बाहरी गतिविधियों से बचना, ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से परहेज करना, शरीर में पानी की कमी न होने देना आदि। दूरगामी कदमों के तहत चेतावनी प्रसारित करने वाली संचार सुविधाओं में सुधार, इमारतों का मौसम-अनुकूल निर्माण, शहरी नियोजन व भू-निर्माण को अपनाने (इसमें खुला व हरित क्षेत्र हो, ताकि हवा का प्रवाह सुगम रहे और प्राकृतिक ठंडक बनी रहे) जैसे काम किए जा सकते हैं। हरित छत की अवधारणा पर भी काम किया जा सकता है। बढ़ते तापमान और अत्यधिक गरमी के खिलाफ हमें संजीदगी दिखानी ही होगी। हम चूंकि जलवायु संकट में फंस चुके हैं, इसलिए इस तरह की कवायद आसन्न मुश्किलों को दूर करने में हमारी मदद कर सकती है।

(साथ में के वेंकटरमना)

मनसा वाचा कर्मणा

संन्यास आखिर किसलिए

परमात्मा और हमारा क्या रिश्ता है? निरंतर मांगने का। हमारी मांग कभी खत्म ही नहीं होती। शायद यह किसी को अच्छा न लगे, लेकिन थोड़ा गौर करें, मंदिरों के बाहर जो लंबी कतारें होती हैं, उनमें हर कोई कुछ न कुछ वहां मांगने के लिए आता है। पता नहीं, यह ख्याल कब और कैसे पैदा हुआ कि हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई और बैठा है? और उसके पास ज्यादा ताकत है, इसलिए वह हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। यह बड़ी अजीब बात है, इच्छाओं से भरे हम हैं, तो क्या उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमें नहीं लेनी चाहिए? यह तो ऐसा ही हुआ कि बच्चे हम पैदा करें और उम्मीद करें कि उन्हें पाले-पोसे कोई और! यह परमात्मा की कल्पना का गलत उपयोग है। पूजा या भक्ति को लेकर यही बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसीलिए न तो भक्ति विकसित होती है और न ही हमारी पूजा में कोई गहराई होती है। वास्तविक भक्ति तो तब होगी, जब सारी सांसारिक मांगें खो जाएं। असली पूजा तब होगी, जब हम अपना अहंकार समर्पित कर दें।

गुरुओं के पास भी लोग जाते हैं, तो यही मानसिकता लेकर जाते हैं, लेकिन ओशो जैसे महागुरु हों, तो इसे सहारा नहीं देते। ओशो एक सच्ची घटना बताते हैं- 'एक मित्र संन्यास लेने आए। संन्यास जब ले रहे थे, तभी मुझे थोड़ा-सा बेबूझ मालूम पड़ रहा था; क्योंकि उनके चेहरे पर संन्यास का कोई भाव न था। पैर भी छुए थे; लेकिन पैर छूने में परंपरागत आदत मालूम पड़ी थी, प्रसाद न था। संन्यास मांग रहे थे, तो मैंने दे दिया। संन्यास लेते ही उन्होंने कहा कि मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूं, इसीलिए आया हूं। मेरी तत्काल बदली करवा दें। पठानकोट में पड़ा हूं और रांची जाना है। यही सोचकर भगवान, आपके चरणों में आ गया हूं कि इतना आप कर देंगे। अब तो आप मेरे हो गए हैं, इतना तो आप करेंगे ही।

मैंने उनसे पूछा, सच-सच कहो, संन्यास इसीलिए तो नहीं लिया? इसको रिश्वत की तरह तो नहीं लिया कि चलो, संन्यास ले लिया, तो यह कहने का हक रहेगा। वह कहने लगे, अब आप तो सब जानते ही हैं,

पता नहीं, यह ख्याल कब और कैसे पैदा हुआ कि हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई और बैठा है! और उसके पास ज्यादा ताकत है, इसलिए वह हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है।

झूठ भी कैसे कहूं आपसे? संन्यास इसीलिए लिया है कि अब तो आप फिक्र करेंगे मेरी!

लेकिन क्या फिक्र करा रहे हो, पठानकोट से रांची! क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या मांग रहे हो? इतने स्पष्ट रूप से शायद बहुत लोगों की मांग नहीं भी होती है, लेकिन गहरे में खोजोगे, अचेतन में झांकोगे, तो ऐसी ही मांगें छिपी पाओगे। तुम क्षुद्र मांग रहे हो विराट से। तुम्हें क्षुद्र तो मिलेगा ही नहीं, विराट से भी चूक जाओगे। पीछे पछताओगे! 'मैं' के आसपास खड़ी हुई कोई भी मांग मत उठाओ। 'मैं' के पार कुछ मांगो।'

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

मई 2024 इतिहास की सबसे गरम मई दर्ज की गई है। लगातार 12 महीने अब तक के सबसे गरम महीने रहे हैं। हमारा ग्रह हमसे कुछ कहता जा रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। यह समय ठोस कदम उठाने का है।

यह हमारी पुरानी अयोध्या तो नहीं

अयोध्या को जो लोग पहले से जानते हैं, उनको पता होगा कि बीते एक दशक में यहां क्या कुछ बदला है! हम सबके प्यारे रामलला, जो पहले टेंट में रहा करते थे, अब महलनुमा मंदिर में रहने लगे हैं। मंदिर के नजदीक ही इतनी सारी आर्थिक गतिविधियां चलने लगी हैं कि भक्तों के साथ-साथ आसपास के लोगों को भी पर्याप्त लाभ मिल रहा है। यहां भक्तों का भारी संख्या में आना स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, यहां विकास-कार्यों को भी काफी गति दी गई है। सड़कों में सुधार हुआ है और बुनियादी ढांचे पहले से बेहतर हुए हैं, फिर भी लोगों को मोदी सरकार का कामकाज पसंद नहीं आया, जो बिल्कुल ही समझ से परे है। इससे यही लग रहा है कि यह पुरानी अयोध्या नहीं है। ऐसा इसलिए भी लगता है, क्योंकि फैजाबाद ही नहीं, जिस निर्वाचन-क्षेत्र का अयोध्या हिस्सा है, आसपास की तमाम सीटों पर एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। यह ठीक है कि चुनाव में किसी को हार, तो किसी को जीत मिलती है और जनता के मत का हमेशा सम्मान होना चाहिए, लेकिन लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि जो पार्टी उनके हितों में काम कर रही है, वे उसे प्रोत्साहित करें। इससे पार्टियों का मनोबल बढ़ता है और वे जनता के हित में कहीं अधिक गंभीरता से काम करती हैं। जब जनता काम करने वाले नेताओं को प्रोत्साहित नहीं करेगी, तो फिर जनहित के काम कोई क्यों करेगा? देखा जाए, तो इस बार यहां के मतदाताओं ने एक बड़ी गलती कर दी है। उनको उसी दल के उम्मीदवारों को संसद भेजना चाहिए, जो यहां अनवरत काम कर रहा है। इसलिए, आज यदि 'बायकॉट अयोध्या' जैसी मुहिम चल रही है, तो मुझे गलत नहीं जान पड़ता। अयोध्यावासी इसी के हकदार हैं। उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए।

कुणाल शर्मा, टिप्पणीकार

बहिष्कार अनिवार्य

अयोध्या का निस्संदेह बहिष्कार होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आप अयोध्या बेशक जाएं, लेकिन अपनी गाड़ी से। खाना-पीना अपने पास रखें, स्थानीय दुकानदारों से कुछ न खरीदें। मंदिर प्रांगण में जाकर रामलला के दर्शन कीजिए, अपने जनपद या गांव से लाया हुआ चढ़ावा चढ़ाइए और वापस लौट जाइए। अगर कुछ दान देना चाहते हैं, तो दान-पेटी में ही दीजिए, किसी स्थानीय को मत दीजिए। मंदिर प्रांगण से बाहर किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन न करें। जो खता अयोध्यावासियों ने इस चुनाव में की है, उसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए।

पंकज कुमार सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

फैजाबाद की हार

ताजा नतीजों से अपना आपा न खोएं

अयोध्या के चुनाव परिणाम को लेकर अनेक आतुर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इनमें से अधिकांश निराधार, अवमाननापरक और कुंठा से भरी हुई हैं। निंदा व प्रशंसा, दोनों ही भावों से अयोध्या का तिरस्कार न केवल अविवेकपूर्ण, अपितु अपराध भी है। भूलोक की प्रथम पुरी यह विश्वविश्रुता अयोध्या ही है, जिसने धर्मविग्रह पुत्र को प्रकट किया, उसे तपाकर मर्यादा पुरुषोत्तम का गौरव दिया और राजा राम के रूप में मानव-चेतना में अनंत काल के लिए अमर कर दिया।

ये अयोध्यावासी ही हैं, जिन्होंने अपने राम के लिए असह्य दुख सहे, त्याग किए और जिनको अपना कहकर श्रीराम ने अपने को बहुमानित समझा। यही अयोध्या है और यही श्रीराम का नाम, जिसने भारत देश को सारे समीकरणों और अनुमानों के पार कल्पनातीत शक्ति व सत्ता का बल दिया और इस लोकतांत्रिक राजनीति की चंचल चालों के बीच तीसरी बार पुनः बहुमत दिया है। यही अयोध्या है, जिसको केंद्र में रखकर भारत देश अपनी स्वायत्तता, संप्रभुता और खोया हुआ स्वाभिमान पुनः प्राप्त कर रहा है। इसी अयोध्या की रज में विश्व का श्रेष्ठतम कहलाने वाला नेता साष्टांग कर जाता है। मगर यह अयोध्या किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता अथवा किसी एक घटना से परिभाषित नहीं होती। इसने अपने राम को वन जाते देखा है, इसने धर्मधुरंधर महाराज दशरथ को बिलख-बिलखकर देह-त्याग करते देखा है। इसने अपने राम के लिए 14 वर्षों तक दुःसाध्य तप किया है और फिर उनको घर लौटाकर सिंहासनाधिरूढ़ किया है, उनका विरुद गान किया है।

अयोध्या किसी के हारने या जीतने से उसकी या परायी नहीं हो जाती। यह बस उनकी है, जो श्रीराम के हैं। यह अपने सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने राम को भी वन भेज देती है, क्योंकि इसका नाम ही सत्या है। इसको अभिशप्त और धोखेबाज कहने वाले अपरिपक्वबुद्धि इसका नाम भी ठीक से न जानते होंगे, इसलिए किसी आवेग में आकर आप आपा न खोएं। राजनीति की क्षणभंगुर उठापटक को देखकर सनातन अवधारणाओं को लांछित न करें। श्रीराम और भगवती सीता की कल्पित कथाओं और तुकबंदियों के छल से मनुष्यता की राजधानी का अपमान न करें। इस बीच कुछ लोग अपनी कुंठाएं व्यक्त करने लगे हैं कि सही मुहूर्त में प्रतिष्ठा न होने का दुष्परिणाम है यह। ऐसी निराधार बातें केवल आपकी, अपितु रामत्व की मर्यादा के भी प्रतिकूल है। *सकृत प्रनामु किहें अपनाये...* वाली उदारकीर्ति वाले प्रभु को मुहुर्त से परिभाषित करने से बचें। आपकी यह 'सियासी वफादारी' न केंद्र की सरकार को पसंद आएगी और न राज्य सरकार को।

आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण, गुरु

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

नई शुरुआत नए अवसर प्रदान करती है

तीसरी बार मोदी सरकार

भारतीय लोकतंत्र की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे राष्ट्रपति भवन ने एक और इतिहास रचते देखा। इस इतिहास की रचना नरेन्द्र मोदी की ओर से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के रूप में हुई। यह देश ही नहीं दुनिया के लिए एक विलक्षण राजनीतिक घटना है, क्योंकि जहां देश में इसके पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वहीं दुनिया में बहुत कम शासनाध्यक्षों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, लेकिन इससे उनकी इस उपलब्धि की महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा बहुमत से कुछ ही दूर है। चूंकि सहयोगी दल मोदी सरकार को सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया इसलिए यह आशा की जाती है कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता से चलेगी। इसका एक कारण यह भी है कि उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा समन्वय की राजनीति करने का कौशल भी। उनकी राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने अनेक ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी-पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में।

पिछले दस वर्षों का उनका कार्यकाल यह बताता है कि वह एक ओर जहां देश में सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे वहीं विश्व पटल पर भी उन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इससे विश्व में भारत का मान बढ़ा और इसे उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल साहसिक फैसले लिए, बल्कि विकास और जनकल्याण के ऐसे कार्य किए जिसने देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। अब वह विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि गठबंधन सरकार के बावजूद कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है और उन्होंने यह कहा है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू ने भी अपनी संकल्पबद्धता जताई है इसलिए मोदी की पीएम के रूप में तीसरी पारी निरंतरता का परिचायक ही होगी। भले ही उनकी गारंटियां भाजपा को पूर्ण बहुमत न दिला पाई हों, लेकिन देश अभी भी एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता का कायल है। यह संभव है कि सहयोगी दल अपने राज्यों के साथ ही अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आग्रह करें, लेकिन यदि वे कोई अनुचित दबाव नहीं डालते तो इसमें कोई बाधा नहीं है और शासन संचालन की पीएम मोदी की जैसी कार्यशैली रही उससे यह सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि वह किसी भी तरह की दबाव की राजनीति में आने वाले नहीं हैं और उनके तीसरे कार्यकाल में देश जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

कड़ी कार्रवाई आवश्यक

पंजाब में कारोबारियों एवं व्यापारियों से रंगदारी मांगने की घटनाओं का न रुकना चिंताजनक है। कनाडा में छिपे आतंकी लखबीर सिंह की ओर से एक माह में बीस करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की बात सामने आना अत्यंत गंभीर मामला है। राज्य में गैंगस्टरों एवं आतंकियों की ओर से पहले भी रंगदारी मांगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ मामलों में तो शिकायत के बाद पुलिस की ओर से सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद गैंगस्टरों ने हत्या कर दी। कई बार तो लोग डर के कारण पुलिस को शिकायत भी नहीं करते हैं। तरनतारन में भी फोन करके कारोबारियों को धमकी दी जा रही है। फोन करने वाला जब लोगों के स्वजनों के नाम लेता है तो लोगों में दहशत पैदा होना स्वाभाविक है। चूंकि फोन करने वाला खुद को लखबीर बता रहा है, इसलिए कई लोग पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं। एक माह में रंगदारी मांगने की सोलह शिकायतों के मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि फोन करने वालों को पुलिस का कोई भय नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस का रवैया लापरवाही वाला है। कई बार तो पुलिस केस भी दर्ज नहीं करती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को यह देखना होगा कि ऐसे कौन से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इतने गंभीर मामलों में भी लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त होने के साथ ही दिखनी भी चाहिए। रंगदारी मांगने वालों पर नकेल कसना आवश्यक है।

कनाडा में छिपे आतंकी लखबीर सिंह की ओर से एक माह में बीस करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की बात सामने आना अत्यंत गंभीर मामला है

नई सरकार से अपेक्षाएं

विवेक देवराय

राजग के राज में निर्णायक फैसलों ने शासन को नया आयाम प्रदान किया है। ऐसे में यही उम्मीद है कि नए कार्यकाल में भी सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा

आदित्य सिन्हा

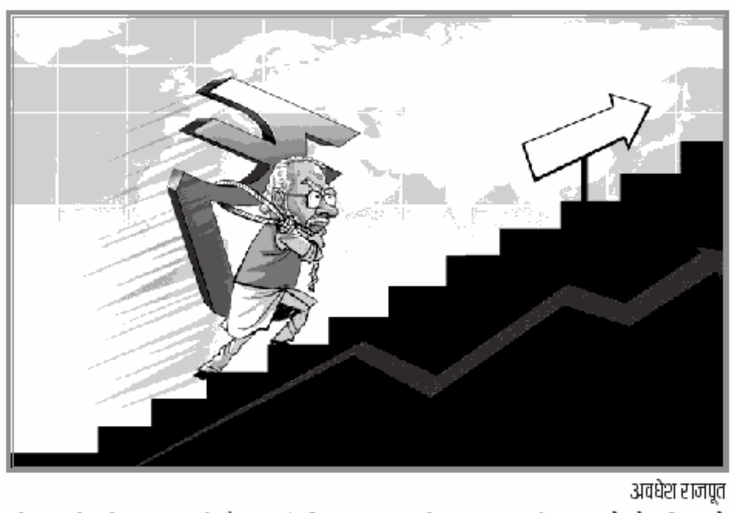

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की सरकार ने कमान संभल ली है। संप्रग सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में गठबंधन की राजनीति के दौरान शासन कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया था, लेकिन राजग के राज में आर्थिक सुधारों से लेकर निर्णायक फैसलों ने शासन को नया आयाम प्रदान किया है। उसे मिला बहुमत भी इसकी स्वीकृति है। ऐसे में, राजग के नए कार्यकाल से भी यही अपेक्षाएं हैं कि सुधारों का सिलसिला पूर्व की भांति रफ्तार पकड़ेगा। श्रम और भूमि अधिग्रहण जैसे क्षेत्र अभी भी सुधारों की प्रतीक्षा में हैं, जो निवेश को लुभाने और अनुकूल कारोबारी परिवेश निर्मित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हालांकि सुधारों के कई मामलों में गेंद राज्यों के पाले में होती है, लेकिन सक्षम केंद्र इस मामले में प्रभावी पहल करके उन्हें सिरे चढ़ाने में सहायक हो सकता है। भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि वह जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं को भुनाना चाहता है तो उसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना होगा। इसके लिए शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना बहुत आवश्यक होगा। नई सरकार को अविलंब अपनी प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ना होगा।

सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। यह राजस्व व्यय की तुलना में आर्थिक वृद्धि को ज्यादा गति देता है। बीते कुछ बजट इस तथ्य की पुष्टि करने वाले रहे हैं। इसलिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह और जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। ये क्षेत्र संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची के विषय हैं। इनसे न केवल आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ती हैं, बल्कि दीर्घकालिक विकास लक्ष्य भी सुनिश्चित होते हैं। इसमें उन परियोजनाओं को वरीयता देनी होगी, जिन्हें केंद्र सरकार सीधे लागू करने की स्थिति में हो। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय भी बनाना होगा, जिनके चलते अक्सर परियोजनाएं लटक जाती हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश की व्यापक संभावनाओं को भुनाने के लिए नई सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधारों को मूर्त रूप देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी। यह सरकार राज्यों को वह नीति जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रेरित करे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि केवल स्कूली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहां शिक्षा के अधिकार कानून ने पढ़ाई-लिखाई तक बच्चों की पहुंच बेहतर बनाई है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी एनएएस के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में विभिन्न राज्यों के स्तर पर विसंगतियां देखने को मिली हैं। एनएएस 2021 के अनुसार चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में छात्र गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ रहे हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से केंद्र से सहयोग लेकर प्रभावी समाधान में जुटना चाहिए। इस मुहिम में एनएएस के डाटा का उपयोग कर लक्षित हस्तक्षेप किया जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता मिले और शैक्षणिक प्रक्रिया में अभिभावकों एवं सामुदायिक सक्रियता बढ़ाई जाए। विभिन्न राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर पर बन रही खाई को पाटने और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये कदम अत्यंत आवश्यक हो गए हैं।

शोध एवं विकास (आरएंडडी) इकोसिस्टम और शोध-अनुसंधान एवं नवाचार के स्तर पर भारत चुनौतियों से जूझता आया है। ऐसे में नई सरकार को इस मोर्चे पर ध्यान देना होगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रतिशत से कम संस्था ही गुणवत्तापरक शोध में संलग्न हैं। इससे देश में शोध से जुड़ी क्षमताएं पूरी तरह आकार नहीं ले पा रही हैं। इन संस्थानों में वित्तीय संसाधनों का अभाव और कुछ अवरोधक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत में आरएंडडी व्यय भी जीडीपी के अनुपात में बहुत मामूली है। इस मामले में वह चीन एवं अमेरिका जैसे नवाचार में अग्रणी देशों से काफी पीछे है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय सुधारों ने आइआइटी, आइआइएसईआर और आइआइएस जैसे संस्थानों के लिए संसाधनों की उपलब्धता और उनके नीतिगत लचीलेपन को प्रभावित किया है।

राजस्व बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार को कर का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रियायतों को सीमित किया जाए और अनुपालन आसान बनाएं ताकि कर संग्रह में और उछाल आए। कारपोरेट इनकम टैक्स और निजी आयकर के स्तर पर व्यापक सुधारों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है। सुगम कर ढांचा और रियायतों की सीमा अनुपालन लागत एवं मुकदमेबाजी घटाने में मददगार बनेगी। प्रत्यक्ष करों में सुधार के तहत नए कर ढांचे में सभी रियायतों को समाप्त कर टैक्स की दरें घटाई जाएं। अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल कर जीएसटी का दायरा बढ़ाने के साथ ही उसकी दरें तार्किक करें, जिससे सक्षमता बढ़ने के साथ ही राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा। जीएसटी परिषद को नियमित तौर पर विमर्श के माध्यम से इन सुधारों को मूर्त रूप देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि यह तंत्र उभरती आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

हालांकि सुधारों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन यदि सरकार इन क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करे तो काफी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इससे सतत एवं तेज आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय स्थायित्व की स्थिति बनेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहकर नई उपलब्धियां हासिल करता रहेगा।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

कसमसाती अयोध्या की बेचैनी

अयोध्या ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। भले ही यह प्रसंग राजनीतिक हो, परंतु इसकी प्रतिध्वनि अनेक आयामों में व्याप्त हुई है। इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या (फैजाबाद) के भाजपा प्रत्याशी की पराजय विशेष उभरकर सामने आई है। विभिन्न प्रकार के वाद-प्रतिवादों के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या के लिए किए गए कामों और उनके चुनावी लाभ का भी आकलन किया जा रहा है। यद्यपि इस बार चुनाव परिणामों की हानि व्यापक है, पर अयोध्या का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। यहां भाजपा प्रत्याशी की हार को कई रूपों में देखा जा रहा है। यह हार नैतिक नहीं, रणनीतिक और प्रायः कूटनीतिक भी है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को पांच लाख मत मिले हैं और अयोध्या विधानसभा से सर्वाधिक मत भी मिले हैं। बावजूद इसके वह चुनाव में विजेता नहीं बन सके। उनकी पराजय ने प्रचलित हिंदू भावना को आहत किया है। कुछ लोग भांति-भांति के तर्कों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन न देने वाली जनता को कोस रहे हैं, पर यह तर्कसंगत नहीं है। मतदाताओं को अपनी रुचि के अनुसार मतदान का अधिकार है, लेकिन इस प्रसंग पर इतनी प्रतिक्रिया भर ही काफी नहीं है। इंटरनेट मीडिया का कोलाहल शीघ्र ही शांत हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक प्रश्न, जो कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण होगा।

लोकतंत्र की राजनीति प्रतीकों से जिंदा रहती है। बहुमत की कामना अधिकांश जन को आकृष्ट और सहमत करने की चेष्टा करती है। इस चेष्टा में बृहत्तर प्रतीकों को चुना जाता है। भाजपा ने धर्मविग्रह श्रीराम का नाम, उनका धाम और उनकी जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को नारा बनाया। जिसने पीढ़ियों की पीड़ा, प्रयत्न और प्रार्थनाओं को मानो स्वर दे दिया। श्रीराम का नाम सभी प्रकार की चारित्रिक जातीय अस्मिताओं के पार तक व्याप्त और प्रभावी है। पांच सौ वर्षों की आस्थापरक त्रासदी, सैकड़ों वर्षों से अधिक का संघर्ष, कई दशकों से अपनी एक थोपी हुई पहचान में बंदिनी अयोध्या के जैसे दिन बहुरे। जो कल्पनातीत था, वह हुआ। श्रीरामजन्मभूमि पर श्रीरामलला विराजमान हुए। भाजपा ने अपनी घोषित प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए कीर्तिमान रच दिए, परंतु धर्म का वह प्रतीक संक्रमित होने लगा। नेताओं के चेहरे श्रीराम से बड़े प्रतीक के रूप में उभरने लगे। अयोध्या का इतिहास तिरोहित होने लगा। श्रीराम की आध्यात्मिक अयोध्या पर भारी बजट वाली एक और चमकदार अयोध्या मढ़ी जाने लगी। भूमि, राजस्व, बाजार, निवेश और विकास जैसी शब्दावली से भरी हुई एक दूसरी रामायण लिखी जाने लगी। इसमें अयोध्या की उपासना, मंदिरों के अनुशासन, अयोध्यावासियों की प्रकृति और बैरागियों की सराय कही जाने वाली इस नगरी की सुगंध बेमानी हो चली। एक नई अयोध्या बसने लगी, एक बसी हुई अयोध्या विस्थापित होने लगी। सड़कें, होटल, बाजार, यात्री-सुविधाएं और पर्यटन के सापेक्ष बसती हुई अयोध्या से इसकी पुराकथाओं के चरित्र विस्थापित होने लगे। इस नई और चमकदार अयोध्या के तर्क इतने धारदार और दावे इतने प्रबल हैं कि विस्थापित होती अयोध्या निःशब्द हो रही। कुछ लोग दौड़े-चिल्लाए, पर लाभार्थी, लोभार्थी कहकर उनको तात्कालिक-अंतरिम समाधान दे दिया गया। यह एक प्राचीन पुरी के चरित्र बदलने जैसी बात है। राष्ट्रीय फलक पर इस चमकती हुई अयोध्या का प्रकाश तो गया, परंतु कसमसाती हुई अयोध्या की बेचैनी नहीं जा सकी। जब किसी ने इस बेचैनी को स्वर देना भी चाहा तो सरकार से पहले उसके समर्थकों ने ही उसे चुप करा दिया।

आचार्य मिथिलेशनंदिनीशरण

यदि श्रीराम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिनेगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी

अयोध्या की पारंपरिक पहचान पर संकट। फाइल

यह कहना नासमझी होगी कि भाजपा के नीति-नियामक इस स्थिति से अवगत नहीं, परंतु राजनीतिक बढ़त की लहर में यह मुद्दा उनके लिए नगण्य हो गया। स्थानीय विपक्ष ने अयोध्या के इस यथार्थ का उपयोग किया। उसने भय और आशंकाओं को अपना शस्त्र बनाया, जिसका सार्थक प्रतिवाद भाजपा संगठन नहीं कर सका। ऐसा नहीं कि उनके पास सही उत्तर न रहे हों, वे वस्तुतः इसको लेकर पर्याप्त गंभीर ही नहीं हुए। यह देखना भी रोचक होगा कि सामान्य चुनाव की इस योजना में जहां प्रति व्यक्ति मतदान का आग्रह होता है, वहां स्थानीय प्रचार भी प्रतीकात्मक हो गए, जिन्हें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की यात्राओं से संपन्न मान लिया गया। यह वह छिद्र है जिससे अनर्थ बहुलता तक पहुंच गया। आज जब समय ने सोचने के लिए बाध्य किया है तो सारी बातें समझे जाने की अपेक्षा है।

यह समझना होगा कि अयोध्या ने भाजपा प्रत्याशी को नहीं हराया। वस्तुतः अत्यधिक आत्मविश्वास या सांगठनिक कार्ययोजना में प्रमाद के कारण वह अपनी जीत को हस्तगत नहीं कर सके। यही वह मूल बिंदु है, जिस पर ध्यान जाने से भाजपा को पराजय के सूत्र मिल सकते हैं। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को संदिग्ध मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदाधिकारियों का पूरा समूह अयोध्या के चुनाव को संभालने में लगा था तो क्या कारण था कि लोकसभा के लिए वैसे प्रयत्न नहीं किए जा सके। जो अंतर्विरोध और चुनौतियां सामान्य जन को दिख रही थीं, उनको लेकर संगठन उदासीन कैसे रहा? आज परिणाम देखकर बचाव के तर्क खोजने के स्थान पर यदि सही समीक्षा का दायित्व लिया जाए तो कल्याण का मार्ग मिल सकता है। यह दोहराने में कोई संकोच नहीं कि भाजपा संगठन और मोदी-योगी की जोड़ी ने अयोध्या के लिए जो किया वह अपूर्व है, परंतु इस अपूर्व को करने में जो व्यावहारिक त्रुटियां हैं उनकी उपेक्षा के स्थान पर उनका समाधान करना ही चाहिए। यदि किसी भी शासनकाल में श्रीराम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिन जाएगी तो उसका कोई भी विकास सराहनीय नहीं होगा।

(लेखक सिद्धपीठ, श्रीहनुमन्निवास अयोध्या के महंत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आरोह-अवरोह

आरोह-अवरोह का शाब्दिक अर्थ है-ऊपर जाना-नीचे उतरना। ये शब्द प्रायः संगीत विधा से जुड़े हुए जाने जाते हैं। संगीत की समस्त राग-रागिनियां इन्हीं पर निर्भर हैं। जीवन में उतार-चढ़ाव आना भी स्वाभाविक है। यहां तक कि जब दो क्षण एक से नहीं होते तो जीवन में भी पल-पल आरोह-अवरोह स्वाभाविक है। जिस प्रकार संगीत के आरोह-अवरोह एक सुंदर राग की रचना करते हैं, हम भी अपने कर्मों एवं विचारों के उतार यानी दुख एवं चढ़ाव यानी सुख को एक साथ बुनकर हर परिस्थिति में समभाव रखते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करें।

परिवार में लोगों को एक-दूसरे से अपेक्षाएं भी निश्चित तौर पर होती ही हैं। उनके पूर्ण न होने पर जीवन में हताशा और पीड़ा आने में देर नहीं लगती। जो लोग जीवन की विपरीत परिस्थितियों को चुनौती मान आगे बढ़ते जाते हैं वे एक दिन सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग दुख-सुख के आरोह-अवरोह को झेलते हुए भी अपने निर्धारित कार्य देर-सबेर करते रहते हैं।

जीवन यात्रा में राग-लय-ताल का मिश्रण हममें आत्मविश्वास जगाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास अतिआवश्यक है। राग भैरवी की गंभीरता, राग बसंत की चंचलता और राग दीपक की ऊष्मता अपने सधे हुए आरोह-अवरोह से मानव मन में सुंदर भाव पैदा करती हैं। इनका समय भी निश्चित है। इसी तरह हमें यह समझ लेना चाहिए कि सुख-दुख का आना-जाना भी निश्चित है। इन्हें तय समय पर होना ही है, लेकिन यह भी सच है कि जब जीवन की नैया दुखों से डगमगाती है, फिर ईश्वर ही एकमात्र आसरा रह जाता है। बेसुरे आरोह-अवरोह को व्यवस्थित कर ताल से ताल मिलाकर एक नया सुर छेड़ना ही तो जीवन है। आध्यात्मिक चिंतन को व्यवहार से जोड़ना समस्त सुख-दुख के आरोह-अवरोह को अपने अनुरूप ढालने का एकमात्र तरीका है।

छाया श्रीवास्तव

दागी नेताओं की बढ़ती संख्या

देवेंद्रराज सुथार

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इस बार 543 नवनिर्वाचित सांसदों में से 46 प्रतिशत यानी 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2019 में आपराधिक मामलों वाले 233 (43 प्रतिशत) सांसद लोकसभा पहुंचे थे। राजनीति में दागी नेताओं का दबदबा गंभीर चिंता का विषय है, जो लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव को खतरे में डालता है।

दागी नेताओं के चुनाव में कई कारक योगदान करते हैं। भारतीय राजनीति में धन और बाहुबल की भूमिका एक प्रमुख कारक है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास काफी वित्तीय संसाधन और प्रभाव होता है, जिसका वे वोट जीतने के लिए लाभ उठाते हैं। किसी भी कीमत पर जीतने की इच्छा से प्रेरित राजनीतिक दल अक्सर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं, यह मानते हुए कि उनके संसाधन और प्रभाव जीत सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य कारक मतदाता जागरूकता और शिक्षा की कमी है। कई मतदाता या तो उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड से अनजान हैं या उनके प्रति उदासीन हैं। कुछ मामलों में मतदाता जाति, धर्म या क्षेत्रीय संबद्धता के कारण दागी उम्मीदवारों का समर्थन भी करते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये उम्मीदवार अपने साफ-सुथरे समकक्षों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से विकास की गंगा बहा देंगे?

राजनीति में दागी नेताओं का दबदबा गंभीर चिंता का विषय है, जो लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव को खतरे में डालता है

दागी सांसदों की बढ़ती संख्या चुनाव सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त कानून होने चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि गंभीर अपराधों के आरोपों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जा सके। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड के प्रकटीकरण में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। मतदाताओं के लिए सुलभ और समझने योग्य प्रारूप में ऐसी जानकारी का अनिवार्य प्रकाशन होना चाहिए। राजनीतिक दलों को दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसमें उन पार्टियों को दंडित किया जाना चाहिए, जो गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को नामांकित करती हैं। इसके लिए न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। साफ छवि वाले उम्मीदवारों को चुनने के महत्व के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने और राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहराने में समाज और मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भाजपा का अति आत्मविश्वास

'अपनी गलतियों से भी मात खाई भाजपा ने' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण किया है। भाजपा के अति आत्मविश्वास और विपक्षियों के रणनीतिक प्रयास ने चुनाव परिणामों को पूरी तरह प्रभावित किया है। एक तरफ जहां भाजपा ने जनता को प्रभावित करने के लिए कोई भी लालच नहीं दिया तो विपक्षी नेताओं ने उसे ही अपना मुख्य हथियार बना लिया। इसके साथ ही वह इस भ्रम को फैलाने में पूरी तरह कामयाब रहा कि यदि भाजपा 400 सीटें जीत गई तो वह संविधान को बदल देगी और एससी, एसटी तथा ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देगी। जिसकी कोई सटीक काट सत्तारूढ़ दल कर पाने में असफल रहा। भाजपा के पुराने सांसदों से लोग बुरी तरह नाराज थे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने इस वास्तविकता को अनदेखा किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि मोदी लहर के आगे सारी नाराजगियां घुटने टेक देंगी, पर ऐसा नहीं हो सका। यह प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा ही है, जो भाजपा इतनी सीटें जीतने में कामयाब हो सकी है कि वह सत्तारूढ़ होने जा रही है। भविष्य में यदि भाजपा शीर्ष नेतृत्व तुरंत सक्रिय नहीं हुआ तो इसका खामियाजा उसे अगले विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

आडवाणी की अवहेलना नहीं

विपक्षी दल भाजपा पर अपने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अवहेलना कर उन्हें अपमानित करने का निराधार आरोप लगाते हैं। उनका आरोप है कि 2014 में एनडीए की जीत के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और उन्हें राष्ट्रपति भी नहीं बनाया। 2009 में भाजपा विजयी होती तो निश्चय ही आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनते, पर उस वर्ष यूपीए-2 की वापसी हो गई। 2014 में आडवाणी 86 वर्ष के हो चुके थे। चुनाव प्रचार हेतु एवं इतने ऊंचे पद के लिए अत्यधिक ऊर्जा एवं सक्रियता की आवश्यकता होती है। तब भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेन्द्र मोदी को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जिनकी प्रशासनिक क्षमता मुख्यमंत्री के रूप में सिद्ध हो चुकी थी। 2017 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय आडवाणी 90 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। कार्यकाल 95 वर्ष की आयु तक चलता। राष्ट्रपति को सेना का प्रमुख होने के साथ अनेक दायित्वों का निर्वहन करना होता है, उनकी आयु इसमें बाधक होती। राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उन्हें ''भारत रत्न'' से अलंकृत किया गया है। वह अभी भी भाजपा के ''मार्गदर्शक'' मंडल के सदस्य हैं।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

भाजपा की गलती

'अपनी गलतियों से भी मात खाई भाजपा ने' शीर्षक आलेख में लोकसभा चुनावों में भाजपा को कम सीट मिलने से एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह पार्टी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से भटक गई है? संजय गुप्त का यह विश्लेषण न केवल घटनाओं का मूल्यांकन है, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य का गहन आत्मावलोकन भी है। पहले पहल, भाजपा की स्थिति का प्रमुख कारण आंतरिक कलह और गुटबाजी को माना जा सकता है। 'अपनी करनी का फल' कहावत यहां पूरी तरह से सार्थक प्रतीत होती है। जब पार्टी के अपने ही सदस्य एक-दूसरे की टांग खींचने में लगे हों, तो जनता का विश्वास कैसे बना रह सकता है? भाजपा के लिए यह समय है कि वह अपनी आंतरिक संरचना को दुरुस्त करे और एकजुटता का परिचय दे। इसके अलावा, जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ी। नींव कमजोर हो तो इमारत कब तक टिकेगी? इस विचारधारा पर ध्यान देते हुए पार्टी ने केवल अपने बड़े नेताओं के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की, जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को नकारा गया। यह वही कार्यकर्ता हैं जो जनता के बीच रहकर पार्टी के संदेश को पहुंचाते हैं। भाजपा को आत्मावलोकन करने की जरूरत है।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

नई शुरुआत नए अवसर प्रदान करती है

तीसरी बार मोदी सरकार

भारतीय लोकतंत्र की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे राष्ट्रपति भवन ने एक और इतिहास रचते देखा। इस इतिहास की रचना नरेन्द्र मोदी की ओर से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के रूप में हुई। यह देश ही नहीं दुनिया के लिए एक विलक्षण राजनीतिक घटना है, क्योंकि जहां देश में इसके पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वहीं दुनिया में बहुत कम शासनाध्यक्षों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं, लेकिन इससे उनकी इस उपलब्धि की महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा बहुमत से कुछ ही दूर है। चूंकि सहयोगी दल मोदी सरकार को सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया इसलिए यह आशा की जाती है कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता से चलेगी। इसका एक कारण यह भी है कि उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा समन्वय की राजनीति करने का कौशल भी। उनकी राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने अनेक ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी-पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में। पिछले दस वर्षों का उनका कार्यकाल यह बताता है कि वह एक ओर जहां देश में सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे वहीं विश्व पटल पर भी उन्होंने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। इससे विश्व में भारत का मान बढ़ा और इसे उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल साहसिक फैसले लिए, बल्कि विकास और जनकल्याण के ऐसे कार्य किए जिसने देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। अब वह विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि गठबंधन सरकार के बावजूद कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है और उन्होंने यह कहा है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू ने भी अपनी संकल्पबद्धता जताई है इसलिए मोदी की पीएम के रूप में तीसरी पारी निरंतरता का परिचायक ही होगी। भले ही उनकी गारंटियां भाजपा को पूर्ण बहुमत न दिला पाई हों, लेकिन देश अभी भी एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता का कायल है। यह संभव है कि सहयोगी दल अपने राज्यों के साथ ही अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आग्रह करें, लेकिन यदि वे कोई अनुचित दबाव नहीं डालते तो इसमें कोई बाधा नहीं है और शासन संचालन की पीएम मोदी की जैसी कार्यशैली रही उससे यह सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि वह किसी भी तरह की दबाव की राजनीति में आने वाले नहीं हैं और उनके तीसरे कार्यकाल में देश जनता की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

साइबर ठगी का संजाल

प्रदेश ही नहीं, देश में भी साइबर अपराध के मामले दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे खास हो या आम, हर दिन कोई न कोई इन साइबर अपराधियों का शिकार बन रहा। हर दिन हो रही साइबर ठगी को समेकित करें तो राशि लाखों-करोड़ों में पहुंच जाती है। लोगों की मेहनत की कमाई हथियाने को ये साइबर ठग किसी न किसी तरह का हथकंडा अपना लेते हैं। बड़ी बात यह कि शिकार होने वाला यह जान भी नहीं पाता कि जिसने साइबर ठगी की, वह असल में है कौन। ये अपराधी कहीं से बैठकर देश के किसी कोने में अपनी ठगी की मंशा सफल बना लेते हैं। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र के साथ राज्यों की पुलिस भी सतर्क हुई है। साइबर ठगों से निपटने के लिए बाकायदा विशेषज्ञों का सेल बनाया गया है। शिकायत के लिए टाल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। लोगों को साइबर ठगी से जागरूक करने के लिए इंटरनेट के अलावा अन्य प्रचार माध्यमों से सतर्कता के संदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन ये अपराधी ठगी के नित नए तरीके अपना रहे हैं। इसने तंत्र की परेशानी बढ़ा रखी है। देश में साइबर ठगी के मामलों के लिए झारखंड के जामताड़ा के बाद बिहार के दो जिले नालंदा व नवादा विख्यात हैं। प्रदेश में इन हाइटेक ठगों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर थाने खोले गए हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) मामलों की निगरानी करती है। साइबर ठगी के बाद खाते में राशि होल्ड कराने के मामले में बिहार देश में पांचवें स्थान पर है। साइबर ठगी के 24 घंटे के अंदर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराने के बाद औसत 30 प्रतिशत राशि को होल्ड कराया जा रहा है। ठगों से बचाए गए 49 करोड़ और नौ हजार मोबाइल सिम ब्लाक किए गए हैं। सिर्फ मई माह में 5.62 करोड़ की राशि होल्ड कराई गई है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइबर ठगी के मामलों की संख्या कितनी बढ़ गई है।

साइबर ठगों पर मजबूती से शिकंजा कसने के लिए तंत्र को तकनीकी रूप से और समृद्ध होने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना चाहिए?

आज का सवाल

क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को और सक्षम एवं जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक हो गया है?

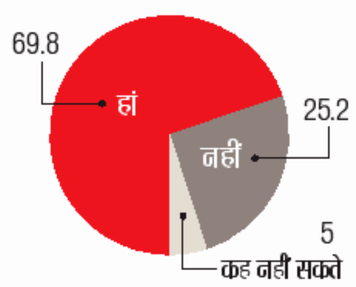

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

नई सरकार से अपेक्षाएं

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

राजग के राज में निर्णायक फैसलों ने शासन को नया आयाम प्रदान किया है। ऐसे में यही उम्मीद है कि नए कार्यकाल में भी सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की सरकार ने कमान संभल ली है। संप्रग सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में गठबंधन की राजनीति के दौरान शासन कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया था, लेकिन राजग के राज में आर्थिक सुधारों से लेकर निर्णायक फैसलों ने शासन को नया आयाम प्रदान किया है। उसे मिला बहुमत भी इसकी स्वीकृति है। ऐसे में, राजग के नए कार्यकाल से भी यही अपेक्षाएं हैं कि सुधारों का सिलसिला पूर्व की भांति रफ्तार पकड़ेगा। श्रम और भूमि अधिग्रहण जैसे क्षेत्र अभी भी सुधारों की प्रतीक्षा में हैं, जो निवेश को लुभाने और अनुकूल कारोबारी परिवेश निर्मित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हालांकि सुधारों के कई मामलों में गेंद राज्यों के पाले में होती है, लेकिन सक्षम केंद्र इस मामले में प्रभावी पहल करके उन्हें सिरे चढ़ाने में सहायक हो सकता है। भारत के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि वह जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाओं को भुनाना चाहता है तो उसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना होगा। इसके लिए शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना बहुत आवश्यक होगा। नई सरकार को अविलंब अपनी प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ना होगा।

सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। यह राजस्व व्यय की तुलना में आर्थिक वृद्धि को ज्यादा गति देता है। बीते कुछ बजट इस तथ्य की पुष्टि करने वाले रहे हैं। इसलिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह और जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। ये क्षेत्र संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची के विषय हैं। इनसे न केवल आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ती हैं, बल्कि दीर्घकालिक विकास लक्ष्य भी सुनिश्चित होते हैं। इसमें उन परियोजनाओं को वरीयता देनी होगी, जिन्हें केंद्र सरकार सीधे लागू करने की स्थिति में हो। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय भी बनाना होगा, जिनके चलते अक्सर परियोजनाएं लटक जाती हैं।

जनसांख्यिकीय लाभांश की व्यापक संभावनाओं को भुनाने के लिए नई सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधारों को मूर्त रूप देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी। यह सरकार राज्यों को वह नीति जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रेरित करे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि केवल स्कूली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहां शिक्षा

अवधेश राजपूत

के अधिकार कानून ने पढ़ाई-लिखाई तक बच्चों की पहुंच बेहतर बनाई है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी एनएएस के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में विभिन्न राज्यों के स्तर पर विसंगतियां देखने को मिली हैं। एनएएस 2021 के अनुसार चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में छात्र गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ रहे हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से केंद्र से सहयोग लेकर प्रभावी समाधान में जुटना चाहिए। इस मुहिम में एनएएस के डाटा का उपयोग कर लक्षित हस्तक्षेप किया जाए। अध्यापकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता मिले और शैक्षणिक प्रक्रिया में अभिभावकों एवं सामुदायिक सक्रियता बढ़ाई जाए। विभिन्न राज्यों के बीच शिक्षा के स्तर पर बन रही खाई को पाटने और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये कदम अत्यंत आवश्यक हो गए हैं।

शोध एवं विकास (आरएंडडी) इकोसिस्टम और शोध-अनुसंधान एवं नवाचार के स्तर पर भारत चुनौतियों से जूझता आया है। ऐसे में नई सरकार को इस मोर्चे पर ध्यान देना होगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रतिशत से कम संस्था ही गुणवत्तापरक शोध में संलग्न हैं। इससे देश में शोध से जुड़ी क्षमताएं पूरी तरह आकार नहीं ले पा रही हैं। इन संस्थानों में वित्तीय संसाधनों का अभाव और कुछ अवरोधक नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत में आरएंडडी व्यय भी जीडीपी के अनुपात में बहुत मामूली है। इस मामले में वह चीन एवं अमेरिका जैसे नवाचार में अग्रणी देशों से काफी पीछे है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय सुधारों ने आइआइटी, आइआइएसईआर और आइआइएस जैसे संस्थानों के लिए संसाधनों की उपलब्धता और उनके नीतिगत लचीलेपन को प्रभावित किया है।

राजस्व बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार को कर का दायरा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। रियायतों को सीमित किया जाए और अनुपालन आसान बनाएं ताकि कर संग्रह में और उछाल आए। कारपोरेट इनकम टैक्स और निजी आयकर के स्तर पर व्यापक सुधारों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है। सुगम कर ढांचा और रियायतों की सीमा अनुपालन लागत एवं मुकदमेबाजी घटाने में मददगार बनेगी। प्रत्यक्ष करों में सुधार के तहत नए कर ढांचे में सभी रियायतों को समाप्त कर टैक्स की दरें घटाई जाएं। अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल कर जीएसटी का दायरा बढ़ाने के साथ ही उसकी दरें तार्किक करें, जिससे सक्षमता बढ़ने के साथ ही राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा। जीएसटी परिषद को नियमित तौर पर विमर्श के माध्यम से इन सुधारों को मूर्त रूप देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि यह तंत्र उभरती आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

हालांकि सुधारों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन यदि सरकार इन क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करे तो काफी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इससे सतत एवं तेज आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय स्थायित्व की स्थिति बनेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहकर नई उपलब्धियां हासिल करता रहेगा।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

कसमसाती अयोध्या की बेचैनी

आचार्य मिथिलेशनंदिनीशरण

यदि श्रीराम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिनेगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी

अयोध्या ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। भले ही यह प्रसंग राजनीतिक हो, परंतु इसकी प्रतिध्वनि अनेक आयामों में व्याप्त हुई है। इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या (फैजाबाद) के भाजपा प्रत्याशी की पराजय विशेष उभरकर सामने आई है। विभिन्न प्रकार के वाद-प्रतिवादों के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या के लिए किए गए कामों और उनके चुनावी लाभ का भी आकलन किया जा रहा है। यद्यपि इस बार चुनाव परिणामों की हानि व्यापक है, पर अयोध्या का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। इसीलिए यहां भाजपा प्रत्याशी की हार को कई रूपों में देखा जा रहा है। यह हार नैतिक नहीं, रणनीतिक और प्रायः कूटनीतिक भी है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को लगभग पांच लाख मत मिले हैं और अयोध्या विधानसभा से सर्वाधिक मत भी मिले हैं। बावजूद इसके वह लोकसभा चुनाव में विजेता नहीं बन सके। उनकी पराजय ने प्रचलित हिंदू भावना को आहत किया है। कुछ लोग भांति-भांति के तर्कों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन न देने वाली जनता को कोस रहे हैं, पर यह तर्कसंगत नहीं है। मतदाताओं को अपनी रुचि के अनुसार मतदान का अधिकार है, लेकिन इस प्रसंग पर इतनी प्रतिक्रिया भर ही काफी नहीं है। इंटरनेट मीडिया का कोलाहल शीघ्र ही शांत हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक प्रश्न, जो कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण होगा।

लोकतंत्र की राजनीति प्रतीकों से जिंदा रहती है। बहुमत की कामना अधिकांश जन को आकृष्ट और सहमत करने की चेष्टा करती है। इस चेष्टा में बृहत्तर प्रतीकों को चुना जाता है। भाजपा ने धर्मविग्रह श्रीराम का नाम, उनका धाम और उनकी जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को नारा बनाया। यह एक असाधारण प्रयोग था जिसने पीढ़ियों की पीड़ा, प्रयत्न और प्रार्थनाओं को मानो स्वर दे दिया। श्रीराम का नाम सभी प्रकार की चारित्रिक जातीय अस्मिताओं के पार तक व्याप्त और प्रभावी है। पांच सौ वर्षों की आस्थापरक त्रासदी, सैकड़ों वर्षों से अधिक का संघर्ष, कई दशकों से अपनी एक थोपी हुई पहचान में बंदिनी अयोध्या के जैसे दिन बहुरे। जो कल्पनातीत था, वह हुआ। श्रीरामजन्मभूमि पर श्रीरामलला विराजमान हुए। देश उत्सवमय हो गया। भाजपा ने अपनी घोषित प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए कीर्तिमान रच दिए, परंतु धर्म का वह प्रतीक संक्रमित होने लगा। नेताओं के चेहरे श्रीराम से

अयोध्या की पारंपरिक पहचान पर संकट ● फाइल

बड़े प्रतीक के रूप में उभरने लगे। अयोध्या का इतिहास तिरोहित होने लगा। श्रीराम की आध्यात्मिक अयोध्या पर भारी बजट वाली एक और चमकदार अयोध्या मढ़ी जाने लगी। भूमि, राजस्व, बाजार, निवेश और विकास जैसी शब्दावली से भरी हुई एक दूसरी रामायण लिखी जाने लगी। इसमें अयोध्या की उपासना, मंदिरों के अनुशासन, अयोध्यावासियों की प्रकृति और बैरागियों की सराय कही जाने वाली इस नगरी की सुगंध बेमानी हो चली। एक नई अयोध्या बसने लगी, एक बसी हुई अयोध्या विस्थापित होने लगी। सड़कें, होटल, बाजार, यात्री-सुविधाएं और पर्यटन के सापेक्ष बसती हुई अयोध्या से इसकी पुराकथाओं के चरित्र विस्थापित होने लगे। इस नई और चमकदार अयोध्या के तर्क इतने धारदार और दावे इतने प्रबल हैं कि विस्थापित होती अयोध्या निःशब्द हो रही। कुछ लोग दौड़े-चिल्लाए, पर लाभार्थी, लोभार्थी कहकर उनको तात्कालिक-अंतरिम समाधान दे दिया गया। यह एक प्राचीन पुरी के चरित्र बदलने जैसी बात है। राष्ट्रीय फलक पर इस चमकती हुई अयोध्या का प्रकाश तो गया, परंतु कसमसाती हुई अयोध्या की बेचैनी नहीं जा सकी। जब किसी ने इस बेचैनी को स्वर देना भी चाहा तो सरकार से पहले उसके समर्थकों ने ही उसे चुप करा दिया।

यह कहना नासमझी होगी कि भाजपा के नीति-नियामक इस स्थिति से अवगत नहीं, परंतु राजनीतिक बढ़त की लहर में यह मुद्दा उनके लिए नगण्य हो गया। स्थानीय विपक्ष ने अयोध्या के इस यथार्थ का उपयोग किया। उसने भय और आशंकाओं को अपना शस्त्र बनाया, जिसका सार्थक प्रतिवाद भाजपा संगठन नहीं कर सका। ऐसा नहीं कि उनके पास सही उत्तर न रहे हों, वे वस्तुतः इसको लेकर पर्याप्त गंभीर ही नहीं हुए। यह देखना भी रोचक होगा कि सामान्य चुनाव की इस योजना में जहां प्रति व्यक्ति मतदान का आग्रह होता है, वहां स्थानीय प्रचार भी प्रतीकात्मक हो गए, जिन्हें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की यात्राओं से संपन्न मान लिया गया। यह वह छिद्र है जिससे अनर्थ बहुलता तक पहुंच गया। आज जब समय ने सोचने के लिए बाध्य किया है तो सारी बातें समझे जाने की अपेक्षा है।

यह समझना होगा कि अयोध्या ने भाजपा प्रत्याशी को नहीं हराया। वस्तुतः अत्यधिक आत्मविश्वास या सांगठनिक कार्ययोजना में प्रमाद के कारण वह अपनी जीत को हस्तगत नहीं कर सके। यही वह मूल बिंदु है, जिस पर ध्यान जाने से भाजपा को पराजय के सूत्र मिल सकते हैं। इस बात को एक और प्रमाण से समझा जा सकता है कि गत विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत को संदिग्ध मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदाधिकारियों का पूरा समूह अयोध्या के चुनाव को संभालने में लगा था तो क्या कारण था कि लोकसभा के लिए वैसे प्रयत्न नहीं किए जा सके। जो अंतर्विरोध और चुनौतियां सामान्य जन को दिख रही थीं, उनको लेकर संगठन उदासीन कैसे रहा? आज परिणाम देखकर बचाव के तर्क खोजने के स्थान पर यदि सही समीक्षा का दायित्व लिया जाए तो कल्याण का मार्ग मिल सकता है। यह दोहराने में कोई संकोच नहीं कि भाजपा संगठन और मोदी-योगी की जोड़ी ने अयोध्या के लिए जो किया वह अपूर्व है, परंतु इस अपूर्व को करने में जो व्यावहारिक त्रुटियां हैं उनकी उपेक्षा के स्थान पर उनका समाधान करना ही चाहिए। यदि किसी भी शासनकाल में श्रीराम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिन जाएगी तो उसका कोई भी विकास सराहनीय नहीं होगा।

(लेखक सिद्धपीठ, श्रीहनुमन्निवास अयोध्या के महंत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आरोह-अवरोह

आरोह-अवरोह का शाब्दिक अर्थ है-ऊपर जाना-नीचे उतरना। ये शब्द प्रायः संगीत विधा से जुड़े हुए जाने जाते हैं। संगीत की समस्त राग-रागिनियां इन्हीं पर निर्भर हैं। जीवन में उतार-चढ़ाव आना भी स्वाभाविक है। यहां तक कि जब दो क्षण एक से नहीं होते तो जीवन में भी पल-पल आरोह-अवरोह स्वाभाविक है। ऐसे में क्या ही अच्छा हो कि जिस प्रकार संगीत के आरोह-अवरोह एक सुंदर राग की रचना करते हैं, हम भी अपने कर्मों एवं विचारों के उतार यानी दुख एवं चढ़ाव यानी सुख को एक साथ बुनकर हर परिस्थिति में समभाव रखते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करें।

हालांकि यह सब कहना जितना सरल है, कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। परिवार में सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों को एक-दूसरे से अपेक्षाएं भी निश्चित तौर पर होती ही हैं। उनके पूर्ण न होने पर जीवन में हताशा और पीड़ा आने में देर नहीं लगती। जो लोग जीवन की विपरीत परिस्थितियों को चुनौती मान आगे बढ़ते जाते हैं वे एक दिन सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग दुख-सुख के आरोह-अवरोह को झेलते हुए भी अपने निर्धारित कार्य देर-सबेर करते रहते हैं।

दरअसल जीवन यात्रा में राग-लय-ताल का मिश्रण हममें आत्मविश्वास जगाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास अतिआवश्यक है। राग भैरवी की गंभीरता, राग बसंत की चंचलता और राग दीपक की ऊष्मता अपने सधे हुए आरोह-अवरोह से मानव मन में सुंदर भाव पैदा करती हैं। इनका समय भी निश्चित है। इसी तरह हमें यह समझ लेना चाहिए कि सुख-दुख का आना-जाना भी निश्चित है। इन्हें तय समय पर होना ही है, लेकिन यह भी सच है कि जब जीवन की नैया दुखों से डगमगाती है, फिर ईश्वर ही एकमात्र आसरा रह जाता है। बेसुरे आरोह-अवरोह को व्यवस्थित कर ताल से ताल मिलाकर एक नया सुर छेड़ना ही तो जीवन है। आध्यात्मिक चिंतन को व्यवहार से जोड़ना समस्त सुख-दुख के आरोह-अवरोह को अपने अनुरूप ढालने का एकमात्र तरीका है।

छाया श्रीवास्तव

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

भाजपा का अति आत्मविश्वास

'अपनी गलतियों से भी मात खाई भाजपा ने' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण किया है। भाजपा के अति आत्मविश्वास और विपक्षियों के रणनीतिक प्रयास ने चुनाव परिणामों को पूरी तरह प्रभावित किया है। एक तरफ जहां भाजपा ने जनता को प्रभावित करने के लिए कोई भी लालच नहीं दिया तो विपक्षी नेताओं ने उसे ही अपना मुख्य हथियार बना लिया। इसके साथ ही वह इस भ्रम को फैलाने में पूरी तरह कामयाब रहा कि यदि भाजपा 400 सीटें जीत गई तो वह संविधान को बदल देगी और एससी, एसटी तथा ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देगी। जिसकी कोई सटीक काट सत्तारूढ़ दल कर पाने में असफल रहा। भाजपा के पुराने सांसदों से लोग बुरी तरह नाराज थे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने इस वास्तविकता को अनदेखा किया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि मोदी लहर के आगे सारी नाराजगियां घुटने टेक देंगी, पर ऐसा नहीं हो सका। यह प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा ही है, जो भाजपा इतनी सीटें जीतने में कामयाब हो सकी है कि वह सत्तारूढ़ होने जा रही है। भविष्य में यदि भाजपा शीर्ष नेतृत्व तुरंत सक्रिय नहीं हुआ तो इसका खामियाजा उसे अगले विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

भाजपा के पास नहीं था राष्ट्रीय मुद्दा

'अपनी ग़लती से भी मात खाई भाजपा' शीर्षक आलेख में संजय गुप्त ने उचित लिखा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे को हासिल करने के लिए पार्टी के पास कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, जो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। यह सही है कि मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर वोट किया, जिसे भांपने में भाजपा गच्चा खा गई। चुनाव में लग रहा था कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर बनने के बाद भाजपा की जीत आसान होगी, परंतु हुआ उल्टा। फैजाबाद (अयोध्या) संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की हुई जीत से भाजपा स्तब्ध है, कि ऐसे कैसे हो गया। आरोप है कि यूपी के अधिकांश संसदीय सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों से 'लाभ' प्राप्त कर कुछ कार्यकर्ता भीतरघात कर दिए। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी में उम्मीदवारों की छंटनी में कोई मेहनत नहीं की गई। अधिकांश उमीदवार इस भ्रम में रहे कि उन्हें मोदी मैजिक एवं श्रीराम मंदिर के नाम पर वोट अवश्य मिलेंगे। जानकार बताते हैं कि ऐसा होता भी, परंतु आइएनडीआइए की ओर से महिलाओं के खाते में 8500 प्रत्येक माह खटाखट भेजने की घोषणा घर-घर पहुंचा दी गई, इसने महिलाओं को आकर्षित किया। विपक्ष द्वारा प्रत्येक चरण के मतदान के बाद स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार किया गया कि भाजपा हार रही है, जिसका जवाब भाजपा की ओर से मजबूती से नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अकेले दो सौ से अधिक रैलियों को संबोधित किया। पार्टी के सभी के सभी प्रत्याशी मोदी पर आश्रित थे। अन्य प्रचारक पार्टी के लिए वैसे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए, जिनके प्रति लोगों के बीच में आकर्षण पैदा हो। भविष्य में भाजपा के हर नेता को मोदी बनना होगा, तभी दुष्प्रचार करने वालों को समय पर करारा जवाब दिया जा सकता है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

मोदी की कार्यशैली हो सकती प्रभावित

केंद्रीय मंत्रिमंडल का रविवार को गठन हो गया। नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड की बराबरी कर ली। इस बार भाजपा का पूर्ण बहुमत में नहीं आना, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कार्य शैली को प्रभावित कर सकता है। अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण जैसे कार्य नहीं कर सकेंगे। इनके साथ टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार की राजनीति के चाणक्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दोनों नेता अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए अपनी-अपनी मांगें मनवा सकते हैं। तीसरे कार्यकाल में मोदी को सहयोगी दलों के साथ मिलकर चलना होगा। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का संबंध लेकर चलना होगा। दो कार्यकाल 2014 एवं 2019 की अपेक्षा इस बार विपक्ष भी मजबूत हुआ है। सरकार चलाने में विपक्ष का साथ भी होना जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधारनी होगी। रोजगारोन्मुखी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा देकर रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है। बिहार के शिक्षकों की भी नई सरकार से काफी अपेक्षा है कि दो केंद्रीय विश्वविद्यालय, दो नए एम्स हास्पिटल खुले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने का कार्य कर सकते हैं। आशा है, इस बार नरेन्द्र मोदी की सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का कार्य करेगी।

डा. किशोर कुमार पासवान, एएनएम कालेज, गया

पोस्ट

एनटीए ने छात्रों का जीवन दूभर कर दिया है। तमाम युवाओं को एनटीए से कई शिकायतें हैं। यदि एनटीए सुधर नहीं सकता तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए। हमारे समय में परीक्षा देना इससे आसान था और तब आज से कम विवाद होता था।

रंगनाथ सिंह @rangnathsingh_

एक मजबूत मीडिया सलाहकार, नियमित प्रेस ब्रीफिंग और दमदार वकीलों की टीम के अभाव में भाजपा नैरेटिव के मोर्चे पर हमेशा पिछड़ी रहेगी।

मिन्हाज मर्चेंट @MinhazMerchant

शेयर बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी से यही पूछना है कि झूठी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी तो करोड़ों भारतीयों को भारी नुकसान हुआ था। तब उस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस किसके लिए काम कर रही थी।

संगीत कुमार रागी @RagiSangit

भारत का नेतृत्व करने के लिए एक और कार्यकाल हासिल करने के लिए नरेन्द्र मोदी को बहुत-बहुत बधाई। मैं जब भी भारत आता हूं तो देश बेहतर से बेहतर होता जाता है। क्या शानदार काम है, सर। नई पारी के लिए ढेर सारी शुभकामना।

केविन पीटरसन @KP24

जनपथ

मोदी जी ने रच दिया आखिर वह इतिहास,
देश लगाए था खड़ा जिसकी खातिर आस।
जिसकी खातिर आस रास ये जिसे न आए,
वो अपने घर बैठ अश्रु की धार बहाए!
कांग्रेस ने साख स्वयं है अपनी खो दी,
बंधु तभी हर बार चुन रही जनता मोदी!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 59

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ सोमवार, 10 जून 2024

जीत से कोई भी समझौता कर सकता है। पराजय को शक्तिशाली लोग ही सहन कर पाते हैं। -एडोल्फ हिटलर

नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री की शपथ का इतिहास बनाने वाले नरेंद्र मोदी की ताजा सरकार का चेहरा जाना-पहचाना है। चूंकि यह साझा सरकार है, इसलिए साथी दलों का प्रतिनिधित्व एक संतुलन की झलक देता है।

शुरू हुई तीसरी पारी

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता में वापसी का पहला प्रतीकात्मक महत्व यह है कि इसके मुखिया नरेंद्र मोदी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का इतिहास रच रहे हैं। लेकिन, सबसे बड़े घटक होने के बावजूद साझे की सरकार बनाने का मौका हो, तो आशंकाएं और अनुमान अपनी गति से चलने लगते हैं। रविवार शाम जब शपथ के बाद सरकार का चेहरा सामने आया, तो उसने कई विपरीत अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। पिछली सरकार के सभी प्रमुख चेहरे इसमें मौजूद हैं और वरीयता के क्रम में भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्री और जुड़ गए हैं। जे पी नड्डा का बतौर भाजपा अध्यक्ष कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इसलिए उन्हें फिर कैबिनेट में जगह मिल गई है। संकेत हैं कि पार्टी के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा है, वहां के संकेत भी ताजा घटनक्रम में देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में अनुभव, वरिष्ठता, विशेषज्ञता, जातिगत, लैंगिक व क्षेत्रीय संतुलन और गठबंधन धर्म के बीच समन्वय साधने की सहज कोशिश की गई है। केरल में भाजपा को प्रवेश दिलाने वाले सुरेश गोपी का मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वाभाविक ही था, कर्नाटक के जद (एस) के एचडी कुमार स्वामी या बिहार के जीतन राम मांझी सहित सभी साथी दलों को उनकी जगह मिली है। यहां तक कि रामदास आठवले भी मौजूद हैं। प्रमुख सहयोगियों में तेलुगु देशम और जदयू की उपस्थिति स्पष्ट है। चिराग पासवान के साथ सबसे युवा राममोहन नायडू पूरी सूची को अलग रंगत देते हैं। दरअसल सारे कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि अंततः पहले जैसी ताकतवर सरकार अब कैसे संचालित की जाएगी? अजित पवार की एनसीपी की चर्चा से इस मसले को हवा देने की कोशिश हुई, लेकिन लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियों को संयोजित कर लिया गया है।

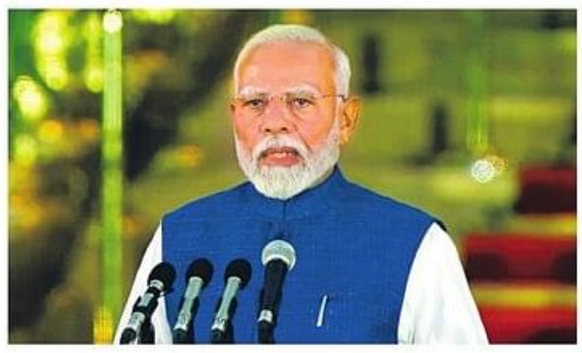

लोकसभा चुनावों में अगर तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राजग पर भरोसा जताया है, तो जाहिर है कि पांच साल सरकार चलाने की परीक्षा भी बड़ी है। ऐसे में, देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई सरकार अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ संतुलन साधते हुए किस तरह अपने घोषित विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ती है।

विकसित भारत की दिशा में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विकसित भारत' के जिस लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उसे प्राप्त करने के लिए राजग गठबंधन के सभी दलों में एक प्रतिबद्ध भाव जगाना भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखना यह है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत एवं उसकी राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है।

बद्री नारायण
राजनीतिक विश्लेषक

भारत के संसदीय चुनाव-2024 का परिणाम आ चुका है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे सामान्यतः राजग कहा जाता है, ने बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय जनतांत्रिक इतिहास में यह दूसरी घटना है। इसके पूर्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था।

चुनाव परिणामों पर काफी समीक्षा हो चुकी है। अब तक शायद ही किसी के पास कुछ नया कहने के लिए बचा हो। लेकिन इतना तो तय है कि यह चुनाव अनेक आश्चर्यों का चुनाव रहा। पहला आश्चर्य तो यह कि जिन दक्षिण भारतीय राज्यों का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सफलता के लिए बंद था, या यों कहें कि जहां की जमीन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए माकूल नहीं मानी जाती थी, इस चुनाव परिणाम ने उन राज्यों, यथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को भाजपा के लिए नई संभावनाओं का प्रदेश बना दिया है।

दूसरा आश्चर्य यह देखने में आया कि ओडिशा, जहां राजनीतिक विचारक बीजू जनता दल (बीजद) के नेता नवीन पटनायक के जादू को उनके जीवित रहने तक समाप्त होता नहीं देख रहे थे, वहां भाजपा ने अपनी महान सफलता दर्ज की। इसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति ओडिशा की जनता में बढ़ता आकर्षण ही है। प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के प्रभावी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे चुनाव अभियान में 'उड़िया अस्मिता' के प्रश्न को एक 'लोकप्रिय जन प्रश्न' में बदल दिया। इस लोकप्रिय अभियान ने ओडिशा की राजनीति के पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। इस चुनाव परिणाम ने यह भी बताया कि विकास का मोदी मॉडल, नवीन मॉडल पर प्रभावी रहा। ओडिशा के युवाओं में नए डिजिटल भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

तीसरा आश्चर्य यह रहा कि जहां उत्तर प्रदेश के आस-पास के हिंदी प्रदेशों, यथा मध्य प्रदेश, बिहार में भाजपा और राजग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं उत्तर प्रदेश में इसका प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा।

'इंडिया' गठबंधन ने आरक्षण, संविधान इत्यादि के खतरे पर आधारित जो वृत्तांत तैयार किया, उसने उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी की जमीन तैयार की। कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि यह ऐसी जातीय गोलबंदी की राजनीति थी, जिसने पिछड़े-अति पिछड़े एवं दलितों के एक हिस्से को समाजवादी पार्टी या 'इंडिया' गठबंधन की तरह गोलबंद होने का आधार तैयार किया। ऐसे विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार की जातीय गोलबंदी ने ही उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के वृहत वृत्तांत को तोड़कर जातियों के अस्मितापरक वृत्तांत को शक्तिवान बनाया।

अब प्रश्न यह उठता है कि अगर ऐसा है, तो यह पैटर्न मंडल राजनीति से गहरे रूप से प्रभावित बिहार या उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश में क्यों सफल होता नहीं दिखाई पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि बिहार में भाजपा और राजग गठबंधन के पास अनेक पिछड़े एवं दलित प्रभावी चेहरों का एक कोलाज मौजूद था, जिसमें नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेता शामिल हैं। नीतीश कुमार का गैर-यादव, पिछड़े समूहों, महादलित सामाजिक समूहों में अपना प्रभाव तो है ही, अगड़े वोटों के एक हिस्से पर भी उनका अच्छा असर है। वहीं जीतन राम मांझी के कारण मुसहर, जो बिहार में एक बड़ी 'महादलित जातीय समूह' है, राजग की तरफ बड़े पैमाने पर झुकी।

चिराग पासवान के कारण संख्या बल में बिहार की सबसे बड़ी दलित जाति दुसाध या पासवान की गोलबंदी राजग के पक्ष में हुई। इसलिए बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के भयदोहन पर आधारित गोलबंदी के वृत्तांत पिछड़ों एवं दलितों में प्रभावी नहीं हो सके।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन की कमजोरी, उसमें प्रभावी नेताओं का अभाव इत्यादि के कारण 'इंडिया' गठबंधन की जातीय अस्मिता आधारित गोलबंदी की राजनीति सफल नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ, मध्य प्रदेश में भाजपा के पास पिछड़े एवं अति पिछड़े समूहों से जुड़े अनेक नेता मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रह्लाद सिंह पटेल आदि अनेक पिछड़े, अति पिछड़े चेहरों ने वहां कांग्रेस एवं 'इंडिया' गठबंधन के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) की राजनीति को इस चुनाव में कमजोर बना दिया।

यह ठीक है कि आगे आने वाले समय में हिंदी पट्टी की राजनीति भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण तो होगी ही, 'इंडिया' गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। एक तरफ भाजपा को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि राज्यों में अपनी सांगठनिक एवं चुनावी रणनीति पर विचार कर उसे पुनर्नवा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ 'इंडिया' गठबंधन से जुड़े राजनीतिक दलों के लिए भी उत्तर प्रदेश में अपने अर्जित प्रभाव को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी।

गैर-यादव पिछड़े, अति पिछड़े एवं दलितों का जो हिस्सा उनकी तरफ झुका है, उन्हें अपने साथ जोड़े रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। राजग गठबंधन को उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के प्रदेशों में पिछड़े, अति पिछड़े एवं दलित समूहों में जमीन से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार करनी होगी, जो इन समूहों को पुनः अपनी तरफ ला सके। हिंदुत्व एवं विकास की राजनीति के साथ उसे अपने पक्ष में सामाजिक समूहों के गठबंधन को पुनर्गठित करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विकसित भारत' के जिस लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं, उसे प्राप्त करने के लिए राजग गठबंधन के सभी दलों में एक प्रतिबद्ध भाव जगाना भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर-परिचित संवाद शैली में राजग गठबंधन की सरकार को अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में चला पाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। देखना यह है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत एवं उसकी राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

विनोबा भावे

जब हम विकर्म की सहायता से स्वधर्म की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो वे अतंत: स्वाभाविक और सहज हो जाते हैं और तब ऐसे कर्म स्वभाव बन जाते हैं। यही कर्मयोग की कुंजी है।

बिना कर्म किए दोषों को जानना संभव नहीं

मन को *समझने के लिए कर्म बहुत जरूरी है। हम अपने दोषों को तभी दूर कर सकते हैं, जब हम उनके प्रति जागरूक हो जाएं। दोषों का ज्ञान हमें कर्म करते समय ही होता है। फिर उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए विकर्म का प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक रूप से विकर्म के निरंतर प्रयोग से हम धीरे-धीरे जानने लगेंगे कि स्वधर्म करते हुए कैसे अनासक्त रहना है, कैसे इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, लोभ, मोह आदि से परे रहना है। अनासक्त और निष्काम कर्म बार-बार और बिना प्रयास के होने लगते हैं, तो हमें उनके होने का पता भी नहीं चलता, जब कर्म प्रयासहीन और भारहीन हो जाता है, तो वह अकर्म में परिवर्तित हो जाता है। अकर्म का मतलब है प्रयासहीन, भारहीन स्वाभाविक कर्म। बच्चा चलना सीखता है, तो वह*

खूब मेहनत करता है। हम उसका उत्साहवर्धन करते हैं। बाद में यही चलना स्वाभाविक हो जाता है, जबकि तैराकी सीखना कठिन है। शुरू-शुरू में थकान लगती है। बाद में थकान दूर करने के लिए तैराकी की जाती है। तैरना थकाने वाली क्रिया नहीं रह जाती, तो शरीर सहजता से पानी पर तैरने लगता है। मन को थकने की आदत होती है, जब वह सचेत रूप से काम में लगा होता है, तब थक जाता है। लेकिन जब कर्म स्वाभाविक रूप से होते हैं, तो कोई तनाव महसूस नहीं होता। तब कर्म अकर्म बन जाता है और तब यही आनंद बन जाता है। कर्म का अकर्म में ऐसा परिवर्तन ही हम चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हमें कर्म करना चाहिए। यदि हम आकाश से पूछें कि क्या वह धूप में तपता है, या सर्दी में ठिठुरता है, तो शायद वह यही कहेगा कि मेरे साथ जो भी घटित होता है, उसे आप ही तय कर सकते हैं, मैं नहीं जानता। यानी जब हम विकर्म की सहायता से स्वधर्म की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, तो वे अंततः स्वाभाविक और सहज हो जाते हैं और तब ऐसे कर्म स्वभाव बन जाते हैं। यही कर्मयोग की कुंजी है। सूरज रोज उगता है, लेकिन क्या वह अंधकार को दूर करने, पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करने और लोगों को काम पर लगाने के लिए उगता है? वह तो बस उगता है। उसके होने से ही सारी दुनिया घूमती है, लेकिन खुद उसे यह नहीं पता। प्रकाश देना सूर्य के लिए स्वाभाविक है। अगर आप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य को धन्यवाद दें, तो वह समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं? ऐसे में वह कहेगा कि 'क्या सचमुच मैंने ऐसा किया है, कृपया थोड़ा अंधकार लाओ। अगर मैं उसे दूर कर सकूंगा, तभी मुझे ऐसा करने का श्रेय देना'। लेकिन सवाल है, क्या हम अंधकार को सूर्य तक ले जा सकते हैं? सूर्य का अस्तित्व अंधकार को दूर करता है और प्रकाश लाता है। कोई उस प्रकाश में अच्छी किताबें पढ़ सकता है, कोई दूसरों की मदद कर सकता है या फिर कोई किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। चाहे कोई अच्छा करे या बुरा, सूर्य उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वह तो यही कहेगा कि प्रकाश मेरा स्वभाव है। मेरे लिए होने का मतलब है चमकना। इसलिए प्रकाश देने में मुझे कोई तनाव नहीं होता।

ज्ञानी व्यक्ति

सूत्र

कर्म, विकर्म और अकर्म का चक्र ही हमें जीवन में पूर्णता का मार्ग दिखाता है। हम जो कुछ भी करें, निरंतरता के साथ तनावमुक्त होकर करें, तभी संपूर्णता हासिल हो सकती है। जब तक कुछ करेंगे नहीं, अपने भीतरी दोषों को कैसे जान पाएंगे! ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विकर्म की सहायता से कर्म करता है और तब उसका कर्म अकर्म बन जाता है।

दूसरा पहलू

इस देश का जैज के साथ एक समृद्ध मौलिक रिश्ता है, जिसमें अमेरिकी तकनीक क्षेत्रीय परंपराओं और लय में समाहित है।

सुनेंगे, तो आप भी करेंगे दक्षिण अफ्रीकी जैज से प्यार

शायद उत्तरी अमेरिका के बाहर किसी भी देश का जैज संगीत के साथ उतना समृद्ध या मौलिक रिश्ता नहीं है, जितना दक्षिण अफ्रीका का है। 1950 और 1960 के दशक में जब रंगभेदी सरकार ने नस्ली पदानुक्रम के एक क्रूर कानून को लागू किया, तो दक्षिण अफ्रीकी संगीतकारों, कवियों, कलाकारों, कट्टरपंथी पादरियों और आयोजकों ने इस संगीत में अश्वेत विश्वबंधुत्व, अंतरजातीय प्रयोग और मुक्त विचार का प्रतीक पाया, जो रंगभेदी शासन के लिए अभिशाप था।

जियोवानी रुसोनेलो

1950 और 1960 के दशक में जब रंगभेदी सरकार ने नस्ली पदानुक्रम के एक क्रूर कानून को लागू किया, तो लोगों ने इस संगीत को अन्याय से मुक्ति का प्रतीक माना।

कई महान संगीतकार निर्वासन में चले गए व कई अपने देश की दमित आबादी के लिए वास्तविक राजदूत बन गए। लेकिन घर लौटकर किप्पी मोकेत्सी, रॉबी जेनसन व डॉली राथेबे जैसे लोगों ने संगीत का विकास जारी रखा।

अमेरिकी बीवोपर्स की शानदार बहादुरी को अपना आदर्श मानते हुए सोफियाटाउन, जोहानिसबर्ग व डिस्ट्रिक्ट सिक्स केप टाउन के मिश्रित आबादी वाले पड़ोस में युवा संगीतकारों ने जैज की तकनीक में अपने उपयोग की चीजों को खोजा और उन्हें अपनी क्षेत्रीय परंपराओं में समाहित किया। जोहानिसबर्ग और पूर्वी कैप में इसिकाथामिया की गायन परंपरा व क्षेत्रों की स्थिर तथा जुलु और खोसा नृत्य लय ने मजबूत प्रभाव डाला। केप टाउन में इंग्रोवाइजर कलाकारों ने टाउनशिप की अश्वेत आबादी के कार्निवल संगीत को अपनाया, जिसमें मलयेशियाई, भारतीय, डच, खोइसन और अश्वेत अफ्रीकी विरासतों का मिश्रण था। कई महान संगीतकार निर्वासन में चले गए व कई अपने देश की दमित आबादी के लिए वास्तविक राजदूत बन गए। लेकिन घर लौटकर किप्पी मोकेत्सी, रॉबी जेनसन व डॉली राथेबे जैसे लोगों ने संगीत का विकास जारी रखा।

तीन दशक पहले जब देश में रंगभेद खत्म हुआ और एक नया वसंत आया, तो संगीतकारों की एक नई पीढ़ी, जिसे कथित तौर पर जन्मजात स्वतंत्र पीढ़ी कहा जाता है, अपने सवालों के साथ जैज संगीत में आई। यह पीढ़ी परंपरा के अर्थ को जानने के लिए उत्सुक थी। अब उनके आदर्श अवैध नहीं रह गए थे। तब से दक्षिण अफ्रीकी समाज और उसके साथ संगीत भी विकसित होता रहा। शर्ली हॉर्न, सारा वॉन, मैक्स रोच और जॉन कोलट्रेन जैसे सितारों के साथ यदि आप पांच-पांच मिनट का समय बिताएं, तो निश्चित रूप से आप दक्षिण अफ्रीकी जैज संगीत से प्यार करने लगेंगे। प्रसिद्ध पियानोवादक अब्दुल्ला इब्राहिम द्वारा गाया गया 'अफ्रीकन मार्केटप्लेस' केप टाउन जैज परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें मजबूत गोएमा लय जोर से बजती है। यह केप टाउन की भावना और हवा में मौजूद आनंद को सामने लाती है। व्यक्ति व समाज के रूप में हमारे सामने तमाम चुनौतियों के बावजूद हमेशा खुश रहने, जीवन में एक मजबूत लय बनाए रखने और गोएमा को महसूस करने का विकल्प होता है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

जल भंडारण में कमी

भारत के जलाशयों में पानी कम बचा है। 150 बड़े जलाशयों में मात्र 22 फीसदी पानी बचा है, जो एक दशक में सबसे कम है।

राजा जनक की सभा में एक ब्राह्मण था, जो भी उसे शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाता था, उसे वह पानी में डुबो देता था। बाद में उसे अष्टावक्र ऋषि ने हराया।

अष्टावक्र का ज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

शास्त्रों के अनुसार ऋषि अष्टावक्र को गर्भ में ही सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। एक बार की बात है, जब उनके पिता से कुछ अशुद्ध पाठ हो गया, तो उन्होंने गर्भ से ही कहा कि आप गलत पाठ क्यों कर रहे हैं? इससे पिता नाराज हुए और कहा कि अभी से इतना टेढ़ा है, तो बाद में क्या करेगा। उन्होंने शाप दिया कि तू आठ जगह से टेढ़ा पैदा होगा। इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा।

राजा जनक की सभा में एक ब्राह्मण ने प्रण किया था कि जो उसे शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकेगा, उसे वह जल में डुबो देगा। धीरे-धीरे कई ब्राह्मण जल में डूब गए, जिनमें अष्टावक्र ऋषि के रिश्तेदार भी थे। इसके बाद अष्टावक्र खुद राजा जनक की सभा में पहुंचे। उन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग उनके ऊपर हंसने लगे। इस पर ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो समझता था कि जनक की सभा में कोई तो ज्ञानी होगा, लेकिन यहां तो सभी चमड़ी के जानने वाले हैं।

बाद में सभी ने उनसे क्षमा याचना की और उस ब्राह्मण को बुलाया गया, जो पानी में डुबो देता था। शास्त्रार्थ हुआ, तो अष्टावक्र जीत गए। उन्होंने उक्त ब्राह्मण से कहा कि चलो पानी में डूबो। वह भागने लगा, तो ऋषि ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसने बताया कि मैं वरुणदेव का दूत हूं। वरुणदेव यज्ञ कर रहे हैं। वहां पंडितों की जरूरत थी, अब यज्ञ संपन्न हो गया है, मैं उनको अभी वापस लाता हूं। इस तरह अष्टावक्र ने सभी ब्राह्मणों को मुक्त कराया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 मई, 1977

जनता पार्टी में चारों घटकों का विलय

जनता पार्टी में चारों घटकों का विलय

संसद में जपा का सी.एफ.डी. एक मात्र घटक

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी के विशेष महाधिवेशनों में आज अपनी-अपनी पार्टियों को भंग कर जनता पार्टी नामक नई राष्ट्रीय पार्टी में विलय किए जाने का प्रस्ताव पारित किया।

झीलें बचेंगी, तभी हम बचेंगे

झीलों एवं तालाबों में ऑक्सीजन की कमी से जैव विविधता को नुकसान तो पहुंचता ही है, मानव अस्तित्व के लिए भी यह खतरनाक है।

पंकज चतुर्वेदी

पर्यावरण

कब्जे के लिए सूखतीं, घरेलू व अन्य निस्तार के कारण बदबू मारतीं, पानी की आवक के रास्ते में खड़ी रुकावटों से सूखतीं, सफाई न होने से उथली होतीं और जलवायु परिवर्तन से जूझतीं दुनिया भर की झीलें बीमार हो रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय पत्रिका *'अर्थ फ्यूचर' के ताजा अंक में प्रकाशित शोध 'ग्लोबल लेक हेल्थ इन एंथरोपोसेन : सोशल इंप्लीकेशन ऐंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीस'* में चेतावनी दी है कि जिस तरह मानव स्वास्थ्य के लिए रणनीति बनाई जाती है, ठीक उसी तरह झीलों की तंदुरुस्ती के लिए व्यापक नीति जरूरी है। इस शोध में 10 हेक्टेयर से अधिक फैलाव वाली दुनिया की 14,27,688 झीलों की सेहत का आकलन किया गया है, जिनमें भारत की 3043 जल निधियां भी हैं। यह समझना होगा कि झीलें जीवित प्रणालियां हैं, जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, प्रसन्न रहने के लिए स्वच्छ पानी, अपने भीतर जीव-जंतु जीवित रखने के लिए संतुलित ऊर्जा

और पोषक तत्वों की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इन्सान की ही तरह झीलें विभिन्न रोगों की शिकार हो रही हैं, जैसे-बुखार आना अर्थात अधिक गरम होना, परिसंचरण, श्वसन, पोषण और चयापचय संबंधी मुद्दों से लेकर संक्रमण और विषाक्तता की तरह झीलों की कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक बात और झीलें बारिश से जितना पानी पाती हैं, उससे दोगुना वाष्पित करती हैं। झीलों की सेहत से बेपरवाही रही, तो समूचे पर्यावरणीय तंत्र पर इसका असर पड़ेगा, जिससे झीलों पर निर्भर बड़ी आबादी के सामाजिक-आर्थिक जीवन में भूचाल आ जाएगा। भारत का हर तालाब अपने आसपास भूवैज्ञानिक इतिहास और पर्यावरणीय महत्व की एक अनूठी कहानी समेटे हुए है। भारत जैसे देश में जहां, तालाबों के किनारे कई पर्व, मान्यताएं और धार्मिक गतिविधियां अनिवार्य मानी जाती हैं, उनका अस्तित्व ही झील की सेहत पर निर्भर है। झील-तालाब बीमार हो, तो इलाके का कार्बन और ताप अवशोषण प्रभावित होता है, जो जैव विविधता को क्षति और बाढ़-सूखे के रूप में सामने आता है। स्थानीय समाज का जलस्रोत यदि सेहतमंद न हो, तो जलजनित रोग बढ़ेंगे।

तालाब-झील में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना भी खतरनाक है। यह अन्य जलचरों और वनस्पति के लिए जानलेवा है। जलकुंभी या फिर पानी में अधिक मात्रा में दूषित अवशिष्ट का मिलना, गंदे पानी का निस्तार ऑक्सीजन कम होने के मूल कारक हैं। इससे पानी की क्षारीयता भी बढ़ती है, जो किसी तालाब के गंभीर रूप से बीमार होने का लक्षण है। इन्सान के स्वस्थ शरीर की ही तरह झीलों को भी पर्याप्त ऑक्सीजन और अति क्षारीयता से मुक्ति चाहिए होती है। एक बात और, यदि दरिया का पानी हृष्ट-पुष्ट न हो, तो उससे उगने वाले उत्पाद में भी पौष्टिकता में कमी होती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि झीलों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। गंभीर जल दोहन और बरसात की अनियमितता के कारण कई झीलों में जलस्तर तेजी से नीचे गिरा, जबकि दूसरी तरफ पेयजल, सिंचाई और मछली पालन आदि में पानी की खपत बढ़ी है। इससे झीलों का पोषण-संतुलन तब गड़बड़ा जाता है, जब उसमें पोषक तत्वों की सांद्रता या तो अधिक हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए। इस तरह झील का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है।

पोषक तत्वों की अचानक अधिकता होने से जल निधियों की ऊपरी सतह पर हरे रंग की परत जमने से हम सभी पहले से वाकिफ हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में 'यूट्रोफिकेशन' कहते हैं। वास्तव में हरापन एक तरह के बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे सूक्ष्म या फिलामेंट्स शैवाल कहा जाता है। गंदे पानी सीवरेज, कारखानों से निकलकर अपशिष्ट जल और खेतों से बहकर आए खाद-उर्वरक के अपवाह से इस तरह का विकार जल्दी वृद्धि करता है। इसके कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। समझना होगा कि इस तरह के शैवाल का कुप्रभाव महज जल निधि तक सीमित नहीं रहता, यह सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि कुछ साइनोबैक्टीरियल से विषाक्त पदार्थों का उत्पादन होता है, जो श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा कर देता है। इस अंतरराष्ट्रीय शोध में बताया गया है कि इस तरह से बीमार हुई झील के न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रभाव होते हैं, जिससे सेलुलर और जीनोमिक क्षति, प्रोटीन संश्लेषण अवरोध और मनुष्यों और वन्यजीवों में संभावित कार्सिनोजेनेसिस होता है।

चिंतन

पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में समावेशी भारत की झलक

भा प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी अपनी तीसरी पारी का आगाज कर चुके हैं। लगातार तीसरी बार पीएम बन कर नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड की बराबरी कर ली है। पीएम मोदी के साथ करीब 65 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मोदी कैबिनेट में शामिल चेहरों के चयन में योग्यता, अनुभव के साथ सामाजिक भागीदारी का ध्यान रखा गया है। कैबिनेट में जहां 20 से अधिक पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे नेताओं को फिर से मौका मिला है, वहीं कई नए चेहरों को भी शामिल किया है। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जैसे कई नेता पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल में चुनावी राज्यों का खास ध्यान रखा गया है। हरियाणा में पांच सांसदों में से तीन नेता मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से आठ और झारखंड से दो मंत्री बनाए गए हैं। इसी वर्ष जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जैसा कि सरकार की ओर से पूर्व में संकेत दिया गया है, सितंबर या अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर से भाजपा के दोनों सांसदों को मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2025 के शुरू में ही दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए इस कैबिनेट में बिहार से आठ तो दिल्ली से दो नेता मंत्री बनाए गए हैं। मोदी कैबिनेट में राजग के सभी सहयोगियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जदयू, टीडीपी, जदएस, एलजीपी (रामविलास), शिवसेना शिंदे, अपना दल, आरपीआई, आजसू आदि सभी छोटे बड़े घटक दलों को राजग मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पूर्व की तरह इस बार भी मोदी ने अपने कैबिनेट में कुछ अप्रत्याशित चेहरों को शामिल कर चौंकाया है। पंजाब से चुनाव हारे रवनीत सिंह बिट्टू और तमिलनाडु से एल मरुगन को मौका दिया गया है। केरल से जीत कर आए सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है। मोदी 3.0 में दक्षिणी राज्यों को साधा गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व का समावेश किया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कैबिनेट को समावेशी रूप दिया गया है। चूंकि इस बार भाजपा की यह सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की नहीं है, बल्कि राजग को मिले बहुमत की है, इसके बावजूद, उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम के रूप में नरेन्द्र मोदी जहां सबको साथ लेकर चलेंगे, वहीं विकास को आगे लेकर जाएंगे, आर्थिक सुधार के नए चरण शुरू करेंगे और अर्थव्यवस्था को नया रूप देंगे। पीएम गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्यकरते रहेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को गति देंगे। पीएम के शपथग्रहण समारोह में भारत ने अपने पड़ोसियों को आमंत्रित किया, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशेल्स, मालदीव और मॉरीशस के राष्ट्र प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मोदी 3.0 सरकार अपने सभी पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नीति चीनपरस्त रही है, वे भारत विरोध नारे के साथ सत्ता में आए हैं, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने शपथग्रहण रूप में मालदीव के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, मालदीव ने इसे स्वीकार भी किया और राष्ट्रपति मुइज्जू आए भी। भारत ने मालदीव को संदेश दिया कि वह अपना पड़ोसी धर्म निभाता रहेगा, चाहे मालदीव की भारत के प्रति जैसी भी सोच हो। भारत ने चीन को भी संदेश दिया कि मोदी सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ प्रगाढ़ दोस्ती कायम रखेगी। पाकिस्तान ने जरूर निराश किया, पाक पीएम ने पीएम मोदी को बधाई तक नहीं दी। उम्मीद है मोदी 3.0 सरकार समावेशी विकास, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित जनाकांक्षाओं पर खरा उतरेगी।

सारा संसार

मनाकुला विनयगर मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर में से एक है जिसका निर्माण फ्रांसीसी क्षेत्र पांडिचेरी के दौरान किया गया था जो 1666 साल पहले का है।

मोदी 3.0
अखिलेश आर्येंदु

जन भावनाओं पर खरा उतरने की चुनौती

> पिछली दो पारियों में जिन निर्णयों की वजह से मोदी के मजबूत इरादों से जनता को उनके संकल्पों के बारे में पता चला था, ऐसे निर्णय क्या फिर मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में ले पाएंगे? जिन जन भावनाओं को पूरा करने की चुनौतियां मोदी के सामने अगले पांच साल में होंगी, जिन पर खरा उतरने के साथ सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं पर भी खरा उतरने की चुनौती मोदी के सामने होगी, अभी हम कह सकते हैं कि देश हित जिसके लिए सर्वोपरि हो, वह हर चुनौती को भी पार करने का दम रखता है। हां, इतनी राहत की बात जरूर है कि सहयोगी दलों ने मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया है उन्होंने निर्णयों में भी साथ देने की बात कही है।

उतार चढ़ाव इस संसार का सबसे बड़ा सच है। इस सच को जो स्वीकारते हुए उचित समय पर सही निर्णय लेने के लिए खुद को बदल लेता है वह कभी हारता नहीं। इस उक्ति को किसी में चरितार्थ देखना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखा जा सकता है। नए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेन्द्र मोदी ने जिस विश्वास और उत्साह से कहा- न हारा था न हारेंगे, वह उनके भावी कदमों और नीतियों का संकेत भर नहीं है बल्कि देशहित में लिए जाने वाले निर्णयों का सूचक भी है। पिछली दो पारियों में जिन निर्णयों की वजह से मोदी के मजबूत इरादों से जनता को उनके संकल्पों के बारे में पता चला था, ऐसे निर्णय क्या फिर मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में ले पाएंगे? जिन जन भावनाओं को पूरा करने की चुनौतियां मोदी के सामने अगले पांच साल में होंगी, जिन पर खरा उतरने के साथ सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं पर भी खरा उतरने की चुनौती मोदी के सामने होगी, अभी हम कह सकते हैं कि देश हित जिसके लिए सर्वोपरि हो, वह हर चुनौती को भी पार करने का दम रखता है। हां, इतनी राहत की बात जरूर है कि सहयोगी दलों ने मोदी को बिना शर्त समर्थन ही नहीं दिया है बल्कि पूरे मन से पांच साल तक साथ रहकर देशहित में लिए जाने वाले निर्णयों में भी साथ देने की बात कही है। गठबंधन की सरकार के स्वभाव के अनुरूप यह अच्छा कहा जा सकता है। अभी से यह किसी को नहीं सोचना चाहिए कि कहीं नीतीश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू बीच में साथ छोड़कर चले गए तो क्या होगा।

भारतीय लोकतंत्र शुरू से भीड़ तंत्र का समर्थक रहा है। मूल्य आधारित लोकतंत्र की बात कही तो जाती है लेकिन अब राजनीति में मूल्यों की बात करना मूर्खता समझी जाने लगी है, इसलिए मोदी का तीसरा कार्यकाल भीड़ तंत्र की उफनाती भावनाओं को पूरा करने की बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले विपक्ष के आरोपों को झूठ साबित करने के लिए आरक्षण और संविधान की रक्षा के संकल्प के लिए दलितों व पिछड़ों में विश्वास पैदा करने की बड़ी चुनौती है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जहां जाति ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान, गुण और क्षमता मानी जाती है। चूंकि आरक्षण की व्यवस्था संविधान के जरिये हुई है और आजादी के बाद से ही पार्टियों के जीतने हारने का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए आरएसएस के हिंदुत्व वाले एजेंडे को छोड़ने और एनडीए के सांझा एजेंडे के मुताबिक कार्य करना होगा। यह मोदी के नेतृत्व की पहली परीक्षा जैसा होगा। पिछले दो कार्यकालों में विपक्ष मजबूत नहीं था। जनता और देशहित में फैसले लेने में कोई खास दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। विपक्ष इस बार मजबूत ही नहीं, आक्रामक भी है। सरकार को बदनाम करने की कवायदें खूब होंगी। जातियों को भड़काने और लड़ाने के अवसर ज्यादा तलाश करते हुए कई दल दिखेंगे। इस चुनौती से भी इस सरकार को पार पाना होगा। इस बार विपक्ष ने आरक्षण, संविधान बचाओ के साथ-साथ बेरोजगारी और महंगाई जनता के दिल को छूने वाले मुद्दे चुनाव के वक्त जोर-शोर से उठाए थे। अगड़ा-पिछड़ा का सवाल चुनाव के

वक्त कहीं ज्यादा जोर-शोर से इस बार उठा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगड़े-पिछड़े की राजनीति पर सरकारें बनती-बिगड़ती रही हैं। वीपी सिंह की सरकार आरक्षण के मुद्दे पर ही चली गई थी, इसलिए आने वाले पांच सालों में इन सभी मुद्दों से निपटना मोदी के लिए कठिन चुनौती हो सकती है। हां, प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनका स्वभाव जिस तरह का है उससे यह कहा जा सकता है कि इस बार वे उन सभी समस्याओं और चुनौतियों का सामना बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पिछले दस साल का अनुभव है। हर व्यक्ति और सरकारें अनुभवों से सीखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी स्वीकार करते हैं कि वे देश समाज से हर पल कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पिछले मोदी काल में समान नागरिक संहिता और एनआरसी का मुद्दा अब सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर हल करना होगा। चंद्र बाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुसलमानों को वहां पिछली सरकार ने 4 प्रतिशत आरक्षण धर्म के आधार पर दिया था। यह भले ही संविधान के अनुरूप न हो लेकिन चन्द्र बाबू नायडू इसकी समीक्षा कर इसे खत्म करेंगे, लगता नहीं है, क्योंकि आन्ध्र में उनकी सरकार को वोट मुसलमानों ने भी दिया है, तो उस वोट बैंक को नाराज करना वे नहीं चाहेंगे। ऐसे में भाजपा अपनी विचारधारा के खिलाफ और संविधान के खिलाफ इसे स्वीकार करेगी, इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। विपक्ष ऐसे में अपने सहयोगी दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश फिर कर सकता है, इसलिए इस बार मोदी को पहले से कहीं ज्यादा सहयोगियों को साधते-संभालते हुए चलना होगा। किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, रोजगार, कृषि विकास को अहमियत देते हुए भुखमरी, गरीबी और कुपोषण जैसे तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए कहीं तेज प्रयास करने होंगे।

इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की विधान सभाओं के चुनाव होने हैं। मोदी के कार्य और लोकप्रियता की एक और परीक्षा इन राज्यों के चुनाव में भी परखी जाएगी, इसलिए इन राज्यों के राजनीतिक समीकरण को साधना एक चुनौती होगी। अग्निवीर योजना की एनडीए के सहयोगी दल समीक्षा करके इसे विवादों से दूर करने की बात अब जोर-शोर से उठाएंगे, इसका संकेत सहयोगी दल के नेता देने लगे हैं। इस बार आम चुनाव में हिंदू जातियों की जन गणना कराने की बात विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। भारतीय जनता पार्टी इसे जातीय एकता और सामाजिक समरता के लिए खतरा बताकर इसे खारिज करती रही है। विपक्ष ऐसे अवसर की तलाश में रहेगा कि यह मुद्दा एनडीए के सहयोगी दल उठाएं और वह उसका समर्थन कर एनडीए की एकता को तोड़ दें। इसलिए देशहित में स्थिर सरकार के मद्देनज़र सहयोगियों को भी ऐसे मुद्दों को अहमियत देने के बजाय सांझा कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने पर जोर देना चहिए। फिर भी मोदी के लिए यह चुनौती रहेगी ही कि सहयोगी दल किसी भी मुद्दे को विपक्ष के लिए अवसर में न बदलने पाएं।

सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास जैसे नारों की समीक्षा भी इस नई सरकार को करनी होगी। नीतियों में पहले से ज्यादा सहमति बनाकर आगे बढ़ने की चुनौती भी कम नहीं होगी। जो जनहितकारी नीतियां केंद्र राज्यों में लागू करेगी अब उसे सहयोगियों की सहमति से ही लागू करना होगा।

चुनावी घोषणा पत्रों की परीक्षा भी अगले पांच सालों में होनी है, खासकर एनडीए में शामिल दलों के घोषणा पत्रों की। सहयोगी दल चाहेंगे कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे मोदी सरकार उसे लागू करे। सहयोगी दलों की घोषणा पत्रों में क्षेत्रगत समस्याओं को दूर करने के भी वादे हुआ करते हैं। उन वादों को सहयोगी दल पूरा करवाने के लिए दबाव बना सकते हैं। यह भी मोदी के लिए चुनौती होगी। जिसमें देश प्रथम समाया हो, उसके लिए चुनौतियां भी समाधान जैसी हो जाती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

चेतना का मूल आधार है अस्तित्व का ज्ञान

संकलित
दर्शन

जब हम दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह ज्ञान होता है कि संपूर्ण विश्व एक है। आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक तथा प्राण-जगत भिन्न-भिन्न नहीं हैं। समस्त विश्व, यहां से वहां तक, एक है। बात इतनी ही है कि अलग-अलग दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण वह विभिन्न प्रतीत होता है। 'मैं शरीर हूं, इस भावना से जब तुम अपनी ओर देखते हो तो यह भूल जाते हो कि मैं मन भी हूं'। और, जब तुम अपने को मनोरूप में देखने लगते हो, तो तुम्हें अपने शरीरत्व की विस्मृति हो जाती है। विद्यमान वस्तु केवल एक है और वह तुम हो। वह तुम्हें जड़ या शरीर के रूप में अथवा मन या आत्मा के रूप में दिख सकती है। जन्म, जीवन, मरण ये सब भ्रम मात्र हैं। न कोई कभी मरता है और ना कोई कभी जन्म लेता है। होता इतना ही है कि मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाता है। लोगों को मृत्यु से इतना भय पाते देख मुझे बहुत दुख होता है। वे मानो जीवन को पकड़ कर रखने की सतत चेष्टा करते रहते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें जीवन दो। हमें मरणोत्तर जीवन दो। यदि कोई आए और उन्हें बताए कि मृत्यु के बाद भी वे विद्यमान रखेंगे, तो वे कितने आनंदित होते हैं? वस्तुतः मनुष्य के अमरत्व में मैं अविश्वास ही किस तरह कर सकता हूं? मैं मृत हूं, यह कल्पना ही मैं किस प्रकार कर सकता हूं? तुम यदि अपने को मृत सोचने की कोशिश करो तो देखोगे कि तुम अपने मृत शरीर को देखने के लिए वर्तमान हो ही।

किसी के बारे में पहले से राय नहीं बनानी चाहिए

संकलित
प्रेरणा

बुद्ध अपने शिष्यों को अलग-अलग घटनाओं की मदद से भी उपदेश दिया करते थे। उनका एक शिष्य ऐसा था जो किसी से ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता, काम पूरा होने के बाद एकांत में चला जाता। वह ध्यान में बैठे रहता था। कुछ शिष्य बुद्ध से एकांत में रहने वाले शिष्य की शिकायतें करने लगे। धीरे-धीरे उस शिष्य की बुराई ज्यादा होने लगी। बुद्ध के पास उस शिष्य की शिकायतें और ज्यादा पहुंचने लगी तो बुद्ध ने सोचा कि इस शिष्य से बात करनी होगी, उसके लिए इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? एक दिन बुद्ध ने एकांत में रहने वाले शिष्य से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? सभी लोग तुम्हारी शिकायतें कर रहे हैं। उस शिष्य ने कहा कि तथागत आपने घोषणा कर रखी है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़ देंगे तो मैंने ये तय किया है कि जब तक आप यहां हैं, मैं आपसे एकांत और मौन का महत्व समझ लूं। आपके बाद मुझे इन बातों को कोई और कैसे समझाएगा। शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि तुम सभी इस शिष्य की गलत शिकायतें कर रहे हो। तुम लोगों ने इसे जाने बिना इसके बारे अपनी गलत राय बना ली है। तुमने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम सभी की आदत है कि दूसरों को गलत तरीके से परखते हो।ध्यान रखें हमें किसी भी व्यक्ति के लिए जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। किसी व्यक्ति से मिलते समय उसके बारे में पहले से कोई राय न बनाएं। पहले उस व्यक्ति की गतिविधियों को देखें, समझें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।

चुनावी नतीजे
चेतनादित्य आलोक

सुनें सबकी करें जन मन की

लोकसभा 2024 चुनाव के नतीजों का पहला संदेश यह है कि समय और परिस्थितियों के अनुरूप नेताओं और राजनीतिक दलों को अपनी नीति-रीति बदलनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के साथ-राजनीति का स्वरूप भी बदलता रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव के 37.3 प्रतिशत मत की तुलना में इस बार भाजपा के कुल मत प्रतिशत में लगभग एक प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट आना तथा 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा को लगभग 60 सीटों तथा राजग को 55 से भी अधिक सीटों का नुकसान होना इस बात को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त कुल 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी को पिछली बार के 19.5 प्रतिशत मतों की तुलना में इस बार 21.2 प्रतिशत वोट मिलना भी इसी बात का परिचायक है। जरा इस चुनाव का गणित तो देखिए कि कांग्रेस को मिले कुल मतों में हुई वृद्धि दो प्रतिशत भी नहीं है, जबकि उसकी सीटों की संख्या इस बार दोगुनी हो चुकी है। इन नतीजों की दूसरी सीख यह है कि भाजपा को केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और गरीबों के लिए पांच किलो मुफ्त राशन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे न रहकर उसे राजनीतिक दांव-पेंचों के निहितार्थों को भी समझना चाहिए। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 'राशन नहीं रोजगार' का गूंजता नारा इसी बात को प्रमाणित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के बीच विपक्षी दलों की ओर से दिखाया गया रोजगार का सपना मोदी के राशन की तुलना में अधिक कारगर साबित हुआ। वैसे एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि जब किसी को कोई वस्तु पहली बार मुफ्त में दी जाती है तो वह उपहार होता है, लेकिन यदि उपहार स्वरूप वही वस्तु किसी व्यक्ति को बार-बार दी जाती रहे तो वह वस्तु भी उपहार न होकर उस व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। तात्पर्य यह कि पीएम मोदी ने जो अब तक गरीबों को पांच किलो मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, उसे जनता ने अपना अधिकार मान लिया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई आर्थिक न्याय की संकल्पना को मतदाताओं ने हाथों-हाथ लिया, जिसके अंतर्गत राहुल गांधी बेरोजगारों और गरीब महिलाओं के खातों में 'टकाटक' 8500 रुपये पहुंचाने और गरीबी मिटाने की बात करते देखे गए थे। यह अलग बात है कि ऐसे किसी 'टकाटक' से गरीबी समाप्त नहीं हो सकती। वैसे सियासी सूरमाओं और राजनीतिक पंडितों का इस हार के बाद सीधे-साधे यह कह देना कि देश के राजनीतिक अखाड़े से 'मोदी मैजिक' अब खत्म हो चुका है यह सच नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ओडिशा, दक्षिण भारत के राज्यों एवं मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे मध्य भारत के प्रमुख राज्यों में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने जिस प्रकार से अपना दबदबा कायम रखा है, वह कदापि संभव नहीं हो पाता। इन नतीजों का तीसरा संदेश यह है कि राजनीति में अति-आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। कई बार राजनीतिक पार्टियां भी अपनी राजनीतिक सहूलियतों के हिसाब से जनता के बीच आत्मविश्वास को अहंकार और अहंकार को आत्मविश्वास बताने और उसे साबित करने की बवायद करती रहती हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पीएम मोदी सुनें सबकी और करें जन की। गौरतलब है कि इस चुनाव का एक बहुत बड़ा फैक्टर भाजपा की संवादहीनता रहा है। दरअसल, आपसी खटपट के कारण इस चुनाव में आरएसएस ने कोई भूमिका नहीं निभाई। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं अब पीएम मोदी को अपनी गलती सुधार कर भाजपा एवं संघ के बीच की खटपट को दूर करते हुए स्वस्थ संवाद की परंपरा फिर से स्थापित करनी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

पर्यावरण को खुद नुकसान पहुंचा रहा इंसान

इस साल तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत के कई शहरों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। इस स्थिति का एक प्रमुख कारण पर्यावरण प्रदूषण या प्रकृति का दोष है। इस कारण प्रकृति पर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन गई है। इसी कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान का सबसे बड़ा दुश्मन वर्तमान में इनसान ही है। मानव रोजाना कई गलतियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य पर्यावरण बचाने के लिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की सीख देनी चाहिए। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के तरीके बता सकते हैं। बच्चों को प्लास्टिक और पॉलीथिन के इस्तेमाल करने से रोकना आवश्यक है क्योंकि इस दोनों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है जो कि सदा प्रदूषण का कारण है। *– श्रवण पांडे, बलौदा बाजार*

ट्रेंड

साथ आने का समय

मुझे समुद्र के पास बड़ा होने का सौभाग्य मिला। मुझे यह देखकर दुख होता है कि मानव गतिविधि इसे कैसे नष्ट कर रही है। अब सरकारों, व्यवसायों, निवेशकों, वैज्ञानिकों और समुदायों के लिए हमारे महासागर को बचाने के लिए एक साथ आने का समय आ गया है।
-एंटोनियो गुटेरेस, यूएन महासचिव

शांति लाने में असमर्थ

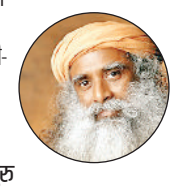

जब हम खुद को शांति की भावना में लाने में असमर्थ होते हैं, तो हर छोटे मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। हर छोटी-छोटी बात के लिए हम एक-दूसरे से झगड़ने लगते हैं।
-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

नीट परीक्षा में हुई धांधली

मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है।
-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

आप कौन हैं

सबसे पहले, यह एक इरादा है। फिर एक व्यवहार, फिर एक आदत उसके बाद फिर एक अभ्यास। तब यह दूसरी प्रकृति बन जाती है। अंततः, यह बस इतना ही है कि आप कौन हैं।
-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

करंट अफेयर

इमरान पाक की राजनीतिक सुलह में बाधक : नवाज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान देश में राजनीतिक सुलह लिए मुख्य बाधा हैं। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि नवाज ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज किसी भी पार्टी से बदला नहीं लेने की भावना के साथ देश में राजनीतिक सुलह के लिए प्रतिबद्ध है। नवाज शरीफ ने सांसदों के साथ एक बैठक के बाद यह टिप्पणी की। बैठक में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के साथ बातचीत के मुद्दे पर चर्चा की गई। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष शरीफ ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री खान खुद हमारे साथ मुद्दों को सुलझाने और बातचीत करने के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। उन्होंने बातचीत की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया क्योंकि पीटीआई इसे सुलझाने के लिए ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही है। नवाज शरीफ ने पार्टी के सांसदों से कहा, 'जब कोई पक्ष गंभीर ही नहीं है तो वह बातचीत कैसे कर सकते हैं?' उन्होंने पिछली कई घटनाओं का उदाहरण दिया जब खान ने पीएमएल-एन के साथ संबंधों को सुधारने वाले प्रस्तावों को ठुकरा दिया था।

ऑफ बीट

दिमाग के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है

'बैलरैट क्लेरेंडन कॉलेज' ने पिछले महीने पांचवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षा में पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर एक परीक्षण किया। स्कूल के अनुसार, 'प्रारंभिक प्रतिक्रिया' से संकेत मिलता है कि ऐसा करने से कक्षा के दौरान शोर कम हुआ और शौचालय जाने के लिए छात्रों के 'ब्रेक' लेने में कमी आई। पानी की बोतलें अब स्कूल के लिए जरूरी मानी जाती हैं लेकिन सवाल यह है कि बच्चों को एक दिन में कितना पानी पीने की जरूरत होती है? इसका उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? बच्चों और किशोरों को कितने तरल पदार्थ की जरूरत होती है? यह मौसम और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है कि बच्चों को कितने तरल पदार्थ की जरूरत है लेकिन सामान्य तौर पर : चार से आठ साल के बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.2 लीटर पानी पीना चाहिए। नौ से 13 साल के लड़कों को 1.6 लीटर पानी पीना चाहिए। नौ से 13 साल की लड़कियों को 1.4 लीटर पानी पीना चाहिए। चौदह साल से अधिक उम्र के लड़कों को 1.9 लीटर पानी पीना चाहिए।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।